सुभाषित *दुनियाकी किसी चीजका आनंद परिपूर्ण नहीं होता, जबतक कि वह किसी मित्रके साथ न लिया जाये।* ❐ *लैटिन*

भारतका मास्टर स्ट्रोक

भारतके पड़ोसी देशोंमें मालदीव भी एक है, जो चीनके दुष्चक्रमें फंसा हुआ है। मालदीवका रवैया भारतके प्रति अच्छा नहीं रहा, लेकिन भारतकी पड़ोसी देशोंके प्रति उदार और सहयोगकी नीतिसे अब मालदीवका भारतके प्रति दृष्टिकोणमें बदलाव आया है। भारत मालदीवको बराबर सहयोग करता रहा है। भारत और मालदीवके बीच भौगोलिक दूरी काफी कम है और पर्यटन उसका प्रमुख उद्योग है। इन पर्यटकोंमें भारतीयोंकी संख्या बहुत अधिक होती है। मालदीवके चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पदभार ग्रहण करनेके लगभग नौ महीने बाद भारतकी ओर से पहली उच्चस्तरीय यात्राके तहत परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर का मालदीव पहुंचना अत्यन्त महत्वपूर्ण होनेके साथ ही द्विपक्षीय सम्बन्धोंको फिर से पटरीपर लानेका प्रयास है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरताको बनाये रखते हुए दोनों देशोंके बीच सुरक्षा सहयोगको मजबूत करनेका भी यह ठोस कदम है। जयशंकर ने राष्ट्रपति मुइज्जू और रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून के साथ सकारात्मक बैठक की। दोनों देशोंके बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोगको बढ़ानेके उपायोंपर सार्थक वार्ता इस बात की ओर संकेत करता है कि आपसी सम्बन्धोंमें सुधार हो रहा है। दोनों देशोंने समुद्री सुरक्षाके लिए संयुक्त पहल और क्षेत्रमें शांति बनाये रखनेके साझा हितोंपर भी जोर दिया। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब मालदीव और चीन के बीच सैन्य सहयोग गहराते जा रहे है। हाल ही में चीन का एक आधुनिक अनुसंधान पोत मालदीवके बंदरगाह पहुंचा जो भारतके लिए चिन्ताकी बात है। चीन आर्थिक और सैन्य शक्तिका उपयोग करके अपना प्रभाव बढ़ानेका प्रयास कर रहा है, जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षाके लिए खतरा है लेकिन भारत अपनी उदार और सहयोग नीतिसे आपसी सम्बन्धोंको मजबूत बनानेमें सफल रहा। वार्तामें सांस्कृतिक रिश्तोंको भी नया आयाम देनेकी कोशिश की गयी है। यात्राके दौरान भारत ने मालदीवमें एकीकृत भुगतान इण्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली शुरू करनेके लिए एक समझौतेपर हस्ताक्षर भी किया, जिसका मालदीवमें पर्यटन उद्योगपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस पहलसे आर्थिक सहयोगको बढ़ावा मिलेगा। भारतका यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इससे मालदीव में चीनके बढ़ते प्रभावको कम करनेमें सहायता मिलेगी। राष्ट्रपति मुइज्जू के बदले रुख से ऐसा प्रतीत होता है कि मालदीव का चीन से मोहभंग हो सकता है, जो दोनों देशोंके हितमें है।

हैवानियत की हद

कोलकाताके एक सरकारी अस्पतालमें प्रशिक्षु महिला डाक्टरकी दुष्कर्मके बाद हत्या बंगालमें कानून व्यवस्थापर सवाल खड़ा करता है। प्रारम्भिक पोस्टमार्टम रिपोर्टमें हत्यासे पहले यौन उत्पीड़नकी पुष्टि हुई है। इस मामलेमें एक आरोपीको गिरफ्तार किया गया है जिसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी अस्पतालमें काम नहीं करता है, पर उसे यहां विभिन्न विभागोंमें बेरोकटोक प्रवेशकी अनुमति थी जो अस्पतालकी लचर व्यवस्थाको कटघरेमें खड़ा करती है। हैवानियत की हदें पार करते हुए दुराचारके बाद जिस नृशंसताके साथ प्रशिक्षु डाक्टर की हत्या की गयी उसने हर किसीको हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्टमें महिला डाक्टर के गले के बायीं ओर की हड्डी टूटी होने और गुप्तांग समेत शरीरमें कई जगहोंपर खून और चोटके निशान उसके साथ हुई दरिंदगीको बयां करते हैं। इस घटनाको लेकर पूरे बंगालमें जूनियर डाक्टरोंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस आक्रोशकी आंच दिल्लीतक पहुंच चुकी है। चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंटकी द्वितीय वर्षकी छात्रासे दुष्कर्म और फिर उसकी बेरहमीसे हत्याकी घटनासे दिल्लीके रेजिडेंट डाक्टर भी आक्रोशित हैं और घटनाकी सीबीआई जांच सहित दिल्लीके अस्पतालोंमें भी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करानेकी मांग की है। अस्पतालोंमें कई स्थान ऐसे है जहां सुरक्षाकर्मी नहीं होते हैं। ऐसेमें रातमें कार्यरत महिला डाक्टरोंमें असुरक्षा की भावना बनी रहती है। अस्पताल प्रशासनको इस घटनासे सबक लेनेकी जरूरत है। इस मामलेको दबानेकी कोशिश भी की जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो यह बेहद दुखद है। इस घटनामें गिरफ्तार आरोपीके अतिरिक्त और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ममता सरकार की जिम्मेदारी है कि मामलेकी जांचमें पारदर्शिता रहे और सच सामने आ सके, तभी दरिंदगीकी शिकार महिला डाक्टर को न्याय और उसकी आत्माको शांति मिल सकेगी।

लोक संवाद

राज्यपालोंका सवैधानिक दायरा

महोदय,-राज्यपालों द्वारा निभायी जानेवाली सक्रिय भूमिका, खास तौरपर गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्योंमें, कोई रहस्य नहीं है और विपक्षके साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसकी काफी आलोचना की गयी है। केन्द्र सरकारने फिरसे राज्यपालोंसे सक्रिय भूमिका निभाने और जनतासे जुड़नेके लिए कहा है। पिछले सप्ताह राज्यपालोंके एक सम्मेलनमें अपने उद्घाटन भाषणके दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूने उनसे गरीबों और वंचितोंसे जुड़ने और राज्यों और केन्द्रके बीच बेहतर समन्वयकी दिशामें काम करनेके लिए कहा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने अपने भाषणमें कहा कि राज्यपालका पद एक ऐसी संस्था है जो लोगोंके कल्याणमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वे बिल्कुल सही थे लेकिन समस्या तब होती है जब इनमेंसे कुछ राज्यपाल खुदको राजनेताओंकी भूमिकामें रखते हैं जो निर्वाचित राज्य सरकारोंको धमकाने और परेशान करनेके लिए काम करते हैं। उनमेंसे कुछ लोग राज्य सरकारों द्वारा पारित विधेयकोंको महीनों और सालोंतक दबाये रखते हैं, अन्य लोग विशेष रूपसे तब आपत्ति जताते हैं जब उनके अपने विशेषाधिकारोंकी जांच हो रही होती है और कुछ लोग सक्रिय रूपसे राजनीतिक टोपी पहनकर परेशानीवाले स्थानोंपर जाते हैं और यहांतक कि सरकारकी आलोचना भी करते हैं। पंजाबके पिछले राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जैसे अपवाद हैं जो राज्य सरकारको बर्खास्त करनेकी धमकी देते थे क्योंकि वह उनके संदेशोंका जवाब नहीं दे रही थी और यहांतक कि मुख्य मंत्रीके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करनेकी धमकी भी देते रहे। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्टने कहा था कि राज्यपाल आगसे खेल रहे हैं। पुरोहितने एक बार स्वीकार किया था कि वे जीवनभर राजनीतिमें सक्रिय रहनेके बाद भी इसे छोड़ नहीं सकते। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडुमें संबंधित राज्यपालों और राज्य सरकारोंके बीच इसी तरहका टकराव हो रहा है। केरल सरकारने हालमें सुप्रीम कोर्टको बताया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खानके पास सात विधेयक अटके हुए हैं, जिनमेंसे दो २३ महीनेसे लंबित हैं और १५ महीनेसे अन्य दो लंबित हैं। कुछ महीने पहले, उन्होंने मुख्य मंत्रीसे राज्यके वित्तमंत्रीको अपने मंत्रिमंडलसे हटानेके लिए कहा था क्योंकि उन्होंने राज्यपालके सुखका आनंद लेना बंद कर दिया था! मुख्य मंत्रीने निश्चित रूपसे उनकी सलाहको अस्वीकार कर दिया था। पश्चिम बंगालमें जून २०२२ से राज्यपाल सी.वी. आनंद बोसके पास आठ विधेयक लंबित हैं। देशने तमिलनाडुमें तमाशा देखा है, जहां राज्यपाल आरएन रविने जान-बूझकर राज्य विधानसभामें अपने भाषणके कुछ अंश नहीं पढ़े और सत्तारूढ़ पार्टीके सदस्यों द्वारा विधानसभामें उनका मजाक उड़ाया गया। दूसरी ओर भाजपा शासित मणिपुरमें, जहां पिछले कई महीनोंसे कानून-व्यवस्थाकी स्थिति खराब है और जहां बर्खास्तगीका मामला बनता है, राज्य सरकार, राज्यपाल और केन्द्र सरकारने आंखें मूंद ली हैं। राज्यपालका पद एक गरिमापूर्ण पद है और पदपर आसीन व्यक्तिको राज्यका प्रथम नागरिक माना जाता है, जिसकी भूमिका काफी हदतक औपचारिक होती है। संविधानने राज्यपालोंको कुछ शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन व्यापक सिद्धांत यह है कि उन्हें मुख्य मंत्रीकी अध्यक्षतावाली मंत्रिपरिषदकी सलाहके अनुसार कार्य करना चाहिए। राज्यपालोंको विरोधी भूमिका नहीं निभानी चाहिए और उन्हें संविधानके तहत उनके लिए परिकल्पित भूमिकातक ही सीमित रहना चाहिए। दुर्भाग्यसे न तो राज्यपालोंकी हालकी नियुक्तियां और न ही राज्यपालोंके सम्मेलनसे निकलनेवाले संकेतोंने विश्वास जगाया है। शायद सर्वोच्च न्यायालयको संविधानकी भावनाके अनुसार राज्यपालोंके लिए सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। **-विपिन, वाया ईमेल।**

समझसे परे जनगणनाका औचित्य

वर्ष १९०० की जनगणनामें ईसाई केवल एक प्रतिशत थे और मुसलमान २१ फीसदी थे। मुसलमानोंमें विदेशी, देसी और शिया भी शामिल थे। इनके अतिरिक्त शेष भारतीय हिंदू हैं। ब्रिटिश सरकारने जनगणनामें हिंदू शब्दको भौगोलिक न मान कर उसे मजहबका द्योतक शब्द मान लिया था।

❐ **कुलदीप चंद अग्निहोत्री**

वर्ष १८५७ की आजादीकी पहली लड़ाईके बाद जब ब्रिटेनने ईस्ट इंडिया कम्पनीको अपदस्थ कर भारतका शासन स्वयं संभाल लिया तो उसने १८८० में भारतमें पहली बार जनगणना शुरू की। उस समय मरदमशुमारीके लिए हिंदू, मुसलमान और ईसाईके नामसे तीन कॉलम होते थे। सिख, बौद्ध, जैनए ईरानी (पारसीको ईरानी कहा जाता था) की गणना भी अलग होती थी। सन् १९०० तक जनगणना इसी हिसाबसे चलती रही। इस जनगणनामें ब्रिटिश सरकारकी यह इच्छा थी कि भारतमें विभिन्न मजहबोंके लोगोंकी संख्या कितनी है, यह जान लिया जाय ताकि आगेकी रणनीति बनानेमें आसानी रहे। अबतक भारतमें विदेशी मूलके मजहबोंको माननेवालोंकी संख्या भी अच्छी खासी हो गयी थी।

विदेशी मूलके तीन मजहब ही भारतमें पैर पसार रहे थे। इस्लाम पंथ, एशिया पंथ और मसीही पंथ (क्रिश्चियन)। तीनोंका भारतमें आगमन मोटे तौरपर आक्रमणकारियोंके माध्यमसे हुआ था। अरबों, तुर्कों एवं मुगलोंके लम्बे शासन कालमें इस्लाम पंथमें मतांतरित हो जानेवाले भारतीयोंकी संख्या भी अबतक काफी हो गयी थी। इस्लाम पंथमें मतांतरित भारतीयोंके अतिरिक्त एटीएमए यानी विदेशी मूलके मुसलमान भी थे। उस समय ईसाइयोंकी गिनती तो इस देशमें नाममात्र ही थी। केरलमें कुछ सीरिआई ईसाई थे, जिन्होंने कभी अपने देशमें इस्लामी आक्रमणोंसे भाग कर इस देशमें शरण ले रखी थी। इसी प्रकार यूरोपीय जातियोंको भी भारतके कुछ हिस्सोंपर राज करते हुए लगभग सौ साल हो ही गये थे। इसलिए ईसाई पंथमें मतांतरित भारतीयोंकी भी कुछ संख्या थी ही। कुछ एंग्लो इंडियन थे। लेकिन इनकी संख्या उस समय निश्चित ही अंगुलियोंपर गिनी जा सकती थी।

अंग्रेजोंके चले जानेके बाद कुछ लोगोंने मांग की थी कि जनगणना जातिके आधारपर की जाये, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरु इसके पीछे छिपी भावनाको समझ गये थे इसलिए उन्होंने इस मांगको ठुकरा दिया था। लेकिन आज नेहरुकी हवेलीपर जिन लोगोंका कब्जा है, वे किसी भी कीमतपर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वे २०२४ में उसी नीतिको फिरसे जीवित करना चाहते हैं जो ब्रिटिश सरकारने शुरू की थी। राहुल गांधी यदि बाबा साहेब अंबेडकरका संविधान सभाके अंतिम सत्रमें दिया गया उनका भाषण पढ़ लें तो देशकी ज्यादा सेवा करेंगे।

वर्ष १९०० की जनगणनामें ईसाई केवल एक प्रतिशत थे और मुसलमान २१ फीसदी थे। मुसलमानोंमें विदेशी मूलके मुसलमान, देसी मुसलमान और शिया मजहबको माननेवाले भी शामिल थे। इन दोनोंके अतिरिक्त शेष भारतीय हिन्दू हैं। लेकिन यह भी साफ हो गया था कि ब्रिटिश सरकारने इस जनगणनामें हिन्दू शब्दको भौगोलिक न मान कर उसे मजहबका द्योतक शब्द मान लिया था। लेकिन १८८५ में कांग्रेस और १९०५ में मुस्लिम लीगके गठनसे देशमें कहीं-कहीं कुछ निकायोंमें भारतीयोंको हिस्सा देनेके लिए कानून बनने शुरू हो गये थे। यह चयन मतदान द्वारा होता था। यह ठीक है कि मतदानका अधिकार कुछ गिने-चुने भारतीयोंको ही दिया जाता था, लेकिन एक नयी पद्धतिकी शुरुआत तो थी ही। १९०९ के अधिनियममें तो विधानपालिकाओंमें भी चुनाव द्वारा कुछ स्थान भारतीयों द्वारा भरे जाने थे। इसलिए १९१० की जनगणनासे पहले मुसलमानोंका एटीएम (अरब, तुर्क, मुगल) मूलका खेमा सक्रिय हो गया। उनकी चिंता थी कि ब्रिटिश सरकारने इस्लाम पंथी (जिसमें मुसलमान और शिया पंथी दोनों ही शामिल थे) एवं मसीहीके अतिरिक्त अन्य सभी भारतीयोंको हिंदू स्वीकार लिया था। इसका अर्थ परोक्ष रूपसे यही था कि हिन्दू इस देशकी भौगोलिक पहचानको ही इंगित करता है। ब्रिटिश सरकारने मुसलमान और मसीही समुदायको तो इस भौगोलिक पहचानसे अलग कर ही दिया था। लेकिन यदि हिन्दूको भी खंडित किया जा सके तो भारतको मानसिक तौरपर घायल करना आसान हो सकता था। १९१० की गणनासे पहले एटीएम और ब्रिटिश सरकारने इस संबंधी पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। उसकी शुरुआत आगा खानके ज्ञापनसे होती है जो उसने जनगणनाके बारेमें सरकारको दिया था। लेकिन हिन्दूके भौगोलिक आधारको आगे बांटनेकी जरूरत ब्रिटिश सरकारको क्यों हुई, इसकी चर्चा भीमराव अंबेडकरने की है। उनका मानना है कि इस प्रश्नका उत्तर मुसलमानों द्वारा आगा खानके नेतृत्वमें १९०९ में ब्रिटिश सरकारको दिये गये प्रतिवेदनमेंसे मिलेगा।

यह मैमोरंडम आगा खानने उस समयके वायसराय लार्ड मिंटोको दिया था। आगा खानने इस प्रतिवेदनमें लिखा था कि १९०० की जनगणनामें मुसलमानोंकी संख्या ६२ मिलियन है, जो कि भारतकी कुल जनसंख्याका १/५ प्रतिशतसे लेकर १/४ प्रतिशतके बीच ठहरता है। आगा खानने आगे कहा कि जनगणनामेंसे असभ्य समुदायके लोगों, जिन्हें छिटपुट मजहब और एनिमिस्टके नाते दर्ज कर रखा है, को निकाल दिया जाय।

दूसरे, उन लोगोंको जिन्हें हिन्दू मान लिया गया है, लेकिन वे हिंदू नहीं हैं, भी निकाल दिया जाय तो देशमें हिन्दुओंकी तुलनामें मुसलमानोंकी संख्याका प्रतिशत और भी बढ़ जायगा। अंबेडकरने वह पूरा मैमोरंडम अपनी किताब 'अछूत कौन थे' में दिया है। लेकिन इस प्रतिवेदनका अगला भाग चौंकाने वाला है, जिसमें आगा खान कहते हैं कि जब भारतीयोंको किसी भी संस्थानमें उनकी संख्याके बलपर हिस्सेदारी दी जाय तो मुसलमानोंको हिस्सेदारीका आधार उनकी संख्याको न माना जाएय, बल्कि यह आधार रखा जाय कि मुसलमानोंने ब्रिटिश साम्राज्यकी कितनी सेवा की है। आज भी यह शक जाहिर किया जाता है कि आगा खानने यह प्रतिवेदन स्वयं दिया था या फिर अंग्रेजोंने उसे ऐसा प्रतिवेदन देनेके लिए कहा था। ब्रिटिश सरकारने शायद तभीसे देशको विभाजित करनेकी योजना बनानी शुरू कर दी थी। अंबेडकरने प्रश्नको आगे और बढ़ाया है। एक बात तो स्पष्ट है कि आगा खानकी पिटीशनसे वायसराय इतना तो समझ गये थे कि प्रथमया, हिन्दूको उसकी भौगोलिकतासे काटकर मजहबसे पहले ही जोड़ दिया गया है, अब कृत्रिम रूपसे उसकी जनसंख्या कम करनेका भी अवसर है।

आगा खानने यह पिटीशन दी थी या ली गयी थी, यह बहसका विषय हो सकता है, लेकिन अंग्रेज सरकारने उसे सही रूपसे पकड़ लिया था। इसका तरीका उन्होंने १९१० की जनगणनामें निकाला। उन्होंने हिन्दूको आगे हिन्दू, जनजाति और अछूत नामसे तीन हिस्सोंमें बांट दिया। उस समय कांग्रेसने इसका विरोध किया था। लेकिन ब्रिटिश नीति कामयाब रही और १९४७ में देश विभाजित हो गया।

अंग्रेजोंके चले जानेके बाद कुछ लोगोंने मांग की थी कि जनगणना जातिके आधारपर की जाय, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरु इसके पीछे छिपी भावनाको समझ गये थे, इसलिए उन्होंने इस मांगको ठुकरा दिया था। लेकिन आज नेहरुकी हवेलीपर जिन लोगोंका कब्जा हो गया है, वे इटलीके मैकियावलीके सिद्धांतोंपर चलते हुए किसी भी कीमतपर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वे आज २०२४ में उसी नीतिको फिरसे जीवित करना चाहते हैं, जो ब्रिटिश सरकारने शुरू की थी। राहुल गांधी सलाहकारोंकी दी हुई स्क्रिप्ट पढ़नेकी बजाय यदि बाबा साहेब अंबेडकरका संविधान सभाके अंतिम सत्रमें दिया गया उनका भाषण पढ़ लें तो वे देशकी ज्यादा सेवा करेंगे।

शिक्षा व्यवस्थाकी खोखली जड़ें

शिक्षाका बाजारीकरण और गुणवत्ताहीन शिक्षा आजकी मुख्य त्रासदी है। यह अचानक मौजूदा समयकी देन नहीं है। दस लाखसे अधिक उम्मीदवार केवल एक हजार सीटोंके लिए सिविल सेवा परीक्षाकी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

❐ **बलबीर पुंज**

हालमें दिल्ली स्थित एक कोचिंग सैंटरकी बेसमैंटमें बरसातका पानी भरनेसे तीन छात्रोंकी मौत हो गयी। सीबीआई मामलेकी जांच कर रही है तो सर्वोच्च न्यायालयने मामलेका स्वतः संज्ञान लेते हुए केन्द्र और दिल्ली सरकारसे जवाब मांगा है। अदालतने अपनी टिप्पणीमें कोचिंग सेंटरोंको डैथ चैंबर कहकर संबोधित किया है। इस हृदयविदारक घटनाक्रमसे दो मुद्दे चर्चाके केन्द्रमें आ गये हैं। पहला, यह घटना लचर प्रशासनिक व्यवस्थाको दिखाती है। स्थापित नियम-कानूनों और सुरक्षा मानकोंको ताकपर रखकर दिल्लीके कई भवनोंके तलघरोंमें शिक्षाके नामपर दुकान लगाकर करोड़ों-अरबों रुपयेका व्यापार होता रहा और शासन-प्रशासन तमाशबीन बने रहे। वे तब जागे, जब दिल्लीके ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटरकी बेसमैंटमें अचानक बारिशका पानी घुस जाने और उसमें चार घंटेसे अधिक समयतक फंसे रहनेके कारण सिविल सेवा परीक्षाकी तैयारी कर रहे तीन छात्रोंकी मौत हो गयी। यह प्रशासनिक उदासीनता नयी नहीं है। पिछले साल दिल्लीके मुखर्जी नगरमें एक कोचिंग सेंटरमें आग लगनेके बाद पुलिसने दिल्ली उच्च न्यायालयको सूचित किया था कि शहरके करीब ६०० कोचिंग संस्थानोंमें से सिर्फ ६७ के पास अधिकारियोंसे अनापत्ति प्रमाणपत्र था। हालिया घटनासे साफ है कि शिक्षण प्रतिष्ठानोंमें सुरक्षा सुनिश्चित करनेके मामलेमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। दूसरा बड़ा मुद्दा शिक्षाका बाजारीकरण और गुणवत्ताहीन शिक्षा है। दस लाखसे अधिक उम्मीदवार केवल एक हजार सीटोंके लिए सिविल सेवा परीक्षाकी प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्ष २०२४ में २० लाखसे अधिक छात्रोंने मैडीकल प्रवेश परीक्षा (नीट) दी, जबकि देशके मेडिकल कालेजों (सरकारी-निजी सहित) में एक लाखसे कुछ अधिक सीटें हैं।

जो लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, वे इस कुस्थितिको व्यावसायिक अवसरके रूपमें भुना रहे हैं। जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाते, वे कोचिंग सेंटरोंके लिए उपभोक्ता होते हैं और माता-पिता भी अपने बच्चोंकी बेहतरीके लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। सिविल सेवा और नीट-जेईई आदिकी तैयारी कर रहे प्रति छात्र और उसके परिवारपर निजी कोचिंग शुल्क, रहना-खाना और अध्ययन सामग्रीका कुल खर्च औसतन प्रतिवर्ष ४.६ लाख रुपयेका दबाव होता है। भारतमें निश्चित रूपसे कई उच्च स्तरके शिक्षण संस्थान हैं। विश्वस्तरीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) आदि ऐसे उदाहरण हैं, जहां उत्कृष्ट स्नातक तैयार होते हैं और अकसर दुनियाके विकसित देशोंमें जाकर देशका मान भी बढ़ाते हैं। परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है।

भारतीय जनसंख्या के संदर्भमें यह 'ऊंटके मुंहमें जीरा' है। देशके अधिकांश स्कूल-कालेज न केवल शिक्षाके मामलेमें, बल्कि उनका ढांचातक जर्जर है। इस संबंधमें १७ जनवरी २०२४ को शिक्षा-केंद्रित गैर-लाभकारी संस्था 'प्रथम फाऊंडेशन' ने २८ जिलों के सरकारी-निजी शिक्षण संस्थानोंमें १४-१८ आयु वर्षके युवाओंकी चिन्ताजनक तस्वीरको उजागर किया है। इसके मुताबिक ५० प्रतिशतसे अधिक युवा गणितके सामान्य सवाल हल करने, २५ प्रतिशत कक्षा-२ की क्षेत्रीय भाषाकी पुस्तक पढ़ने और करीब ४३ प्रतिशत अंग्रेजीके एक वाक्यको धाराप्रवाह पढ़नेमें असमर्थ हैं। अन्दाजा लगाना कठिन नहीं कि यह समूह किसी रोजगारमें कितनी गुणवत्ताके साथ न्याय कर पा रहे होंगे।

शिक्षाके मूलतः दो उद्देश्य होते हैं। पहला, मनुष्यको समाजकी बेहतरीके लिए उत्कृष्ट रूपमें विकसित करना, जिससे उसमें दूसरोंके प्रति दयाका भाव और सद्भावना आये। दूसरा, व्यक्ति संसारमें अपने ज्ञान-कौशल द्वारा अर्जित आजीविकासे स्वयं और अपने परिजनोंकी जरूरतोंको पूरा करनेमें सक्षम बने। आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ के अनुसार बढ़ते कार्यबलकी जरूरतोंको पूरा करनेके लिए भारतीय अर्थव्यवस्थाको गैर-कृषि क्षेत्रमें २०३० तक सालाना औसतन लगभग ७८.५ लाख नौकरियां पैदा करनेकी आवश्यकता है। इस संबंधमें मोदी सरकारने दो लाख करोड़ रुपयेसे पांच योजनाएं शुरू की हैं। क्या इससे कोई आमूलचूल परिवर्तन आयगा। देशके बहुत बड़े वर्गमें धारणा बनी हुई है कि रोजगारका मतलब सरकारी नौकरी ही होता है और वे इसी दिशामें अपनी तैयारी भी करते हैं। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तीमें ६० हजार कांस्टेबल पदोंके लिए ५० लाखसे ज्यादा आवेदन आये थे। गत वर्ष नवंबरमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने चतुर्थ श्रेणीके १३,५०० से अधिक पदोंके लिए १३.८४ लाख युवाओंने पंजीकरण कराया था। सच तो यह है कि अधिकांश भारतीयोंको सरकारी नौकरियां अधिक वेतन, भत्तों, विशेषाधिकार, सामाजिक सुरक्षा और अकसर ऊपरी कमाई करनेके अवसरोंके कारण आकर्षित करती हैं। पूर्व प्रशिक्षु (ट्रेनी) आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर संबंधित प्रकरण इसका उदाहरण है। पूजापर न केवल फर्जी पहचान-पत्र बनवाने, धोखाधड़ी करके परीक्षा देनेका आरोप है, साथ ही बतौर आईएएस अपने पदका बेजा दुरुपयोग करने, निर्धारित सीमासे अधिक सुविधा मांगने, वरिष्ठ अधिकारीका कार्यालय हथियाने, अपने निजी वाहनमें लालबत्ती लगाने और उसपर महाराष्ट्र सरकारकी प्लेट लगवानेका आरोप है। व्यवसायतक सीमित कोचिंग सेंटर, नीट विवादए पेपर लीकके बाद पूजा खेडकर मामला इस बातका सूचक है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्थामें सड़ांध कितनी बढ़ चुकी है।

आत्मबोध

शिवलिंग

❐ **धर्मेश कुशवाहा**

प्रत्येक देवी-देवताओंकी पूजा केवल साकार रूप जो पूरे अंग सहित होती है लेकिन शिवजीकी पूजा साकार और निराकार दोनों रूपमें होती है। शिवलिंग शिवजीका निराकार रूप है। शिवलिंगकी पूजा प्रत्येक मासमें की जाती है उसके लिए समय विचार करना होता है। श्रावण मास शिवजीको समर्पित मास है। इस मासमें बिना समय देखे शिवजीकी पूजा की जा सकती है। शिवजीकी पूजा शिवलिंग या वेर (मूर्ति) पर जो प्राणी श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनो साधनोंके अनुष्ठानमें समर्थ नहीं है वह भी कर सकता है। इस संबंधमें शिव पुराणमें विस्तारसे जानकारी दी गयी है। (श्रवणादि त्रिकेअशक्तो लिगं वेरम च शांकरम्।) शिव जीकी पूजामें वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ, फल आदि व्यंजनोंसे युक्त भांति-भांतिके भक्ष्य-भोज्य अन्न नैवेद्यके रूपमें समर्पित कर भी अपना कल्याण कर सकते है। शिवलिंगका तात्पर्य कल्याण प्रतीक होता है। शिवजीकी पूजा लिंगमें भी इसलिए होती है कि भगवान शिव ब्रह्मरूप होनेके कारण निष्कल (निराकार) कहे गये हैं। रूपवान होनेके कारण उन्हें सकल भी कहा गया। शिवजी इसी कारण सकल और निष्कल दोनों हैं। निष्कल (निराकार) होनेके कारण ही उनकी पूजा आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ। शिवजीके निराकार स्वरूपका प्रतीक शिवलिंग है। इसी तरह शिवजीके सकल या साकार होनेके कारण उनकी पूजाका आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। सकल और अकल रूप होनेसे ही वे ब्रह्म शब्दसे कहे जानेवाले परमतत्व है। एक बार विष्णुजी और ब्रह्माजीमें मतैक्य न होनेसे जगतके कल्याण करनेकी इच्छासे ही उनके मध्य निष्कल स्तंभके रूपमें अपना स्वरूप प्रकट किया, जो निराकार परमतत्व शिवजीने लिंगमें परिवर्तित कर दिया उसी समयसे संसारमें शंकरके शिवलिंगकी पूजा प्रचलित हुई। शिवलिंगका अर्थ अनन्त भी है जो अनंत ऊर्जाका द्योतक है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने वातावरण और उपग्रह चंद्रके साथ एक धुरीपर घूमती है उसी प्रकार शिवलिंग भी एक अक्षकी तरह पूरे ब्रह्मांडको धारण किये हैं। इस प्रकार शिवलिंग असीम ऊर्जाके साथ पूरे जगतका कल्याण करता है। श्रावण मासमें शिवजीके पूजाका विशेष विधान भी है पार्थिव शिवलिंगपर मंत्र सहित पुष्प, खंडरहित धानके अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जल धारासे अभिषेक करना चाहिए। शमीके पत्रोंसे पूजा करनेसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है।

उत्तर प्रदेशमें धर्मान्तरण कानूनमें बड़ा बदलाव

❐ **रोहित माहेश्वरी**

चार साल पहले उत्तर प्रदेशमें योगी सरकारने गैर-कानूनी धर्मपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया था। अब सरकारने धर्मान्तरण कानूनमें बड़ा बदलाव किया है, जिसमें सजा और जुर्माना राशि दोनों बढयी गयी है। साथ ही इसे अधिक व्यापक रूपसे लागू करने योग्य बनाया गया है। बीते दिनों विधानमंडलके मानसून सत्रमें विधानसभामें सरकार द्वारा पेश किये गये इस संशोधन विधेयकके उद्देश्योंको लेकर कहा गया है कि यह विधेयक कुछ समूहों, जिनमें नाबालिग, दिव्यांग, महिलाएं, एससी-एसटी समुदायोंके लोग शामिल हैं, की सुरक्षाके उद्देश्यसे लाया गया है। सरकारका तर्क है कि धर्मान्तरणके मामलेमें कड़ी सजा और जुर्मानेकी जरूरत थी, जो इसमें किया गया है। नये धर्मान्तरण कानूनमें कहा गया है कि यदि कोई शख्स किसी व्यक्तिको जबरन डरा-धमकाकर या जान-मालकी धमकी देकर उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो यह गम्भीर अपराधकी श्रेणीमें आयगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति धर्मपरिवर्तनके बाद जान-बूझकर किसी नाबालिग लड़कीसे शादी करता है या महिलाकी तस्करी करता है तो यह भी गम्भीर अपराध माना जायगा। संशोधित कानूनमें दो प्रावधान सबसे अहम हैं। पहला, यदि दोषी व्यक्ति विदेशी या गैर-कानूनी एजेंसियोंसे जुड़ा पाया जाता है तो उसे दस लाख रुपयेका जुर्माना और १४ सालतककी कैद हो सकती है। दूसरा, किसी व्यक्तिको बहला-फुसलाकर या उकसाकर गैर-कानूनी धर्मान्तरण करानेपर बीस सालसे लेकर उम्रकैदतककी सजाका प्रावधान है। यह प्रावधान खास तौरपर एससी-एसटी समुदायकी नाबालिग लड़कियों या महिलाओंके गैर-कानूनी धर्मान्तरणके मामलोंपर लागू होगा। दोषी व्यक्तियोंको अवैध धर्मान्तरणका शिकार हुए लोगोंको मुआवजा भी देना होगा। २०२१ में पारित अधिनियममें गैर-कानूनी धर्मान्तरणके लिए अधिकतम दस सालकी सजाका प्रावधान था।

सरकारके अनुसार अभीके दंडात्मक प्रावधान इन समूहोंसे जुड़े लोगोंका एकल धर्मान्तरण और सामूहिक धर्मान्तरणको रोकने और नियंत्रण करनेके लिए पर्याप्त नहीं हैं। विधेयकमें इलाहाबाद हाईकोर्टके न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवालके १ जुलाईको दिये आदेशकी रोशनी भी झलकती है। अपने आदेशमें एक आरोपीकी जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीशने कहा था, उत्तर प्रदेशमें एससी-एसटी और आर्थिक रूपसे कमजोर लोगोंको ईसाई धर्ममें धर्मान्तरणकी अवैध गतिविधियां बड़े पैमानेपर चल रही हैं। यह संशोधन पूर्वमें उत्पन्न कठिनाइयोंका भी समाधान करेगा जो धारा-४ के तहत दर्ज हुई थी। धारा-४ किसी भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन या किसी भी अन्य व्यक्तिको जो रक्त सम्बंधी, विवाह या गोद लेनेसे सम्बंधित हैं, को ही रिपोर्ट दर्ज करानेकी अनुमति देनेसे जुड़ी थी। इलाहाबाद हाईकोर्टने वर्ष २०२३ में कम से कम दो मौकोंपर यह निर्धारित किया है कि किसी भी पीड़ितका मतलब यह नहीं है कि कोई भी गैर-कानूनी धर्मान्तरणके लिए एफआइआर दर्ज करा सकता है। सितम्बर २०२३ में जोस पापाचेन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामलेमें कोर्टने निर्धारित किया था, केवल पीड़ित व्यक्ति ही और उसका परिवार माता-पिता, भाई-बहन आदि ही धर्मान्तरण मामलेमें प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। फरवरी २०२३ में भी हाईकोर्टने फतेहपुर सामूहिक धर्मान्तरण मामलेमें भी इसी तरहका आदेश दिया था।

संशोधनके जरिये एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है, के शब्दोंमें भी बदलाव किया गया है। धारा-४ के शब्दोंमें बदलाव कर उन कठिनाइयोंको सम्बोधित किया गया है जो उत्पन्न हुई हैं। संशोधित प्रावधानमें उल्लेखित है, कोई भी व्यक्ति २०२१ के अधिनियमके उल्लंघनपर प्राथमिकी दर्ज करा सकता है जैसा कि नये आपराधिक प्रक्रिया कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ में प्रावधान है। बीएनएसएसकी धारा १७३ में एफआईआर दर्ज करानेके प्रावधानोंमें है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी थानेमें अधिनियमके तहत कथित अपराधोंके लिए रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। २०२१ के अधिनियमकी धारा-३ गलत तरीकों, बलपूर्वक, अनुचित दबाव, लालच आदिसे धर्मपरिवर्तनको दंडनीय अपराध बनानेसे सम्बद्ध है। धारा-३ के तहत आरोपित लोगोंके लिए कठोर जमानत शर्तोंको उसी तरह लागू करनेका प्रावधान है जिस तरह मनी लॉण्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम २००२ और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम १९६७ में है। अब एक नयी धारा-७ के तहत किसी भी आरोपीको जमानतपर तबतक रिहा नहीं किया जा सकता, जबतक दो शर्तें पूरी न हो जायं। इसमें पहली शर्त है-पब्लिक प्रॉसीक्यूटरको जमानत अर्जीका विरोध करनेका अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरी शर्त है कि कोर्टको इस बातसे संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसा विश्वास करनेके लिए उचित आधार है कि व्यक्ति ऐसे अपराधका दोषी नहीं है और जमानतपर रहनेके दौरान कोई अपराध नहीं करेगा। दंड एवं जुर्माना राशिमें कितनी वृद्धि धारा-५ के तहत अपराधमें दो नयी श्रेणियोंको जोड़ा गया है। पहला-अवैध धर्मपरिवर्तनके लिए आरोपीने किसी विदेशी या अवैध संस्थाओंसे धन लिया हो, उसे सातसे चौदह वर्षके कठोर कारावाससे दंडित किया जायगा और उसे न्यूनतम दस लाख रुपयेका जुर्माना भी देना होगा। दूसरा, धर्मान्तरणके लिए किसीको डराने, विवाहका वादा करने या फिर महिला या व्यक्तिकी तस्करी करने या उन्हें बेचनेकी साजिश रचनेपर कमसे कम बीस वर्षके कठोर कारावासकी सजाका प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावासतक बढ़ाया जा सकता है। २०२१ में पारित कानूनमें अधिकतम सजा दस साल थी। भाजपाशासित अन्य राज्यों जैसे उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेशमें भी धर्मान्तरण विरोधी कानून बनाये गये हैं। उत्तर प्रदेशके संशोधन विधेयककी तर्जपर अन्य राज्योंमें भी ऐसे ही विधेयक पेश किये जा सकते हैं। राजस्थान विधानसभाके इसी सत्रमें धर्मपरिवर्तनपर रोकथामके लिए सख्त कानून बनानेकी मांग उठी है। नये धर्मान्तरण विधेयकके खिलाफ समाजवादी पार्टीसे लेकर कांग्रेसतकने मोर्चा खोल दिया है। विपक्षका सबसे बड़ा तर्क है कि इससे झूठी शिकायतोंकी बाढ़ आ जायगी। कांग्रेसका कहना है कि राज्य सरकारको एक कमीशन भी बनाना चाहिए, जो इस बातकी जांच करे कि जो शिकायत दी गयी है वह सही भी है या नहीं। समाजवादी पार्टीका कहना है कि यह संवैधानिक अधिकारोंके खिलाफ है। इन कानूनोंका विरोध भी हो रहा है। यही वजह है कि व्यक्तिगत रूपसे अनेक लोगों, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) तथा जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द जैसे एनजीओने ऐसे कानूनोंको विभिन्न अदालतोंमें चुनौती दी है। सीजेपीने ऐसी सभी चुनौतियोंको सुप्रीम कोर्टमें स्थानान्तरणके लिए याचिका लगायी है। शीर्षस्थ अदालतको अभी निर्णय करना बाकी है। धर्मान्तरण विरोधी कानून भारतमें एक बहसका विषय हैं। कुछ लोगोंका मानना है कि देशकी सांस्कृतिक और सामाजिक एकताके लिए ये कानून जरूरी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्टने तो हालमें ये टिप्पणी की थी कि यदि धर्मान्तरणपर लगाम नहीं लगी तो बहुसंख्यक हिन्दू अल्पसंख्यक हो जायगा।

वक्फ संशोधन विधेयक पर बवाल क्यों

भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया ह्यवक़्फ (संशोधन) विधेयक-2024ह्ल मौजूदा ह्यवक़्फ अधिनियम-1995ह्ल में व्यापक एवं आवश्यक बदलाव का प्रस्ताव करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों की देखरेख करने वाले नियमों को अद्यतन करते हुए उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में वक्फ बोर्डों के प्रबंधन को बेहतर और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई संशोधन पेश किए गए हैं। इसका लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं को दूर करना और इस दिशा में प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना है। कुछ लोग वक़्फ (संशोधन) विधेयक-2024 के विषय में मुस्लिम समुदाय को यह सुझाव देते हुए कि संशोधन हानिकारक हो सकते हैं, अनावश्यक रूप से गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं, हालांकि यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि ये सुधार मूल रूप से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं। देखा जाए, तो वक्फ संपत्तियों को ऐतिहासिक रूप से प्रायः कुप्रबंधन और अतिक्रमण से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पंजीकरण, वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रशासन-प्रबंधन के लिए नए नियमों को लागू कर, विधेयक का उद्देश्य इन मुद्दों से सीधे निपटना है। इस दृष्टि से संपत्ति पंजीकरण और विस्तृत वित्तीय प्रकटीकरण के लिए एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से इन संपत्तियों को अनधिकृत उपयोग से बचाने में सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि उनका प्रबंधन उनके इच्छित उद्देश्यों के अनुरूप किया जाए। ये परिवर्तन वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कई वर्षों से चिंता का विषय रहे हैं। विधेयक में पेश किए गए सुधार उन समस्याओं के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया हैं, जिन्होंने अतीत में वक्फ प्रबंधन को परेशान किया है। बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण और दुरुपयोग से बचाने में निःसंदेह सहायता मिलेगी। ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक प्रतिबद्धता है। इस क्रम में समुदाय के दीर्घकालिक लाभ के लिए इन परिवर्तनों का समर्थन करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वक़्फ (संशोधन) विधेयक-2024 को लेकर अनेक चिंताएं और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित होती रही हैं, विशेषकर उन लोगों की ओर से जिनके पास यथास्थिति बनाए रखने में निहित स्वार्थ हो सकते हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि विधेयक हानिकारक है, लेकिन इन संशोधनों को पारदर्शिता और जवाबदेही के चश्मे से देखना आवश्यक है। प्रस्तावित परिवर्तन मूल रूप से वक्फ प्रणाली में सुधार के बारे में हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपत्तियों का प्रबंधन अधिक प्रभावी और नैतिक रूप से किया जाए। विधेयक में संशोधनों में वक्फ संपत्तियों के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस और पोर्टल की स्थापना सम्मिलित है, जो सभी संपत्तियों का एक व्यापक रिकॉर्ड सुरक्षित एवं संरक्षित करेगा। यह विधेयक वक्फ भूमि के कुप्रबंधन और अनधिकृत उपयोग की संभावनाओं को कम करने की दिशा में एक विकासात्मक पहल है। अच्छा है की इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। उम्मीद है वहां क्षुद्र दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के सांसद उसके गुण -दोष पर सार्थक चिंतन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

तिरंगे के रचयिता को ही राष्ट्रध्वज नसीब न हुआ!

के. विक्रम राव

तभी का किस्सा है। चालुक्यों की गौरवमयी राजधानी रही काकीनाडा (गोदावरी तटीय) की घटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन (26 दिसंबर 1923) हुआ। यह शहर चालुक्यों के सम्राट पुलकेशिन से जुड़ा था। यहीं वेंकैया ने कांग्रेस में शरीक होकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रारुप पर चर्चा किया था। यह अधिवेशन दो घटनाओं के लिये ऐतिहासिक था। यहीं मौलाना मोहम्मद अली ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वन्दे मातरम् गाने पर एतराज किया था। वॉक आउट किया। तभी से यह राष्ट्रगान अधूरा हो गया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जायेगा।सर्वाधिक निर्धारण जब महत्वपूर्ण था कि काकीनाडा अधिवेशन में ही वेंकैया ने राष्ट्रध्वज की आवश्यकता पर बल दिया था। उनका यह विचार गांधीजी को बहुत पसंद आया। गांधीजी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने का सुझाव दिया। पिंगली वेंकैया ने पांच सालों तक तीस विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया और अंत में तिरंगे के लिए सोचा। विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया महात्मा गांधी से मिले थे और उन्हें अपने द्वारा डिजाइन लाल और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया। तब तक ब्रिटिश यूनियन जैक ध्वजा ही कांग्रेस सम्मेलनों में फहरती थी। मगर बाद में तिरंगा फहराने लगा। देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में दो रंगों वाले अंग्रेजी झंडे का प्रयोग बंद हो गया। लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से अधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली थी। इस बीच जालंधर के हंसराज ने झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया। इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में माना गया। बाद में गांधी जी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने शांति के प्रतीक सफेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। बाद में 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे तीन रंगों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। फिर राष्ट्रीय ध्वज में इस तिरंगे के बीच चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। राष्ट्रध्वज वेंकैया द्वारा निरूपित हो जाने से गीत का प्रस्ताव आया उसी की पंक्ति थी जो हम लोग गुलाम भारत (1945–46) में स्कूलों में गाते थे। ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' ने की थी। पद वाले इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस ने तीन पद (पद संख्या 1, 6 व 7) को संशोधित करके ह्यध्वजगीतह्ल के रूप में मान्यता दी। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिये देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना : 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। वीरों को हरषाने वाला, मातृभूमि का तन-मन सारा।'

हर घर तिरंगा के पावन दिन पर आज यह सियासी दुखांतिका है, राष्ट्रीय त्रासदी भी। जिन्हें नाज है हिन्द पर वे सभी जान ले। राष्ट्रध्वज के रूपरेखाकार पिंगली वेंकैया एक तेलुगुभाषी निर्धन स्कूल मास्टर थे। वे कंगाली में जन्में (2 अगस्त 1876 : सागरतटीय मछलीपट्टनम, आंध्र) तथा अभाव में पले। इस विप्र के शवदाह में पर्याप्त ईंधन नहीं मिला। उनका अधूरा ख्वाब था कि तिरंगे में लपेटकर उनकी लाश ले जायी जाये। 10 अगस्त को मीडिया और नरेंद्र मोदी से लेकर सभी उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

वेंकैया ने जीवन में कई ज्वार भाटा देखे। मेधावी छात्र थे। लाहौर के वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी के अध्यापक रहे। कैंब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ली। मगर भारत लौटकर आये तो निजी रेलवे कंपनी में जीविका पायी। लखनऊ में भी एक शासकीय नौकरी की। उनके रोजगार में विविधता रही। भूविज्ञान तथा कृषि क्षेत्र में निष्णात रहे। खदानों के जानकार रहे। फिर आयी उनके जीवन की विलक्षण बेला। ब्रिटिश सेना का दक्षिण अफ्रीका में बोयर युद्ध हुआ। भारतीय लोग भी वहां गये। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैनिक थे मोहनदास कर्मचन्द गांधी। वे चिकित्सक (स्वयं सेवक) की भूमिका में थे। तभी वेंकैया भी ब्रिटिश सैनिक के रोल में गये। गांधीजी से भेंट हुई, परिचय हुआ। फिर भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में दोनों में प्रगाढ़ता सर्जी।

तभी का किस्सा है। चालुक्यों की गौरवमयी राजधानी रही काकीनाडा (गोदावरी तटीय) की घटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन (26 दिसंबर 1923) हुआ। यह शहर चालुक्यों के सम्राट पुलकेशिन से जुड़ा था। यहीं वेंकैया ने कांग्रेस में शरीक होकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रारुप पर चर्चा किया था। यह अधिवेशन दो घटनाओं के लिये ऐतिहासिक था। यहीं मौलाना मोहम्मद अली ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वन्दे मातरम् गाने पर एतराज किया था। वॉक आउट किया। तभी से यह राष्ट्रगान अधूरा हो गया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जायेगा।सर्वाधिक निर्धारण जब महत्वपूर्ण था कि काकीनाडा अधिवेशन में ही वेंकैया ने राष्ट्रध्वज की आवश्यकता पर बल दिया था। उनका यह विचार गांधीजी को बहुत पसंद आया। गांधीजी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने का सुझाव दिया।

पिंगली वेंकैया ने पांच सालों तक तीस विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया और अंत में तिरंगे के लिए सोचा। विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया महात्मा गांधी से मिले थे और उन्हें अपने द्वारा डिजाइन लाल और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया। तब तक ब्रिटिश यूनियन जैक ध्वजा ही कांग्रेस सम्मेलनों में फहरती थी। मगर बाद में तिरंगा फहराने लगा। देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में दो रंगों वाले अंग्रेजी झंडे का प्रयोग बंद हो गया। लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से अधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली थी। इस बीच जालंधर के हंसराज ने झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया। इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में माना गया। बाद में गांधी जी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने शांति के प्रतीक सफेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। बाद में 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे तीन रंगों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। फिर राष्ट्रीय ध्वज में इस तिरंगे के बीच चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली।

राष्ट्रध्वज वेंकैया द्वारा निरूपित हो जाने से गीत का प्रस्ताव आया उसी की पंक्ति थी जो हम लोग गुलाम भारत (1945–46) में स्कूलों में गाते थे। ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' ने की थी। पद वाले इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस ने तीन पद (पद संख्या 1, 6 व 7) को संशोधित करके ह्यध्वजगीतह्ल के रूप में मान्यता दी। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिये देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना : 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। वीरों को हरषाने वाला, मातृभूमि का तन-मन सारा।'

जब 9 अगस्त 1942 में गोवालिया टैंक मैदान मुंबई (अगस्त क्रांति मैदान) में सारे नेताओं के कैद हो जाने पर क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली ने यह ध्वज फहराया था। वे भी गुनगुना रही थी : 'इसकी शान न जाने पाये। चाहे जान भले ही जाये।'

मगर इतिहास की विडंबना है कि भारी विरोध के बाद भी तिरंगा सत्तारूढ़ कांग्रेस का पार्टी झण्डा भी हो गया। आम जन को भ्रम होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत को भ्रम में डालने का यह एक और किस्सा है। जैसे गांधी उपनाम का नेहरू वंश वालो का इस्तेमाल धोखा ही हुआ।

तुलसीदास के मानस में अवतारवाद और राष्ट्रधर्मी ऋषि स्वामी विवेकानंद

गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर विशेष

डॉ. राधानंद सिंह

(संरक्षक, गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन)

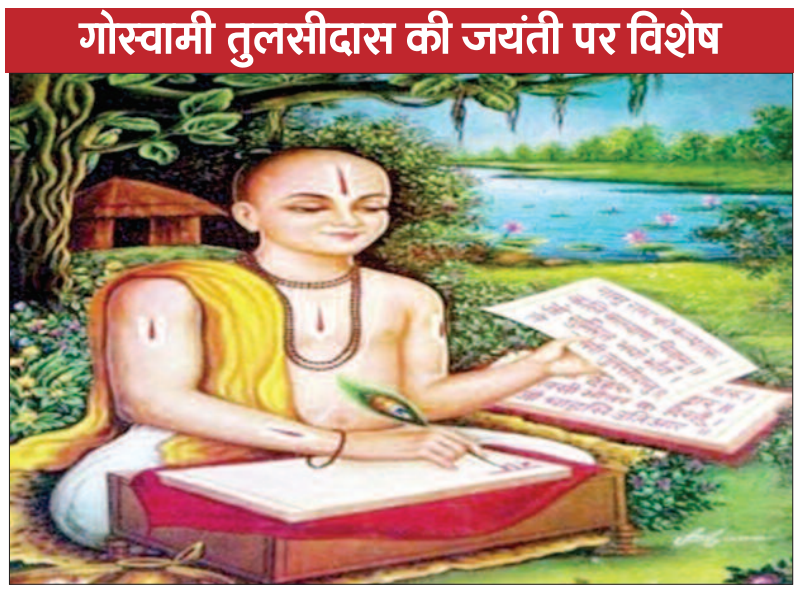

श्री अरविंद भी स्वामी जी के उपर्युक्त मत से सहमत थे।उनकी मान्यता यह थी कि राम,कृष्ण आदि अवतार हैं और उस ब्रह्म के अंश से अवतरित महान संत, युगपुरुष आदि विभूति हैं।उनके एक परम मित्र ने जब अवतारवाद पर उनसे पूछा कि राम और कृष्ण ब्रह्म के अवतार थे, तब उन्होंने मुसकराकर कहा कि वे दोनों अवतार नहीं थे,तो क्या तुम हो। इस संदर्भ में उपर्युक्त प्रसंग की प्रासंगिकता यह है कि आज भी तुलसीदास के श्रीराम पर लौकिक व्याख्या करने वाले भ्रान्तिवश उनकी अलग व्याख्या करने लग जाते हैं।भगवान श्री राम के ब्रह्म और नर के रूप को तुलसीदास जी ने अत्यंत कुशलता से अभिव्यक्त किया है।मैंने अपने शोध ग्रंथ मिथकीय अवधारणा और तुलसी साहित्य में इसे ब्राह्मीनरलीलामिथक कहा है। कबीर दास निर्गुण-निराकार ब्रह्म के दृढ़ समर्थक हैं। गोस्वामी जी उनके इस बात को मानते हुए इतना ही कहते हैं- अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।। (1/116/2) सच ही कहा गया है कि कबीरदास टूट जाते हैं, परंतु झुकते नहीं और तुलसीदास जी झुक जाते हैं, परंतु टूटते नहीं। आज भी व्यावहारिक धरातल पर एक ऐसे राम की आवश्यकता तो है ही, जो मेरे प्रत्यक्ष भरोसे का रूप धारण कर सर्वहित के भाव के साथ जुड़े हों। जनक जी जैसे परमज्ञानी को भी श्रीराम के दर्शन के पश्चात इसकी अनुभूति हुई थी।

श्रीराम के अवतरण की प्रामाणिकता ही मानस का मूल प्रतिपाद्य है।भारतीय आर्ष परंपरा के गौरव ग्रंथ श्रीरामचरितमानस में आद्योपांत इसी तथ्य की पुष्टि की गई है।इसका बोध तत्कालीन ऋषि-वसिठ जी,विश्वामित्र जी,भारद्वाज जी,वाल्मीकि जी और अगस्त्य जी को भी था।बाद में यह परंपरा भी चलती रही और स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद आदि ने भी इस अवतारवाद की पुष्टि की।

तुलसीदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हुए लोकहित के लिए धनुर्धर श्री राम की अनिवार्यता समझी।यह युग की माँग थी।परंतु उन्होंने इस व्यापकता से त्रेतायुगीन श्री राम के चरित्र का निरूपण किया कि उनके श्री राम युग-युगीन हो गए।आज भी तुलसीदास के श्री राम युग जीवन के सर्वविध कल्याण के लिए सर्वथा प्रासंगिक हैं।

एक बार स्वामी विवेकानंद जयपुर के फौज बख्शी ठाकुर हरिसिंह लड़खानी के घर बैठे थे।उन्होंने स्वामी जी से पूछा- मेरी समस्या यह है स्वामी जी! कि मैं कल्पना ही नहीं कर पाता कि इस त्रिगुणात्मक माया का स्वामी, निर्गुण निराकार परम पुरुष अपनी ही माया के अधीन होकर त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया यह मानव शरीर धारण करेगा? स्वामी जी ने कहा- इस संकट से जूझने वाले आप पहले व्यक्ति तो नहीं हैं ठाकुर साहब! आपने गोस्वामी तुलसीदास का ग्रंथ श्रीरामचरितमानस पढ़ा होगा। ड्डड्डड्डउनकी प्रतिज्ञा है कि ब्रह्म ने ही राम के रूप में जन्म लिया है।कबीर की उक्ति 'दसरथ सुत तिहूँ लोक बखाना।राम नाम को मरम है आना।।' भी उनके ध्यान में रही होगी।वे बार-बार कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम ही ब्रह्म हैं।और इसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए सारा मानस लिखा गया है।ह्र स्वामी जी ने रुककर हरिसिंह को देखा, 'आप सोचिए, तुलसी के युग में आपकी समस्या कितने लोगों की समस्या रही होगी कि तुलसीदास को उसका निराकरण करने के लिए और अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिए ही रामचरितमानस लिखना पड़ा।' (नरेंद्र कोहली : पूत अनोखो जायो,पृष्ठ 271-272) इस संबंध में वहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

श्री अरविंद भी स्वामी जी के उपर्युक्त मत से सहमत थे।उनकी मान्यता यह थी कि राम,कृष्ण आदि अवतार हैं और उस ब्रह्म के अंश से अवतरित महान संत, युगपुरुष आदि विभूति हैं।उनके एक परम मित्र ने जब अवतारवाद पर उनसे पूछा कि राम और कृष्ण ब्रह्म के अवतार थे, तब उन्होंने मुसकराकर कहा कि वे दोनों अवतार नहीं थे,तो क्या तुम हो।

इस संदर्भ में उपर्युक्त प्रसंग की प्रासंगिकता यह है कि आज भी तुलसीदास के श्रीराम पर लौकिक व्याख्या करने वाले भ्रान्तिवश उनकी अलग व्याख्या करने लग जाते हैं।भगवान श्री राम के ब्रह्म और नर के रूप को तुलसीदास जी ने अत्यंत कुशलता से अभिव्यक्त किया है।मैंने अपने शोध ग्रंथ मिथकीय अवधारणा और तुलसी साहित्य में इसे ब्राह्मीनरलीलामिथक कहा है। कबीर दास निर्गुण-निराकार ब्रह्म के दृढ़ समर्थक हैं।गोस्वामी जी उनके इस बात को मानते हुए इतना ही कहते हैं- अगुन अरूप अलख अज जोई।भगत प्रेम बस सगुन सो होई।।(1/116/2)

सच ही कहा गया है कि कबीरदास टूट जाते हैं,परंतु झुकते नहीं और तुलसीदास जी झुक जाते हैं, परंतु टूटते नहीं।आज भी व्यावहारिक धरातल पर एक ऐसे राम की आवश्यकता तो है ही,जो मेरे प्रत्यक्ष भरोसे का रूप धारण कर सर्वहित के भाव के साथ जुड़े हों।जनक जी जैसे परमज्ञानी को भी श्रीराम के दर्शन के पश्चात इसकी अनुभूति हुई थी। मानस प्रेमियों को इस प्रसंग को उस दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए। जनकपुर-प्रसंग इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने दार्शनिक, धार्मिक और विशेषतः राष्ट्रीय व्याख्यान में तुलसीदास और उनके साहित्य मानसादि के अंश का दसाधिक प्रसंगों में उल्लेख किया है।वे सीता जी के चरित से अभिभूत हैं।उनके अनुसार समाज और परिवार सीता जी के चरित्र का अनुसरण किए बिना कभी सुखी नहीं हो सकता। वे यहाँ तक कहते हैं- सीता चरित्र अद्वितीय है।यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है।राम तो कदाचित अनेक हो गए हैं,किंतु सीता और नहीं हुई। भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श हैं।स्त्री-चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं वे सीता के चरित्र से ही उत्पन्न हुए हैं। (विवेकानंद साहित्य, भाग-5,पृष्ठ 150)

स्वामी विवेकानंद जी जैसे राष्ट्रीयता के पुरोधा के उपयुक्त विचार की व्यंजना यह है कि भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कोई भौतिक राष्ट्रवाद नहीं है। इस राष्ट्रवाद की आत्मा को समझे बिना हम भारतीय और भारतीयता की बात कर ही नहीं सकते।स्वामी विवेकानंद के उपर्युक्त विचारों को आधार बनाकर ही श्रीरामचरितमानस के राष्ट्रीय भाष्य के तत्त्वार्थ को हम समझ सकते हैं। स्वामी जी मूलतः वेदांती थे।उनकी भारतीय आर्ष परंपरा में गहरी आस्था थी।मैंने आज इस प्रसंग को इस भाष्य की आत्मा को समझने के लिए प्रस्तुत किया है।तुलसीदास जी के मानस की आत्मा को समझे बिना सामान्य रूप से उनकी कृति के मर्म को समझना कठिन है।ऐसी ही मति आज संशय और विवाद को जन्म देती है।एतदर्थ मानस के राष्ट्रीय भाष्य को स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

छोटे किसान खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत

वैश्विक खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण भी काफी जरूरी है। कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कहना बेहद अहम है। इसकी कई वजहें हैं। खाद्यान्न उत्पादन में भारत हमेशा से समृद्ध और सक्षम रहा है। आजादी के वक्त भले हमारी स्थिति कमजोर थी और खाद्य सुरक्षा चुनौती थी, मगर आज हम खाद्य अधिशेष देश हैं। दूध, दाल एवं कई मसालों का सबसे बड़ा व खाद्यान्न, फल-सब्जी, कपास, चीनी, चाय व मछली का दूसरा बड़ा उत्पादक हैं। दरअसल, यह सबकुछ संभव हुआ है खेती में नई नीतियों का समायोजन करके। चूंकि भारत में छोटे किसान खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं इस नाते भारत वैश्विक हो रही खाद्यान्न समस्या को सही और समग्र तरीके से समझने वाला देश है और इसके निदान के लिए भारत के मॉडल कई देशों के काम आ सकते हैं। देश की 70 फीसद से ज्यादा की आबादी खेती-किसानी करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तार और ताकत देने में खेती का बहुमूल्य योगदान है। साफ है कि कृषि हमारी आर्थिक नीतियों के केंद्र में है। जहां तक बात वैश्विक तौर पर खाद्य संकट को दूर करने की है तो भारत ने ऐसे कई उपाय तलाशे हैं, जिससे इस बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक खेती का चलन सबसे कारगर है। अच्छी बात है कि इसके परिणाम भी सुखद आ रहे हैं। स्वाभाविक है सरकार के लिए यह वाकई सुखकारी स्थिति है। यही वजह है कि इस बार के बजट में कृषि के सतत विकास पर बड़ा फोकस है। हां, चुनौती भी हमारे दरपेश है। क्योंकि जलवायु में हाहाकारी बदलाव ने कृषि के रंग-ढंग को बदल कर रख दिया है। इस नाते शोध की जरूरत आन पड़ी है। हालांकि हमारा जोर शोध व नवाचार पर है और जलवायु के अनुकूल फसल की 1900 प्रजातियां हमने दुनिया को दी हैं। पानी की कमी या चावल उत्पादन में पानी की भारी जरूरत ने यह चर्चा भी तेज कर दी है कि हमें अब ऐसी फसल के उत्पादन पर सोच-समझकर फैसला लेना होगा, जहां पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन सबके बावजूद कृषि की हमारी प्राचीन मान्यताओं के दम पर हमें यह कहने में कतई गुरेज नहीं कि वैश्विक खाद्य संकट का निदान हम ही दे सकते हैं। पूरी दुनिया हमारी काबिलियत से वाकिफ है और यही हमारी ताकत भी है।

राजनैतिक दलों का आत्मचिंतन

खबर है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने देश के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वहां के उप मुख्यमंत्रियों से दो दिन तक मंथन किया । अब मीडिया में यह तो नहीं आया कि इस मंथन की विषय वस्तु क्या थी, परन्तु यह तो निश्चित ही है कि भाजपा के गिरते ग्राफ और कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों की प्रति असंतोष पर गहन चर्चा हुई होगी । मीडिया में यह तो आया है कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य व अन्य उप मुख्यमंत्रियों का योगी जी द्वारा आहूत बैठकों में भाग न लेने को अनुशासनहीनता माना गया है । मैं पहले लिख चुका हूं कि प्रोटोकॉल के अनुसार नड्डा जी को केशव प्रसाद मौर्य को समय देकर उनसे नहीं मिलना चाहिए था । पिछले कुछ दिनों से केशव प्रसाद मौर्य खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है । परन्तु भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी को बदलने नहीं जा रहा है । प्रधानमंत्री तो कई बार कह चुके हैं कि यूपी योगी यानि 'उपयोगी' । यह खबर भी काफी प्रचलित है कि योगी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर देख रहे हैं । परन्तु 2029 के लोकसभा चुनाव में भी अभी मोदी जी ही चौथा टर्म करेंगे । योगी जी की बुलडोजर नीति घरेलू मामले में कामगार हो सकती है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में योगी जी की परीक्षा अभी हुई नहीं हैं । विश्व स्तर पर आज मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं । कई करोड़ से ज्यादा विदेशी भी मोदी जी के भक्त हैं । जिस तरह मोदी जी यूक्रेन और रूस तथा रूस और अमरीका के बीच भारत के संबंधों में बैलेंस बनाये हुये हैं, ऐसी डिप्लोमेसी शायद अभी किसी अन्य नेता के पास डिप्लोमेसी नहीं है । परन्तु भाजपा की तत्काल चिंता अपना वोट बैंक बढ़ाने की है । 400 पार और स्वयं के लिए 370 का नारा फेल हो गया और भाजपा 240 पर ही सिमट गई । वह स्वयं के 272 जीतकर भाजपा की सरकार नहीं बना पाई । आज गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं । असल में दूसरी पार्टी से लाये गये लोगों को तत्काल मंत्री बनाने से पुराने भाजपाई खुश नहीं हैं । मध्य प्रदेश में जिस प्रकार विजयपुर के विधायक रामनिवास रावत को पहले राज्य मंत्री और फिर पन्द्रह मिनट बाद कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, इससे भाजपाई विधायक आहत हैं । फिर उन्हें मंत्रालय भी उनकी पसंद का दिया गया है । वे भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं । परन्तु अभी तक उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है और न ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दल परिवर्तन के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की है । असल में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष उसी पार्टी का होता है, अतः वह नियम की अपेक्षा पार्टी हित ज्यादा देखता है ।

आज़ादी के बाद के सबक

आरती कुमारी

आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि भारत को विकसित बनाने के लिए हमें पांच प्रमुख क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है। इनमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना व संचार तकनीक, भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक पॉवर, महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भरता। ये पांचों क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े तो हैं ही, एक-दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए इनमें बेहतर सामंजस्य होना चाहिए। यह देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हममें यह सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए कि हम कुछ नया अविष्कार करके ही अपने देश में अच्छा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि विज्ञान और तकनीक से ही मानव कल्याण, शांति और खुशहाली आ सकती है। भारत ने वैश्विक पहचान हासिल करने के लिए ढेर सारी चुनौतियों को पार करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक बनने के लिए छोटे कदम उठाए। भारत ने आजादी के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, कई सही और गलत फैसलों से परहेज किया है, जो कई ऐसे स्थलों को पीछे छोड़ता है जो विभाजन की पीड़ा से एक मजबूत, शक्तिशाली और विकासशील राष्ट्र की यात्रा को परिभाषित करते हैं। हाल ही के दशकों में भारत धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्थान पर ऊपर चढ़ता जा रहा है और इसके कारण विश्व की एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में इसका वैश्विक प्रभाव भी नजर आने लगा है. पिछले चार दशकों में एक जबरदस्त ताकत के रूप में उभरकर सामने आया है और भारत ने भी काफ़ी ऊँचाइयाँ हासिल कर ली हैं. इसके कारण विश्व की आर्थिक शक्ति का केंद्र यूरोप और उत्तरी अमेरिका से हटकर एशिया की ओर स्थानांतरित होने लगा है. उदीयमान प्रबल शक्ति के बावजूद भारत अक्सर वैचारिक ऊहापोह में घिरा रहता है. यही कारण है कि देश के उज्ज्वल भविष्य और वास्तविकता में अंतर दिखाई देता है. हालांकि भारत महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में प्रमुख बिंदुओं पर खरा उतरता है, लेकिन व्यापक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में घरेलू मुद्दों के कारण वह कमजोर पड़ जाता है. हालांकि भारत के कई नेता गति को आगे बढ़ाने और सामाजिक राजनीतिक संकट से बचने में विफल रहे, यह भी राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता की कमी का मामला था। भारत में विविधता के कारण, कहीं न कहीं आना मुश्किल है। हालांकि, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) यानी एक समान नागरिक संहिता लगने के प्रयासों को रूढ़िवादी वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दावा किया कि इससे सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा होगा। पानी की तरह किलोमीटर पर भारत में भाषा बदल जाती है। इसलिए,हिंदी केवल आधिकारिक भाषा के रूप में लाना मुश्किल था और 1965 में तमिलनाडु के हिंदी-विरोधी आंदोलन जैसे हिंसा और गरमागरम बहस देखी गई। जनसंख्या नियंत्रण कानून 2019 का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जिसे 2022 में वापस ले लिया गया था। दो संतान नीति को आजादी के बाद से 35 बार संसद में पेश किया गया है। इन मसौदे की आम जनता द्वारा भारी आलोचना की गई थी। कृषि अर्थशास्त्री और अन्य हितधारक दशकों से कृषि बाजार में सुधार की वकालत कर रहे हैं। इसने संकट से बचने के लिए तीन प्रमुख कृषि सुधार कानून जिन्हें निरस्त कर दिया गया को फिर से चुपके मोड में आगे बढ़ाने के बारे में सरकार को झिझक दिया। लेबर कोड पर नियम आज तक टाले गए। कोड के परिणामस्वरूप कम टेक-होम पे और आसान छंटनी होगी। निःसंदेह सरकार को सुधार के मार्ग पर बहुत सावधानी से चलना होगा। लोकतंत्र की सफलता में पहला है मतदान को अनिवार्य बनाना, जैसा कि कम से कम 30 लोकतंत्रों में किया गया है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़कर 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है। वर्तमान में, भारत में मतदान प्रतिशत कम है। आईपीसी की धारा 124ए का घोर दुरुपयोग एक उपहास है लेकिन अधिकांश राजनीतिक दल नहीं चाहते कि कानून के इस प्रावधान को हटाया जाए। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय अर्ध-सैन्य पुलिस का उपयोग करना चाहिए। घुसपैठ, भाड़े के सैनिकों, आतंकवादियों और आतंकवादियों से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के नागरिक क्षेत्रों से सशस्त्र बलों को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ले जाने के लिए अधिनियम को हटाना एक मजबूत मामला है। राजनीतिक हस्तक्षेप और पुलिस जांच में अपर्याप्तता को देखते हुए, भारत ने औपनिवेशिक काल से यूरोप में प्रचलित जिज्ञासु प्रणाली से आरोप लगाने वाली प्रणाली से एक संरचनात्मक परिवर्तन करने का समय आ गया है। जस्टिस वी.एस. मलीमथ ने रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर अपनी रिपोर्ट में भी इसका सुझाव दिया है। जीएम खाद्य फसलों के लिए भारत अभी भी आनुवंशिक रूप से इंजीनियर या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएम) फसलों पर अनिर्णीत है। राजनीतिक इच्छा देश की खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित एक आधुनिक कृषि नीति ढांचे को अपनाने और लागू करने की कमी है। राजनीतिक प्रतिष्ठान ने राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन से खुद को बचा लिया है। भारत में सामाजिक राजनीतिक अशांति के बावजूद नेताओं द्वारा कई कठोर निर्णय सुधार किए गए जैसे 1991 के सुधारों के दौरान नेताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति को याद रखना चाहिए। हम उस नेतृत्व की सराहना करते हैं जिसने भारत को "चट्टान से गिरने" से बचाया और भुगतान संकट के आसन्न संकट के साथ फंड और बैंक की मजबूरी के तहत सुधारों का प्रबंधन किया। 1960 में भारत में हरित क्रांति ने गेहूं और दालों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के साथ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखी। 1976 सामूहिक नसबंदी अभियान संजय गांधी द्वारा शुरू किया गया था और एक वर्ष में लगभग 6.2 मिलियन पुरुषों की नसबंदी की गई थी, जिसमें लगभग 2000 लोग सर्जरी के कारण मारे गए थे। 1990 वीपी सिंह सरकार द्वारा कुछ जातियों को जन्म के आधार आरक्षण पर सरकारी नौकरी देने के विरोध में पूरा देश विरोध की चपेट में था, बावजूद इसके निर्णय जारी रहा। भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु बम परीक्षण किए, "ऑपरेशन शक्ति" कोडनेम के साथ निरस्त्रीकरण के वैश्विक दबाव में कठोर निर्णय लिया। इसने भारत को एक पूर्ण परमाणु राष्ट्र बना दिया। 2016 में, सरकार ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। कई किसान, व्यापारी और युवा वर्ग सभी आंदोलन कर रहे थे लेकिन काले धन के खिलाफ एक कदम के रूप में इसे आगे बढ़ाया गया माल और सेवा करः यह प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों को शामिल करने के बाद परिणामी कर था। कश्मीर की पहेली सुलझाना राज्य के पूर्ण एकीकरण के लिए अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण लंबे समय से लंबित था और इसे जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर सीधे रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सालों पहले किया जाना चाहिए था। आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि सुधारों की प्रक्रिया को अधिक परामर्शी, अधिक पारदर्शी और संभावित लाभार्थियों को बेहतर ढंग से संप्रेषित किया जाना है। यह समावेशिता ही है जो भारत के लोकतांत्रिक कामकाज के केंद्र में है। हमारे समाज की तर्कशील प्रकृति को देखते हुए, सुधारों को लागू करने में समय और विनम्रता लगती है। लेकिन ऐसा करना सुनिश्चित करता है कि हर कोई जीत जाए। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें पांच प्रमुख क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है। इनमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना व संचार तकनीक, भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक पॉवर, महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भरता। ये पांचों क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े तो हैं ही, एक-दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए इनमें बेहतर सामंजस्य होना चाहिए। यह देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हममें यह सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए कि हम कुछ नया अविष्कार करके ही अपने देश में अच्छा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि विज्ञान और तकनीक से ही मानव कल्याण, शांति और खुशहाली आ सकती है। छोटे से छोटे भ्रष्टाचार का सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। करप्शन फ्री इंडिया के सपने को साकार करने के लिए इंडिया बात करने लगा है। कभी फिल्म और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाला भारत अब भ्रष्टाचार मुक्त देश बनना चाहता है। आज भी भारत में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां लड़कियों को सिर्फ इस लिए नहीं पढ़ने दिया जाता क्यों कि वो लड़की हैं। ऐसे भी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश का हर नागरिक स्वतंत्र नहीं है। यदि वास्तव में देश को आगे बढ़ाना है तो लिंग भेद को समाप्त करना होगा। आज का भारत मर्डर, रेप जैसे बड़े क्राइम्स के साथ साथ बहुत से छोटे क्राइम्स से भी परेशान है। कहीं न कहीं इन क्राइम्स के पीछे एक बड़ा कारण बेरोजगारी भी है लेकिन सोच बदलकर कर रोजगार मुहैया करवाकर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है। देश जितना हिन्दू- मुसलमान सोशल मीडिया पर दिखाई देता है उतना है नहीं। आज का भारत किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। बदलते भारत के लोगों में अपने विवेक के आधार पर निर्णय करके देश को प्राथमिकता देने जैसी बातें प्रमुखता से सामने आईं। बिना साक्षरता के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में सभी शिक्षित हों तभी सारी समस्याओं से आजादी पाई जा सकती है।। साक्षरता के साथ-साथ देश भर में बढ़ती बेरोजगारी युवाओं को गुलामी का अहसास देती है, आखिर वो कब इस से आजाद होगा। सोचना होगा।

लोकसभा चुनाओं से उत्साहित उत्तरप्रदेश कांग्रेस को संजीवनी देने में जुटे हैं राहुल गाँधी

अशोक भाटिया , मुंबई

उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जोड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रही। उत्तरप्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीट सपा और 6 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। राहुल-अखिलेश की जोड़ी के आगे भाजपा की एक नहीं चली और 62 से घटकर 33 पर आ गई। बाद में अपनी संख्याबल के जोर पर राहुल गाँधी लोकसभा में विरोधी दल के नेता बन गए । राहुल गांधी का विपक्ष का नेता बनना ऐसी बात है जिसकी अंदाज़ा पहले से था।बीते दो चुनावों में कांग्रेस के पास संसद का 10 फ़ीसदी सीट शेयर (54 सीट) भी नहीं रहा था। ऐसे में कांग्रेस सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश ही नहीं कर पाई थी। 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीटें थीं और 2019 में 52 सीटें थीं। इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं।राहुल गांधी का विपक्ष का नेता बनना ऐसी बात है, जिसकी अंदाज़ा पहले से था। जब चार जून को चुनाव के नतीजे आए तो उस वक़्त ही कांग्रेस मुख्यालय- 24 अकबर रोड पर कांग्रेस के समर्थक भी कहने लगे थे- 'इस बार संसद में राहुल गांधी पूरे विपक्ष की आवाज़ बनेंगे। अब पहली बार राहुल गांधी ने संसद में संवैधानिक पद लिया है। विरोधी दल का संवैधानिक पद लेते ही राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट को अपनी कर्मभूमि बनाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में साढ़े तीन दशक से वेंटीलेटर पर पड़ी कांग्रेस को सियासी संजीवनी देने में जुट गए हैं। इसकी झलक 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे आने और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही राहुल गांधी की हाथरस यात्रा और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी में देखा जा सकता है। राहुल गांधी एक महीने में उत्तरप्रदेश का तीन बार दौरा कर चुके हैं, जिसके संदेश साफ है कि उनकी नजर सूबे की सियासत पर है तो सपा भी 2024 के नतीजे के बाद देशभर में अपनी पार्टी के विस्तार करने की दिशा में लगी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र और हरियाणा में होने विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर सियासी रणभूमि में उतरने का प्लान बना रहे है, लेकिन कांग्रेस क्या उसके लिए सीटें देगी, यह बड़ा सवाल है। सपा महाराष्ट्र में 10, हरियाणा में पांच सीटों मांग रही है, जिसके बदले उत्तरप्रदेश में उपचुनाव और 2027 में सीट देने का प्लान बनाया है। सपा नेतृत्व ने भविष्य के लिए कांग्रेस को अपना फलसफा भी समझा दिया है-एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो'। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस अगर सपा को सीटें नहीं देती है तो फिर उत्तरप्रदेश में वह सीटें नहीं देगी। हालांकि, राहुल गांधी की कोशिश सपा के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने की है, जिसे लेकर अखिलेश यादव के साथ संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पर राजनीतिक केमिस्ट्री बनाए रखने की है। इसकी पीछे वजह यह है कि उत्तरप्रदेश में जिस तरह चुनावी नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आई हैं, उसके चलते ही भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई है। ऐसे में भाजपा की कोशिश सपा-कांग्रेस की दोस्ती में दरार डालने की है तो दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस सूबे में अपने-अपने सियासी आधार को बढ़ाए रखने की है। राहुल गांधी की कोशिश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिखरे हुए वोट बैंक को एक बार फिर से जोड़ने की है। राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में काफी हद तक सफलता मिलती दिखी है। कांग्रेस का परंपरागत वोटबैंक एक दौर में दलित-मुस्लिम-ब्राह्मण हुआ करता था। कांग्रेस इन्हीं तीनों के सहारे उत्तरप्रदेश में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही, लेकिन नब्बे के दशक में राम मंदिर आंदोलन और सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स ने उसके समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया। साढ़े तीन दशक से कांग्रेस के लिए सत्ता का वनवास बना हुआ है, लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम ने उसके लिए एक राह दिखा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का एकमुश्त वोट इंडिया गठबंधन को मिलना और संविधान वाले मुद्दे पर दलित समुदाय के झुकाव ने कांग्रेस को उत्तरप्रदेश में फिर से खड़े होने की उम्मीद जगाई है। उत्तरप्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.33 फीसदी वोट मिले थे, लेकिन दो साल बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 6.39 फीसदी पर पहुंच गया। कांग्रेस का सियासी बेस उत्तरप्रदेश में बन जाने के चलते ही राहुल गांधी एक्टिव हैं और दोबारा से कांग्रेस को खड़े करने का प्लान है। राहुल की सक्रियता से सियासी दलों की बेचैनी बढ़नी लाजमी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा जिस सियासी जमीन पर खड़ी नजर आ रही है, वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। बाबरी विध्वंस के बाद मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर होकर सपा के साथ चला गया था। इसके बाद से मुस्लिमों का बड़ा तबका सपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के 'भारत जोड़ो यात्रा' के बाद से कांग्रेस के लिए मुस्लिमों का दिल पसीजा है। राहुल गांधी मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर नजर आते हैं। इसी का नतीजा है कि 2024 में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकमुश्त वोट किया है। माना जाता है कि उत्तरप्रदेश में कांग्रेस का जिस भी सियासी दल के साथ गठबंधन होता, मुस्लिमों का झुकाव उसके तरफ होता। इस तरह राहुल गांधी की सक्रियता से अखिलेश यादव की सियासी बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि मुस्लिम के सहारे की सपा की पूरी सियासत टिकी हुई है। मुसलमानों का वोट अगर कांग्रेस अपने साथ जोड़ने में सफल रहती है तो सपा के लिए चिंता का सबब बन सकती है। इसलिए माना जाता है कि अखिलेश यादव उत्तरप्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस नहीं देना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में सपा ने कांग्रेस को उत्तरप्रदेश की 80 में से 17 सीटें दी थीं, ये सीटें ऐसी थीं जहां पर 40 साल से कांग्रेस को जीत नहीं मिल सकी थी। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद स्थिति बदल गई है और कांग्रेस अपने सियासी आधार को बढ़ाने में जुटी है। कांग्रेस उत्तरप्रदेश में अगस्त के महीने से अपना सियासी अभियान शुरू करने जा रही है और 2027 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। ऐसे में कांग्रेस और सपा की दोस्ती में सहारनपुर और रायबरेली जैसे जिले की विधानसभा सीट का बंटवारा सियासी बाधा बन सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र की पांच सीटों में से चार सीटें सपा जीतने में कामयाब रही थी और एक सीट पर मामूली वोटों से हार गई थी। अब रायबरेली से राहुल गांधी के सांसद बनने और उनके ताबड़तोड़ दौरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साह से भर दिया है और 2027 में कांग्रेस सीटों की दावेदारी कर सकती है। ऐसे में सपा क्या अपनी जीती हुई सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। इसके अलावा सहारनपुर में जिस तरह से इमरान मसूद सांसद बने, जिसके बाद से सपा के मुस्लिम नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। सपा के मुस्लिम नेताओं के साथ इमरान मसूद के छत्तीस के आंकड़े हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर अड़चन आ सकती है और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के चलते 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस उपचुनाव में तीन से चार सीटें मांग रही है जबकि सपा सिर्फ दो सीटें ही छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए शर्त लगा दिया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उसे सीट दें। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल की दोस्ती कितने दिनों तक उत्तर प्रदेश में चल पाएगी, क्योंकि दोनों ही दलों का वोट बैंक एक ही है। सपा मुस्लिम वोट पर अपनी पकड़ हर हाल में बनाए रखना चाहती है को कांग्रेस मुस्लिम परस्त बनने के लिए बेताब है। कई दशकों से उत्तरप्रदेश की राजनीति को कवर करने वाले वीरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद दोनों दल एकजुटता का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा में छह सीट जीतने के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। इस कारण वह भी उत्तरप्रदेश में सपा के बराबर की राजनीति करती नजर आएगी। सपा के सामने मजबूरी है कि वह उपचुनाव में कांग्रेस को साध के चले क्योंकि सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए और राज्यों में भी पैर फैलाने होंगे। इसके लिए उसे गठबंधन के जरिए ही आगे बढ़ना होगा। शायद सपा मुखिया इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसी कारण वह उपचुनाव में कांग्रेस को सीट देने में पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में सपा भी इंडिया गठबंधन के जरिए इन दोनों राज्यों पर चुनाव लड़ने के सपने देख रही है। इसलिए फिलहाल अभी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। रावत का कहना है कि दोनों दलों के बीच जल्द सीटों का बंटवारा होने की उम्मीद है, जिससे दोनों ही दल अपने हिस्से आई सीटों पर गतिविधियां बढ़ा सके। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे का कहना है कि उत्तरप्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेगी।

मेष राशिःछात्रों के करियर में आज कुछ नया बदलाव आयेगा, जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। आज आपका अपने प्रियजनों के साथ बहुत ही बेहतरीन समय बीतेगा। घरेलू कामों में रुचि बनी रहेगी और रिलैक्स महसूस करने के लिए मनोरंजन संबंधी योजनएं भी बन सकती हैं। पारिवारिक व्यवस्था को बनए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा।

वृष राशिःआज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। व्यवस्थित दिनचर्या और खान-पान आपका स्वास्थ्य ठीक रखेगा। और आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता रखेंगे। व्यवसायिक उथल-पुथल और आर्थिक स्थिति की वजह से परिवार के सदस्यों के खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनएं बन रही हैं, तो वास्तु सम्मत नियमों का भी पालन करन उचित रहेगा।

मिथुन राशिःआज किसी खास काम में आपको फायदा मिलेगा। माता-पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवनसाथी आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। आज आपके स्वभाव में वहम और गुस्से की स्थिति देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से परिवार के लोग भी परेशान रहेंगे। आज आपको घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी।

कर्क राशिःआज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा। लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज मीडिया और कम्युनिकेशन से संबंधित व्यवसाय में उपलब्धियों के योग बन रहे हैं। इस उचित समय का भरपूर सदुपयोग करेंगे। व्यवसायिक पार्टियों के साथ संबंध मधुर बनने का प्रयास करेंगे। आज पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। इससे घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बन रहेगा। आज कुछ समय घर के बुजुर्गों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी जरूर बिताएंगे।

सिंह राशिःआज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। घर में नजदीकी रिश्तेदारों के आने से उत्सव का माहौल रहेगा। कई तरह के विचारों का आदान- प्रदान रहेगा। आज घर में काफी समय बाद निकट संबंधियों का आगमन होगा और आपसी विचारों को साझा करने से घर के वातावरण को खुशनुमा बनकर रखेगा।

कन्या राशिःआज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज घर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है। बेहतर होगा कि वरिष्ठ सदस्य की सलाह और मार्गदर्शन करते हुए ध्यान दें। आप तनव मुक्त होकर अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की शिक्षा और करियर से संबंधित भी कोई काम हो सकता है। आज बिजनेस में आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं।

तुला राशिःआज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। इस समय बढ़ते खर्चों में कटौती संभव नहीं है। धैर्य और संयम रखें और गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालेंगे। फालतू बातों में ध्यान न दे, और अपने काम में ही व्यस्त रहें। आज दोपहर बाद परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी। आज समय का उचित सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलने के योग हैं।

वृश्चिक राशिःआज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज काफी हद तक तनवमुक्त महसूस करेंगे।आज बहुत व्यवस्थित रहने का समय है। आज आप ध्यान रखेंगे कि आपकी बात से किसी को आघात न पहुंचे। अपनी महत्वपूर्ण चीजों की संभाल खुद करेंगे। आज व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। परंतु कर्मचारियों का सहयोग आपको तनव मुक्त भी रखेगा।

धनु राशिःआज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अपने कार्यक्षेत्र में जो बदलाव किए हैं, उसके भी भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। कोई ऑफिशियल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। प्रमोशन की भी संभावनएं बन रही है। दांपत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक भावनएं रहेंगी और घर में सुकून भरा और खुशनुमा माहौल रहेगा। भावुकता में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है आज किसी पर भी ज्यादा विश्वास रखन उचित नहीं है।

मकर राशिःआज आपका दिन कॉन्फिडेंससे भरा रहेगा। आज ऑफिस के काम में आप थोड़े बिजी होंगे। आपको थोड़ी थकान महसूस होगी, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आज राजनैतिक और अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मदद आपके व्यवसाय को नई दिशा देगी। आर्थिक स्थिति आज सामान्य बनी रहेगी। आज अपने पर्सनल कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल न करें।

कुंभ राशिःआज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। आज अचानक ही आपको कहीं से सहयोग और उचित सलाह भी हासिल होगी। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचन मिल सकती हैं।

मीन राशिःआज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज योजनबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, इससे आपके कार्य सफल होंगे। नजदीकी संबंधी से चल रहे मन-मुटाव दूर होने से संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा।

शब्द सामर्थ्य -146

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं
1. संबंध, लगाव, नाता, काम 2. सिसकने की आवाज, सीत्कार 4. आग की ज्वाला, दहक 5. दियासलाई 7. प्रतिकार, प्रतिशोध 8. बाबुल की दुआएं लेती जा... गीतवाली बलराज साहनी, मनोजकुमार, राजकुमार, वहीदा की फिल्म 11. करतल ध्वनि 13. आपसी व्यवहार का संबंध, वास्ता 15. वचन, जीभ 16. रोगियों को स्वस्थ और मृतकों को जीवित कर देने वाला 17. एक सुंदर फूलदार वृक्ष 19. पत्नी, बीवी 20. मसालेदार सुगंधित सुरती।

ऊपर से नीचे
1. उचित, उपयुक्त, जायज 2. किवाड़ को अंदर से बंद करने लगा छड़, चटखनी 3. मांस के अत्यंत छोटे टुकड़े 4. माथा, मस्तक 6. कटोरी के आकार का नलीदार पात्र जिसमें तंबाकू रखकर पीते हैं 9. रेखा 10. खून से लथपथ 11. छिपकर बुरी नजर से ताकने की क्रिया, रह रहकर ताकने की क्रिया 12. व्यापार, धंधा 13. श्रृंगार करना, साजन 14. श्रवणइंद्रीय 16. सीमा, हद 18. चमड़ा, चाम 19. बोझ, दबाव।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 145 का हल

मै	दा	न	■	स	र	ग	म	■
त्री	■	सी	■	■	क्षा	■	धु	र्रा
■	सा	ह	स	■	■	■	र	■
स्वा	ग	त	■	स	म	झौ	ता	■
व	र	■	■	र	■	■	■	म
लं	■	वि	ला	स	■	■	दा	म
बी	न	■	ज	■	सा	मा	न	ता
■	ज	■	वा	हि	या	त	■	■
त	र	की	ब	■	ना	■	खा	ली

सू- दोकू क्र.146

	9			2				1
		5	1				3	
7				9		8		5
	8		3		7		5	
2		7				1		3
	4			1			8	
6		2			9			
	5		7			3		
		8		5			6	7

नियम
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.145 का हल

7	8	2	6	3	1	4	5	9
6	4	1	8	5	9	2	7	3
9	3	5	4	7	2		1	8
2	6	3	1	9	7	5	8	4
5	7	8	3	6	4	1	9	2
1	9	4	5	2	8	7	3	6
4	5	7	2	8	3	9	6	1
3	1	6	9	4	5	8	2	7
8	2	9	7	1	6	3	4	5

संपादकीय

श्रीजेश को अनुपम विदाई !

विश्व के सार्वकालिक श्रेष्ठ गोलकीपरों में से एक भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश के लिए भारतीय हॉकी टीम द्वारा दो लगातार ओलिम्पिक में ब्रांज मेडल के तोहफे से बेहतर विदाई और कोई हो ही नहीं सकती थी। हालांकि उम्मीद तो इस बार गोल्ड या सिल्वर की थी। फिर भी ओलिंपिक में मेडल जीतना कोई कम बड़ी बात नहीं है। भारतीय हॉकी टीम के लिए आगे भी अच्छे प्रदर्शन के साथ-साथ श्रीजेश जैसा कोई दूसरा गोलकीपर ढूंढने और तैयार करने की भी बड़ी चुनौती रहेगी। जैसे ही पेरिस में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता, श्रीजेश ने मैदान में लेटकर दर्शकों को साष्टांग नमस्कार किया। बाकी सारे खिलाड़ी प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते रहे। उसके बाद श्रीजेश अपने अंदाज में गोलपोस्ट पर जा चढ़े और सभी का अभिवादन किया। उसके पहले सभी साथी खिलाड़ियों ने 'बो डाउन' कर अपने इस सबसे सीनियर साथी और मार्ग दर्शक का अभिनंदन किया। वह दृश्य सचमुच अत्यंत यादगार था। और क्यों न हो, श्रीजेश जैसा गोलकीपर किसी भी हॉकी टीम को आसानी से नहीं मिलता। श्रीजेश लगभग दो दशकों से भारतीय हॉकी टीम के अडिग गोलकीपर रहे। पेरिस ओलिम्पिक में भारतीय टीम के सफल अभियान के पीछे जितनी भूमिका प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ गोल करने की थी, उससे कहीं ज्यादा श्रीजेश की थी, जिन्होंने दसियों गोल बचाए। इसी वजह से श्रीजेश को क्रिकेट के राहुल द्रविड़ की तर्ज पर भारत की अटल चट्टान कहा जाता है। अपनी गोलकीपिंग में लगातार दो ओलिंपिक मेडल जीतने की उपलब्धि ने श्रीजेश को अब तक के महान गोलकीपरों अर्जेंटीना के मैनुअल विवाल्डी, जर्मनी के निकोलस जेकोबी, आस्ट्रेलिया के एन्ड्रयू चार्टर, नीदरलैंड के जॉय स्टॉकमैन की श्रेणी में ला बिठाया है। श्रीजेश ने भारत के लिए 250 अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेले हैं। हर मैच में उनकी गोलकीपिंग पहले से ज्यादा बेहतर और अचूक नजर आई है। उनके पास अनुभव का खजाना है और गोलकीपरों के लिए तो वह अब लीजेंड बन चुके हैं। केरल के रहने वाले श्रीजेश के घर ओलिपिंक के ब्रांज मेडल मैच में भारत की विजय के बाद दीवाली मनाई गई। श्रीजेश केरल सरकार के खेल विभाग में संयुक्त निदेशक हैं। उनकी पत्नी भी जानी मानी खिलाड़ी रह चुकी हैं। श्रीजेश की गोलकीपिंग की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो गेंद की गति और दिशा का अंदाजा दूर से लगा लेते थे। उनके रहते भारतीय गोल पोस्ट में बॉल डालना सामने वाली टीम के लिए दुरूह होता था। इंग्लैंड के साथ इस बार क्वार्टर फाइनल में श्रीजेश ने पेनाल्टी शूट आऊट में जिस तरह पेनाल्टी स्ट्रोक बचाए, वो लाजबाव और उनकी उच्च स्तरीय गोलकीपिंग का नमूना था। यह कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय टीम वह मैच श्रीजेश की वजह से ही जीती। श्रीजेश ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से अपने रिटायरमेंट का ऐलान इस ओलिपिंक के पहले ही कर दिया था। उनके साथ पिछले 13 सालों से खेल रहे मनप्रीत सिंह का भी यह चौथा ओलिंपिक है। उन्होंने कहा कि यह कांस्य पदक श्रीजेश के लिए है, क्योंकि यह उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच था। यह सही है कि श्रीजेश जैसे खिलाड़ी बिरले ही जन्म लेते हैं। एक जमाने में भारतीय गोलकीपर शंकर लक्ष्मण का बड़ा जलवा था। लेकिन बाद में श्रीजेश जैसे महान खिलाड़ी ने गोलकीपिंग की नई इबारत लिखी। भारत को अब नया गोलकीपर तलाशना होगा तथा उसे श्रीजेश की तरह तैयार करना होगा। अगर श्रीजेश यह जिम्मेदारी लें तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। बहरहाल भारत के इस महान हॉकी खिलाड़ी को उनके खेल संन्यास के बाद भावी जीवन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस पर विशेष

पिछले पांच वर्षों में भारत में अप्राकृतिक कारणों से 528 हाथियों की हुई मौत

पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों का है महत्त्व : करना होगा संरक्षण

संजय कुमार

हर साल 12 अगस्त को 'विश्व हाथी दिवस' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के महत्त्व को स्वीकार करना है और उसका संरक्षण करना है। 'विश्व हाथी दिवस' हाथियों के द्वारा दैनिक जीवन में सामना करने वाले खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर बल देता है। हाथियों के अवैध शिकार, पालतू हाथियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उनके अधिवास को क्षति पहुँचाने जैसे कारकों को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मामला सिर्फ हाथियों के संरक्षण तक का नहीं है, बल्कि इनके संरक्षण की पहल से इन्सान को भी संरक्षण मिलेगा। विभिन्न कारणों से हाथियों की मौत तो होती रहती है, साथ ही हाथियों से इंसानी मौत की खबर भी आती रहती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्टों और पिछले दिनों संसद उठे सवाल को देखें तो पिछले पांच वर्ष (2019-2024) में हाथियों के कारण कुल 2899 मानव दुर्घटनाएं हुई, तो वहीँ पिछले पांच वर्षों में भारत में अप्राकृतिक कारणों से 528 हाथियों की मौत हुई है, जिनमें अवैध शिकार, जहर, बिजली का झटका और ट्रेन दुर्घटनाएं शामिल हैं। पिछले पांच वर्ष (2019-2024) में ट्रेन दुर्घटनाओं में 73, बिजली के झटके से 392, अवैध शिकार में 50 और जहर के कारण 13 हाथियों की मौत हुई है। हाथियों की मौत और हाथियों के कारण मानवीय मौत को कम करने की जारी पहल के बीच दोनों को बचाने की कोशिश चल रही है। बात भारत में हाथियों की जनसंख्या की तो, वर्ष 2007 में 27669-27719, 2012 में 29391-30711 और 2017 में 29964 तक पहुंची है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार करीब 100 वर्ष पूर्व तक सिर्फ अफ्रीका में ही 1 करोड़ से ज्यादा हाथी थे। 1979-80 तक अफ्रीका में इनकी संख्या 20 लाख तक रह गई थी। अगले दस वर्षों में, 1990 तक मात्र 6 लाख हाथी अफ्रीका में बचे थे। 1977 से 1990 की छोटी अवधि में ही पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र के लगभग 75त्न हाथी समाप्त कर दिये गये थे। 1987 के बाद अफ्रीका में इनका अवैध शिकार बेतहाशा बढ़ गया और 1987 से अब तक अफ्रीका सवाना हाथियों की संख्या में 80त्न व अफ्रीकी जंगली हाथियों की संख्या में करीब 45त्न की गिरावट आयी है। सिर्फ 2002 से 2011 के मध्य ही अफ्रीकी हाथी 62त्न तक कम हो गये तथा उनके प्राकृतिक आवासीय क्षेत्रों में 30त्न की कमी आई। 2016 तक पूरे अफ्रीका में हाथियों की कुल संख्या 4 लाख से कुछ ही अधिक थी। हाल के वर्षों में अफ्रीका में करीब 15000 हाथी प्रति वर्ष हाथीदाँत के लिये मारे जा रहे हैं।

एशियाई हाथियों की स्थिति भी अधिक बेहतर नहीं है। 1980 से अब तक इनके प्राकृतिक निवास क्षेत्र में 50त्न से अधिक की कमी आई है। 1980 तक एशिया में करीब 93 लाख हाथी थे, जो अब सिर्फ 45 हज़ार से 50 हज़ार तक सीमित रह गये हैं। इनमें से भी लगभग 60त्न भारत व नेपाल में हैं, शेष श्रीलंका, थाइलैंड, म्यांमार आदि देशों में थोड़ी-थोड़ी संख्या में हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा में ये अपना प्राकृतिक आवासीय क्षेत्र 70त्न तक खो चुके हैं और आईयूसीएन ने वहाँ इन्हें %अत्यधिक संकटापन्न श्रेणी में शामिल किया है। वर्तमान में भारत में हाथियों की कुल तादाद लगभग 27 हज़ार से 30 हज़ार के बीच है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय भारत सरकार ने हाथियों और उनके आवास के संरक्षण के लिए यों तो कई उपाय किए हैं। मसलन, हाथियों, उनके आवासों और गलियारों के संरक्षण, मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों के समाधान और देश में बंदी हाथियों के कल्याण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना 'प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट' के तहत राज्यों/केंद्र

शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य विभिन्न योजनाएं जल स्रोतों को बढ़ाकर, चारे वाले पेड़ लगाकर, बांस के पुनर्जनन आदि के माध्यम से हाथियों के प्राकृतिक आवास में सुधार करने में योगदान दे रही हैं।

मानव-हाथी संघर्ष भी एक गंभीर मुद्दा है। मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए मंत्रालय की ओर से फरवरी, 2021 में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। यह एडवाइजरीं समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, संघर्ष वाले हॉटस्पॉट की पहचान, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना, अनुग्रह राहत की मात्रा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन, शीघ्र भुगतान के लिए मार्गदर्शन/दिशा निर्देश जारी करना और व्यक्तियों की मृत्यु और घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर अनुग्रह राहत पहुँचाना शामिल है। मंत्रालय ने 3 जून, 2022 को फसलों को होने वाली हानि सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें वन सीमांत क्षेत्रों में ऐसी फसलों को बढ़ावा देना शामिल है जो जंगली जानवरों के लिए अरुचिकर हों।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के साथ समन्वय करके भारत में 15 हाथी क्षेत्र वाले राज्यों, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 150 हाथी गलियारों का स्थलीय मान्यता दी है और हाथी गलियारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सूचित किया है। इसके अलावा, हाथियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हाथी आवासों को %हाथी रिजर्व% के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब तक 14 प्रमुख हाथी राज्यों में 33 हाथी रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। ये हाथी रिजर्व टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित वनों के साथ ओवरलैप करते हैं। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्य जीव संघर्ष स्थितियों से निपटने के लिए नियामक कार्यों का प्रावधान किया गया है। समय समय पर मंत्रालय द्वारा मानव-हाथी संघर्ष आदि मामले को लेकर दिशानिर्देश भी जारी किए जाते रहते हैं। वैसे, मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और हाथियों की प्रतिशोधात्मक हत्या से बचने के लिए स्थानीय समुदायों को जंगली हाथियों द्वारा उनकी संपत्ति और जीवन हानि के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। जंगली जानवरों द्वारा हुई मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है। रेल दुर्घटना में हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति भी गठित की गई है। साथ ही रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि ट्रेन की टक्कर और बिजली के झटके से हाथियों की आकस्मिक मृत्यु के मुद्दे का समग्र रूप से समाधान किया जा सके। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में हाथी के संरक्षण को लेकर लगातार कार्यशाला और जागरूकता अभियान चलायी जाती है।

वन्य-जीव पारितंत्र में हाथियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी में इन्हें ÷की-स्टोन प्रजाति या अंब्रेला प्रजाति दर्जा प्राप्त है, अर्थात अपने पारितंत्र में ये वह प्रजाति हैं जो संख्या में बहुत कम होने के बाद भी पारितंत्र की सेहत पर अति निर्णायक प्रभाव डालती हैं तथा पारितंत्र के बहुत से प्राणियों का अस्तित्व इन्हीं पर निर्भर करता है। इसी कारण इन्हें ÷फ्लैगशिप प्रजाति भी कहा जाता है, जिनका संरक्षण करना अत्यावश्यक है। परागण क्रिया इनकी भूमिका अहम् है। हाथी वन में भ्रमण करते समय अपने अति विशाल आकार के कारण वृक्षों, लताओं, पत्तियों आदि से घर्षण क्रिया करते हुये चलते हैं जिसके कारण विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े पौधों के बीज व परागकण उनके शरीर से चिपक जाते हैं। हाथी किसी अन्य स्थान पर जब जाते हैं तब ये बीज व परागकण वहाँ पर छिटक जाते हैं जिससे नये पौधों का विकास होता है। तो आइये हाथी मेरे साथी का संरक्षण करें।

(लेखक केंद्रीय संचार ब्यूरो एवं पत्र सूचना कार्यालय पटना में उप निदेशक हैं)

अध्यात्म

बीते हुए कल के लिए अपना वर्तमान और भविष्य न बिगाड़ें

बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे, 'हमें धरती की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। वह अपना अहित करने वालों पर भी क्रोध नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि क्रोध ऐसी आग है, जिसमें दूसरों के साथ-साथ क्रोध करनेवाला भी जलता है।' सभा में सभी बुद्ध की वाणी को शांतिपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। कुछ देर तक वह ये बातें सुनता रहा, फिर अचानक क्रोध में खड़ा होकर बोलने लगा, 'तुम पाखंडी हो। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो।'

उस व्यक्ति के कड़वे वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह बुद्ध का अपमान करके वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह उसी स्थान पर पहुंचा। लेकिन उसे वहां बुद्ध दिखाई नहीं दिए। पूछने पर उसे पता चला कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास वाले गांव में गए हैं।

बुद्ध के बारे में लोगों से पूछते हुए वह व्यक्ति वहां पहुंच गया, जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणो में गिर गया और बोला, 'प्रभु! मुझे क्षमा कीजिए।' बुद्ध ने उससे पूछा, 'कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो?' उसने कहा, 'क्या आपको बिलकुल याद नहीं कि मैं कौन हूं? मैं वही व्यक्ति हूं, जिसने कल आपकी सभा में आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन आपने मुझ पर बिलकुल भी क्रोध नहीं किया। आप शांत भाव से मुस्कुराते रहे। मैं आपसे अपने इस व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूं। मैं आपके पास क्षमा याचना करने आया हूं।'

बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, 'तुम्हें अपनी गलती का अहसास हो गया। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें, बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो।'

यह सुनकर उस व्यक्ति के मन का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़कर अपने क्रोध करने की बुरी आदत त्यागने का संकल्प लिया। उस दिन से उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी।

आरक्षण में कोटे में कोटा : सुप्रीम कोर्ट का क्रांतिकारी निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का उक्त फैसला सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए ही है। इससे ओबीसी और सामान्य जाति वर्ग के आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए कोटे में कोटा का फैसला हुआ है। किन्तु इसे तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण में भी कोटे में कोटा का आरक्षण का प्रावधान नहीं हो। उदाहरण के लिए पिछड़े वर्ग में यादव, पाटीदार, आंजना आदि भी आते है जो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न हैं। जबकि पिछड़ी जाति में वास्तव में ऐसी अनेक उप जातियाँ हैं, जो वास्तव में पिछड़ी है, इन्हें भी आरक्षण में कोटे में कोटा का लाभ मिलना चाहिए।

डॉ. चन्दर सोनाने

सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से हाल ही में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीव्हाय चन्द्रचूड़ ने इस संबंध में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाकर इस श्रेणी में अति पिछड़ों को अलग से कोटा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है। इसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कोटे में कोटा का फैसला 7 जजों की संविधान पीठ ने 565 पृष्ठ में 6 फैसलें लिखे हैं। इनमें से 5 फैसले सहमति के हैं और 1 फैसला असहमति का है। यह फैसला 6:1 के बहुमत का है। असहमति वाला फैसला जस्टिस सुश्री बेला एम त्रिवेदी ने लिखा है। सीजेआई श्री डीव्हाय चन्द्रचूड़ और जस्टिस श्री मनोज मिश्रा ने संयुक्त रूप से फैसला लिखा है। जस्टिस श्री बी आर गवई, जस्टिस श्री विक्रम नाथ, जस्टिस श्री पंकज मित्तल और जस्टिस श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने अपने-अपने फैसले लिखे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ के उक्त निर्णय से अब राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वे एससी और एसटी वर्ग में शामिल सभी समुदायों के लिए आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय कर सकते हैं। अभी देश में एससी वर्ग के लिए 15 प्रतिशत और एसटी वर्ग के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। इस प्रकार देश में कुल 22.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। राज्य सरकारें एससी और एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय कर सकेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अब यह राज्य सरकारों को तय करना है कि वह इसका किस तरह से पालन सुनिश्चित करें। किस वर्ग को कितना आरक्षण देना है, उसे तय करने के लिए राज्य सरकारें विशेषज्ञ पैनल बना सकती है। ये पैनल रिसर्च और डेटा के माध्यम से बतायेगा कि कौन सा वर्ग आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर कितना पिछड़ा है ? इसके लिए जरूरी है कि विशेषज्ञ पैनलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गा के लोगों को भी अब यह सोचने की आवश्यकता है कि उन्हीं के बीच की अभी भी ऐसी अनेक उपजातियाँ हैं, जो अत्यन्त गरीब हैं और वे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछड़े हैं। इसलिए उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे अब अपने उन भाईयों पर भी ध्यान केन्द्रित करें, जो उनसे भी ज्यादा दयनीय स्थिति में है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है कि जिन्होंने आरक्षण लाभ ले लिया है, वे त्याग करें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभी भी कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ऐसे हैं, जिन्होंने समर्थ होने पर स्वेच्छा से आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, ताकि उनके अन्य भाई आरक्षण का लाभ ले सके। यह करके उन्होंने सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो प्रदेश में अनुसूचित

जाति वर्ग की 48 उपजातियाँ है और अनुसूचित जनजाति वर्ग की 46 उपजातियाँ है। किन्तु इन उपजातियों में से कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है? यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। इसलिए बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार बहुत सोच समझ कर इस संबंध में पूरी जानकारी एकत्रित करने के बाद ही निर्णय लें कि कोटे के अंदर कोटा किनका और कितना दिया जाना है ?मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत आरक्षण है। किन्तु इसका सर्वाधिक लाभ जाटव, महार, मेहरा, अहिरवार आदि को मिला है। इसी वर्ग की अन्य उपजाति में बेड़िया, बंसोर, बेलदार, भंगी, मेहतर, चड़ार, झमराल, पासी, कुछबंदिया, खंगार, झइझर, कालबेलिया, सपेरा, नवदीगार, कोटवाल, चितार आदि को आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं मिला है। इस कारण इन्हें भी आरक्षण में लाभ मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदेश में 20 प्रतिशत आरक्षण है। इस वर्ग में सरकारी नौकरियों में गोंड, कौल, भील, भिलाला, बारेला, डामोर आदि जाति का सर्वाधिक कब्जा है। किन्तु सहरिया, उरांव, नगेसिया, मवासी, धनुका, धनगड़, पनिका आदि उपजातियों में तुलनात्मक रूप से बहुत कम प्रतिनिधित्व है। इस कारण इन्हें भी आरक्षण में लाभ मिलना ही चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का उक्त फैसला सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए ही है। इससे ओबीसी और सामान्य जाति वर्ग के आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए कोटे में कोटा का फैसला हुआ है। किन्तु इसे तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण में भी कोटे में कोटा का आरक्षण का प्रावधान नहीं हो। उदाहरण के लिए पिछड़े वर्ग में यादव, पाटीदार, आंजना आदि भी आते है जो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न हैं। जबकि पिछड़ी जाति में वास्तव में ऐसी अनेक उप जातियाँ हैं, जो वास्तव में पिछड़ी है, इन्हें भी आरक्षण में कोटे में कोटा का लाभ मिलना चाहिए। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के आरक्षण में भी कोटे में कोटा का प्रावधान किया जाना चाहिए। क्योंकि सामान्य वर्ग में भी कई उप जातियाँ ऐसी हैं, जो गरीब है। उसे भी कोटे में कोटा का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान ने आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग मुख्य रूप से सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हैं। अभी भी इन दोनों वर्ग के ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जायेंगे जो आर्थिक रूप से तो सम्पन्न हो गए हैं, किन्तु अभी भी सवर्ण वर्ग के लोग विवाह के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों से बेटी देने या लेने के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों पर क्रीमीलेयर लागू नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय देने वालों में एक जस्टिस श्री बीआर गवई ने अपने फैसले में यह कहा है कि क्रीमीलेयर को एससी एसटी पर भी लागू किया जाना चाहिए। किन्तु अभी इसका समय नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि अभी ओबीसी और सवर्ण आरक्षण में सालाना 8 लाख रूपए से ऊपर कमाने वाले लोग क्रीमीलेयर के अर्न्तगत आते हैं।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष

आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप इस समय कोई बदलाव न करें।

वृषभ

आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो सकती है।

मिथुन

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होगी। आप कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ उठाएंगे।

कर्क

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था, तो वह भी मिल सकता है।

सिंह

किसी काम को लेकर गलतफहमी चल रही है, तो उसे परिवार में किसी सदस्य के सामने मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें।

कन्या

आप कोई निर्णय भावुकता में न लें, नहीं तो इससे बाद में आपको समस्या होगी। आपका किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है।

तुला

दिन आय को बढ़ाने वाला रहेगा। आपका लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान रहेगा। आप अपनी वाणी की सौम्यता से लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेंगे।

वृश्चिक

दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी पैतृक संपत्ति के मिलने की संभावना है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी।

धनु

आपका धन यदि कहीं फंसा हुआ था, तो उसके मिलने की संभावना है। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था, तो वह आज सुलझ सकता है।

मकर

आज का दिन आपके लिए आय को बढ़ाने वाला रहेगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, इसलिए आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता आसानी से मिल सकेगी।

कुंभ

आपको कार्यक्षेत्र में किसी काम के दबाव में आने से बचना होगा। आपको किसी नई संपत्ति की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा।

मीन

दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा। आपको किसी बात को लेकर यदि टेंशन चल रही थी, तो वह भी बढ़ सकती है।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 12 अगस्त 2024

बेहतर हुए रिश्ते

विदेश मंत्री एस जयशंकर की पिछले सप्ताह हुई मालदीव यात्रा के दौरान वहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का जैसा दोस्ताना रवैया दिखा, उसे भावनात्मक राजनीति के तकाजों पर कूटनीति की ठोस हकीकतों की जीत के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। पिछले करीब एक साल की अवधि में दोनों देशों के रिश्तों ने तो हिचकोले खाए ही, एक देश के रूप में भी मालदीव कई कड़वे अनुभवों से गुजरा।

चुनाव प्रचार में भारत विरोध | इस प्रकरण की शुरुआत पिछले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से मानी जा सकती है जिसमें एक प्रत्याशी के तौर पर मुइज्जू ने भारत विरोधी भावनाओं पर दांव लगाया था। वह बार-बार सार्वजनिक तौर पर यह संकल्प करते देखे गए कि सत्ता में पहुंचते ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से विदा कर देंगे। हालांकि सबको पता था कि भारतीय सैनिकों की वहां मौजूदगी सांकेतिक ही थी।

जयशंकर की यात्रा दोस्ताना माहौल में

चीन से करीबी | चुनावों के दौरान ही यह साफ हो गया था कि मुइज्जू भारत के साथ रिश्तों में आ रही संभावित दूरी की भरपाई चीन से करीबी रिश्तों के रूप में करना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स तब भी इस बात की ओर ध्यान खींच रहे थे कि भू-राजनीति की वास्तविकताओं के मद्देनजर यह संभव नहीं है कि मालदीव में जो भूमिका भारत निभा सकता है, वह चीन निभाने लगे।

मंत्रियों की टिप्पणी | राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद मुइज्जू के बयानों में हलकी सी नरमी जरूर दिखी, लेकिन नीतियों की दिशा बदलने का प्रयास भी जारी रहा। चुनावों के दौरान बने माहौल का असर ही कहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर मालदीव के एकाधिक मंत्रियों ने सार्वजनिक मंचों से ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में धीरे-धीरे बनता तनाव अचानक बेकाबू हो गया। सोशल मीडिया पर 'बॉयकॉट मालदीव' का हैशटैग ट्रेंड करने लगा।

वेट एंड वॉच की पॉलिसी | मालदीव की नई सरकार के रुख को देखते हुए भारत ने भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार कर ली। नतीजा यह हुआ कि भारत से छुट्टियां बिताने मालदीव जाने वाले टूरिस्टों की संख्या कम होने लगी। इस साल के शुरुआती चार महीनों की अवधि में वहां भारतीय टूरिस्टों की संख्या में 42% की कटौती दर्ज की गई। ध्यान रहे, मालदीव की GDP में टूरिज्म का योगदान 30% है।

रुख बदलने के संकेत | इतना ही नहीं, भारत के सहयोग से चलने वाले इन्फ्रा प्रॉजेक्ट्स और हेल्थ, एजुकेशन और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कई प्रॉजेक्ट्स का भविष्य भी अधर में लटका दिखाई देने लगा। मुइज्जू सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती थी। किसी अन्य देश का सहयोग भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता था। ऐसे में मुइज्जू सरकार ने पिछले कुछ समय से अपने रुख में बदलाव का संकेत देना शुरू कर दिया था। भारत ने भी इन संकेतों का सम्मान किया। नतीजा यह कि दो पड़ोसी देशों के पुराने रिश्ते फिर पटरी पर लौटते दिख रहे हैं।

चक्र-व्यू

जादू आलू का

राहुल पाण्डेय

जरूरी नहीं कि नाम का वही अर्थ निकले, जिसके लिए वह बोला जा रहा हो। जरूरी नहीं कि गाजर हमेशा गाजर हो, टमाटर हमेशा टमाटर हो या आलू हमेशा आलू हो। शुरुआती क्राइम रिपोर्टिंग के दिनों में एक बार मेरी ड्यूटी मेरठ की एक चुंगी पर लगा दी गई। काम था कि चुपचाप बैठे रहो और देखो कि पुलिस वाले 'चढ़ावे' के लिए कैसे-कैसे कोड बोलते हैं। एक-दो दिन कुछ समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। पुलिस वाले हमेशा अपने टिन शेड में ही बैठे रहते, बमुश्किल ही बाहर निकलते। और वैसे भी हिंदुस्तानी ट्रैफिक को पुलिस की न तो पहले जरूरत रही, और न ही आज है। हिंदुस्तानी ट्रैफिक रास्ता देखकर निकलता है, पुलिस देखकर नहीं। और जब नहीं निकल पाता है तो पुलिस को जेब से निकालकर एक जादू दिखाता है, और सर्र से निकल जाता है। अब जादू का तो हिसाब-किताब यही है कि जितना दिखाओ, लोग उतना ही और देखना चाहते हैं। फिर पुलिस भी तो इंसान ही है। वह बार-बार जादू देखना चाहती है। लोग बार-बार जेब से निकालकर कभी नीला, कभी हरा और बंद होने से पहले गुलाबी जादू दिखाते रहे हैं। शायद ऐसा कोई नहीं, जिसने पुलिस को यह जादू न दिखाया हो और जादू देखकर पुलिस का खिलता-खिलखिलाता चेहरा ना देखा हो। हर इंसान में एक बच्चा होता है तो आखिर पुलिस में क्यों न हो? तो चुंगी पर मैं कई दिन पुलिस को बच्चों के जैसे खिलखिलाते देखता रहा। फर्री, चुटकी, बैरियर जैसे कुछ कोडवर्ड हाथ लगे तो आकर खबर लिख दी।

जादू पर तो खबर क्या, किसी का असर नहीं हो सकता। लेकिन जादू के मंत्रों पर कुछ असर हुआ और कोडवर्ड बदल गए। साथी रिपोर्टर ने खबर दी कि इन दिनों प्याज, टमाटर चल रहा है, और महंगा होगा तो आलू भी चलेगा। पिछले हफ्ते एक दरोगा जी पांच किलो आलू मांगते पकड़े गए। अब यहां आलू वो वाला आलू नहीं है जो नाना पाटेकर साहब कोट पैंट पहनकर ठेले पर लादकर हांक लगाते हुए बेच रहे थे। ये वाला आलू बिकता नहीं, खरीदता है। हमारे एक गुरुवर बताते हैं कि दरोगा का तो मालूम नहीं, पर दस्तूर के हिसाब से एक किलो आलू का मतलब है 10 हजार नकद। उन्हें यह बात एक परिचित ने बताई थी, जिनसे पेशकार ने पांच किलो आलू मंगाए थे। हालांकि ट्रैफिक में एक किलो आलू का दाम कम होता है। ट्रैफिक की चौकी से तीन सितारे वाले थाने तक पहुंचते-पहुंचते इसका दाम बढ़ जाता है। बढ़ना भी चाहिए। दाम अगर ना बढ़े तो यह पुलिस की नहीं, आलू की बेइज्जती है। और दुनिया में किसी की इज्जत रहे या ना रहे, आलू की इज्जत बनी रहनी चाहिए। आलू है तो जादू है। आलू है तो चमक है।

एकदा

सैनिकों के लिए भोजन

अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। कुछ समय बाद अमेरिकी सेना को गेहूं के अभाव का संकट झेलना पड़ा। सैनिकों के भूखे मरने की नौबत आ गई। आखिर अन्न की कमी को कैसे पूरा किया जाए? पता चला कि Tuskegee School की प्रयोगशाला में शकरकंद के प्रयोग से डबल रोटी बनाई जाती है। यह भूख तो मिटाती ही है, पोषणयुक्त भोजन भी है। अधिक जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि जॉर्ज वॉशिंगटन कॉर्वर नाम के

Subrata Dhar

एक नीग्रो वैज्ञानिक ने मूंगफली और शकरकंद से कितने ही व्यंजन बनाए हैं। इनसे एक गरीब व्यक्ति और सैनिक बदहाल परिस्थिति में भी अपना गुजारा कर सकता है। यह जानकर उन्हें सैनिकों की मदद के लिए बुलाया गया। वहां आकर जॉर्ज कॉर्वर ने लोगों को शकरकंद से डबलरोटी, बिस्कुट, आटा बनाना सिखाया। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि शकरकंद की एक बहुत बड़ी खासियत है, यदि इसका निर्जलीकरण कर दिया जाए तो 100 पौंड शकरकंद का आटा एक छोटे-से डिब्बे में रखा जा सकता है। इससे इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखकर विषम परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शकरकंद की यह खासियत वाकई युद्ध में सैनिकों के लिए बहुत अनमोल थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों और वहां की जनता को भूख से मुक्ति मिली। वह जीवनभर गरीब किसानों की मदद के लिए ही प्रयोग करते रहे।

संकलन : **रेनू सैनी**

भारत को ओलिंपिक्स की मेज़बानी के बजाय पदकों की संख्या बढ़ाने पर देना चाहिए ध्यान

पैरिस ने जो सिखाया, याद रखना होगा

बोरिया मजूमदार

पैरिस ओलिंपिक्स में भारत से दहाई अंकों में मेडल जीतने की उम्मीद थी। हमारे पास 117 खिलाड़ी थे, जिनमें से कई दुनिया के टॉप ऐथलीट थे। इसलिए ये उम्मीदें जायज थीं। लेकिन, परिणाम उतना अच्छा नहीं रहा, जितना सोचा गया था। सबसे बड़ी निराशा यह रही कि भारत पैरिस ओलिंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया।

ख्वाब टूटा | विनेश फोगाट वाले मामले ने इस तकलीफ को और बढ़ा दिया है। युई सुसाकी जैसी महान खिलाड़ी को हराने के बाद विनेश गोल्ड के लिए सबसे मजबूत दावेदार थीं, लेकिन आखिरी मैच से पहले जब उनका वजन हुआ तो वह 100 ग्राम अधिक निकला। इसलिए उन्हें मैच की खातिर अयोग्य घोषित कर दिया गया और गोल्ड का ख्वाब टूट गया।

6 खिलाड़ी चौथे नंबर पर | सरसरी तौर पर देखें तो पैरिस ओलिंपिक्स भारत के लिए आसान नहीं रहा। लेकिन गहराई से देखें तो कुछ उम्मीदें भी नजर आती हैं। नीरज चोपड़ा का कहना है कि 'छह चौथे स्थान आसानी से नहीं मिलते। इसका मतलब है कि हमारे खिलाड़ी लगभग-लगभग वहां तक पहुंच रहे हैं। हम उनका समर्थन करते रहें तो हम इन चौथे स्थानों को पदकों में बदल सकते हैं।'

रोमानिया से जीते | निशांत देव, विनेश फोगाट और सात्विक और चिराग की जोड़ी का प्रदर्शन देखते हुए दहाई अंकों में मेडल जीतना संभव लग रहा था। महिला टेबल टेनिस में भी भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दो भारतीय लड़कियों का प्री-क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचना एक ऐतिहासिक घटना थी और टीम इवेंट में रोमानिया को हराना भी। रोमानिया के खिलाफ भारत ने शानदार जीत दर्ज की।

बड़े मौके पर गलतियां | धीरज और अंकित भगत मिक्स्ड आर्चरी में मेडल के बहुत करीब पहुंच गए थे। लक्ष्य सेन ने एक गेम का फायदा और 8-3 की बढ़त गंवा दी। सत्विक और चिराग भी एक गेम से आगे थे और फाइनल सेट में 14-10 से आगे थे, लेकिन फिर हार गए।

ओलिंपिक्स के सबक
- 6 ऐथलीट चौथे स्थान पर रहे
- मैनेजमेंट से कुछ गलतियां भी हुईं
- 2028 में अधिक पदक पर हो ध्यान

आत्मनिरीक्षण की जरूरत | कुछ खेलों में, जैसे ऐथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और महिला बैडमिंटन में आत्मनिरीक्षण करने की बहुत गुंजाइश है। चोपड़ा और अविनाश साबले (3000 मीटर स्टीपलचेज) और कुछ हद तक पारूल चौधरी (3000 मीटर स्टीपलचेज) को छोड़कर, बाकी सभी ट्रैक एंड फील्ड ऐथलीटों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया।

शूटिंग में वापसी | निशानेबाजों ने तीन मेडल जीते। रियो 2016 और तोक्यो 2020 की निराशाओं के बाद पैरिस ओलिंपिक्स में इस प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि भारतीय खिलाड़ी फिर से पुरानी चमक हासिल कर रहे हैं और आगे भी उनका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। हॉकी में कांस्य पदक मिला। यह भी बेहद खुशी का विषय है। तोक्यो के बाद पैरिस ओलिंपिक्स में भारत ने लगातार दूसरी बार यह मेडल हासिल किया है।

कहां हुई गलती | भारत कहां गलती कर रहा था? ऐथलीटों के प्रबंधन में। सहायक कर्मचारियों, जिनमें पोषण विशेषज्ञ और खेल वैज्ञानिक शामिल हैं, उन्हें अंतिम पंघाल की नाकामी के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कैसे हो सकता है कि उसके पास बाउट के दौरान कोई ऊर्जा न बची हो? जब आप सुनते हैं कि उसने वजन कम करने के लिए 48 घंटे तक भूखे रहकर प्रतियोगिता की, तो यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। मुक्केबाज अमित पंघाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। और विनेश के मामले में गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। हालांकि इस मामले में साजिश की जो थिअरी चल रही है, उसमें कोई दम नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं किसी ने गलती की, जिसकी वजह से भारत को पदक गंवाना पड़ा।

खिलाड़ियों की संख्या बढ़े | आगे चलकर, भारत को एक सरल बात पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वह है, 2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक्स में ऐथलीटों की संख्या तिगुनी करने का प्रयास करना। पैरिस में, अमेरिका के 600 से अधिक ऐथलीट थे, जबकि जापान के 400 से अधिक। भारत ने केवल 117 ऐथलीट पैरिस ओलिंपिक्स में भेजे थे। अगर भारत इस संख्या को तीन गुना बढ़ाने में सक्षम होता है तो स्वाभाविक है कि पदकों की संख्या भी बढ़ेगी।

पहले पदक बढ़ें | 2036 में खेलों की मेजबानी करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, ध्यान पूरी तरह से 2028 ओलिंपिक्स और उसके बाद के आयोजनों में पदकों की संख्या बढ़ाने पर होना चाहिए। तभी हम ओलिंपिक्स नेशन बन सकते हैं और तभी दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी का कोई मतलब होगा।

परछाइयों में छिपी खुशियों को कभी तलाशा क्या

प्रह्लाद आचार्य कोई जादूगर नहीं हैं, फिर भी उन्हें जादू आता है। कभी वह हाथों से कोई जानवर निकालते हैं, तो कभी इंसान। कभी कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ उनकी हथेलियों के बीच प्रकट हो जाता है, तो कभी कोई बूढ़ा पेड़ कहानी सुनाने लगता है अपनी। प्रह्लाद यह सब कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रोशनी का इस्तेमाल कैसे करना है।

वह एक शैडो आर्टिस्ट हैं। शैडो आर्टिस्ट मतलब परछाइयों से खेलने और उससे खेल दिखाने वाला कलाकार। वह कभी सामने नहीं आता। उसकी कला खिलती ही पर्दे के पीछे रहकर है। सामने आता है बस उसका काम, जिसे देखकर सामने बैठे दर्शक खिलखिला उठते हैं। परछाई होती है काले रंग की, लेकिन जब वह पर्दे पर उतरती है, तो उसमें कल्पनाओं के रंग अपने आप भरते चले जाते हैं। कलाकार की अंगुलियों से पैदा हुई समंदर की लहर या उगते सूरज से जगमगा रहे आसमान के बारे में दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं कि उसका रंग क्या होगा। वह बात अनकही, लेकिन समझी-बूझी है। ऐसा ही खेल तो परछाइयां हमारे साथ हर दिन खेलती हैं। बिना कहे वे हमें तरह-तरह की चीजें दिखाती हैं, और इसमें भी वही आनंद है जो शैडो प्ले में।

परछाई हवा की तरह है, जो हथेलियों पर आकर बैठ जाती है, लेकिन मुट्ठी में कैद नहीं होती। यह बादलों की तरह है, जो आपको बिल्कुल वही दिखा सकती है जो उस समय आप देखना चाहते हैं। परछाइयों से खेलना पजल गेम में उलझने जैसा है। आप बस सोचिए कि देखना क्या है और रोशनी से मिलकर परछाई वह चीज पेश कर देगी।

AI Image

जीवन आनंद

गौर कीजिए कि पेड़ों की परछाई क्या बना रही है, कमरे में पड़ा बेड, मेज पर रखा सामान, कुर्सियां और डोरी पर उड़ते कपड़े किस तरह का करतब रच रहे हैं।

कहा जाता है कि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, और जब छोड़ती है तो वक्त वाकई बुरा होता है। लेकिन, क्या परछाई सही में साथ छोड़ देती है या शायद वह हमारे साथ ही रहती है, पर दिखती नहीं! अंधेरा कभी भी घिर सकता है, बिल्कुल मुश्किलों की तरह। तब ऐसा लग सकता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन, दरअसल अंधेरे के कारण हम ही नहीं देख पाते। परछाई तो वहीं रहती है।

हमारे साथ चलते हुए परछाई कभी पीछे रह जाती है, कभी आगे निकल जाती है, लेकिन वह कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होती। उसके आसपास कई रंग हैं। लेकिन कभी किसी परछाई को नहीं देखा होगा आपने कि वह रंगों के पीछे भागे। जो है जैसा है, वह संतुष्ट है उसमें। लेकिन, इसके साथ ही वह यह भी बताती है कि आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। अगर रोशनी के साथ तालमेल सही बन जाए, तो एक छोटी-सी परछाई भी बड़ी होकर किसी को भी आगोश में ले सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें हिचक नहीं है और आत्मविश्वास तो कूट-कूटकर भरा है। देखिए, कितनी गंदगी है सड़क पर, आजकल तो हर जगह कीचड़ ही कीचड़, ऊपर से नकारात्मक बातें। लेकिन, बढ़ती हुई परछाई जब इनके बीच से गुजरती है, तो भी इनके असर में नहीं आती। कितनी भी खराब स्थिति हो, वह उसमें से निकलती बिल्कुल साफ है। उसे किसी बात का डर नहीं है, न किसी की आलोचना का, न किसी की डांट-फटकार या मार का। वह तो उस अंधेरे से भी नहीं डरती, जो उसे खत्म करने पर तुला है। उसे पता है कि अंधेरा हुआ है, पर हमेशा तो नहीं रह पाएगा। उसे हटना ही पड़ेगा और तब वह फिर सामने आ जाएगी। तब तक वह हम में समा जाती है। उसे हम पर भरोसा है, तो हमें अपनी परछाई पर भरोसा क्यों नहीं।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं **nbtreader@timesofindia.com** पर, और सब्जेक्ट में लिखें-**'जीवन आनंद'**

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

जब आनंद अपने भीतर है, दुनिया के भरोसे क्यों रहना

प्रेम रावत जी

इस संसार में आपके लिए सबसे मूल्यवान चीज कौन-सी है? वह जो सबसे सरल हो, आसान हो, मुफ्त हो और जिसके लिए किसी प्रयास की जरूरत न हो, पर जिसे सारी दुनिया के धन से भी नहीं खरीदा जा सकता हो? इतनी सस्ती और इतनी महंगी चीज़ क्या है?

एक सांस है! यह सरल है। इसको लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह अपने आप आती है, अपने आप जाती है। कभी सोचा कि यह सांस कितनी अनमोल है? एक-एक करके आती है और जब तक आती रहती है, तुम्हारे लिए सब कुछ है। सारे रिश्ते-नाते इसीलिए हैं, क्योंकि ये सांस आ रही है। जिस दिन सांस आनी बंद हुई, लोग इकट्ठा होंगे और फूंक-फांक देंगे। यह सांस का ही तो चक्कर है।

बनाने वाला तुमको ये मुफ्त में दे रहा है। अगर मनुष्य ने इसकी क़दर नहीं जानी तो यह आई और चली गई। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी चीज़ आई, उसके पास धनों का धन आया, परंतु वह उस चीज़ को नहीं पहचान सका। यह इस जीवन को पहचानने की बात है। इस प्यास को पहचानने की बात है। मैं आपको प्यास देने की कोशिश नहीं कर रहा। जो प्यास पहले से ही आपके अंदर है, उस प्यास से आपका परिचय होना चाहिए। यह आपकी अपनी चीज़ है। अगर इस प्यास से आपका परिचय नहीं हुआ तो समय निकल जाएगा! बनाने वाले ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है, अपने जीवन में इस कृपा को पहचानो।

हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ है और वह है परमानंद। उस परमानंद का स्वयं अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव का आनंद उठाया जा सकता है। उसको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। ढूंढने से वह नहीं मिलेगा। वह पहले से ही वहीं है, जहां है। जो चीज़ तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे पास ही मिलेगी। लोग समझते हैं कि अगर सारी लड़ाइयां बंद हो जाएं तो शांति हो जाएगी।

इस जीवन के अंदर आनंद की अभिलाषा हर एक व्यक्ति को है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो। सबको आनंद चाहिए, सुख-शांति चाहिए। आनंद मिल रहा है तो सब कुछ ठीक है। कोई मंदिर में नहीं जाता है यह कहने के लिए कि, 'हे भगवान! बहुत ज्यादा आनंद दे दिया, अब थोड़ा-सा कम कर दो।' कोई नहीं जाता है, क्योंकि यह तुम्हारी प्रकृति है कि तुम्हारे लिए सुख सहने की कोई सीमा नहीं है और दुःख ज़रा भी नहीं झेल सकते।

यह सारा संसार हमसे वायदा करता है कि हमारी तरफ चलो। जैसा हम कहें, वैसे चलो और तुमको सुख मिलेगा। परंतु यह दुनिया सिर्फ दुःख देती है। यही होता है। तो कैसे मिलेगा सुख? कहां है असली सुख? ऐसा सुख कहां है, जो जिंदगी भर बना रहे?

लोग बड़े-बड़े प्लान बनाते हैं। पर क्या तुमने इस जीवन का भी कोई प्लान बनाया है? तुम्हारे अंदर भी एक जगह है, वह है असली स्वर्ग। वहां कौन बैठा है वह 'हंस' बैठा है तुम्हारे अंदर, जो सबको आनंद विभोर कर देता है। उसको जानो, ढूंढो! जहां मिले वहीं ठीक है, नहीं मिले तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं।

प्रस्तुति : आर.डी.अग्रवाल 'प्रेमी'

चीन के कितने चेहरे, जानते हैं आप?

मृत्युंजय राय

चीन के आर्थिक मॉडल और उसकी कामयाबी की अक्सर चर्चा होती है। किस तरह से चीन ने 'मिरैकल इकॉनमी' का दर्जा हासिल किया और कैसे वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने पूंजीवाद का एक अलग ही रास्ता दुनिया को दिखाया। कई देशों ने इसकी नकल करने की भी कोशिश की, लेकिन चीन जैसी तरक्की कोई हासिल नहीं कर पाया। हमारे यहां भी यह चर्चा होती आई है कि क्या भारत इस मॉडल को अपनाकर मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी ताकत नहीं बन सकता ताकि कृषि क्षेत्र से अधिक कामगारों की खपत वाले उद्योग धंधों की ओर लोगों को शिफ्ट किया जा सके और बेरोजगारी में कमी लाई जाए। इस बारे में जानकार दो धड़ों में बंटे हुए हैं। कुछ इसके पक्ष में तो कुछ विरोध में।

AI Image

विचार विंडो

चीन फिलहाल आर्थिक दुश्वारियों से गुजर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास, भूगोल और विरासत के जरिये भी इस देश को समझा जा सकता है। इस नजरिये से देखने पर चीन की कैसी तस्वीर सामने आती है? **At the Edge of Empire: A Family's Reckoning with China** में एडवर्ड वोंग (Edward Wong) ने यही कोशिश की है। यह किताब संस्मरण है, जिसके जरिये लेखक ने चीन के अंदर निहित विरोधाभासों को सामने लाने का प्रयास किया है। एडवर्ड इसमें अपने पिता और चाचा के बारे में लिखते हैं। दोनों का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हॉन्गकॉन्ग में हुआ था। 1948 में एडवर्ड के चाचा अमेरिका पढ़ाई के लिए चले गए और पिता 1950 में पेइचिंग। उनके पिता क्रांति के सिपाही बनने गए थे। उन्हें पार्टी ने शिंगच्यांग में तैनात किया।

क्रांति के इस सिपाही का क्यों माओवाद से मोहभंग हुआ, इस बारे में एडवर्ड लिखते हैं कि जब उनके पिता ने बाद के वर्षों में देखा कि क्रांति के कई नायकों की हत्या कर दी गई और माओ की 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' पॉलिसी की वजह से चीन को कैसे भुखमरी से गुजरना पड़ा तो उन्हें इसके खोखलेपन का अहसास हुआ। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत माओवादी चीन ने औद्योगिक ब्रिटेन की बराबरी करने का लक्ष्य तय किया था। एडवर्ड के पिता ने चीन से भागने का फैसला किया। वह पहले हॉन्गकॉन्ग गए, जहां ब्रिटेन की हुकूमत थी और लोकतंत्र था। अफीम युद्ध में हार के बाद हुए समझौते की वजह से हॉन्गकॉन्ग को 100 वर्षों के लिए चीन ने ब्रिटेन को लीज पर दिया था। खैर, एडवर्ड के पिता हॉन्गकॉन्ग में भी ज्यादा वक्त नहीं रुके और 1962 में अमेरिका पहुंच गए। कोई एक दशक बाद यहीं एडवर्ड का जन्म हुआ।

एडवर्ड की वापसी चीन में 2008 में हुई। वह एक अमेरिकी अखबार के संवाददाता के रूप में चीन पहुंचे। वह अपने पिता के गांव गए। यहां उन्होंने देखा, किस तरह से कन्फ्यूशियस के पारिवारिक रिश्तों के बारे में विचार आज तक समाज पर प्रभाव रखते हैं। उन्होंने इसकी कमियां भी देखीं। ये विचार चीन में Individualism में बाधा बनते हैं, जबकि अमेरिका में एडवर्ड के परिवार ने इसी Individualism की बदौलत तरक्की हासिल की थी। वह शिनच्यांग, तिब्बत और हॉन्गकॉन्ग भी गए, जहां उनके पिता रह चुके थे। उन्होंने देखा कि किस तरह से अलग सांस्कृतिक, धार्मिक और औपनिवेशिक इतिहास के कारण लोगों में कम्युनिस्ट सत्ता को लेकर नाराजगी है और सरकार कैसे इसे दबाने की कोशिश करती रहती है। अपने परिवार के किस्सों के जरिये एडवर्ड चीन की तस्वीर रखने में कामयाब रहे हैं और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने चीन के अंतर्विरोधों को भी सामने रखा है।

रिश्तों में बराबरी

प्रणव प्रियदर्शी

स्त्री-पुरुष संबंधों को अक्सर तर्कों से परे कहा जाता है। किस तरह के लड़के और किस तरह की लड़की में बनेगी और कौन किसे पसंद करेगा, यह तय करने का कोई फॉर्म्युला नहीं है। हालांकि फॉर्म्युला खोजने की कोशिशें कम नहीं हुईं। रूप-गुण से लेकर कुंडली मिलाने तक की तमाम कवायदें इसी का नतीजा हैं। बहरहाल, बात पसंद की उतनी नहीं, जितनी पसंद के बाद शुरू होने वाली साझा जिंदगी की है। अक्सर बड़े साहित्यकार, मानव मन के जानकार भी इस तरह का निष्कर्ष देते हैं कि प्यार में लड़का और लड़की के बीच बराबरी नहीं हो सकती क्योंकि रोमांस के विचार में ही पुरुष प्रधानता का तत्व गुंथा होता है। इसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए अपेक्षाकृत उदार विचारों वाले कुछ लोग कहते हैं कि मैन-वुमन रिलेशनशिप में बराबरी की तलाश मृगतृष्णा है क्योंकि यह व्यवहार में संभव नहीं। उनका कहना है कि कौन कब डॉमिनेट करेगा यह तय नहीं है। कुछ खास स्थितियों में एक पक्ष ऊपर होता है तो दूसरे हालात में दूसरा पक्ष। मगर गैर-बराबरी की कीमत होती है। फ्रांस की फेमिनिस्ट राइटर और पत्रकार ने अपनी पुस्तक **Reinventing Love : How the Patriarchy Sabotages Hetrosexual Relations** में इस पहलू पर रोशनी डाली है। सवाल कई हो सकते हैं। मसलन, एक स्त्री और एक पुरुष के साथ रहने के आधार पर ही क्या यह माना जा सकता है कि कोई रिश्ता प्यार से निर्देशित हो रहा है? और, अगर रिश्ते में पजेसिवनेस या स्वामित्व का भाव, पालन-पोषण करने और खर्चा चलाने का भाव हावी हो जाए तो भी क्या इसे प्यार से निर्देशित माना जाएगा? आखिरी बात, प्यार में समर्पण के भाव के चलते इंगो की खास भूमिका नहीं रह जाती। लिहाजा हिसाब-किताब भी नहीं होता कि कितनी मैंने पार्टनर की सुनी और कितनी पार्टनर ने मेरी। लेकिन अपनी न सही तो पार्टनर की ही सोचकर रिश्तों में बराबरी सुनिश्चित करने की कोशिश तो हो ही सकती है, बल्कि होनी चाहिए।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ जीवन की खुशियां

5 अगस्त को 'जीवन आनंद' कॉलम में 'एक ट्रिक आजमाइए, काम से प्यार हो जाएगा' लेख पढ़ा। लेखक ने यह बताया है कि किस तरह हम अपने काम में मजा ढूंढ सकते हैं। अक्सर हम काम को बोझ समझते हैं और बॉस की बातें सुनकर तनाव और थकावट महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने काम को केवल एक नौकरी के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा मानें। हर बड़ा काम छोटे-छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम काम को प्यार से करते हैं तो उसमें आनंद महसूस होता है। काम से जुड़ी चुनौतियां और समस्याएं हमें आगे बढ़ने का अवसर देती हैं।

सुधांशु शेखर मिश्र, ईमेल से

■ सुखी जीवन के फॉर्म्युले

ट्रिक्स जीवन को सरल और सुखमय बनाने में मदद कर सकते हैं, बशर्ते हम समय और हालात के बीच तालमेल बैठा लें। योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या को व्यवस्थित करने से जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। 5 अगस्त के लेख 'एक ट्रिक आजमाइए, काम से प्यार हो जाएगा' में इस बात को बेहतर अंदाज में समझाया गया है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क है। इन ट्रिक्स को अपनाएं तो ये गणित और फिजिक्स के फॉर्म्युले की तरह हर समस्या को सॉल्यूशन तक पहुंचा देते हैं।

गरिमा रावत, ईमेल से

जीवन आनंद

■ आगे की उम्मीद

जीत चाहे बड़ी हो या छोटी, वह जीत ही होती है। हाल ही में ओलिंपिक्स खेलों में भारत ने केवल 6 मेडल जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह छोटी उपलब्धि नहीं है। भले ही यह संख्या कुछ अन्य देशों की तुलना में कम हो, लेकिन हर एक मेडल और हर एक खिलाड़ी ने अपने प्रयासों से हमें गौरवान्वित किया है। आगे की उम्मीद रखकर अपनी खुशियों को इन सफलताओं से जोड़ना चाहिए।

उज्ज्वल कुमार, पीतमपुरा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

यूक्रेन को 12.5 करोड़ डॉलर देगा अमेरिका - एक खबर

- यह युद्ध की आग में घी डालने का तो काम नहीं है!

प्रमोद यादव

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष फांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 12 अगस्त • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

हताश न होना सफलता का मूल है, और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है, और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है।
-वाल्मीकि

editpagesahara@gmail.com

वायनाड में आश्वासन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को आश्वासन दिया कि केंद्र वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री वायनाड में जिला कलक्ट्रेट में जमीनी हालात की समीक्षा करने और भूस्खलन पीड़ितों की पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इससे पूर्व वायनाड जाते समय उन्होंने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला, मुंडक्कई और पुंचिरीमट्टम का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने एक राहत शिविर का भी दौरा किया और भूस्खलन से विस्थापित हुए कुछ लोगों से बातचीत की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। भूस्खलन की इस आपदा में 226 लोगों की मौत

हो चुकी है, और 130 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते अति मौसमी घटनाओं के कारण आपदाएं आने का सिलसिला बढ़ गया है। देश के पहाड़ी राज्यों में तो इन घटनाओं से जान-माल का खासा नुकसान होता है, और आये साल होने वाली इन घटनाओं के मद्देनजर इन घटनाओं को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग विशेषकर विपक्षी दलों की तरफ से उठती है। वायनाड में भूस्खलन इस आपदा के लिए भी यह मांग जोर-शोर से उठी, लेकिन केंद्र ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार किया है। बताया गया है कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार के तत्कालीन गृह राज्यमंत्री मुल्लापल्ली रामचद्रन द्वारा 2013 में संसद में दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए बल दिया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों में 'राष्ट्रीय आपदा' जैसी कोई अवधारणा नहीं है। एक प्रश्न के जवाब में रामचंद्रन ने कहा था कि केंद्र सरकार कई स्थितियों के आधार पर तय करती है कि आपदा की प्रकृति क्या है, जिसमें इसकी तीव्रता, राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने में राज्य सरकार की क्षमता और राहत प्रदान करने के लिए योजना के भीतर उपलब्ध विकल्प आदि को ध्यान में रखा जाता है। प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में तत्काल राहत और सहायता प्रदान करना प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि 'राष्ट्रीय आपदा' के लिए तो कोई निर्धारित मानदंड नहीं है, अलबत्ता, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। बहरहाल, वायनाड भूस्खलन गंभीर किस्म की आपदा करार दी जा सकती है, और इसलिए बेहद जरूरी है कि तमाम संभव उपाय करके प्रभावितों और पीड़ितों को संकट के दंश से उबारा जाए।

सिद्धांतों की अनदेखी

सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सत्रह माह तक जेल में रहने के बाद जमानत दे दी। अदलत ने अधीनस्थ अदालतों की आलोचना करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई हुए बगैर ही लंबे समय तक जेल में रखे जाने से वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए। सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ यह जमानत मिली है जिसमें पासपोर्ट विशेष अधीनस्थ अदालत में जमा कराने

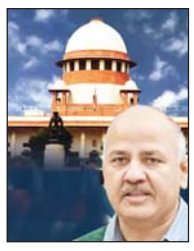

और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने, गवाहों को प्रभावित न करने के प्रयास शामिल हैं। पीठ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया की समाज में गहरी पैठ बताई और कहा कि अपीलकर्ता के देश से भागने और मुकदमे का सामना करने के लिए उपलब्ध न होने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया ने इसे ईमानदारी और सच्चाई की जीत बताई। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने नई आबकारी नीति लागू कर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसमें तीन पूर्व सरकारी अफसरों समेत नौ कारोबारी और दो कंपनियां भी दोषी मानी गईं। चूंकि सिसोदिया के पास उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट भी था इसलिए कथित तौर पर उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। इस विवाद की शुरुआत से ही आप का दावा है कि भाजपा दिल्ली सरकार की ईमानदार छवि को बिगाड़ने के लिए जान-बूझकर षडयंत्र कर रही है। जैसा कि सबसे बड़ी अदालत ने कहा जेल अपवाद है, जमानत के नियम हैं, परंतु दोषी साबित होने से पहले ही सजा नहीं प्रारंभ की जा सकती। बार-बार जमानत की अपील खारिज होती रही तथा सवा साल से ज्यादा समय तक सिसोदिया को जेल की सलाखों के भीतर रखना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में जघन्य अपराधियों और सजायाफ्ता आरोपियों को भी जनता की नुमाइंदगी का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में चुने हुए नेताओं के साथ वैमनस्यपूर्ण बर्ताव को सही नहीं ठहरा सकते। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भले हो मगर संविधान का सम्मान रखते हुए जनता के समक्ष उदाहरण पेश करना भी आवश्यक है। अदालती कार्रवाई चालू है, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। धन शोधन के आरोपियों को सख्त सजा का प्रावधान मौजूद है। वास्तव में सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई जरूरी है।

परिधि/ राजीव मंडल

चेतावनी को चुनौती समझें

विकास कार्यों में घनघोर लापरवाही से आजिज आकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पंजाब सरकार को चेतावनी देना अकारण और अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों और ठेकेदारों पर हिंसा और धमकी देने के बाद गडकरी ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर यह चेतावनी दी कि अगर मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पंजाब में करीब 14,288 करोड़ रुपए की लागत वाली आठ प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को रद्द कर देगा। अगर राज्य के विकास को लेकर पंजाब सरकार का रवैया वाकई में लचर है तो यह निःसंदेह तकलीफदेह प्रकरण है।

विकास के किसी भी काज में अगर कोई व्यवधान डालता है तो स्पष्ट रूप से वह अक्षम्य है। और सरकार को ऐसे अपराधियों पर सख्ती से नकेल डालने की जरूरत है। अगर प्रशासन का इकबाल खत्म हो जाएगा तो विकास के काम औंधे मुंह गिर जाएंगे। बिहार और झारखंड के वर्षों तक पिछड़ा रहने के पीछे अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल और सरकार की काहिली बड़ी वजह है। नक्सली इलाकों को जब-जब विकास के रास्ते पर लाने की कोशिश की गई तब-तब अपराधी तत्वों ने उन्हें तंग किया, न केवल तंग किया बल्कि महंगे उपकरण बर्बाद कर दिए और मारपीट कर उन्हें भगा दिया। आज ये दोनों सूबा विकास के पायदान पर कहां हैं, जगजाहिर है। पंजाब को इन राज्यों की बर्बादी से सबक लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस मसले पर सक्रिय होने के साथ ही सख्त बर्ताव दिखाना होगा। आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपनी ऊर्जा खपाने से बेहतर होगा कि वह राज्य में कानून-व्यवस्था का धागा मजबूत करें और विकास के पथ पर सरपट दौड़ें। वैसे भी यह कोई दुष्कर काम नहीं है। हां, इच्छाशक्ति मजबूत रखने से इस मामूली सी बाधा पर पार पाया जा सकता है। दक्षिण भारत के राज्य समेत महाराष्ट्र और गुजरात ने अपने-अपने यहां कानून का राज स्थापित कर प्रगति की है। पंजाब एक समय में बेहद विकसित सूबा था। हालांकि 80 के दशक में आतंकवाद के कारण वह जरूर पिछड़ गया। गडकरी की चेतावनी को भगवंत मान-सम्मान दें और इसे नसीहत के साथ-साथ चुनौती की तरह लें। सब बातों का लब्बो-लुआब तो यही है कि कानून का राज आएगा तो विकास भी सरपट भागेगा।

संदेश की गंभीरता समझें

बांग्लादेश

विनीत नारायण

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं परंतु इन सबमें अहम सवाल भारत और बांग्लादेश के संबंधों का है। पड़ोसी और मित्र होने के चलते जिस तरह भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अपदस्थ नेता शेख हसीना को दिल्ली में शरण दी है वह आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर गहरा असर डाल सकता है क्योंकि आम बांग्लादेशियों की नजर में शेख हसीना और भारत एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। ऐसे में अगले कुछ महीने दोनों देशों के रिश्तों के लिए तनाव भरे भी हो सकते हैं। बांग्लादेश में बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत के साथ किस तरह पेश आती है, यह अभी कहा नहीं जा सकता। यह हमारी चिंता का विषय रहेगा।

कई देशों में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत के अनुसार यह ऐसा संकट है जो वाजिब संदेह से परे नहीं है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहीं महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का बांग्लादेश में हो रहीं घटनाओं के त्वरित क्रम में, अचानक इस्तीफा, निष्कासन और प्रस्थान अप्रत्याशित था। उनके कार्यकाल के दौरान उनके प्रशासन ने बांग्लादेश को महत्त्वपूर्ण स्थायित्व प्रदान किया। इसके कारण उसकी आर्थिक प्रगति भी प्रभावशाली रही पर साथ ही शेख हसीना के शासन में बढ़े भारी भ्रष्टाचार और उनके अहंकार के साथ-साथ उन पर चुनावों में गड़बड़ी करवाने के आरोपों ने उनकी विरासत को कलंकित किया। अपने ही दल के लोगों को स्वतंत्रता सेनानी बता कर सरकारी नौकरियों में लगातार तीस फीसद आरक्षण देना युवाओं में उनके भारी विरोध का मुद्दा बना।

हालांकि जुलाई के तीसरे सप्ताह में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सुलटा दिया था। फिर भी यह विवाद का बड़ा मुद्दा बना रहा। इसी के चलते 300 से अधिक छात्रों और प्रदर्शनकारियों की मौत के साथ स्थिति बिगड़ गई। वो महत्त्वपूर्ण मोड़ था जब सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह घटनाक्रम श्रीलंका और मिस्र में देखे गए संकटों की प्रतिध्वनि है। इस बीच, बांग्लादेश नेशनिलस्ट पार्टी की नेता बेगम खालिदा जिया की नजरबंदी रद्द कर दी गई है जो फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के करीब मानी जाती हैं। हमारे लिए यह चिंता का कारण है।

उधर, बांग्लादेश की सेना के लिए भी आने वाला समय आसान नहीं है क्योंकि सेना प्रमुख ने जनता विशेषकर छात्रों से इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के मामले में कार्रवाई और जांच का आश्वासन देते हुए सहयोग मांगा है। ऐसा है तो

क्या उग्र और अनियंत्रित भीड़ द्वारा शेख हसीना के कार्यालय, आवास और संसद में की गई तोड़फोड़ को नजरअंदाज किया जाएगा? गौरतलब है कि बांग्लादेश के लोगों खासकर युवाओं को लंबे समय तक चलने वाला सैन्य शासन पसंद नहीं है। यदि एक समय के बाद सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण नहीं किया गया तो सेना को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के कुछ जानकर ऐसा भी मानते हैं कि बांग्लादेश में आरक्षण ही मुद्दा होता तो शेख हसीना जनवरी, 2024 में भारी बहुमत से चुनाव कैसे जीतीं? ऐसा क्या हुआ कि मात्र छह महीनों में ही उन्हें देश छोड़ कर जाने पर मजबूर होना पड़ा? उनका कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अलग होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी जासूस एजेंसी आईएसआई हमेशा से बांग्लादेश में सक्रिय रही है जिसने इस तख्तापलट की पटकथा लिखी है क्योंकि शेख हसीना ने पिछले 15 वर्षों से भारत के साथ अच्छे संबंध रखे और वे भारतीय हितों को पोषित करने वाली मानी जाती थीं जिससे पाकिस्तान बेचैन था। ऐसे पड़ोसी मित्र का सत्ता से अचानक हटना भारत के लिए चिंता का सबब अवश्य है। प्रश्न है कि भारत जैसे मजबूत देश और भारत का एक तेज-तर्रार खुफिया तंत्र होने के बावजूद ढाका में होने वाले राजनैतिक घटनाक्रम की भनक तक क्यों नहीं लगी? क्या इसे भी पुलवामा की तरह 'इंटेलिजेंस फेलियर' माना जाए? उल्लेखनीय है कि 1975 में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बांग्लादेश में तख्तापलट की भनक लगी तो तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक सप्ताह पहले ही हेलीकॉप्टर भेज कर शेख मुजीबुर रहमान को भारत में शरण लेने की सलाह दी थी, परंतु वे नहीं माने। परिणामस्वरूप उन्हें और उनके बेटों और परिवार के 17 सदस्यों को ढाका में उनके घर में ही मार दिया गया। यदि उसी तरह हमारी खुफिया एजेंसियां ढाका में होने वाले ताजा घटनाक्रम की खबर समय रहते दे देतीं तो शायद प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश को संकट से बचा भी सकते थे।

दूसरी ओर, यदि हमारे पास घटनाक्रम की जानकारी थी तो हमने बांग्लादेश के समर्थन में समय रहते कठोर कदम क्यों नहीं उठाए? विदेशी मामलों के ये जानकार यह भी कहते हैं कि भारत ने 2014 तक अपनी कूटनीति के चलते दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को अपने पांव पसारने नहीं दिए। नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत सहित सात देशों के समूह ने भारत की पहल पर ही सार्क का गठन किया जिसमें पाकिस्तान के अलावा भारत के सभी से अच्छे संबंध रहे, परंतु किन्हीं कारणों से हमारी विदेश नीति में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि 2015 के बाद से सार्क देशों की एक भी बैठक नहीं हुई। सार्क के बिखरते ही चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते पहले पाकिस्तान और फिर भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए परंतु यह सब होते हुए हम चुपचाप बैठे देखते रहे।

नतीजतन, आज भारत चारों और से चीन के प्रभाव वाले पड़ोसियों से घिर गया है। अब छोटे से देश भूटान को छोड़कर कोई हमारा मित्र नहीं है। बांग्लादेश के साथ हमारा लाखों करोड़ का व्यापार चल रहा है। दोनों देशों के बीच काफी लंबी सीमा भी लगती है जो हमारी बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हमारे हक में होगा कि बांग्लादेश में जो भी सरकार चुनी जाए वह भारत के हित की ही बात करे वरना जहां हमारी दो सीमाएं पहले से ही नाजुक स्थिति में हैं, कहीं हम चारों ओर से दुश्मनों से घिर न जाएं। अब यह उत्सुकता से देखना होगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बाद जो भी सरकार बने वह भारत के साथ कैसे संबंध रखती है। इसलिए ढाका में हुए घटनाक्रम को दिल्ली को गंभीरता से लेना होगा।

> कई देशों में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत के अनुसार यह ऐसा संकट है जो वाजिब संदेह से परे नहीं है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहीं महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का बांग्लादेश में हो रहीं घटनाओं के त्वरित क्रम में, अचानक इस्तीफा, निष्कासन और प्रस्थान अप्रत्याशित था। उनके कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश को महत्त्वपूर्ण स्थायित्व मिला था

संकट से उबारती सिल्वर इकॉनमी

- सिल्वर इकॉनमी बुजुर्गों से जुड़े उत्पादों और सेवाओं की होती है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब देश की अर्थव्यवस्था महंगाई आदि आर्थिक दिक्कतों से घिर जाती है
- इन दिनों अमेरिका में 1965 से पहले पैदा हुए लोग साल-दर-साल अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि कुछ अमेरिकी सिल्वर इकॉनमी को अपना गुप्त हथियार कहते हैं
- कोविड के दौरान सिल्वर इकॉनमी ने कई देशों में यकीनन सिल्वर बुलेट का काम किया होगा जिससे उन्हें संकट से उबरने में मदद मिली होगी सिल्वर इकॉनमी बुजुर्गों से जुड़े उत्पादों और सेवाओं की होती है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब देश की अर्थव्यवस्था महंगाई आदि आर्थिक दिक्कतों से घिर जाती है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

जिस किसी को नेहरू-इंदिरा युग की ज्यादा जानकारी की दरकार होती तो नटवर सिंह संदर्भ व्यक्ति थे जिनकी याददाश्त गजब की थी...मुझे व्यक्तिगत रूप से ऑन-ऑफ रिकार्ड बातचीत में इससे काफी फायदा हुआ। राजनयिक, लेखक, राजनेता, सही मायने में उनके व्यक्तित्व के विविध आयाम थे। और हां, वह साठ के दशक के क्रिकेट स्कोरों को चुटकियों में याद दिला देते थे। ॐ शांति!

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार@sardesairajdeep

जीवित रहे संस्कृति का संस्कार

आर्थिक प्रगति

प्रह्लाद सबनानी

किसी भी देश में सत्ता का व्यवहार उस देश के समाज की इच्छा के अनुरूप ही होने के प्रयास होते रहे हैं। जब-जब सत्ता द्वारा समाज की इच्छा के विपरीत निर्णय लिए गए हैं अथवा समाज के विचारों का आदर सत्ता द्वारा नहीं किया गया है तब-तब उस देश में सत्ता परिवर्तन होता दिखाई दिया है। लोकतंत्र में तो सत्ता की स्थापना समाज द्वारा ही की जाती रही है। साथ ही, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए देश में शांति बनाए रखना सबसे पहली आवश्यकता मानी जाती है। समाज में विभिन्न मत पंथ मानने वाले नागरिक आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे तो शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकेगी।

भारत पिछले लगभग 2000 वर्षों के खंडकाल में से अधिकतम समय (लगभग 250 वर्षों के खंडकाल को छोड़कर) पूरे विश्व में आर्थिक ताकत के रूप में अपना स्थान बनाने में सफल रहा और इसे 'सोने की चिड़िया' कहा जाता रहा। 712 ईस्वी में भारत पर हुए आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भी भारत की आर्थिक प्रगति पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा था परंतु 1750 ईस्वीं में अंग्रेजों (ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में) के भारत में आने के बाद से भारत की आर्थिक प्रगति को जैसे ग्रहण ही लग गया था। आक्रांताओं एवं अंग्रेजों ने न केवल भारत को जमकर लूटा, बल्कि भारत की संस्कृति पर भी गहरी चोट की थी और भारत के नागरिक जैसे अपनी जड़ों से कटकर रहने लगे थे। आक्रांताओं एवं अंग्रेजों के पूर्व भी भारत पर आक्रमण हुए थे, शक, हूण, कुषाण आदि ने भी भारत पर आक्रमण किया था परंतु लगभग 250/300 वर्षों तक भारत पर शासन करने के उपरांत उन्होंने अपने आपको भारतीय सनातन संस्कृति में ही समाहित कर लिया था। इसके ठीक विपरीत आक्रांताओं एवं अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत की लूटखसोट करने के साथ ही अपने धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी था। आक्रांताओं ने जोरजबरदस्ती एवं मारकाट मचाकर भारत के मूल नागरिकों का धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाया तो अंग्रेजों ने लालच का सहारा लेकर एवं दबाव बनाकर भारतीय नागरिकों को ईसाई बनाया। कुछ

विदेशी ताकतों द्वारा भारत में आज पुनः इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे है कि हिन्दू समाज को किस प्रकार आपस में लड़ाकर छिन्न-भिन्न किया जाए। ऐसा विमर्श खड़ा करने का प्रयास हो रहा है कि देश में हिन्दू हैं ही नहीं, बल्कि सिख हैं, दलित हैं, राजपूत हैं, जैन हैं आदि-आदि। जातियों के आधार पर जन गणना की मांग की जा रही है ताकि समस्त सुविधाओं को हिन्दू समाज की विभिन्न जातियों की जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जा सके जिससे अंततः देश में विभिन्न जातियों के बीच झगड़े पैदा हों और इस प्रकार भारत को पुनः गुलाम बनाए जाने में आसानी हो सके। विदेशी ताकतों द्वारा आज भारत के एकात्म समाज को टूटा-फूटा समाज बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार पुनः भारत ऐसे खंडकाल में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में भारत की तूती पूरे विश्व में बोलती दिखाई देगी। ऐसे में कुछ देशों द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति के सामने बाधाएं खड़ी किए जाने के प्रयास हो रहे हैं। देश में निवासरत 80 प्रतिशत आबादी हिन्दू सनातन संस्कृति की अनुयायी है एवं हिन्दू समाज में व्याप्त समस्त जातियों, मत, पंथों को मानने वाले नागरिकों में त्याग, तपस्या, देशप्रेम का भाव, स्व-समर्पण का भाव कूट-कूट कर भरा है। कहा भी जाता है कि हिन्दू जीवन दर्शन ही पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में मददगार बन सकता है। भारतीय जीवन प्रणाली अपने आप में सर्व समावेशक है। हिन्दू सनातन धर्म का अनुपालन करने वाले नागरिक पशु, पक्षी, वनस्पति, पहाड़, नदियों आदि में भी ईश तत्त्व का वास मानते हैं, और उनकी पूजा भी करते हैं।

हिन्दू संस्कारों में पला-बढ़ा नागरिक सहिष्णु होता है। इसी के चलते कहा जा रहा है कि कई देशों में बढ़ रही हिंसा को नियंत्रित करने में हिन्दू सनातन संस्कृति के अनुयायी ही सहायक हो सकते हैं। और फिर, हिन्दू जीवन दर्शन का अंतिम ध्येय तो मोक्ष को प्राप्त करना है। इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी हिंदू सनातन संस्कृति के अनुयायी कोई भी काम आत्मविचार, मनन एवं चिंतन करने के उपरांत ही करता है। इस प्रकार, इनसे किसी भी जीव को दुखाने वाला कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। कई देशों के बीच कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं, अपने नागरिकों को खो रहे हैं। यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध एवं हमास- इस्राइल युद्ध इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बांग्लादेश में अशांति व्याप्त हो गई है। इसी प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे शांतिप्रिय देश भी आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए शांति स्थापित करने एवं आर्थिक विकास को गतिशील बनाए रखने के उद्देश्य से आज हिन्दू सनातन संस्कृति के संस्कारों को आज पूरे विश्व में फैलाने की महती आवश्यकता है।

विनम्रता

श्रीराम शर्मा आचार्य

विनम्रता आपके आंतरिक प्रेम की शक्ति से आती है। दूसरों को सहयोग और सहायता का भाव ही

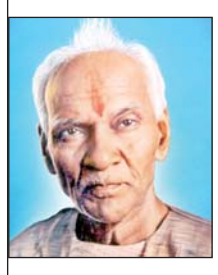

आपको विनम्र बनाता है। कहना गलत है कि यदि आप विनम्र बनेंगे तो दूसरे आपका अनुचित लाभ उठाएंगे जबकि यथार्थ स्वरूप में विनम्रता आपमें गजब का धैर्य पैदा करती है। आप में सोचने-समझने की क्षमता का विकास करती है। विनम्र व्यक्तित्व का एक प्रचंड आभा मंडल होता है। धूर्तों के मनोबल उस आभा से निस्तेज हो स्वयं परास्त हो जाते हैं। उल्टे जो विमम्र नहीं होते वे आसानी से धूर्तों के प्रभाव में आ जाते है क्योंकि धूर्त को तो अहंकारी का मात्र चापलूसी से अहं सहलाना भर होता है। बस, चापलूसी से अहंकार प्रभावित हो जाता है। किंतु जहां विनम्रता होती है वहां तो व्यक्ति को सत्य की अथाह शक्ति प्राप्त होती है। सत्य की शक्ति, मनोबल प्रदान करती है। विनम्रता के प्रति पूर्ण समर्पणयुक्त आस्था जरूरी है। मात्र दिखावे की ओढ़ी हुई विनम्रता अक्सर असफल ही होती है। सोचा जाता है-'पहले विन्रमता से निवेदन करूंगा यदि काम न हुआ तो भृकुटि टेढ़ी करूंगा' यह चतुरता विनम्रता के प्रति अनास्था है, छिपा हुआ अहं भी है। कार्य पूर्व ही अविश्वास व अहं का मिश्रण असफलता ही न्योतता है। सम्यक विनम्र व्यक्ति, विनम्रता को झुकने के भावार्थ में नहीं लेता। सच्चाई उसका पथ प्रदर्शन करती है। निश्छलता उसे दृढ़ व्यक्तित्व प्रदान करती है। अहंकार सदैव आपसे दूसरों की आलोचना करवाता है। आपको आलोचना-प्रतिआलोचना के एक प्रतिशोध जाल में फंसाता है। अहंकार आपकी बुद्धि को कुंठित कर देता है। आपके जिम्मेदार व्यक्तित्व को संदेहयुक्त बना देता है। अहंकारी दूसरों की मुश्किलों के लिए उन्हें ही जिम्मेवार कहता है और उनकी गलतियों पर हंसता है जबकि अपनी मुश्किलों के लिए सदैव दूसरों को जवाबदार ठहराता है और लोगों से द्वेष रखता है। विनम्रता हृदय को विशाल, स्वच्छ और ईमानदार बनाती है। आपको सहज संबंध स्थापित करने के योग्य बनाती है। न केवल दूसरों का दिल जीतने में कामयाब होती है अपितु आपको अपना ही दिल जीतने के योग्य बना देती है जो आपके आत्म-गौरव और आत्म-बल में ऊर्जा का अनवरत संचार करती है। आपकी भावनाओं के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। व्याकुलता और कठिनाइयां भी स्वतः दूर होती चली जाती है।

रीडर्स मेल

आरक्षण का मुद्दा है बेहद पेचीदा

बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे ने तबाही मचाई है। इसको सभी राज्य सरकारों को जरूर समझना होगा और इससे सबक लेना होगा। आरक्षण बेहद पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण संबंधी निर्णय के संदर्भ में भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराया है कि मुद्दे का सम्मानजनक समाधान निकाला जाना चाहिए। सांसदों ने अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में क्रीमीलेयर का विरोध किया है जिस पर कैबिनेट मीटिंग में भी सहमति बनी है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आरक्षण में क्रीमीलेयर नहीं होगा, बल्कि संविधान में दिए गए संवैधानिक प्रावधानों के तहत जारी व्यवस्था लागू रहेगी। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णय के बाद कांग्रेस ने भी चुप्पी तोड़ते हुए क्रीमीलेयर पर सवाल उठाया है, लेकिन जो वास्तविक तनाव का मुद्दा है उसे पर न बीजेपी, न कांग्रेस चर्चा कर रही है। वह मुद्दा है आरक्षण में वर्गीकरण का। इस मुद्दे पर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लगातार केंद्र सरकार से संशोधन की मांग की है और न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग करके इसको बड़ी बहस का मुद्दा बना दिया है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

संसद में हंगामा गलत

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष हंगामा खड़ा करता है। यह लोकतंत्र की मजाक है। लोक सभा और राज्य सभा में विपक्षी दल प्रश्नकाल के दौरान हो-हल्ला कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करते हैं। न भूलें कि यह देश लोकतंत्र की जननी है। देश की गौरवशाली परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही में कोई विवाद और बेतुकी बयानबाजी से दूर रहा जाना चाहिए। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्य सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं कही, जबकि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले हो रहे हैं। विपक्ष तुष्टिकरण पर आज भी अडिग है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम सरकार को बधाई देते हुए हिन्दुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, लेकिन कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अल्पसंख्यक के लिए कोई टिप्पणी नहीं की गई। हिन्दुओं की सुरक्षा पर चुप्पी साधना भेदभावपूर्ण नीति की पक्षधारिता है।

कांतिलाल मांडोत, सूरत

युवाओं का दमखम

भारत ने युवाओं के दम पर पेरिस ओलंपिक में एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज, कुल पांच पदक जीत कर परचम लहराया है। विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हमारे युवाओं ने परचम न लहराया हो। इसीलिए नेपथ्य के परिदृश्य में आवाज सदैव बुलंद होती है कि युवा देश के युवा नागरिकों आगे बढ़ो, दुनिया को मुट्ठी में कर लो, भविष्य हमेशा तुम्हारा है, और रहेगा। किसी राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए वर्षों की मेहनत, अथक प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ संयम एवं उच्च मनोबल की आवश्यकता होती है, तब जाकर राष्ट्र मजबूत तथा विकासवान बन पाता है। हमें सदैव वर्तमान में जीना चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ सदैव अग्रसर होते रहना चाहिए। नागरिकों के समेकित प्रयास और मनोबल से ही प्रेरणादायक राष्ट्र बनने की क्षमता को मूर्ताकार किया जा सकता है।

संजीव ठाकुर, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 360

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

युवा हताश क्यों

भारत दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या और विकासशील देशों में से एक है लेकिन बेरोजगारी की समस्या गम्भीरता से बढ़ रही है और यह समस्या समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित कर रही है। कुछ पदों के लिए लाखों आवेदक आ जाते हैं और स्थिति सम्भालनी मुश्किल हो जाती है। मुम्बई पुलिस में महिला कांस्टेबलों और महिला ड्राइवरों के 1257 पदों के लिए 1.11 लाख आवेदन मिले। मरीन ड्राइव पर फिजिकल टैस्ट देने के लिए भारी संख्या में महिला आवेदकों की भीड़ लग गई। टैस्ट देने आई लड़कियों को बारिश में भी फुटपाथ पर सोना पड़ा। अनेक ने रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर रात गुजारी। मुम्बई पुलिस के पास इन युवतियों को एक रात के लिए भी ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछले महीने भी एयर इंडिया द्वारा आयोजित किए गए वाक-इन-इंटरव्यू में इतनी भीड़ पहुंच गई थी कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। कहते हैं मुम्बई से कोई खाली हाथ नहीं जाता लेकिन बेरोजगारी का यह आलम देखिये कि 600 पदों की भर्ती के लिए 25000 से ज्यादा युवा पहुंच गए। अनेक तो बिना खाये-पिये घंटों रुकने के बाद बिना इंटरव्यू दिए वापिस लौट गए। नौकरी की तलाश में भारतीय युवा इजराइल के युद्ध क्षेत्र तक में नौकरी करने के लिए वहां पहुंच गए हैं। ऐसे दृश्य न केवल चिंता पैदा करते हैं, बल्कि युवाओं में हताशा पैदा कर रहे हैं।

इस वर्ष जून में बेरोजगारी दर बढ़कर 8 महीने के उच्च स्तर 9.2 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। यद्यपि हर महीने बेरोजगारी की दर घटती-बढ़ती रहती है लेकिन कुल मिलाकर दृश्य परेशान करने वाला है। भारत में कुल बेरोजगारों में से 83 फीसदी युवा हैं। इस हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं। देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या सन् 2000 के मुकाबले अब डबल हो चुकी है। वर्ष 2000 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2 प्रतिशत थी। 2022 में बढ़कर 65.7 प्रतिशत हो गई और 2024 तक आते-आते यह और भी बढ़ गई। इन आंकड़ों में उन पढ़े-लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिनकी कम से कम 10वीं तक शिक्षा हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है लेकिन आर्थिक प्रगति की हाईप रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रही। क्योंकि अर्थव्यवस्था में बुनियादी समस्याएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं युवाओं में जो स्नातक हैं उनके आंकड़े भी काफी निराशाजनक हैं। अच्छा वेतन देने वाली नौकरियों के इच्छुक शिक्षित युवाओं को खपा सकने वाली नौकरियों का अभाव है। शिक्षा की गुणवत्ता में खामियों के चलते बड़ी संख्या में शिक्षित युवा अब भी नौकरी के मानक को पूरा करने में अक्षम रह रहे हैं। इसके अलावा मुद्रास्फीति को शामिल करने के बाद भी वेतन या तो ठहरे हुए हैं या फिर उनमें कमी देखी गई है।

इस वर्ष जून में बेरोजगारी दर बढ़कर 8 महीने के उच्च स्तर 9.2 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। यद्यपि हर महीने बेरोजगारी की दर घटती-बढ़ती रहती है लेकिन कुल मिलाकर दृश्य परेशान करने वाला है। भारत में कुल बेरोजगारों में से 83 फीसदी युवा हैं। इस हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं। देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या सन् 2000 के मुकाबले अब डबल हो चुकी है। वर्ष 2000 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2 प्रतिशत थी। 2022 में बढ़कर 65.7 प्रतिशत हो गई

हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाये रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास के इस मोड़ पर युवाओं में कौशल का अभाव भारी नुक्सान का कारण बन सकता है। एक ओर कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों से निकले लोग वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के स्तर पर हैं तो दूसरी ओर स्नातकों की बड़ी संख्या के पास सामान्य रोजगार तक के लिए क्षमता की कमी है। पिछले साल के एक अध्ययन में पाया गया था कि देश में केवल 3.8 प्रतिशत इंजीनियर हैं, जिनके पास स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर संबंधी नौकरी के लिए जरूरी कौशल है। हमारे देश में शिक्षा की जरूरत और मांग को देखते हुए निजी क्षेत्र का योगदान अहम है लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी है, प्रयोगशालाएं नहीं हैं और पढ़ाई का स्तर निम्न है। हालांकि सरकारी और निजी संस्थाओं की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय संस्थान एवं विभाग हैं, फिर भी अगर गुणवत्ता का अभाव है तो यह बेहद चिंता की बात है। आईआईटी के स्नातकों को आज नहीं तो कल नौकरी मिल जायेगी लेकिन बाकी के कौशल एवं प्रशिक्षण के बारे में सोचना बहुत जरूरी है।

यही कारण रहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रोजगार वृद्धि को मुख्य उद्देश्य माना। देश की 500 बड़ी कम्पनियों में एक करोड़ युवाओं के इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराना एक बेहतर सोच है और इंटर्नशिप के लिए युवाओं को मासिक तौर पर 5000 रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान भी सराहनीय है लेकिन इंटर्नशिप के बाद स्थायी रोजगार की उपलब्धता पर नीतियां अभी भी अस्पष्ट हैं। बेरोजगारी संकट दूर करने के लिए औद्योगिक उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीक, कृषि आधारित क्षेत्र में बहुफसल, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग जैसे उपायों को अपनाने, किताबी ज्ञान की बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ध्याद देने और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर देने से ही समस्या का निदान हो सकता है। युवाओं को भी अपनी सोच में बदलाव कर अपनी पसंद के विषयों पर अपनी प्रतिभा को चमकाना चाहिए क्यों हर युवा को व्हाईट कॉलर जॉब उपलब्ध नहीं हो सकती।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

वो सर्वस्व न्यौछावर कर तिरंगे पर ...

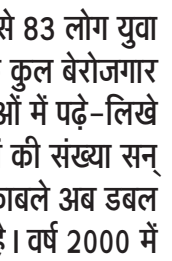

गीता पाढा

"वो सर्वस्व न्यौछावर कर तिरंगे पर लिख छोड़
गए अपने लहू की निशानियां,
आज भी देश के कोने-कोने से सुनायी देती हैं
उनकी वीरगाथा की अमर कहानियां,,
कितनी सुहागिनों ने दी हैं अपने सिंदूर की कुर्बानियां,
इस देश की सुरक्षा और अखंडता की यज्ञवेदि में
आहूत कर दी उन बेटों ने अपनी जवानियां...।।"

विलेज डिफेंस ग्रुप के साथ मिलकर सीमा पर सुरक्षा मजबूत करेंगे : डीजीपी आर आर स्वैन

सांबा, (पंजाब केसरी): जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर.आर. स्वैन ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा के राजपुरा में विलेज डिफेंस ग्रुप (वीडीजी) के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वीडीजी की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा मजबूत की जाएगी। डीजीपी स्वैन ने कहा, सांबा और कठुआ जिले में विलेज डिफेंस ग्रुप (वीडीजी) की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि हम वीडीजी के साथ मिलकर सीमा पर सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं। सरकार भी इस पर काफी जोर दे रही है। हम हमेशा इस चीज का यकीन रखते हैं कि पब्लिक भागेदारी और सहयोग के बिना हम उचित परिणाम हासिल नहीं कर सकते हैं।

ढाके की मलमल और टैगोर प्रदत्त राष्ट्रगान

डा. चन्द्र त्रिखा

chandertrikha@gmail.com

दो बातों के लिए विश्व में चर्चित ढाका इन दिनों अपने अस्तित्व के सर्वाधिक नाजुक चरण से गुजर रहा है। गुरुदेव टैगोर के एक गीत को अपना राष्ट्रगान बनाने वाले इस देश को निरंतर अपने भीतरी आक्रोश व तूफानों से गुजरना पड़ा है। अभी भी तबाही का सिलसिला थमा नहीं है।

हमें 'जन गण मन' का राष्ट्रगान देने वाले टैगोर ही बंगलादेश के राष्ट्रगान 'आमार सोनार बांग्ला' के रचयिता थे। फिलहाल बंगलादेश, इस 'आमार सोनार बांग्ला' की विशिष्ट पहचान, इसके साहित्य और समृद्ध संस्कृति के अलावा 'ढाका की मलमल' से जुड़ी हुई है।

ये तथ्य वहां की नई पीढ़ी को शायद स्मरण नहीं होंगे। लगभग 200 वर्ष पूर्व 'ढाका की मलमल' पूरे विश्व में सर्वाधिक बहुमूल्य मानी जाती थी। वैसे 17वीं सदी में ढाका की इन मखमली मुलायम मलमल के वस्त्र मुगल शासक भी पहनते थे। कहा तो यह भी जाता है कि मलमल की कताई-बुनाई इतनी महीन व मखमली होती थी कि इसका एक थान, एक अंगूठी में से गुजारा जा सकता था। वैसे इस शब्द 'मलमल' से पहला परिचय प्रख्यात विश्व यात्री मार्कोपोलो ने मोसुलर (इराक) के हवाले से दिया था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में फैशन-इतिहासकार सूसन ग्रीन ने भी पूरे ब्यौरे के साथ इससे दुनिया का परिचय कराया था। तब यह मलमल दुर्लभ थी और बेहद महंगी भी। इसके 100 थान दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उपहार के रूप में चीन के तत्कालीन सम्राट के भेजे थे।

ऐसा क्या था जो इस वस्त्र को दुर्लभ भी बनाता था और इसे ढाका व आसपास के इलाकों से ही जोड़े रखा गया था। इसके कपासी पौधों का उत्पादन मेघना नदी के किनारे वाले सूखे क्षेत्रों में ही होता था। इसकी कताई के लिए भी अलग किस्म के उपकरण बनाए जाते थे। जितनी यह 'मलमल' मुलायम थी उतनी ही इस पर विशेष चित्रकारी भी की जाती थी। बाद में इसी से 'जामदानी साड़ियां' भी बनाई जाने लगी थीं।

यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि इस मलमल पर लोकगीत भी रचे गए, गीत भी और फिल्में भी बनी। ढाका में इसका अलग से एक म्यूजियम भी है

मगर न जाने अब उसका क्या हश्र हुआ होगा लेकिन जो ढाका की मलमल 200 साल तक इस धरती का सबसे कीमती कपड़ा बनी रही और फिर सिरे से गायब हो गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ?

ढाका की मलमल का सफर लंबा रहा है। एक दौर में यह दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा माना जाता था और सबसे कीमती भी लेकिन वक्त के साथ यह सिमटता चला गया। आजकल इस कपड़े की शान फिर से लौटाने की कवायद चल रही है।

ढाका की मलमल सोलह चरणों से गुजरने के बाद तैयार होती है। वह उस नायाब कपास से बनाई जाती थी जो बंगलादेश (तत्कालीन भारतीय बंगाल) की मेघना नदी के किनारे पैदा किया जाता था।

हजारों साल से यह कपड़ा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता रहा था। प्राचीन ग्रीस में देवियों की मूर्तियों को मलमल के कपड़े पहनाए जाते थे। कई देशों की साम्राज्ञियों के परिधान मलमल से तैयार होते थे। भारतीय उप महाद्वीप में राज करने वाले मुगल बादशाहों और अमीर-उमरावों के वस्त्र भी इसी कपड़े से तैयार होते थे। मलमल का ये कपड़ा कई किस्मों का होता था। राजदरबार के कवियों ने इससे प्रभावित होकर इसका नाम 'बफ्त हवा' यानी बुनी हुई हवा रखा। कहा जाता है कि आला दर्जे का यह कपड़ा हवा जितना हल्का होता था। यह इतना महीन होता था कि आप 300 फीट लंबे कपड़े के टुकड़े को अंगूठी से निकाल सकते थे। एक अन्य यात्री ने लिखा था कि आप 60 फीट लंबे कपड़े को तह करके सूंघनी की छोटी डिबिया में रख सकते थे।

आमतौर पर मलमल उन दिनों साड़ी या जामा (कुरता) बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन ब्रिटेन में यह संभ्रांत लोगों का कपड़ा बन गया। यह इतना पारदर्शी हुआ करता था कि कई बार इसे पहनने वाले उपहास के भी पात्र बने।

हालांकि ढाका की मलमल की लोकप्रियता कम नहीं हुई। जो लोग इसे खरीदने की क्षमता रखते थे वही पहनते थे। यह उस दौर का सबसे महंगा कपड़ा था। साल 1851 के आसपास एक गज मलमल की कीमत 50 से 400 पाउंड के बीच होती थी। आज के हिसाब से यह 7 हजार से लेकर 56 हजार पाउंड का बैठता है। इसके संभ्रांत कद्रदानों की कमी नहीं थी। इनमें फ्रांस की क्वीन मैरी एंटोनेट से लेकर साम्राज्ञी बोनापार्ट और जेन ऑस्टिन तक शामिल थीं लेकिन जब तक यह कपड़ा नव जाग्रत यूरोप पहुंचा तब तक यह गायब होना शुरू हो गया।

20वीं सदी की शुरूआत तक ढाका की मलमल दुनिया के हर कोने से गायब हो चुकी थी। जो कुछ थोड़ा बहुत कपड़ा बच गया वह लोगों के प्राइवेट कलेक्शन और संग्रहालयों में रह गया था। यह पूरी तरह सामुदायिक काम था जिसमें युवा और बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब शामिल होते थे। पहले कपास के छोटे गोले बोआल मछली के दांत के कंघों से साफ किए जाते थे। इसके बाद सूत की कताई होती थी। धागे तैयार करने के लिए काफी नमी की जरूरत पड़ती था ताकि ये खिंच सके। इसलिए यह काम नावों पर किया जाता था। यह काम बिल्कुल सुबह या ढलती दोपहरी में होता था जिस वक्त सबसे ज्यादा नमी होती है। बुजुर्ग सूत नहीं कातते थे क्योंकि अपनी कमजोर आंखों की वजह से वे महीन धागे को ठीक से देख नहीं पाते थे। साल 2012 में मलमल पर किताब लिखने वाली लेखिका और डिजाइन इतिहासकार सोनिया आशमोर कहती हैं कि सूती धागे में बीच-बीच में महीन गांठ होती थी जो पूरे धागे को जोड़े रखती थी। इससे धागे की सतह पर एक रुखापन होता था जो काफी अच्छा अहसास देता है। ढाका की मलमल इतनी शानदार थी कि इस इलाके में आने वाले लोगों को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता था कि यह इंसानी हाथों से बना हुआ है। कुछ लोग तो यह मानते थे कि इसे जलपरियां या भूत बनाते हैं।

बंगलादेश नेशनलिस्ट क्राफ्ट काउंसिल की प्रेसिडेंट रूबी गजनवी का कहना है कि मलमल इतनी हल्की और मुलायम होती है कि इसका जवाब ही नहीं। आज यह कपड़ा कहीं नहीं दिखता। साल 2013 में यूनेस्को ने जामदानी बुनाई को एक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर संरक्षित किया था।

आशमोर कहती हैं मुगलकाल मलमल के लिए सबसे अच्छा समय था। मुगल बादशाहों और उनकी रानियों ने मलमल को खूब संरक्षण दिया। उन दिनों फारस (अब ईरान) इराक, तुर्की और मध्य पूर्व के देशों तक मलमल का व्यापार होता था।

ढाका की मलमल इतनी बारीक होती थी कि इसकी कई तहों के बावजूद शरीर के अंग इससे दिखते थे। कहा जाता है एक बार औरंगजेब ने मलमल पहन कर दरबार में आने पर अपनी बेटी को डांटा था जबकि उसने सात तह किए हुए मलमल के कपड़े पहने थे जिन दिनों लंदन में लोग मलमल के कपड़े पहन कर गर्व महसूस कर रहे थे ठीक उसी वक्त इसके कारीगर कर्ज में डूब कर आर्थिक तौर पर बर्बाद हो रहे थे। 'गुड्स फ्रॉम द ईस्ट 1600-1800 नाम की एक किताब में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के आखिर में मलमल बनाने की नाजुक प्रक्रिया में टांग अड़ाना शुरू किया। सबसे पहले कंपनी ने मलमल के स्थानीय खरीदारों को हटा कर इसे खुद खरीदना शुरू कर दिया। आशमोर कहती हैं कि उन्हें इसके प्रोडक्शन पर शिकंजा कस लिया और फिर पूरे कारोबार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वे बुनकरों से कम कीमत पर ज्यादा कपड़ा तैयार करने को कहने लगे। अब वह स्वर्ण युग समाप्त हो चुका है।

बंगलादेश के संदेश को गंभीरता से लिया जाए

विनीत नारायण

www.vineetnarain.net

भारत के पड़ोसी देश बंगलादेश में जो हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं परंतु इन सब में एक अहम सवाल भारत और बंगलादेश के संबंधों का है। पड़ोसी व मित्र होने के चलते जिस तरह भारत ने बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री व अपदस्थ नेता शेख हसीना को दिल्ली में शरण दी है। वह आने वाले समय में भारत और बंगलादेश के संबंधों पर गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि आम बंगलादेशियों की नजर में शेख हसीना और भारत एक-दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। ऐसे में अगले कुछ महीने दोनों देशों के रिश्तों के लिए तनाव भरे भी हो सकते हैं। बंगलादेश में बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत के साथ किस तरह पेश आती है ये अभी कहा नहीं जा सकता। ये हमारी चिंता का विषय रहेगा।

कई देशों में भारत के राजदूत रहे पूर्व आईएफएस अधिकारी अनिल त्रिगुणायत के अनुसार यह एक ऐसा संकट है जो वाजिब संदेह से परे नहीं है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्तारूढ़ रही महिला प्रधानमंत्री और बंगलादेश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का बंगलादेश में हो रही घटनाओं के त्वरित क्रम में अचानक इस्तीफा, निष्कासन और प्रस्थान अप्रत्याशित था। उनके कार्यकाल के दौरान उनके प्रशासन ने बंगलादेश को महत्वपूर्ण स्थायित्व प्रदान किया। इसके कारण उसकी आर्थिक प्रगति भी प्रभावशाली रही। पर साथ ही शेख हसीना के शासन में बढ़े भारी भ्रष्टाचार और उनके अहंकार के साथ-साथ उन पर चुनावों में गड़बड़ी करवाने के आरोपों ने उनकी विरासत को कलंकित किया। सरकारी नौकरियों में अपने ही दल के लोगों को स्वतंत्रता सेनानी बताकर लगातार सरकारी नौकरियों में तीस फीसदी आरक्षण देना युवाओं में उनके भारी विरोध का मुद्दा बना। हालांकि जुलाई के तीसरे सप्ताह में बंगलादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सुलटा दिया था। फिर भी ये विवाद का एक बड़ा मुद्दा बना रहा। इसी के चलते 300 से अधिक छात्रों और प्रदर्शनकारियों की मौत के साथ वहां स्थिति बिगड़ गई। वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। घटनाओं का यह क्रम श्रीलंका और मिस्र में देखे गए संकटों की प्रतिध्वनि है। इस बीच, बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता बेगम खालिदा जिया की नजरबंदी रद्द कर दी गई है जो अब फिर से सक्रिय हो रही हैं, वे कट्टरपंथियों व पाकिस्तान के क़रीब मानी जाती हैं। ये हमारे लिए चिंता का कारण है। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने दावा किया है कि अब एक राजनीतिक गाथा खत्म हो गई है, क्योंकि उनका परिवार अब बंगलादेश को अव्यवस्था की खाई में से निकालने या पाकिस्तान के जाल से बचाने और उग्रवाद के भंवर में फंसने से बचाने के लिए वापस बंगलादेश नहीं आएगा, क्योंकि शेख हसीना द्वारा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन 'जमात-ए-इस्लामी' हाल में सेना के साथ सरकार बनाने की बातचीत करने वाली टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वाजेद ने यह भी कहा कि अब हसीना का राजनीति से नाता भी खत्म हो चुका है। आवामी लीग को एक नया कथानक और अपना नया स्वीकार्य नेता ढूंढना होगा। ये रुझान आने वाली परिस्थितियों के स्वरूप का संकेत देते हैं। उधर बंगलादेश की सेना के लिए भी आने वाला समय आसान नहीं है, क्योंकि सेना प्रमुख ने जनता विशेषकर छात्रों से इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के मामले में कार्रवाई और जांच का आश्वासन देते हुए सहयोग मांगा है। यदि ऐसा है तो क्या उग्र और अनियंत्रित भीड़ द्वारा शेख़ हसीना के कार्यालय, आवास और संसद में की गई तोड़फोड़ को नजरअंदाज किया जाएगा?

गौरतलब है कि बंगलादेश के लोगों, खासकर युवाओं को लंबे समय तक चलने वाला सैन्य शासन पसंद नहीं है, इसलिए यदि एक समय सीमा के बाद सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण नहीं किया गया और उसे राजनेताओं को नहीं सौंपा गया तो सेना को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, बड़ी संख्या में छात्र सेना द्वारा थोपी गई अंतरिम सरकार के विचार से भी खुश नहीं हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कुछ अन्य जानकर ऐसा भी मानते हैं कि बंगलादेश में यदि आरक्षण ही मुद्दा होता तो शेख हसीना जनवरी 2024 में भारी बहुमत से चुनाव कैसे जीतीं? ऐसा क्या हुआ कि मात्र छह महीनों में ही उन्हें देश छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा? उनका कहना है कि पाकिस्तान बंगलादेश के अलग होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी जासूस एजेंसी आईएसआई हमेशा से ही बंगलादेश में सक्रिय रही है। जिसने इस तख्ता पलट की पटकथा लिखी है, क्योंकि शेख़ हसीना ने पिछले 15 वर्षों से भारत के साथ अच्छे संबंध रखे और वे भारतीय हितों को पोषित करने वाली मानी जाती थी जिससे पाकिस्तान काफ़ी बेचैन था। ऐसे पड़ोसी मित्र का सत्ता से अचानक हटना अब भारत के लिए चिंता का सबब अवश्य है। प्रश्न है कि भारत जैसे मज़बूत देश और भारत का एक तेज़-तर्रार ख़ुफ़िया तंत्र होने के बावजूद ढाका में होने वाले राजनैतिक घटनाक्रम की भनक तक क्यों नहीं लगी? ये बात गले नहीं उतरती। उल्लेखनीय है कि 1975 में जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बंगलादेश में तख्तापलट होने जा रहा है, इसकी भनक लगी तो तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगभग एक सप्ताह पहले ही अपने हैलीकॉप्टर भेज कर शेख मुजीबुर रहमान को भारत में शरण लेने की सलाह दी थी परंतु वे नहीं माने। परिणामस्वरूप उन्हें व उनके बेटों और परिवार के 17 सदस्यों को ढाका में उनके घर में ही मार दिया गया। यदि उसी तरह हमारी खुफिया एजेंसियां ढाका में होने वाले ताजा घटनाक्रम की खबर समय रहते दे देती तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी बंगलादेश को इस संकट से बचा भी सकते थे, वहीं दूसरी ओर यदि हमारे पास इस घटनाक्रम की जानकारी थी तो हमने बंगलादेश के समर्थन में समय रहते कठोर कदम क्यों नहीं उठाए?

विदेशी मामलों के जानकार यह भी कहते हैं कि भारत ने 2014 तक अपनी कूटनीति के चलते दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को अपने पांव पसारने नहीं दिये। नेपाल, म्यांमार, श्री लंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत सहित सात देशों के समूह ने भारत की पहल पर ही सार्क का गठन किया, जिसमें पाकिस्तान के अलावा भारत के सभी से अच्छे संबंध रहे परंतु किन्हीं कारणों से हमारी विदेश नीति में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि 2015 के बाद से सार्क देशों की एक भी बैठक नहीं हुई। सार्क के बिखरते ही चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते पहले पाकिस्तान और फिर भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिये परंतु ये सब होते हुए हम चुपचाप बैठे देखते रहे। नतीजन आज भारत चारों ओर से चीन के प्रभाव वाले पड़ौसियों से घिर गया है। अब छोटे से देश भूटान को छोड़कर कोई हमारा मित्र नहीं है। ग़ौरतलब है कि चीन से पहले अमरीका भी श्रीलंका और बंगलादेश पर अपनी नज़र बनाए हुए था परंतु चीन ने श्री लंका पर भी अपनी पकड़ बना कर अमरीका का सपना तोड़ दिया। बंगलादेश के साथ हमारा लाखों करोड़ का व्यापार चल रहा है। दोनों देशों के बीच काफी लंबी सीमा भी लगती है जो हमारी बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए हमारे हक़ में होगा कि बंगलादेश में जो भी सरकार चुनी जाए वह भारत के हित की ही बात करे।

वरना जहां हमारी दो सीमाएं पहले से ही नाजुक स्थिति में हैं, कहीं हम चारों ओर से दुश्मनों से घिर न जाएं। अब ये उत्सुकता से देखना होगा कि बंगलादेश की अंतरिम सरकार के बाद जो भी सरकार बने वह भारत के साथ कैसे संबंध रखती है। इसलिए ढाका में हुए घटनाक्रम को दिल्ली को बहुत गंभीरता से लेना होगा।

इंदिरा-राजीव के करीबी नटवर सिंह ने रिश्तों का हमेशा रखा मान

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का शनिवार देर रात निधन हो गया। अपने राजनीतिक करियर में कई अहम पदों पर रहने वाले नटवर सिंह के सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी से रिश्ते कभी मधुर तो कभी तल्ख रहे।

आलाकमान के करीबियों में हमेशा नटवर सिंह का नाम शुमार रहा। यही वजह है कि कांग्रेस के राजदार भी माने जाते थे। गांधी परिवार से करीबी ही उनकी सियासत में एंट्री की मजबूत वजह बनी। नौकरशाह से सियासतां का सफर एक जैसा नहीं रहा। पार्टी में रहे या फिर खुद को अलग किया तब भी अपने कद के साथ समझौता नहीं किया।

प्रशासनिक सेवा का सफर 1953 में शुरू हुआ। भारतीय विदेश सेवा के लिए चुने गए। अहम पदों पर रहे लेकिन फिर सियासत के प्रति रुचि और गांधी फैमिली से नजदीकी के चलते नौकरी छोड़ दी।1984 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी ने उन्हें राजस्थान के भरतपुर से चुनावी मैदान में उतारा और सफर का आगाज शानदार जीत से

हुआ। बतौर सांसद सदन में पहुंचे।

बताया जाता है कि नटवर सिंह ही वही शख्स थे, जिन्होंने राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी को राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। पूर्व दिवंगत कांग्रेस नेता के पार्टी संग मधुर और तल्ख संबंध रहे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा था तो यूपीए-1 सरकार में उनके रिश्ते सोनिया गांधी से बिगड़ भी गए। 2005 में मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वजह तेल के खेल नाम से सुर्खियों में रही। ईरान को तेल के बदले अनाज कांड को लेकर रिपोर्ट सामने आई। इसमें नटवर सिंह का नाम शामिल था। इसके बाद रिश्तों में खटास आ गई। नटवर सिंह ने 'द लिगेसी ऑफ नेहरू: ए मेमोरियल ट्रिब्यूट' और 'माई चाइना डायरी 1956-88' सहित कई किताबें भी लिखीं। उन्होंने उनकी आत्मकथा 'वन लाइफ इज नॉट इनफ' में गांधी परिवार को लेकर कई दावे भी किए। जिस पर सियासी भूचाल आ गया। उन्होंने दावा किया था कि साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए तो सोनिया गांधी ने राहुल की वजह से प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाला। क्योंकि राहुल को डर था कि सोनिया के साथ भी इंदिरा और राजीव गांधी जैसा न हो। बताते हैं कि नटवर सिंह की किताब के बाजार में आने से पहले सोनिया और प्रियंका गांधी उनके घर भी गई थीं, उनसे माफी मांगी थी।

जब-जब नटवर सिंह उनकी आत्मकथा को लेकर सवाल किया जाता था तो वह इसे टाल दिया करते थे। उन्होंने कभी अपनी आत्मकथा में लिखी बातों पर सफाई नहीं दी।

नटवर सिंह 1966 से 1971 के बीच पाकिस्तान में भारत के राजदूत थे। इसके अलावा उन्होंने यूके, अमेरिका और चीन में भी सेवाएं दी।

बसपा सभी 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव : मायावती

लखनऊ,(पंजाब केसरी): बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को ऐलान किया कि निकट भविष्य में राज्य की 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। मायावती ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक समीक्षा बैठक में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की। विधानसभा की कुल 10 सीटें रिक्त है, जिनमें करहल,

मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवां और सीसामऊ विधानसभा सीटें शामिल है। अमूमन उपचुनावों से दूर रहने वाली बसपा ने इस उपचुनाव को पूरे दमखम से लड़ने का फैसला किया है। कहा, लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में रिक्त हुई 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों के लिए अभी चुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ रही है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

आवास योजना का विस्तार

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत आगामी पांच वर्षों में तीन करोड़ घरों का निर्माण होगा, जिनमें दो करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में तथा एक करोड़ आवास शहरी क्षेत्र में होंगे. इस निर्णय पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इस चरण में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 4.35 ट्रिलियन रुपये खर्च किये जायेंगे. शहरी गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों के आवास पर कुल निवेश 10 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है, जिसमें सरकार 2.3 ट्रिलियन रुपये का अनुदान देगी. ग्रामीण आवासों पर केंद्र और राज्य सरकारें 3,06,137 करोड़ रुपये खर्च करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय के प्रारंभ में ही ग्रामीण भारत के हर परिवार के लिए आवास उपलब्ध कराने को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया था. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत अप्रैल, 2016 में की गयी थी, जिसके तहत मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था. शहरी क्षेत्र में आवास मुहैया कराने की योजना जून, 2015 में प्रारंभ की गयी थी. अनुदान और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ निर्माण को बढ़ावा देने पर आधारित इस योजना से अब तक करोड़ों परिवारों को लाभ पहुंचा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न और मध्य वर्ग के वैसे सभी परिवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है. शहरी क्षेत्र में तो किराये पर पक्का मकान लेने के लिए भी योग्य आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं. हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो मकान बना पाने की स्थिति में नहीं है. हालांकि पहले भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आवास मुहैया कराने या सस्ती दरों पर कर्ज की व्यवस्था कराने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं, पर प्रधानमंत्री आवास योजना अपने लक्ष्य एवं उपलब्धि में अग्रणी है. घर का सपना पूरा होना महज एक सपने का साकार होना ही नहीं है, यह परिवार के लिए एक उपलब्धि और उत्साह का आधार होता है, जो उसे उत्तरोत्तर प्रगति के लिए प्रेरित करता है. बीते वर्षों में आवास के अलावा अनाज, रसोई गैस, बिजली, चिकित्सा आदि के लिए भी अनेक कल्याण योजनाएं शुरू की गयी हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, निशुल्क राशन, बिजली में छूट, उज्ज्वला योजना आदि. ऐसी योजनाओं ने गरीब और निम्न आय वर्गीय परिवारों की मुख्य चिंताओं का काफी हद तक समाधान किया है, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं. आवास योजना के विस्तार से बड़ी संख्या में घर बनने से सीमेंट, लोहा आदि अनेक उद्योगों को भी लाभ होगा तथा रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 4.35 ट्रिलियन रुपये खर्च किये जायेंगे.

बांग्लादेश में संकट के पीछे कई ताकतें

प्रो शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित
कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयनयी दिल्ली
santishreepandit@gmail.com

कुछ रिपोर्टों में यह संकेत दिया जा रहा है कि चीन, अमेरिका या पाकिस्तान जैसे सरकारी कारकों की भूमिका हो सकती है. इसके साथ-साथ इस्लामिक आतंकी समूहों और अपने तरह के 'लोकतंत्र' को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे दूसरे तत्वों की भूमिका पर भी विचार करना जरूरी है. ऐसी रिपोर्टों को इस्लाम विरोधी या अनुदार कह कर खारिज करना उसी तरह खतरनाक हो सकता है, जैसे बिल्ली को देख कर कबूतर इस उम्मीद में आंख बंद कर लेता है कि खतरा अपने-आप टल जायेगा.

बांग्लादेश का हालिया संकट बाहरी हस्तक्षेप तथा चुनाव जीतने एवं लोकतांत्रिक बदलाव लाने में असफल रहे उसके आंतरिक सहयोगियों की भूमिका को इंगित करता है. अवामी लीग सरकार के नाटकीय पतन तथा शेख हसीना के देश छोड़ने से इस क्षेत्र में उथल-पुथल के लगातार जोखिम तथा बाहरी दखल और अंदुरुनी गड़बड़ी के खतरे का भी पता चलता है. क्या सड़क पर भीड़ और छात्रों के प्रदर्शन बिना बाहरी समर्थन के हो रहे हैं? अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे ताकतवर दानदाता स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व को पसंद नहीं करते हैं. उनकी तानाशाहों से खूब बनती है और वे अपने हितों को साधने के लिए धार्मिक अतिवाद, यहां तक कि आतंकियों को भी समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं. बांग्लादेश उर्दू थोपने के विरोध में बंगाली होने के अपने धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर पाकिस्तान से अलग हुआ था. बांग्लादेश स्वाधीनता संग्राम के नेता और देश के पहले राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान की पाकिस्तान-समर्थक इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हत्या के बाद वहां यह बहस केंद्र में आ गयी कि बांग्लादेश पहले बंगाली है या इस्लामिक.

अमेरिकी पत्रकार और अकादमिक गैरी जे बास की किताब 'द ब्लड टेलीग्रामः निक्सन, किसिंजर, एंड ए फॉरगॉटन जेनोसाइड' (2013) ढाका में तत्कालीन अमेरिकी वाणिज्य राजदूत आर्चर ब्लड द्वारा 1971 में भेजे गये एक टेलीग्राम पर आधारित है. उसमें बांग्लादेश जनसंहार पर अमेरिकी विदेश विभाग के रवैये पर असंतोष व्यक्त करते हुए लिखा गया था कि अमेरिकी सरकार लोकतंत्र के हनन और भयंकर दमन की निंदा करने में विफल रही, जिसे कई लोग नैतिक दिवालियापन मानेंगे. यह तार आज भी प्रासंगिक है. अंतरराष्ट्रीय दानी एनजीओ की भूमिका पर संदेह स्वाभाविक है. जिस गठजोड़- पाकिस्तान का आइएसआइ, अमेरिका और चीन- पर 1971 के जनसंहार का दोष था, इस बार उसी पर शक हो रहा है. पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च, 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक दमन के साथ हिंदू और बंगाली विरोधी बांग्लादेश जनसंहार की शुरुआत की थी. अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लोग हिंसा को देखकर अचंभित रह गये थे और उन्होंने अमेरिकी सरकार से हस्तक्षेप करने का निवेदन किया. आर्चर ब्लड ने बाद में अपनी सरकार की प्रतिक्रिया को 'भयावह चुप्पी' की संज्ञा दी थी. उसके बाद ही रोष जताते हुए वह तार भेजा गया था. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे चीन से कूटनीतिक संबंध बहाल करने के लिए पाकिस्तान की मदद लेने की कोशिश कर रहे थे.

विभिन्न मुद्दों, जो कई देशों में भी हैं, पर आंतरिक झंझट बांग्लादेश में शीघ्र ही बहुत ही उग्र और हिंसक हो गया, इसे देखते हुए बाहरी- सरकारी और गैर-सरकारी दोनों- हस्तक्षेप को लेकर चिंता स्वाभाविक है. अधिकतर विश्लेषण में सामान्य तर्क ही दिये जा रहे हैं और अक्सर विदेशी मिलीभगत की संभावना को परे रख दिया जा रहा है. लेकिन, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उचित ही कहा है, किसी भी आयाम को मानना या नहीं मानना अभी जल्दबाजी होगी. कुछ रिपोर्टों में यह संकेत दिया जा रहा है कि चीन, अमेरिका या पाकिस्तान जैसे सरकारी कारकों की भूमिका हो सकती है. इसके साथ-साथ इस्लामिक आतंकी समूहों और अपने तरह के 'लोकतंत्र' को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे दूसरे तत्वों की भूमिका पर भी विचार करना जरूरी है. ऐसी रिपोर्टों को इस्लाम विरोधी या अनुदार कहकर खारिज करना उसी तरह खतरनाक हो सकता है, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर इस उम्मीद में आंख बंद कर लेता है कि खतरा अपने-आप टल जायेगा. कुछ खबरों में पिनाकी भट्टाचार्य द्वारा हाल के महीनों में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने के बारे में बताया गया है. इस व्यक्ति पर तबलीगी जमात का प्रभाव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'पड़ोसी प्रथम' की पहल अच्छा पड़ोस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसका प्रारंभ तब हुआ था, जब दक्षिण एशियाई के नेताओं को 2014 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था. क्षेत्रीय संबंध केवल भारत के प्रयासों पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि पड़ोसी देशों के घरेलू कारक भी अहम भूमिका निभाते हैं. 'इंडिया आउट' का एक चिंताजनक प्रचार चल पड़ा है, जिसे भारत के विरोधी संसाधन देते हैं.

बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक अब उस कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे हैं कि कथित 'शांतिपूर्ण संक्रमण' या 'जनता की जीत' का मामला बहुत जटिल है. पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लाये गये नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैश्विक आलोचना हालिया घटनाओं को देखते हुए अदूरदर्शी साबित हुई है. अब वे आलोचक चुप हैं क्योंकि ऐसी नीतिगत पहलों की दूरदर्शिता स्पष्ट दिख रही है. बांग्लादेश के मसले के पीछे हिंदू विरोध है या भारत को कमजोर करने की सोची-समझी रणनीति, इसे रेखांकित कर पाना कठिन है. पर यह तो स्पष्ट है भारत का आर्थिक, राजनीतिक और भू-राजनीतिक विकास इस क्षेत्र के साथ ठोस संबंधों पर निर्भर करेगा. भारत के सामने अजीब स्थिति है- क्या उसे अपने पड़ोसियों के साथ गहरा जुड़ाव स्थापित करना चाहिए ताकि बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा न हो या फिर उसे दूर रहना चाहिए और उन देशों को अपने मसले स्वयं सुलझाने देना चाहिए? इन दोनों विकल्पों में खतरे भी बहुत हैं. गहरे जुड़ाव को 'बिग ब्रदर' के हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जिससे भारत विरोधी भावनाएं बढ़ सकती हैं. दूसरी तरफ, किनारे खड़े रहने से प्रभाव कम हो सकता है, भारत के लिए भी जोखिम बढ़ सकता है और अलग-थलग पड़ने का खतरा भी है.

कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बांग्लादेश के बारे में पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था. दिसंबर, 2023 में रूसी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा था कि अगर शेख हसीना चुनाव के बाद सत्ता में आती हैं, तो अमेरिका उनकी सरकार गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. उनके कहने का अर्थ यह था कि कुछ साल पहले अरब देशों में हुए प्रदर्शनों की तरह बांग्लादेश में भी स्थिति पैदा की जा सकती है. तब छात्रों का ही इस्तेमाल किया गया था.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

अंतरिक्ष अनुसंधान के अग्रदूत विक्रम साराभाई

जयंती विशेष

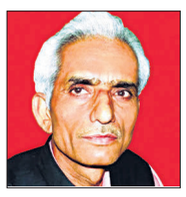

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

स्वाभाविक ही विक्रम 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह' कहलाये. वे 1963 में 21 नवंबर को केरल में तिरुअनंतपुरम के पास थुम्बा में देश का पहला रॉकेट लांच कर 'रॉकेट पिता' भी बन चुके थे. दुनिया के महान भौतिक विज्ञानियों में शुमार विक्रम खगोलशास्त्री और उद्योगपति भी थे.

हम जब भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अगुआई में देश को अंतरिक्ष में ऊंची छलांगें लगाते देखते हैं, तो गर्व से भर जाते हैं. क्या ऐसे अवसरों पर हमें इसरो की नींव की ईंट रहे वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई की याद भी आती है? उनकी ही कमान में 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को 15 अगस्त, 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का रूप दिया गया. विक्रम 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह' हैं. वे 1963 में 21 नवंबर को केरल में तिरुअनंतपुरम के पास थुम्बा में देश का पहला रॉकेट लांच कर 'रॉकेट पिता' भी बन चुके थे. दुनिया के महान भौतिक विज्ञानियों में शुमार विक्रम खगोलशास्त्री और उद्योगपति भी थे. वे जीवनभर प्रयासरत रहे कि विज्ञान के विभिन्न प्रयोग आम आदमी के काम आएं. उनका मानना था कि ऐसा नहीं हुआ, तो वैज्ञानिक प्रयोगों की कोई सार्थकता नहीं रहेगी. साल 1975 में भारत ने एक रूसी कॉस्मोड्रोम से 'आर्यभट्ट' उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दुनिया को चकित कर डाला. यह विक्रम की परियोजना की सफलता थी.

देश 24 जनवरी, 1966 को एक विमान दुर्घटना में अपने परमाणु कार्यकम के जनक होमी जहांगीर भाभा को गंवा कर ठगा-सा रह गया था. उनके रहते हमारा परमाणु कार्यक्रम दुनिया की कई शक्तियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था, जिसके चलते उक्त दुर्घटना को लेकर यह संदेह भी जताया गया. तब यह सवाल गंभीर था कि उनकी जगह किसे दी जाए, जो उक्त कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके. अंततः यह तलाश विक्रम साराभाई पर ही खत्म हुई और मई, 1966 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला. साल 1919 में 12 अगस्त को अहमदाबाद के स्वतंत्रता आन्दोलन को समर्पित एक प्रगतिशील विचारों वाले उद्योगपति परिवार में जन्मे विक्रम अपने पिता अंबालाल व माता सरला देवी की आठ संतानों में से एक थे. उनके माता-पिता वहां 'रिट्रीट' नामक निजी स्कूल चलाते थे और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा इसी स्कूल से प्राप्त की. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ, जे कृष्णामूर्ति, मोतीलाल नेहरु, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, सी एफ एड्रूज व सी वी रमन जैसी शख्सियतें जब भी अहमदाबाद आतीं, उनके माता-पिता की अतिथि बनती थीं. एक बार तो महात्मा गांधी भी उनके घर में रहे थे. बालक विक्रम का सौभाग्य कि उस पर इन महान व्यक्तित्वों के सान्निध्य का गहरा असर हुआ.

विक्रम साराभाई
जन्म- 12 अगस्त, 1919
निधन- 30 दिसंबर, 1971

द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत में वे कैम्ब्रिज से अध्ययन कर वापस आये तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू में सर सीवी रमन के शोध छात्र बनकर वैज्ञानिक गतिविधियों को समर्पित हो गये. साल 1945 में वे फिर कैम्ब्रिज गये और 1947 में लौटकर अहमदाबाद में प्रयोग व अनुसंधान का अपना सपना पूरा करने में लग गये. इससे पहले 1942 में शास्त्रीय नर्तकी मृणालिनी से विवाह कर उन्होंने दांपत्य जीवन में प्रवेश कर लिया था. उनकी दो संतानें हैं- मल्लिका व कार्तिकेय. मल्लिका ने कुचीपुड़ी व भरतनाट्यम की नृत्यांगना, मंचों की अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ख्याति अर्जित की है, तो कार्तिकेय दुनिया के अग्रणी पर्यावरण शिक्षकों में से एक हैं.

उनका 30 दिसंबर, 1971 की रात तिरुअनंतपुरम से मुंबई जाने का कार्यक्रम था. वे अपने उन दिनों के सहयोगी एपीजे अब्दुल कलाम से बात कर सोये ही थे कि उन्हें हृदयाघात हुआ और नींद में ही उनका निधन हो गया. उस वक्त वे महज 52 वर्ष के थे. अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को तिरुवनंतपुरम से अहमदाबाद ले जाया गया. उन्होंने समय के साथ अपने योगदानों को लेकर भरपूर प्रशंसाएं व मान्यताएं हासिल कीं. उन्होंने 1947 में अहमदाबाद में जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की थी, वह आगे चलकर भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के उद्गम स्थल के रूप में विख्यात हुई. साल 1962 में उन्होंने शांतिस्वरूप भटनागर पदक प्राप्त किया, तो 1966 में पद्मभूषण. मरणोपरांत उन्हें 1972 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया. अगले साल 1973 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने फैसला किया कि सेरेनिटी सागर में एक चंद्र क्रेटर 'बेसेल ए' को साराभाई क्रेटर के रूप में जाना जायेगा. भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-2 के लैंडर (जिसको 20 सितंबर, 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना था) का नाम भी विक्रम रखा गया.

अहमदाबाद में उनके द्वारा स्थापित एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र से भी अब उनका नाम जोड़ दिया गया है. हैदराबाद के बीएम बिड़ला विज्ञान केंद्र में स्थित अंतरिक्ष संग्रहालय भी उनको ही समर्पित है. साल 2019 में उनकी जन्म शताब्दी पर इसरो ने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार भी शुरू करने की घोषणा की. यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है, जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान, अनुप्रयोग और अनुसंधान की रिपोर्टिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर इयू के शुल्क का मामला डब्ल्यूटीओ में

चीन की इलेक्ट्रिक कारें अपनी सस्ती कीमतों के कारण यूरोप के कार बाजार पर काले साये की तरह मंडरा रही हैं. चीनी ईवी से बचने के लिए यूरोप ने उन कारों पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है. कोई सुलह होते न देखकर चीन ने डब्ल्यूटीओ में अपील की है. चीन का कहना है कि यूरोपीय संघ के तात्कालिक निर्णय का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है. उसका यह निर्णय विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है. विदित हो कि इस वर्ष जुलाई में यूरोपीय संघ ने चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर लगभग 38 प्रतिशत तक अस्थायी शुल्क लगा दिया था. इससे पहले यूरोपीय आयोग ने एक जांच के बाद पाया कि चीन, यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों को अनुचित रूप से हानि पहुंचा रहा है. चीन का इलेक्ट्रिक कारों पर नया शुल्क यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों की पुष्टि के बाद नवंबर से लागू होगा. चीन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, तकनीक, मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के कई मुद्दों पर विवाद रहा है. परंतु ब्रसेल्स के सामने अपनी इलेक्ट्रिक कार उद्योग को सुरक्षा देने के अतिरिक्त पर्यावरण सम्मत विकास की ओर बढ़ने और चीन से झगड़े को रोकने की चुनौती है. यूरोपीय संघ ने सोलर पैनल, पवन चक्कियां और ट्रेन बनाने वाली कंपनियों को दी जा रही सरकारी सब्सिडी की जांच शुरू की है. इस बीच चीन ने यूरोप से आयात की जाने वाली ब्रांडी और पोर्क की जांच शुरू कर दी है. चीन का यह झगड़ा केवल यूरोपीय संघ से नहीं, अमेरिका से भी चल रहा है. अमेरिका ने तो चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर 110 प्रतिशत का शुल्क लगाया है. कनाडा भी ऐसा ही कदम उठाने पर विचार कर रहा है. चीन और यूरोपीय संघ के पास नवंबर तक अपना झगड़ा सुलझाने का समय है. यदि तब तक दोनों के बीच सुलह नहीं होती है, तो अगले पांच वर्षों के लिए अस्थायी शुल्क लागू हो जायेगा.

बोधि वृक्ष

संसार सच है या केवल भ्रम

जिस संसार में हम रहते हैं, उसके तीन आधारभूत दृष्टिकोण है. पहला दृष्टिकोण भौतिकवाद का है जिसमें लोग इस संसार को वास्तविक रूप में देखते हैं. दूसरा वह है जिसमें दुनिया पूरी तरह एक भ्रम है और तीसरा तीनों दृष्टिकोणों मे सबसे बढ़िया है और वह है कि संसार भगवान की पवित्र संपत्ति है. यह वास्तविक है परंतु प्रत्यक्षीकरण में अस्थायी है. अब यह अवधारणा कि वास्तविकता में संसार ही केवल एक सत्य है, यह हमारी चेतना को सोचने की अनुमति देता है. जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि संसार ही केवल वास्तविकता है, तो हमारे तथाकथित नैतिक सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं. उसके बाद हम फिर लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध, अहंकार और भ्रम जैसी भावनाओं से पीड़ित हो जाते हैं. दूसरे सिद्धांत के अनुसार, संसार कुछ नहीं बल्कि एक भ्रम है. वास्तविकता में इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है. सच वास्तविक है पर पूरा संसार एक भ्रम है. जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए मृत्यु के बाद मुक्ति के बारे में सोचने के लिए यह एक अच्छी प्रेरणा है क्योंकि यदि दुनिया ही एक भ्रम है, तो यह बात मायने नहीं रखती कि हम जीते हैं या मरते हैं. बस यह मायने रखता है कि जितनी जल्दी संभव हो, हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाए. यदि यह दुनिया भ्रम है तो कोई भी पानी और हवा को गंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता. यह बात मायने नहीं रखती कि हम पीछे छोड़कर क्या जाते हैं. हमारा कर्म केवल मुक्ति पाने के लिए है. श्री चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानुजचार्य और माधवाचार्य ने श्रीमद भगवद्गीता और भगवद्गीता में वैष्णव धर्म के सिद्धांत में जो सिखाया है उसकी अलग ही व्याख्या है. ईशा उपनिषद के अनुसार उन्होंने 'ओम पूर्णम् आदा पूर्णमिदम्' सिखाया है. परम सत्य यह है कि जो भी अस्तित्व में है उन सबका स्रोत है. कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं कि 'संसार भगवान की संपत्ति है.' यदि हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम स्वामी नहीं बल्कि रखवाले हैं.

- राधानाथ स्वामी

प्रबंध सूत्र

रीलबाजी में समय बेकार न करें

उम्रे-दराज मांग कर लाये थे चार दिन, दो फेसबुक पर कट गये और दो ट्विटर वार में. गौर से देखिए, दिन का कितना बड़ा हिस्सा फालतू रील देखने में निकल जाता है- रील एक के बाद एक. कई घंटे खराब करने के बाद ख्याल आता है कि यह तो कतई बेहूदा काम हो गया. समय नष्ट हो गया. पर दोबारा भी यही होता है. समय सबके पास सीमित है. उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी रीलबाजी में खत्म हो रहा है. समय खराब करने के कई तरीके हैं, मोबाइल के जरिये कई तरीके आप तक पहुंच जाते हैं. जिस प्लेटफार्म से आप रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं. उन्हें पता चल जाता है कि आपको इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है, फिर फिर यूट्यूब या कोई और प्लेटफार्म उन वीडियो की कतार आपके सामने पेश कर देता है, जिनमें आपकी रुचि हो सकती है. धीमे धीमे होता यह है कि उस टाइप के वीडियो की बाढ़ में आप डूब जाते हैं. यह सिलसिला चलता जाता है. फिर आप इसके आदी हो जाती हैं, आदत लत में बदल जाती है. लत किसी आइटम को खाने की हो सकती है, लत किसी किस्म के वीडियो को देखने की हो सकती है.

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

जरा चेक कीजिए, कितना वक्त जा रहा है इन सब में. दिन के बहुत कीमती घंटे इन सब में जा रहे हैं. परम फालतू काम, पर सबसे जरूरी काम. एक लत जैसा हाल है. आप किसी एटीएम के किसी गार्ड साहब को देखिये, वह मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहे होंगे. आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में जाइए, वहां के गार्ड साहब भी मोबाइल पर वीडियो देख रहे होंगे. एक आंधी आपके आसपास चल रही है. आसपास क्या, आपकी अपनी जिंदगी में भी चल रही होगी. पर हमें इसका अंदाज नहीं है. हमारे पास उन चीजों के लिए वक्त नहीं है, जो हम करना चाहते हैं. पर हमारे पास दिन में दो चार घंटे उन वीडियो को देखने के लिए है, जो हमारी ही राय में परम फालतू हैं. कोई गृहिणी सब्जी काटते हुए नाच रही है. नाचना अच्छी बात है और सब्जी काटते हुए नाचना तो बहुत बड़ी कला है. पर ऐसे वीडियो में दो-चार घंटे लगाना विशुद्ध मूर्खता है.

मूर्खता है, पर करनी है क्योंकि इसकी लत लग चुकी है. लत का सबसे पहला लक्षण यह होता है कि लती इसे मानने से इनकार कर देता है कि उसे कोई लत है. रील, वीडियो अगर सीमा में देखे जायें, तो मनोरंजन के माध्यम हैं. पर मनोरंजन ही जीवन हो जाए, तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, जिनका धंधा ही मनोरंजन है, पर ज्यादातर लोगों को तमाम काम करने होते हैं. उनके अगर कई घंटे इस तरह के वीडियो रील आदि में जायेंगे, तो समस्या ही है. और, यह समस्या लगातार बढ़ रही है. गौर से देखिए, कहीं आपको भी इसकी लत तो नहीं हो गयी है.

आपके पत्र

अशोक राजपथ की हालत जर्जर

अशोक राजपथ राजधानी पटना का लाइफलाइन है. पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय समेत कई बड़े संस्थान इस मार्ग पर हैं. अशोक राजपथ पूर्वी पटना से गांधी मैदान को जोड़नेवाला प्रमुख मार्ग है. लेकिन, इसकी स्थिति इतनी खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. ओवरब्रिज और मेट्रो का काम चल रहा है, जिससे सड़क जर्जर हो गयी है. बारिश होने से सड़क में बने गड्ढे में पानी भर गया है. इससे बाइक सवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लोगों की परेशानियों को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए.

ऋचा राय, गायघाट (पटना)

सरकारी स्कूलों को मिले बिजली

अब नियमित रूप से सरकारी स्कूल खुल रहे हैं. शिक्षक भी नियमित आने लगे हैं और छात्र-छात्राओं की संख्या भी बढ़ी है. लेकिन, गर्मी के दिनों में बिजली की अनियमित आपूर्ति से छात्रों के साथ शिक्षकों को परेशानी होती है. इसलिए सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगा कर बिजली का इंतजाम करना चाहिए. इससे बिजली नहीं रहने पर भी कक्षा में पंखा चले और लाइट जले. पिछले दिनों गर्मी से छात्र-छात्राओं के बेहोश होने की खबरें आयीं. इसमें एक बात का पता चला कि क्लास में पंखे का इंतजाम नहीं था. इससे गर्मी में छात्र परेशान रहे.

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

हमारे छह पदक

पेरिस ओलंपिक 2024 के मीठे-खट्टे अनुभवों को भारत एक सबक की तरह हमेशा याद रखेगा। छह पदकों (एक रजत, पांच कांस्य) के साथ ओलंपिक 2024 में भारत के सफर का समापन हो गया। यह याद आना स्वाभाविक है कि पिछले टोक्यो ओलंपिक में हमने सात पदकों (एक स्वर्ण, दो रजत, चार कांस्य) के साथ इससे बेहतर प्रदर्शन किया था। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि अगर पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता का मामला न होता, तो भारत अपने प्रदर्शन को दोहराने में सफल हो जाता। यह भी याद किया जाएगा कि विनेश फोगाट के मामले ने देश में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस देश में राजनीति और खेल संघों को अलग-अलग न किया जा सके, वहां ऐसे विवाद स्वाभाविक हैं। यह 100 ग्राम से उपजी सियासत भी सुबूत है कि हम खेलों व खिलाड़ियों के प्रति पूरी तरह पेशेवर या समर्पित नहीं हैं। विनेश प्रकरण के अनेक परत हैं, जिन पर हमें गौर करना होगा। फिर भी प्रशंसा करनी चाहिए कि हमने ओलंपिक की खेल अदालत में विनेश की शिकायत को पुरजोर ढंग से उठाया है और मुमकिन है कि 13 अगस्त को एक और रजत पदक हमारी झोली में आ जाए।

सबसे बड़ी खुशी राष्ट्रीय खेल हॉकी को लेकर है कि हमने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। इससे निस्संदेह भावी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, हम लगातार अपने खेल को सुधारते और पदक जीतते चले जाएंगे। इस ओलंपिक को नीरज चोपड़ा के रजत पदक और उनके साथी पाकिस्तानी अरशद नदीम के स्वर्ण पदक के लिए भी याद किया जाएगा। नीरज और नदीम की मां के उद्गार भी याद आएंगे। लंबे समय बाद पाकिस्तान की झोली में एक पदक, वह भी स्वर्ण आया है और पाकिस्तानियों को चर्चा के लिए एक सकारात्मक विषय मिला है। नदीम वहां प्रेरणास्रोत बनें, तो इसमें दक्षिण एशिया का हित है। यह ओलंपिक निशानेबाज मनु भाकर के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने एक कांस्य पदक व्यक्तिगत शूटिंग में और दूसरा सरबजोत के साथ मिश्रित टीम में जीता है। निशानेबाज स्वप्निल कुसाले और पहलवान अमन सहरावत ने भी कांस्य जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। यह ओलंपिक हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेश की शानदार विदाई के लिए भी याद किया जाएगा। ये खिलाड़ी अब प्रेरणा-स्रोत बनकर भारतीय खेल इतिहास में दर्ज हो गए हैं।

अब यहां से खेल प्रबंधकों और निर्णायकों के लिए काम शुरू हो जाता है। क्या सोचा गया था और क्या हुआ है? आगे क्या सुधार करना है?

अब यहां से खेल प्रबंधकों-निर्णायकों के लिए काम शुरू हो जाता है। क्या सोचा गया था और क्या हुआ है? आगे क्या सुधार करना है? किससे क्या सीखना है? खेल निर्णायकों को युद्ध स्तर पर काम करना होगा, तभी उनकी सार्थकता है, वरना पदक तालिका तो अभी कहीं उत्साह से दिखाने लायक भी नहीं है। सबसे ज्यादा पदक अमेरिका ने जीते हैं, पर चीनी खिलाड़ियों ने रणनीति के तहत स्वर्ण पर निशाना साधा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली इत्यादि के पदक गिनने के बजाय हमारा जोर अपने प्रदर्शन को सुधारने पर होना चाहिए। हमें सोचना होगा कि हमारा ध्यान किधर ज्यादा है? मुक्केबाजी और भारोत्तोलन में क्यों हमारी अवनति हुई है? खैर, यह पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सत्कार का समय है। हम जब खिलाड़ियों के साथ मजबूती से खड़े होने लगेंगे, तो खेलों में सुधार की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। हॉकी के पुनरोत्थान और ओडिशा सरकार के सहयोग से भी सीखना चाहिए।

राष्ट्रवाद की एक बुनियाद बने ओलंपिक

रॉन्जॉय सेन | राजनीतिक विज्ञानी व खेल विशेषज्ञ

खेल और राष्ट्रवाद के बीच संबंध पुराना है। चीन सहित अनेक देशों ने पदक तालिका में स्थिति सुधारकर अपनी पहचान बनाई है, भारत भी इसी दिशा में बढ़ रहा है।

हर चार साल में भारत निशानेबाजी की बारीकियों और पिस्तौल, राइफल, ट्रैप व स्कीट के बीच के अंतर से परिचित होता है। ऐसा निशानेबाजी के प्रति उसके प्यार के कारण नहीं होता, बल्कि निशानेबाजों पर टिकी उम्मीदों की वजह से होता है कि वे एक दुर्लभ चीज लाएंगे, जो है ओलंपिक पदक। यह कहना गलत नहीं होगा कि हाशिये पर पड़े खेलों को ओलंपिक पदकों से काफी ऊर्जा मिलती है। यह स्थिति कई देशों की है, उस चीन की भी, जिसने खिलाड़ियों की सफलता को अपने राष्ट्रवाद का स्तंभ बनाया और पूरी दुनिया में जगह बनाई। पुराने दौर में रूस ने भी यही किया था।

खेल और राष्ट्रवाद के बीच का संबंध काफी पुराना है। यह ओलंपिक संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन के मत के बिल्कुल विपरीत है, जिनका मानना था कि प्रतिस्पर्द्धा करें, फिर चाहे आपको उसमें जीत मिले या न मिले। जॉर्ज ऑरवेल ने शायद अतिशयोक्ति की थी, जब उन्होंने शीत युद्ध के संदर्भ में खेल को 'वार माइनस द शूटिंग' कहा था, जिसका भावार्थ है- बिना गोलीबारी वाली वैश्विक जंग। हालांकि, एरिक हॉब्सबॉम यह उचित ही लिखते हैं कि ग्यारह नामित खिलाड़ियों की टीम लाखों लोगों के किसी समुदाय, समाज, देश से कहीं अधिक वास्तविक लगती है। टीम को हम प्रतिनिधि रूप में देखते हैं।

कुछ शुरुआती ओलंपिक खेलों में ऐसे प्रतिभागी भी थे, जो जरूरी नहीं कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हों, लेकिन जल्द ही देश का प्रतिनिधित्व करना नियम बन गया। जाने-माने खेल इतिहासकार एलन बैरनर ने लिखा है, खेल किसी भी अन्य सामाजिक गतिविधियों की तुलना में कहीं अधिक ध्वजा लहराने और राष्ट्रगान बजाने की सुविधा प्रदान करता है। यह ओलंपिक खेलों के लिए विशेष रूप से सच है। मुकुल केसवन के शब्दों में कहें, तो ओलंपिक ने खेल और राष्ट्र की निरंतर पहचान का बीड़ा उठा रखा है।

यह बात रविवार को खत्म हुए ओलंपिक खेलों में

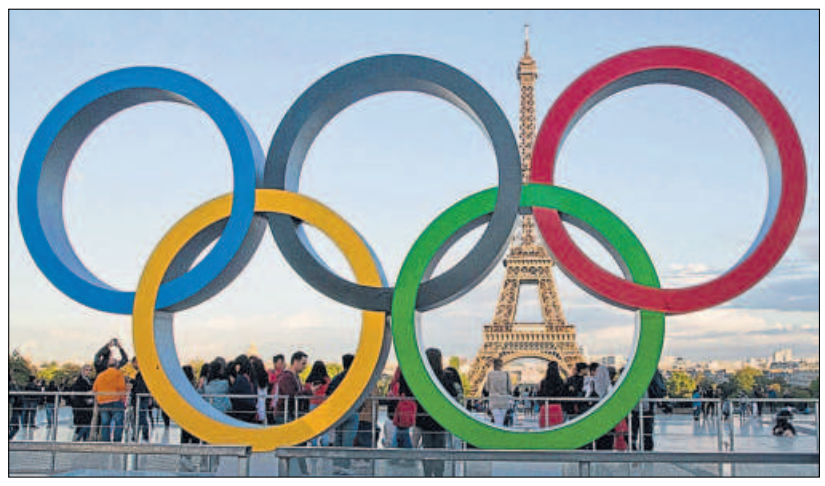

बैडमिंटन पुरुष युगल के फाइनल में भी साफ-साफ दिखी, जब ताइवान की जोड़ी चीन के खिलाफ मुकाबिल थी। इसमें ताइवानी खिलाड़ी अपने ध्वज नहीं, बल्कि चीनी ताइपे के झंडे तले मुकाबला कर रहे थे। दर्शकों में जो कोई भी ताइवान का झंडा लहराता दिखता, उसे या तो बाहर निकाल दिया जाता या फिर उसका झंडा जब्त कर लिया जाता था। मुकाबले में चीनी ताइपे की जोड़ी भारी पड़ी और इस जीत को कई ताइवानियों ने विश्व समुदाय में ताइवान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा। ताइवानी राष्ट्रपति ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा कि इस जीत ने मुल्क को एकजुट कर दिया है।

राष्ट्रवादी नजरिये से जीत को परिभाषित करने का यह कोई एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि ओलंपिक खेल ऐसे अनेक उदाहरणों से भरे पड़े हैं। साल 1980 के मॉस्को व साल 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों के दौरान शीत युद्ध के दौर में बहिष्कार जैसी कार्रवाइयां तस्दीक करती हैं कि खेलों के इर्द-गिर्द किस कदर राजनीति होती रही है।

बहरहाल, भारत सहित ज्यादातर देशों की पदक-तालिका में अपनी स्थिति मजबूत बनाने की नीयत काफी हद तक राष्ट्रवादी प्रवृत्ति और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली बनने की महत्वाकांक्षा से जुड़ी है। पुराने जमाने में सोवियत संघ और सोवियत गुट के कुछ सदस्यों ने व्यवस्थित रूप से ऐसा ही किया था। आज के समय में चीन ने भी यही रास्ता दिखाया है। भारत के विपरीत, जिसने आजादी से पहले हॉकी में सोना जीता था, चीन ने अपना पहला सोना 1984 के खेलों में जीता, जब वह ओलंपिक में फिर से शामिल हुआ था। तब से यह देश तेजी से आगे बढ़ा है और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ही 48 सोना जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अमेरिका से आगे निकल गया था। चीन बाद के ओलंपिक खेलों में भी शीर्ष स्थान के लिए अमेरिका के साथ होड़ लगाता दिखा है। माओत्से तुंग हमेशा खेल और राष्ट्रवाद के बीच गहरा रिश्ता बताते रहे। 2001 में बीजिंग को 2008 के खेलों की मेजबानी के लिए चुने जाने के बाद से ही चीन ने पदकों का पीछा करना शुरू कर दिया था। चीन की सरकार ने 'प्रोजेक्ट-119' के तहत अपने बच्चों को चैंपियन बनाने के लिए 3,000 से भी अधिक अकादमियों में अरबों डॉलर निवेश किए। इसका नाम प्रोजेक्ट-119 इसलिए रखा गया था, क्योंकि उस समय जल क्रीड़ा और एथलेटिक्स में 119 पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया था। दो चीनी इतिहासकारों ने बताया है कि स्वर्ण पदक को लेकर चीन की भूख ने चीनी एथलीटों पर भारी सियासी बोझ डाल दिया, जिनका मिशन था, चीन की छवि को सुधारना और राष्ट्र के पुनरोद्धार के लिए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना।

भारत ने आजादी के शुरुआती वर्षों में खेलों को लेकर अलग नीति अपनाई थी। 1951 के दिल्ली एशियाई खेलों में जवाहरलाल नेहरू के संबोधन में भले ही डे कुबर्टिन के आदर्शों की ध्वनि निकल रही थी, जब उन्होंने कहा था कि खेल प्रतियोगिताएं मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंद्विता विकसित करने के लिए अच्छी हैं और प्रत्येक खिलाड़ी को इसमें अपनी भूमिका शालीनता से निभानी चाहिए, लेकिन तब से अब तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। हाल के वर्षों में तो भारत सरकार और उद्योग जगत, दोनों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के प्रदर्शन को सुधारने के लिए काफी पैसे लगाए हैं। हालांकि, भारत की खेल नीति के कुछ अन्य पहलू भी हैं। बेशक, इसका खेल के बुनियादी ढांचे के विकास और खेल व स्वास्थ्य सुविधाओं तक बच्चों की बेहतर पहुंच पर बहुत असर नहीं पड़ा हो, लेकिन इसने हमारे खेल प्रदर्शन को काफी अधिक सुधारा है, भले ही हमें पदक के मामले में अभी पीछे रहना पड़ रहा है।

पिछले एक दशक में भारत में भी खेल राष्ट्रीय गौरव, वैश्विक रुतबे का विषय बना है। भारत ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के प्रयासों में लगा है। यही कारण है कि इस साल ओलंपिक में टोक्यो से भी बेहतर प्रदर्शन की इच्छा जताई गई थी। इसने किसी खिलाड़ी की सफलता में आत्म-गौरव और उनकी हार पर सामूहिक निराशा पैदा की, फिर चाहे वह विनेश फोगाट का ही मामला क्यों न हो। वास्तव में, विनेश फोगाट की अयोग्यता को राष्ट्रीय आपदा के रूप में देखने जैसी प्रतिक्रिया भारत में खेलों के प्रति बढ़ते प्रेम के साथ ही राष्ट्रवाद व ओलंपिक के संबंधों का ही एक रूपक है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दुनिया में हुए युवा आंदोलनों को याद करने की जरूरत

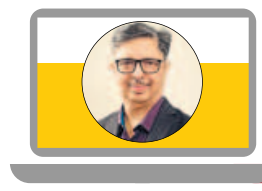

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और बिहार के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जब 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब कई देशों में हुए एक और युवा आंदोलन को याद करना जरूरी है, जिसके घटनाक्रम अब भी हमारी स्मृतियों में ताजा हैं। चंद महीनों बाद उस आंदोलन के 15 साल पूरे हो जाएंगे, जिसे हम 'अरब स्प्रिंग' के नाम से जानते हैं। ट्यूनीशिया से शुरू हुआ यह आंदोलन जब एक के बाद एक पश्चिम एशिया के तमाम देशों में फैलने लगा, तो पूरी दुनिया की खैर-खबर रखने वाले तकरीबन सभी आलिम-फाजिल दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर थे। लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया, बहरीन जैसे देशों में नौजवान सड़कों पर आ चुके थे। वे तानाशाही की तमाम पाबंदियां हटाने और मानवाधिकार देने की मांग कर रहे थे। यह हवा इतनी तेज थी कि मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सूडान और यहां तक कि सऊदी अरब में भी इसके झोंके महसूस किए गए। आंदोलन का भूगोल भले ही सीमित रहा हो, लेकिन इसने दुनिया के तानाशाहों और लोकतांत्रिक ताकतों को यह संदेश दे दिया था कि इस नए दौर में पुराने तौर-तरीकों से नौजवान पीढ़ी को ज्यादा समय तक भरमाए नहीं रखा जा सकता।

डर इसी बात का है कि बांग्लादेश के नौजवान जितना हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं, कहीं वे उससे ज्यादा गंवा न बैठें।

नए दौर का जिक्र यहां इसलिए जरूरी है कि इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के आगमन के बाद का यह पहला बड़ा आंदोलन था, जो एक साथ कई देशों में फैला। तकनीक ने देश की सीमाओं से परे लोगों को आपस में जुड़ने का मौका दे दिया था। इनसे लोगों को लामबंद किया गया, धरना स्थलों तक खींच लाया गया और जो नहीं पहुंच सके, वे लाइक, कमेंट और फॉरवर्ड से भागीदार बनते रहे। इस सबका असर भी दिखा। कई देशों के शासनाध्यक्षों को गद्दी छोड़नी पड़ी। कई राजाओं ने अपनी गद्दी तो नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। तमाम जगहों पर सरकारें भंग की गईं और नए सिरे से चुनाव कराए गए।

मगर इन सबके बाद क्या रक्तहीन क्रांति की बात करने वाले इन देशों के नौजवानों ने वह हासिल कर लिया, जिसके लिए वे सड़कों पर निकले थे? इसका जवाब पाने के लिए हमें अमेरिकी थिंक टैंक 'कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन' के एक अध्ययन को देखना होगा। यह अध्ययन बताता है कि इन सबमें ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश है, जहां लोकतंत्र स्थापित हुआ। बाकी सभी देशों में तानाशाही जैसी थी, कम या ज्यादा वैसी ही बनी रही। अपवाद सिर्फ मिस्र और सीरिया को कह सकते हैं, जहां सत्ता पहले से ज्यादा सख्त हो गई। तमाम देशों में लोगों के अधिकार कम कर दिए गए और उनके जीवन-स्तर में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि ट्यूनीशिया में भी, जहां लोकतंत्र काफी हद तक स्थापित हो चुका था। युवा आंदोलनों के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि वे बेरोजगारी की कुंठा से उपजते हैं। इलाज भी यही बताया जाता है कि नौजवानों को काम में लगाकर घर-गृहस्थी में उलझा दो, तो वे सड़कों पर नहीं निकलेंगे। यह धारणा कितनी सही है और कितनी नहीं, इस विस्तार में जाए बिना अगर हम 'अरब क्रांति' के दौरान आंदोलित देशों को देखें, तो आंदोलन के बाद भी वहां की सरकारों ने इस इलाज को अपनाने की या तो कोशिश नहीं की या फिर इसमें सफलता हासिल नहीं की। ज्यादातर देशों में बेरोजगारी दर कम या ज्यादा वैसी ही बनी रही, जैसी वह पहले थी।

हम अरब देशों की इस क्रांति को तब याद कर रहे हैं, जब हमारे पड़ोस बांग्लादेश में युवा उबाल का एक अन्य रूप हमने अभी देखा है। चंद हफ्तों के युवा आंदोलन ने 15 साल से जमी-जमाई उस सरकार को उखाड़ फेंका, जो आई तो लोकतंत्र के दरवाजे से थी, लेकिन पूरे देश को तानाशाही की गहरी गुफाओं में ले गई। इस आंदोलन का स्वागत किया जाना चाहिए, पर अरब स्प्रिंग के सबक यहां हमें आशंकित करते हैं। डर है कि ये नौजवान जितना हासिल करने के लिए घर से निकले हैं, कहीं उससे ज्यादा वे खो न दें। इस डर का कारण भी है। सत्ता में बदलाव के बाद वहां जिस तरह से हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक तत्वों को खेलने का मौका मिला है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, वह भविष्य को लेकर कोई उम्मीद नहीं बनाता। क्या पश्चिम एशिया के नौजवानों की तरह ही बांग्लादेश के नौजवानों को भी एक अंधेरे के बदले दूसरा अंधेरा मिलेगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

स्वतंत्रता का मंदिर

न्यूयॉर्क में प्रवेश करते ही आपका स्वागत करती है एक महाकाय स्वतंत्रता की देवी 'द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।' चबूतरे सहित लगभग 305 फीट ऊंची, एक हाथ में मशाल और दूसरे में किताब लिए यह तांबे की प्रतिमा लगभग डेढ़ सौ सालों से समुंदर के बीच खड़ी है। फ्रांसीसी शिल्पकार फ्रेडरिक बार्थोल्दी ने इसे बनाया था। यह न केवल अमेरिका और फ्रांस की मुक्ति की आकांक्षा का प्रतीक है, बल्कि मनुष्य के जन्मजात अधिकार की घोषणा करती है और वह अधिकार है स्वतंत्रता का। विचारणीय बात यह है कि ग्रीक और रोमन 'माइथोलॉजी' में स्वतंत्रता का भगवान एक स्त्री है। इसीलिए अमेरिका ने भी स्वतंत्रता का उद्घोष करने की खातिर एक दैवी स्त्री को चुना, जबकि विरोधाभास यह है कि मानवीय स्त्री को न यूरोप और न अमेरिका में कोई स्वतंत्रता है। आज तक अमेरिका में एक भी स्त्री राष्ट्रपति नहीं बन पाई।

भारत में स्वतंत्रता की न कोई देवी है और न देव। चारों तरफ इतने सारे मंदिर हैं, लेकिन स्वतंत्रता का कोई मंदिर नहीं, क्योंकि देवता हो, तो ही मंदिर बनता है। वजह शायद यह होगी कि इस देश में स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ गुलामी से विद्रोह करना नहीं है, यहां स्वतंत्रता को हमेशा आत्मिक मुक्ति के रूप में देखा गया है। वस्तुतः पूरी आत्मिक खोज ही स्वतंत्रता को पाने के लिए है। मनीषी कहते हैं कि मनुष्य अपने गहरे में स्वतंत्र ही है। वह केवल मानता है कि बंधा हुआ है। जैसे ही वह अपने अंतरतम के निकट पहुंचता है, उसे अपनी ज्योति का अनुभव होता है। वह दिव्य हो जाता है। यह एक नितांत व्यक्तिगत विकास और अनुभूति है।

इसीलिए विद्रोह भारतीय मानसिकता का हिस्सा ही नहीं है। यहां के लोग हमेशा एक तरह के स्वीकार भाव में जीते रहे। इसीलिए यह चमत्कार हुआ कि सदियों तक भारत पर लगातार राजनीतिक आक्रमण होते रहे, लेकिन वे आक्रांता भारतीय अस्मिता को जीत न सके।

ओशो कहते हैं कि भारतीय मानस स्त्रैणतत्व से बना है। स्त्रैण का अर्थ है ग्रहण, शील, सात्विक, शांतिप्रिय, सहज समर्पण करने वाला, रचनात्मक, स्वीकार भाव से युक्त। स्वतंत्रता के भी यही सारे गुण हैं। जो स्वतंत्र है, वह आक्रामक नहीं होता, वह किसी को जीतने की लालसा नहीं रखता। वह इतना तृप्त हो जाता है कि उसे दिखाने की आकांक्षा भी नहीं रहती कि मैं स्वतंत्र हूं। फूल कब घोषणा करता है कि मैं खिल गया! जिसने स्व का तंत्र, स्व का छंद पा लिया, उसे दूसरे को काबू में करने का ख्याल भी नहीं उठता। स्त्री-ऊर्जा प्रकृति के साथ घुल-मिलकर जीती है, क्योंकि वह स्वयं प्रकृति ही है। समूची प्रकृति ही स्वतंत्रता का मंदिर है, अलग से बनाने की जरूरत कहां?

जो सचमुच स्वतंत्र है, वह आक्रामक नहीं होता, वह किसी को जीतने की लालसा नहीं रखता। वह इतना तृप्त हो जाता है कि उसे दिखाने की आकांक्षा भी नहीं रहती कि मैं स्वतंत्र हूं।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

परमाणु हमले में नागासाकी की तबाही के 80 साल बीत गए। उसे याद करना ही काफी नहीं है। ऐसी सूरत फिर कभी न पैदा हो, हमें इसका उपक्रम करना चाहिए और इसका एक ही रास्ता है- परमाणु हथियारों का अंत!

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले 12 अगस्त, 1949

आर्थिक एकीकरण

पिछले दो वर्षों में देश के नक्शे तक में भारी परिवर्तन हो गये हैं। विदेशी शासकों ने इस देश के दो हिस्सों के बीच एक अस्वाभाविक दीवार खींच रखी थी। हमारे देश का एक हिस्सा ब्रिटिश भारत कहलाता था और दूसरा भारतीय भारत, जो राजाओं द्वारा शासित होता था। ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत की शासन-प्रणाली में कोई समानता न थी। भारतीय भारत लगभग पौने छः सौ भागों में विभाजित था और हरेक भाग अपनी खिचड़ी अलग पकाता था। देशी राज्य भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से देश के अविभाज्य अंग थे, किन्तु उनके पृथक् राजनीतिक अस्तित्व ने उनको देश की सामान्य जीवन-धारा से जुदा कर दिया था। देश की स्वतंत्रता और उसका भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन साथ-साथ आये। एक ही राष्ट्र के दो टुकड़े हो गये। इससे उसकी शक्ति क्षीण हुई। जिन लोगों के सिर पर राष्ट्र-निर्माण का गुरुतर दायित्व था, उन्होंने महसूस किया कि विभाजन के बाद देश का जो हिस्सा बच रहा है, उसी को एक मजबूत इकाई के रूप में संगठित कर दिया जाये, ताकि सदियों पश्चात् जो दुर्लभ स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसकी रक्षा की जा सके और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सके। उन्होंने सबसे पहले देश को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का काम हाथ में लिया। अंग्रेज जाते-जाते राजाओं को स्वच्छन्द कर गये थे। स्वतंत्र भारत की सरकार ने उन्हें भारतीय संघ के पाश में आबद्ध किया।

राजाओं ने भारतीय संघ का अंग बनना स्वीकार किया और रक्षा, यातायात और वैदेशिक संबंध- ये तीन आवश्यक विषय केन्द्रीय सरकार के हवाले कर दिये। छोटे-बड़े सैकड़ों राज्यों के पृथक् अस्तित्व की समस्या को इस तरह हल किया गया कि कुछ को पड़ोसी प्रान्तों में मिला दिया गया, कुछ को आपस में संघबद्ध कर दिया गया और कुछ बड़ी रियासतें स्वतंत्र रूप में कायम रहने दी गईं। देश के राजनीतिक एकीकरण की यह प्रक्रिया दो वर्ष के समय में प्रायः पूरी हो चुकी है। रियासतों का राजनीतिक एकीकरण पहली बड़ी मंजिल थी। उसके बाद हमको शेष भारत के साथ रियासतों के आर्थिक एकीकरण की दूसरी मंजिल तय करनी होगी। इसके बिना रियासतों को प्रान्तों की सतह पर नहीं लाया जा सकेगा।

इन्हें क्रांतिकारी नहीं, अराजकतावादी कहिए

बेरोजगार आंदोलनकारी बिना किसी कारण शेख हसीना को दोषी साबित करने पर तुले हुए हैं। चूंकि इन युवाओं ने ही बांग्लादेश में सत्ता गिराई है, इसलिए इन्हें बस अपने को सही साबित करना है। शेख हसीना कट्टरपंथ से निपट रही थीं, जमात व आतंकी गुटों के आगे नहीं झुक रही थीं, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रही थीं और यह सब वहां के कई कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा था। बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, जीडीपी ऊंचाइयां छू रही थी, विशेषज्ञों का अनुमान था कि बांग्लादेश जल्द ही काफी मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा, लेकिन आतंकियों को जीडीपी से क्या लेना-देना? उनके लिए तो जीडीपी का अर्थ अलग है। उनकी जीडीपी, यानी जन्नत डेवलपमेंट प्रोग्राम।

देश और सत्ता चलाने के लिए सख्ती और बल, दोनों आपको बराबर मात्रा में चाहिए होता है। शासक अगर हर किसी की सुनने लग जाए और सबके हिसाब से देश चलाने लग जाए, तो फिर उसे कभी गधे पर बैठना पड़ेगा, तो कभी गधे को अपनी पीठ पर लादकर चलना पड़ेगा। लोग तो जाने क्या-क्या कहेंगे, पचास पार्टियां और उनके सैकड़ों सिद्धांत, करोड़ों जनता और उनकी अनगिनत महत्वाकांक्षाएं, जाति-मजहब सबको अपने हिसाब से कुछ न कुछ चाहिए। देश इन सबसे पूछकर नहीं चलाया जाता है। जो एक बड़ी आबादी और देश के भविष्य के लिए अच्छा होता है, शासक को वैसा निर्णय लेना होता है। शेख हसीना वही कर रही थीं। वह चाहतीं, तो कट्टरपंथियों की बातें मान लेतीं, आरक्षण वाली मांग मान लेतीं, लेकिन वह जानती थीं कि भविष्य में क्या सही रहेगा, इसलिए वह अपनी बातों पर अड़ी रहीं। एक अच्छे शासक की यही तो पहचान होती है।

बाकी, जो यह कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और सम्मान के योग्य होती है, ये सब बेकार की बातें हैं। क्रांति करने वाली जनता बस भीड़ होती है, जिनमें ज्यादातर लफंगे, लुच्चे, नशेड़ी और कामचोर लोग होते हैं। जो ढंग की जनता होती है, वह अपने काम-धंधे में फंसी होती है, देश की जीडीपी बढ़ा रही होती है, टैक्स दे रही होती है और जनहितकारी कार्यों में अपनी भागीदारी निभा रही होती है। शेख हसीना बहुत ही मजबूत औरत हैं और उन्होंने जो भी किया, बहुत अच्छा किया। शासन ऐसे ही किया जाता है। उनके शासन में कमी नहीं थी। जो आज उन पर हंस रहे हैं, वे दरअसल दुनिया की हर अराजकता से खुश होते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। ये दुनिया में कहीं भी शांति स्थापित नहीं होने देते, क्योंकि अराजकता से ही इनको ऊर्जा मिलती है।

सिद्धार्थ ताबिश, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

तख्तापलट या क्रांति

इस छात्र क्रांति को हल्के में नहीं ले सकते

देश छोड़कर भाग आईं प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर हथौड़ा चलता देखकर लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखने वाला कोई भी व्यक्ति आहत हुआ होगा! लेकिन बंगबंधु की विरासत जमींदोज हुई है, तो इसमें उनकी पुत्री का योगदान कैसे भुलाया जा सकता है? शेख हसीना के राज में बांग्लादेश एकदलीय शासन में बदल गया था। खबर 2021 की है। ढाका की एक अदालत में जब कार्टूनिस्ट अहमद कबीर किशोर को पेश किया गया, तो उनके भाई उनकी स्थिति देखकर सदमे में आ गए, क्योंकि कबीर काफी कमजोर और डरे-सहमे दिख रहे थे। हिरासत में उन्हें प्रताड़ित किया गया था। उनका कथित अपराध यह था कि कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कुछ कार्टून सोशल मीडिया पर डाले थे। अदालत ने उनको जमानत देने से छह बार इनकार किया। जमानत मिलने तक किशोर 'द डिजिटल सिक्योरिटी ऐक्ट' (डीएसए) के तहत दस महीने जेल में बिता चुके थे।

यह कहानी सिर्फ किशोर की नहीं है। बांग्लादेश में संपादकों और सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद अक्तूबर 2018 में डीएसए लागू किया गया। आलोचकों का कहना है कि असहमति की आवाज और सरकार की आलोचना को दबाने के लिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया पर नजर रखने वाली ब्रिटेन स्थित संस्था आर्टिकल-19 के मुताबिक, साल 2020 में बांग्लादेश में डीएसए कानून के तहत 312 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें 70 पत्रकार शामिल थे।

सवाल यह भी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरोकार कही जाने वाली शेख हसीना के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां लोकतंत्र कितना महफूज रह गया था? अमेरिका, इंग्लैंड समेत तमाम पश्चिमी देशों ने 2024 के चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए थे। मानवाधिकारों का उल्लंघन और प्रेस की आजादी खत्म करने के लिए हसीना सरकार की तीखी आलोचना की थी। यह सब जब हो रहा था, तब बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति और जीडीपी का डंका बजाया जा रहा था। यह डंका इतना तेज बज रहा था कि भीषण गरीबी, चौड़ी होती असमानता की खाई, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही आवाजें दब गईं। शेख हसीना के खिलाफ सुलग रही चिनगारी जब छात्र-युवा आंदोलन के रूप में भड़की, तब उसमें कट्टरपंथी ताकतों की घुसपैठ रोक पाना मुश्किल हो गया! सिर्फ इसी आधार पर बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसका दूरगामी असर पड़ेगा।

हेमंत कुमार, टिप्पणीकार

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 12 अगस्त, 2024

दैनिक जागरण

प्रसन्नता की कुंजी तो मन के पास होती है

ओलिंपिक में भारत

पेरिस ओलिंपिक के समापन के पहले ही भारत का सफर खत्म हो चुका था। इस बार भारत एक रजत पदक समेत कुल छह पदक ही हासिल कर सका। इस प्रदर्शन को उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत तमाम तैयारी के बावजूद पिछले प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा सका। इससे यही रेखांकित होता है कि भारत को खेलों में बड़ी शक्ति बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। पदक तालिका में भारत का स्थान पहले 50 देशों में भी नहीं है। सबसे बड़ी आबादी वाले देश का पदक तालिका में इतना पीछे रहना ठीक नहीं। इस बार कुछ ही खेलों में भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इनमें सर्वोपरि रहे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पिछली बार स्वर्ण पदक जीतकर करिश्मा किया था और इस बार उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। इसके बाद भी वह भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। शूटिंग में मनु भाकर ने भी चमत्कृत करने वाला प्रदर्शन किया। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा के साथ युगल प्रतिस्पर्धा में भी सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता। शूटिंग में ही ऐसा ही प्रदर्शन स्वप्निल कुसाले ने भी किया। कुश्ती में अमन सहरावत के कांस्य के रूप में एक ही पदक मिला। विनेश फोगाट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। पदकों की संख्या कम रह जाने का एक कारण यह भी रहा कि लक्ष्य सेन, अर्जुन बबूटा समेत कई खिलाड़ी चौथे स्थान से आगे नहीं जा सके। हाकी टीम की ओर से लगातार दूसरा कांस्य पदक हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि यही बताती है कि भारतीय हाकी अपने स्वर्णिम दिनों की ओर लौट रही है।

ओलिंपिक में समापन के साथ ही हमारे नीति-नियंताओं, खेल संगठनों, खेल प्रशासकों और स्वयं खिलाड़ियों को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि भारत ओलिंपिक में इतना पीछे क्यों है। यह तो साफ है कि अपने देश में वैसी खेल संस्कृति विकसित नहीं हो सकी है, जैसी अब तक हो जानी चाहिए थी। चूंकि खेल संस्कृति का सही तरह विकास नहीं हो सका है इसलिए विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं की तलाश और उनका समुचित प्रशिक्षण नहीं हो पाता। इस काम में सरकारी विद्यालय भी पीछे हैं और निजी स्कूल भी। विभिन्न खेल संगठन भी खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें निखारने का काम नहीं कर पाते। एक समस्या यह भी है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के साथ ही अपने करियर की भी चिंता करनी पड़ती है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केंद्र सरकार के साथ कुछ ही राज्य सरकारें खेलों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर दिखती हैं। खेलों और खिलाड़ियों का विकास कैसे हो, इसकी सीख चीन समेत अन्य देशों से भी ली जानी चाहिए। अब जब भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आर्थिक विकास खेलों के विकास में सहायक होता है तब फिर भारत को ओलिंपिक की पदक तालिका में पहले बीस स्थानों में तो अपनी जगह बनानी ही चाहिए।

कड़ी कार्रवाई जरूरी

पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह की चेतावनी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है उसे देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल कदम उठाना चाहिए। प्रोजेक्ट के निर्माण में लगे स्टाफ से मारपीट और जान से मारने की धमकी देना गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस को शिकायत करने के बाद भी समुचित कार्रवाई न होना हैरानीजनक है। यह जांच का विषय है कि जालंधर एवं लुधियाना में जब शिकायत की गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो या कानून व्यवस्था का, यदि केंद्र की ओर से प्रोजेक्टों को रद कर दिया जाता है तो इससे नुकसान पंजाब का ही ज्यादा होगा। खास करके दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे तो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके पूरा होने के बाद पंजाब से जम्मू एवं दिल्ली जाने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से पंजाब के व्यापार एवं कारोबार में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। निवेश की संभावना भी बढ़ेगी, जिसकी राज्य को बहुत आवश्यकता है। पंजाब पर तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है और बीस हजार करोड़ रुपये केवल ब्याज देना पड़ रहा है। निवेश ज्यादा आएगा तो राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। निवेश तभी आएगा जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी। हाईवे निर्माण में लगे स्टाफ को जिन लोगों ने भी धमकी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है।

नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में लगे स्टाफ से मारपीट और जान से मारने की धमकी देना गंभीर मामला है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए

भारतीय कृषि का अमृतकाल

शिवराज सिंह चौहान

मोदी सरकार में किसानों को सशक्त बनाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक हर वह फैसला लिया गया, जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए

अवधेश राजपूत

कृषि विकास और किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्न के माध्यम से हमारे जीवन संचालन के सूत्रधार अन्नदाता के जीवन में सुख-समृद्धि लाना हमारा संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। किसान की आय बढ़ाने के लिए हमने छह सूत्रीय रणनीति बनाई है। उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम दिलाना, प्राकृतिक आपदा में राहत की उचित राशि दिलाना, कृषि का विविधीकरण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसके अहम पहलू हैं। उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए सबसे जरूरी हैं अच्छे बीज, जो कम पानी और विपरीत मौसम में भी बेहतर उत्पादन में सक्षम हो सकें। ऐसे बीजों की 109 नई किस्मों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र और किसानों को समर्पित किया है।

बीते 10 वर्षों में कृषि परिदृश्य तेजी से बदला है। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के बीच उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अगले पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में तैयार करने का है। वर्तमान में विज्ञान से ही किसानों का कल्याण संभव है। मुझे अपने कृषि विज्ञानियों पर गर्व है जो जलवायु अनुकूल किस्में तैयार कर रहे हैं। कृषि में किए जा रहे नवाचारों से कृषि एवं किसान कल्याण सुनिश्चित होगा।

किसान होने के नाते मैं भलीभांति समझता हूं कि बढ़िया उत्पादन के लिए अच्छे बीज कितने आवश्यक हैं। अगर बीज उन्नत और मिट्टी एवं मौसम की प्रकृति के अनुकूल होंगे तो उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मोदी जी ने यह समझा और व्यापक विजन के साथ इस दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शित किया। विविधता भारतीय कृषि की विशेषता है। यहां कुछ दूरी के अंतराल पर ही खेती का मिजाज बदल जाता है। जैसे मैदानी खेती अलग है तो पहाड़ों की खेती अलग। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं को ध्यान में रखते हुए फसलों की 109 नई किस्में जारी की गई हैं। इनमें खेती की 69 किस्में और बागवानी की 40 किस्में राष्ट्र को समर्पित कर दी गई हैं। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने और श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है।

हमारा संकल्प है कि किसान के परिश्रम का उचित मूल्यांकन हो और उन्हें फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है और उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ भारत की चिंता भी रही है कि मानव शरीर और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पादन हो। आज भारत नई हरित क्रांति का साक्षी बन रहा है। हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता तथा ईंधनदाता भी बन रहे हैं। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, औषधीय खेती, फूलों-फलों की खेती सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा रहा है।

पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकता में कृषि और किसान रहे ही नहीं। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27 हजार 663 करोड़ रुपये था जो 2024-25 में बढ़कर 1 लाख 32 हजार 470 करोड़ रुपये हो गया है। यह बजट सिर्फ कृषि विभाग का है। कृषि से संबद्ध क्षेत्रों और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अलग बजट है। मोदी सरकार किसानों को यूरिया और डीएपी सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है। यूरिया पर सरकार किसानों को करीब 2,100 रुपये सब्सिडी जबकि डीएपी के एक बैग पर 1083 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान स्वावलंबी और सशक्त हुआ है। फसलों के नुकसान पर भी फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है।

मोदी सरकार में किसान को सशक्त बनाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक हर वह फैसला लिया, जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए। उनकी मुश्किलें कम करे और मुनाफा बढ़ाए। इसी कड़ी में एक लाख करोड़ रुपये की एग्री इन्फ्रा फंड के जरिये कृषि से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। पूरे देश में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसान और विज्ञान को जोड़ रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिये टेक्नोलाजी से दूरदराज की हमारी माताओं-बहनों को भी जोड़ा जा रहा है। कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने के पहले चरण में अब तक 35 हजार कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मोदी जी का विजन है कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में भी रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में हम 18,000 करोड़ रुपये की लागत से 100 निर्यात केंद्रित बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 1500 से अधिक मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। साथ ही 6,800 करोड़ रुपये की लागत से तिलहन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने की भी तैयारी है। इससे छोटे किसानों को सब्जियों-फल और अन्य उपज के लिए नए बाजार और बेहतर दाम मिलेंगे। सरकार ने यह संकल्प भी लिया है कि दलहन फसलों में तुअर, उड़द और मसूर की पूरी खरीद एमएसपी पर की जाएगी।

यजुर्वेद में उल्लिखित है 'अन्नानां पतये नमः क्षेत्राणां पतये नमः' अर्थात अन्न के स्वामी और खेतों के स्वामी अन्नदाताओं को नमन। कृषि पराशर में भी उल्लेख है-अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है एवं अन्न ही समस्त प्रयोजनों का साधन है। किसानों के बिना इस देश का अस्तित्व ही अधूरा है। इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी किसानों को प्रणाम किया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसका आत्मा। हमारे लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा है। आज प्रधानमंत्री के दीर्घकालिक विजन तथा सर्वांगीण, समावेशी और समग्र विकास वाले सोच के साथ भारत एवं भारतीय कृषि निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई-बहन आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और समृद्ध संपन्न होने के साथ-साथ देश के अन्न भंडार भरते रहेंगे।

(लेखक केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं)

response@jagran.com

जमीन पर उतरती नई शिक्षा नीति

बद्री नारायण

नई शिक्षा नीति तभी साकार रूप ले सकेगी जब उसके अनुरूप पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होंगी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लागू होने के बाद उसके क्रियान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा शिक्षा से जुड़ी अन्य संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है कि इस नई शिक्षा नीति के आत्मा को कैसे ज्ञान सृजन एवं शिक्षण में उतारा जाए? हमें समझना होगा कि नई शिक्षा नीति मात्र एक ढांचागत परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के नवनिर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली नीति है। नई शिक्षा नीति का पूर्ण क्रियान्वयन तभी संभव हो पाएगा जब इस पर आधारित नई पाठ्यपुस्तकें जल्द से जल्द तैयार हों। देखा जाए तो नई शिक्षा नीति के दर्शन एवं आत्मा में आजादी के बाद बनीं अनेक राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की निरंतरता दिखाई पड़ती है। इसमें राधाकृष्णन कमेटी एवं डीएस कोठारी कमेटी तथा शिक्षा क्षेत्र में हुए अन्य विमर्शों की छवियां भी दिखाई पड़ती हैं। इसमें अपनी जमीन, अपनी मातृभाषा, अपनी अस्मिता एवं राष्ट्रीयता की छवियां दिखाई एवं उनकी ध्वनियां भी सुनाई पड़ती हैं।

यह जानना सुखद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक निर्माण के कार्य में लगी है। ये पाठ्यपुस्तक छप कर आनी भी शुरू हो गई हैं। अभी हाल में कक्षा छह के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित एवं प्रकाशित पुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसायटीः इंडिया एंड बियोंड' देखने को मिली। इसका हिंदी संस्करण भी शायद कुछ दिनों में आ जाए। यह पाठ्यपुस्तक बहुत रचनात्मक ढंग से छात्रों में विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं वृत्तांत क्षमता विकसित करने वाली है। सामाजिक ज्ञान को अपने आसपास के उदाहरणों से सरल भाषा में छात्रों में प्रवाहित करने का बहुत सुंदर प्रयास करती दिखती है। विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान की चेतना जगाने की यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इस पाठ्यपुस्तक में अनेक प्रेरणादायी उद्धरणों एवं रचनात्मक अभ्यासों को अत्यंत तारतम्यता से प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऐसे-ऐसे चित्र दिए गए हैं जो किशोर मन को गहराई से छूते हैं। इस प्रकार से छात्रों में सामाजिक विज्ञान से जुड़े ज्ञान को प्रवाहित करने की कोशिश की गई है। साथ ही छात्रों को महत्वपूर्ण तथ्यों और विश्लेषणों की ओर आकर्षक ढंग से बार-बार ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है।

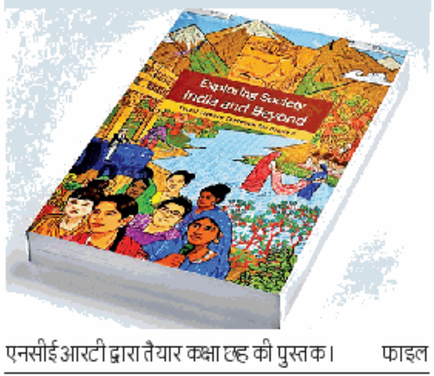

एनसीईआरटी द्वारा तैयार कक्षा छह की पुस्तक। फाइल

भारतीय समाज की विविधता में एकता का भाव इस पाठ्यपुस्तक की एक विशेषता है। इसमें देश की इस विविधता को बनाए रखने पर खासा जोर दिया गया है। इस पाठ्यपुस्तक में शुरू से अंत तक सभी अध्यायों में संवाद के जरिये ज्ञान प्रवाहित करने की रचनात्मक कोशिशें दिखाई पड़ती हैं। भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा को भी अत्यंत निरपेक्ष एवं ज्ञानपरक ढंग से इस पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ते हुए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में 'एक में अनेक' रचने का भाव दिखाई पड़ता है। यह जानना रोचक है कि इस पाठ्यपुस्तक की शुरुआत भारतीय संविधान के मुख्य तत्वों से होती है। यह पाठ्यपुस्तक छात्रों में भारतीय संविधान के मूल आत्मा को प्रवाहित करने का सफल प्रयास करती दिखती है। अत्यंत सरल ढंग से इस पाठ्यपुस्तक में दो पृष्ठों में संविधान में बताए गए मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को प्रस्तुत किया गया है। 'गवर्नेंस एवं डेमोक्रेसी' नामक पाठ में जमीन से जुड़ी अनेक केस स्टडी, प्रेरक व्यक्तित्वों एवं घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इन उदाहरणों से यह बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार भारत में पंचायती राज की व्यवस्था ने हाशिये पर बसे अनेक समूहों में भी नेतृत्व विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे आजादी के बाद अनेक आदिवासी एवं सीमांत समूहों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, ट्रांसजेंडर एवं सामाजिक परिवर्तन में लगे तमाम प्रेरक व्यक्तित्वों का एक बड़ा नेतृत्वकारी वर्ग विकसित हुआ है।

इस पाठ्यपुस्तक में परिवार एवं समुदाय पर भी एक अत्यंत उपयोगी पाठ दिया गया है, जिसमें बहुत ही सरलता एवं ग्राह्यपरकता के साथ भारतीय परिवार व्यवस्था को सहजतापूर्वक समझाया गया है। उम्मीद है कि इससे छात्रों में अपने परिवार एवं आसपास के समुदायों के साथ आत्मिक एवं ज्ञानात्मक संबंध विकसित हो पाएगा। इस पाठ्यपुस्तक की शुरुआत में विद्यार्थियों के नाम एक छोटा पत्र लिखा गया है, जिसमें इस पाठ्यपुस्तक को कैसे पढ़ें, इसे कैसे समझें, इसके बारे में काफी सरल ढंग से बताया गया है।

जाहिर है, यह एक नवोन्मेषी प्रयास है, जिससे छात्रों को इस पाठ्यपुस्तक से निर्मित होने वाले ज्ञान की संरचना एवं उसका ढंग आसानी से समझ में आ सकता है। यह एक प्रकार से एक 'मास्टर की' की तरह है जिससे यह पुस्तक छात्रों एवं शिक्षकों के लिए खुलती जाती है। इसके अंत में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिससे छात्र सामाजिक विज्ञान से जुड़े अत्यंत रोचक ज्ञानपरक वीडियो, पहेली, खेल एवं कहानी देख पाएंगे। इन सबके कारण यह पाठ्यपुस्तक 'नए समय की पाठ्यपुस्तक' के रूप में हमारे सामने आती है। यूं तो एनसीईआरटी हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अपने बेहतर पाठ्यपुस्तक निर्माण के लिए हमेशा प्रशंसित होती रही है, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत पाठ्यपुस्तक निर्माण का उसका यह प्रयास बेहद सराहनीय है। हमारे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए यह एक नया अनुभव बनकर सामने आया है। उम्मीद है, इसका सबको लाभ मिलेगा।

(लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भक्ति और सुख

परमपुरुष का गुणगान करना कीर्तन है। संस्कृत में 'कीर्तन' का मतलब है जोर से उच्चारण करना जिससे ध्वनि दूसरों के कानों तक पहुंचे। वैसे परमपुरुष को कीर्तन की प्रतीक्षा नहीं रहती, फिर भी मनुष्य कीर्तन क्यों करता है? वास्तव में इसके पीछे का विज्ञान यह है कि मनुष्य स्थूल यानी भौतिक से सूक्ष्म यानी आध्यात्मिक जगत की ओर जाना चाहता है। पहले भी मनुष्य को गाना और नाचना पसंद था। हालांकि यह बहुत स्थूल था। धीरे-धीरे लोगों ने गानों और नृत्य को परिष्कृत किया। भगवान शिव ने विभिन्न छंदों, राग-रागिनियों और तांडव नृत्य का आविष्कार किया। इसी तरह स्थूल से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ने की इस प्रगति को 'नंदनविज्ञान' कहा जाता है। नंदनविज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने सुंदरता और आनंद की अनुभूति की। अंततः यह अवस्था 'मोहनविज्ञान' में बदल जाती है। इसमें व्यक्ति खुद मोहित हो जाता है व स्वयं को भूल जाता है। कीर्तन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां व्यक्ति परमपुरुष को आनंद देने की कोशिश में स्वयं को भूल जाता है।

कीर्तन न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता हासिल करने का भी स्रोत है। इससे व्यक्ति को आत्मिक संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। इसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि कीर्तन के समय उच्चारित होने वाली ध्वनियां और गीतों की लय हमारी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर करती हैं। ध्वनि के माध्यम से उत्पन्न होने वाली तरंगें हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और इस प्रकार एकाग्रता बढ़ाती हैं। कीर्तन के दौरान जो भावना उत्पन्न होती है, वह हमें परमपुरुष के निकट ले जाती है और हमें शांति का अनुभव कराती है। कीर्तन के माध्यम से हम अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार यह हमें आत्मिक प्रगति की ओर ले जाता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

धैर्य के साथ लक्ष्य साधें युवा

डा. मोनिका शर्मा

आस्था का भाव धैर्य की सौगात देता है। धीरता का गुण जीवन के हर लक्ष्य साधना आसान बनाता है। अपने लक्ष्यों को पाने के मार्ग पर बिना रुके-थके आगे बढ़ते रहने का यह व्यावहारिक सा भाव है। यह इंसान के मनोविज्ञान को बल देने वाली बात है। हाल ही में पेरिस ओलिंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भारत की डबल मेडल विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने जीत के बाद गीता की चर्चा की। मनु भाकर ने कहा कि 'मैंने बहुत बार गीता पढ़ी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बस वही करो जो तुम्हें करना है।' ध्यातव्य है कि मनु भाकर के हिस्से बहुत सी मुश्किलें आईं। टोक्यो ओलिंपिक में पिस्टल में खराबी आने से वह पदक पाने से चूक गई थीं। नतीजतन, लंबे समय तक अवसाद के दौर से गुजरीं। इन परिस्थितियों में मनु ने गीता पढ़कर कर्मशील रहने की सीख ली। मन को सही दिशा देते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफलता पाई। पेरिस में पदक जीतने के बाद मनु ने कहा कि 'मेरे दिमाग में गीता के श्लोक चल रहे थे। मैंने कर्म पर फोकस किया, फल की चिंता नहीं की। मेरे दिमाग में चल रहा था कि वह करो जो आप कर सकते हो और मैंने वही किया।'

असल में कर्मशील रहने वाले लोग कामयाबी तो पाते ही हैं, उतार-चढ़ाव को झेलने की शक्ति भी जुटा लेते हैं

जीवन के पीड़ादायी दौर में अवसाद, आत्महत्या और आपराधिक गतिविधियों के घेरे में आने वाली युवापीढ़ी के लिए यह विचारणीय बात है। असल में कर्मशील रहने वाले लोग कामयाबी तो पाते ही हैं, उतार-चढ़ावों को झेलने की शक्ति भी जुटा लेते हैं। देश की युवा खिलाड़ी की प्रतिबद्धता और सकारात्मक सोच, दोनों ही युवाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। युवाओं को समझाती है कि मन की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। इस बल को पाने के लिए मन-जीवन का एक सकारात्मक आधार चुनना चाहिए। यह आपका परिवार, आध्यात्म, योग या आशावादी सोच, कुछ भी हो सकता है। दरअसल, अंतर्मन की शक्ति को साधने के लिए अपने भीतर विश्वास की मजबूत नींव बनाना बेहद जरूरी है।

दरअसल, असफलता के दौर में बहुत से युवा जीवन से ही हार मान लेते हैं। अवसाद के घेरे में आ जाते हैं। यही वजह है कि सधी जीवनशैली और सार्थक प्रयास कामयाबी ही नहीं, नाकामयाबी के समय भी आवश्यक हैं। गीता में अनुशासन और स्व-नियंत्रण के महत्व को बहुत सहज ढंग से समझाया गया है। इतना ही नहीं, जीवन के कई मोर्चों पर संयम, संतुलन और प्रबंधन की शिक्षा भी शामिल है। भटकाव भरे इस दौर में वाकई युवाओं को संयमित जीवनशैली अपनाने की जरूरत है। हर हाल में सकारात्मक बने रहने की दरकार है। संयम, समर्पण और निष्ठा से कर्मरत रहने का सोच सांसारिक सफलता की राह दिखाने वाली तो है ही, आत्मिक उन्नति से भी जुड़ा है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

भयंकर एवं त्रासद बांग्लादेश

'अनिश्चितता से घिरा बांग्लादेश' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने भारतीय चिंताओं को तो उजागर किया ही है, साथ ही यह भी बताया कि बांग्लादेश के लिए भी इसमें कई संदेश निहित हैं। आज के सार्वभौम विश्व में बांग्लादेश जैसी घटनाएं आश्चर्यजनक और त्रासद हैं, जो झकझोर कर रख देती हैं। अपने ही देश के एक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लक्ष्य कर उन्हें जान से मारना, उन पर अत्याचार करना, उनकी संपत्ति को तहस-नहस करना भला किस आंदोलन का मकसद हो सकता है। यह कैसा आंदोलन है, जो अपने ही देश में रह रहे एक समुदाय विशेष पर अत्याचारों को प्रोत्साहित कर रहा है। भारत का बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका से लेकर उसकी तरक्की में भी बहुत योगदान रहा है। जिन देशों के चंदे और शह पर बांग्लादेश में यह सत्ता परिवर्तन हुआ है वे अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने में लगे हुए हैं। इस बात को बांग्लादेश जब तक समझेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इस समय सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा की है जिसके प्रति कार्यवाहक प्रमुख मुहम्मद यूनुस भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लगता है उन्हें अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों सहित भारतीय चिंताओं का भी भान है। वह नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत विभूति हैं और विश्व में उनकी प्रतिष्ठा है। हमें आशा करनी चाहिए कि वह बांग्लादेश में अराजक तत्वों को काबू करने में तत्पर होंगे।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

मेलबाक्स

हिंदू एकता का शंखनाद

जहां भीड़तंत्र हावी हो जाता है, वहां लोकतंत्र के लिए स्थान नहीं बचता। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के नाम पर हुई व्यापक हिंसा में वहां सैकड़ों हिंदुओं को हिंसा का शिकार होना पड़ा है। हिंदुओं के खिलाफ की गई यातनाओं से यह साबित हो गया है कि शेख हसीना शासन के दौरान बांग्लादेश के भारत से संबंध प्रगाढ़ होना इस्लामिक कट्टरपंथियों को नहीं पच रहा था। बांग्लादेश के आंदोलन में हिंदुओं को चोट पहुंचाना दुखद है। इस विवाद से भारत-बांग्लादेश के धागा व्यापार पर भी भारी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बेशक इस्लामिक कट्टरपंथ के विरोध एवं हिंदुओं के समर्थन में अपनी आंखें, कान और मुंह बंद कर लिए हैं, लेकिन देश-विदेश में हिंदू एकता का शंखनाद सिर चढ़ कर बोल रहा है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

अनिश्चितता से भरा बांग्लादेश

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। सेना उसके साथ है। इसके बावजूद न हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा रुक रही है, न शांति स्थापित हो रही है। यहां तक कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का घेराव कर, इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया है। इससे तो यही दिख रहा है कि अंतरिम सरकार अराजक आंदोलनकारियों पर आवश्यक सख्ती नहीं बरत रही है। शेख हसीना पर निरंकुश शासक का आरोप लगता रहा है। लेकिन जहां जमात ए इस्लामी जैसे संगठन सक्रिय हों, जो बांग्लादेश की अपेक्षा पाकिस्तान के प्रति वफादार हों। इस आंदोलन में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान ने अपने-अपने स्वार्थों के लिए आग में घी डाला। अमेरिका बांग्लादेश के एक द्वीप में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, जो शेख हसीना को मंजूर नहीं था। चीन शेख हसीना के भारत से घनिष्ठ संबंध से चिढ़ता था, उसने पाक के जरिये आंदोलन को हवा दी। पाकिस्तान के मन में तो पुरानी रंजिश है ही, अब उसे अवसर मिल गया। कुल मिलाकर आरक्षण तो मात्र एक बहाना था, असल मकसद शेख हसीना को अपदस्थ करना था। भारत के लिए बांग्लादेश के हालात परेशान करने वाले हैं। एक तो हिंदुओं पर अत्याचार के कारण। दूसरा आशंका यही लग रही है कि नेपाल, मालदीव, म्यांमार की तरह बांग्लादेश भी चीन से अधिक नजदीकी रखेगा। यह सच सिद्ध हुआ तो दोनों के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

सीपी बंसल, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

ओलिंपिक में भारत

पेरिस ओलिंपिक के समापन के पहले ही भारत का सफर खत्म हो चुका था। इस बार भारत एक रजत पदक समेत कुल छह पदक ही हासिल कर सका। इस प्रदर्शन को उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत तमाम तैयारी के बावजूद पिछले प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा सका। इससे यही रेखांकित होता है कि भारत को खेलों में बड़ी शक्ति बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। पदक तालिका में भारत का स्थान पहले 50 देशों में भी नहीं है। सबसे बड़ी आबादी वाले देश का पदक तालिका में इतना पीछे रहना ठीक नहीं। इस बार कुछ ही खेलों में भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इनमें सर्वोपरि रहे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पिछली बार स्वर्ण पदक जीतकर करिश्मा किया था और इस बार उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। इसके बाद भी वह भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। शूटिंग में मनु भाकर ने भी चमत्कृत करने वाला प्रदर्शन किया। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा के साथ युगल प्रतिस्पर्धा में भी सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता। शूटिंग में ही ऐसा ही प्रदर्शन स्वप्निल कुसाले ने भी किया। कुश्ती में अमन सहरावत के कांस्य के रूप में एक ही पदक मिला। विनेश फोगाट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। पदकों की संख्या कम रह जाने का एक कारण यह भी रहा कि लक्ष्य सेन, अर्जुन बबूटा समेत कई खिलाड़ी चौथे स्थान से आगे नहीं जा सके। हाकी टीम की ओर से लगातार दूसरा कांस्य पदक हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि यही बताती है कि भारतीय हाकी अपने स्वर्णिम दिनों की ओर लौट रही है। ओलिंपिक में समापन के साथ ही हमारे नीति-नियंताओं, खेल संगठनों, खेल प्रशासकों और स्वयं खिलाड़ियों को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि भारत ओलिंपिक में इतना पीछे क्यों है। यह तो साफ है कि अपने देश में वैसी खेल संस्कृति विकसित नहीं हो सकी है, जैसी अब तक हो जानी चाहिए थी। चूंकि खेल संस्कृति का सही तरह विकास नहीं हो सका है इसलिए विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं की तलाश और उनका समुचित प्रशिक्षण नहीं हो पाता। इस काम में सरकारी विद्यालय भी पीछे हैं और निजी स्कूल भी। विभिन्न खेल संगठन भी खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें निखारने का काम नहीं कर पाते। एक समस्या यह भी है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के साथ ही अपने करियर की भी चिंता करनी पड़ती है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केंद्र सरकार के साथ कुछ ही राज्य सरकारें खेलों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर दिखती हैं। खेलों और खिलाड़ियों का विकास कैसे हो, इसकी सीख चीन समेत अन्य देशों से भी ली जानी चाहिए। अब जब भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आर्थिक विकास खेलों के विकास में सहायक होता है तब फिर भारत को ओलिंपिक की पदक तालिका में पहले बीस स्थानों में तो अपनी जगह बनानी ही चाहिए।

पुलों की निगरानी

प्रदेश में पुलों के ध्वस्त होने की कड़ी में वैशाली जिले के राघोपुर का एक और पुल जुड़ गया है। ईंट का यह पुल 20 वर्ष पहले बनाया गया था। जवाबदेह विभाग का कहना है कि यह पुल 2021 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था तथा इससे होकर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। खैर, जो भी कारण हो, पुल ध्वस्त हो गया। शुक्र है कि इस वर्ष जो पुल ध्वस्त हुए हैं, उनमें जनहानि नहीं हुई। सवाल उठता है कि 20 साल पहले बने पुल कैसे ध्वस्त हो रहे हैं। क्या उनकी लाइफलाइन 20 वर्ष ही थी? बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बने पुल के ध्वस्त होने के मामले की निगरानी की चार सदस्यीय टीम ने जांच की। जांच के बाद टीम ने दो टूक कहा कि निर्माण कार्य की नियमित जांच नहीं की गई। पाये की पाइलिंग व ढलाई में अनियमितता बरती गई थी। हालांकि, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। गत 18 जून को यह पुल ध्वस्त हो गया था। इधर, पुलों के अचानक ध्वस्त होने की कई घटनाओं के बाद पुलों के रखरखाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारियों को कई निर्देश दिए थे। पथ निर्माण विभाग ने अब अपने इंजीनियरों के लिए ट्रेनिंग आरंभ कराई है। उन्हें बताया जा रहा कि पुलों के मेंटेनेंस के लिए किस तरह की सक्रियता के साथ काम करना है। प्रशिक्षण में पुलों के स्ट्रक्चरल आडिट पर भी बात चल रही। ध्वस्त हुए पुलों की जांच में जो भी दोषी पाए जाएं, उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि वह नजीर बन जाए।

20 साल या उससे अधिक समय के पुलों का आडिट कराया जाए, ताकि कोई खामी मिले तो समय रहते उसे दूर किया जा सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

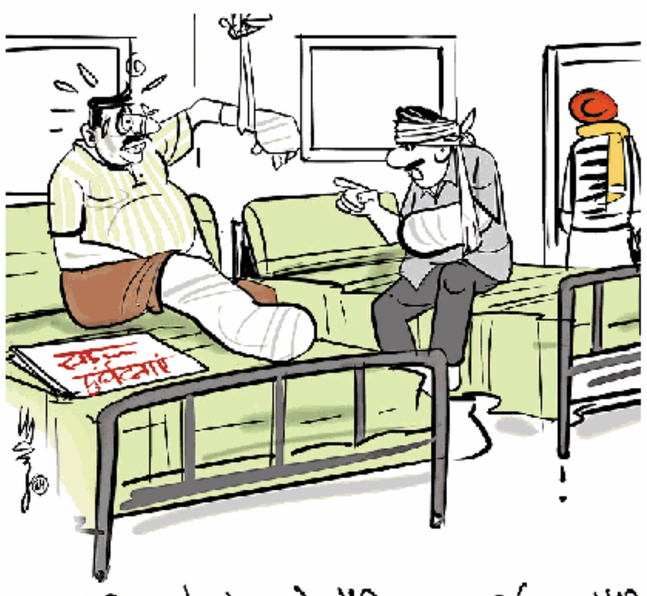

आप! किस क्षेत्र के गड्ढे में गिरकर चर्चित हुए हैं?

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या केंद्र सरकार ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने से इन्कार कर सही किया?

आज का सवाल

क्या आप मानते हैं कि ओलिंपिक स्तर पर दमदार प्रदर्शन के लिए भारत को नए खेल कार्यक्रम की जरूरत है?

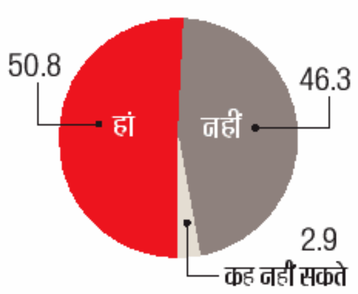

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भारतीय कृषि का अमृतकाल

शिवराज सिंह चौहान

मोदी सरकार में किसानों को सशक्त बनाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक हर वह फैसला लिया गया, जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए

कृषि विकास और किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्न के माध्यम से हमारे जीवन संचालन के सूत्रधार अन्नदाता के जीवन में सुख-समृद्धि लाना हमारा संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। किसान की आय बढ़ाने के लिए हमने छह सूत्रीय रणनीति बनाई है। उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम दिलाना, प्राकृतिक आपदा में राहत की उचित राशि दिलाना, कृषि का विविधीकरण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसके अहम पहलू हैं। उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए सबसे जरूरी हैं अच्छे बीज, जो कम पानी और विपरीत मौसम में भी बेहतर उत्पादन में सक्षम हो सकें। ऐसे बीजों की 109 नई किस्मों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र और किसानों को समर्पित किया है।

बीते 10 वर्षों में कृषि परिदृश्य तेजी से बदला है। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के बीच उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अगले पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में तैयार करने का है। वर्तमान में विज्ञान से ही किसानों का कल्याण संभव है। मुझे अपने कृषि विज्ञानियों पर गर्व है जो जलवायु अनुकूल किस्में तैयार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि में किए जा रहे नवाचारों से कृषि एवं किसान कल्याण सुनिश्चित होगा।

किसान होने के नाते मैं भलीभांति समझता हूं कि बढ़िया उत्पादन के लिए अच्छे बीज कितने आवश्यक हैं। अगर बीज उन्नत और मिट्टी एवं मौसम की प्रकृति के अनुकूल होंगे तो उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मोदी जी ने यह समझा और व्यापक विजन के साथ इस दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शित किया। विविधता भारतीय कृषि की विशेषता है। यहां कुछ दूरी के अंतराल पर ही खेती का मिजाज बदल जाता है। जैसे मैदानी खेती अलग है तो पहाड़ों की खेती अलग। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं को ध्यान में रखते हुए फसलों की 109 नई किस्में जारी की गई हैं। इनमें खेती की 69 किस्में और बागवानी की 40 किस्में राष्ट्र को समर्पित कर दी गई हैं। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने और श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है।

हमारा संकल्प है कि किसान के परिश्रम का उचित मूल्यांकन हो और उन्हें फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है और उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ भारत की चिंता भी रही है कि मानव शरीर और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पादन हो। आज भारत नई हरित क्रांति का साक्षी बन रहा है। हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता तथा ईंधनदाता भी बन रहे हैं। मोदी जी के प्रयासों से खेती के साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन, औषधीय खेती, फूलों-फलों की खेती सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा रहा है।

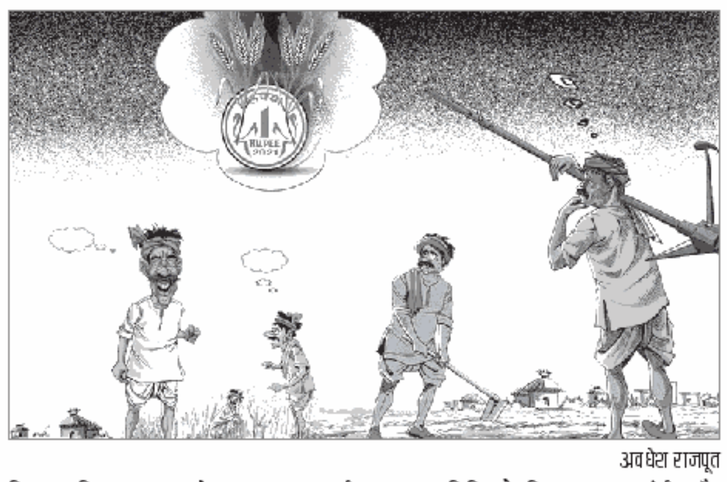

अवधेश राजपूत

पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकता में कृषि और किसान रहे ही नहीं। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27 हजार 663 करोड़ रुपये था जो 2024-25 में बढ़कर 1 लाख 32 हजार 470 करोड़ रुपये हो गया है। यह बजट सिर्फ कृषि विभाग का है। कृषि से संबद्ध क्षेत्रों और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अलग बजट है। मोदी सरकार किसानों को यूरिया और डीएपी सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है। यूरिया पर सरकार किसानों को करीब 2,100 रुपये सब्सिडी जबकि डीएपी के एक बैग पर 1083 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान स्वावलंबी और सशक्त हुआ है। फसलों के नुकसान पर भी फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है।

मोदी सरकार में किसान को सशक्त बनाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक हर वह फैसला लिया, जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए। उनकी मुश्किलें कम करे और मुनाफा बढ़ाए। इसी कड़ी में एक लाख करोड़ रुपये की एग्री इन्फ्रा फंड के जरिये कृषि से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। पूरे देश में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसान और विज्ञान को जोड़ रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिये टेक्नोलाजी से दूरदराज की हमारी माताओं-बहनों को भी जोड़ा जा रहा है। कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने के पहले चरण में अब तक 35 हजार कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मोदी जी का विजन है कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में भी रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में हम 18,000 करोड़ रुपये की लागत से 100 निर्यात केंद्रित बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 1500 से अधिक मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। साथ ही 6,800 करोड़ रुपये की लागत से तिलहन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने की भी तैयारी है। इससे छोटे किसानों को सब्जियों-फल और अन्य उपज के लिए नए बाजार और बेहतर दाम मिलेंगे। सरकार ने यह संकल्प भी लिया है कि दलहन फसलों में तुअर, उड़द और मसूर की पूरी खरीद एमएसपी पर की जाएगी।

यजुर्वेद में उल्लिखित है 'अन्नानां पतये नमः क्षेत्राणां पतये नमः' अर्थात अन्न के स्वामी और खेतों के स्वामी अन्नदाताओं को नमन। कृषि पराशर में भी उल्लेख है-अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है एवं अन्न ही समस्त प्रयोजनों का साधन है। किसानों के बिना इस देश का अस्तित्व ही अधूरा है। इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी किसानों को प्रणाम किया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसका आत्मा। हमारे लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घकालिक विजन तथा सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, समावेशी और समग्र विकास वाले सोच के साथ भारत एवं भारतीय कृषि निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई-बहन आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और समृद्ध संपन्न होने के साथ-साथ देश के अन्न भंडार भरते रहेंगे।

(लेखक केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं)

response@jagran.com

जमीन पर उतरती नई शिक्षा नीति

बद्री नारायण

नई शिक्षा नीति तभी साकार रूप ले सकेगी जब उसके अनुरूप पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होंगी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लागू होने के बाद उसके क्रियान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा शिक्षा से जुड़ी अन्य संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है कि इस नई शिक्षा नीति के आत्मा को कैसे ज्ञान सृजन एवं शिक्षण में उतारा जाए? हमें समझना होगा कि नई शिक्षा नीति मात्र एक ढांचागत परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के नवनिर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली नीति है। नई शिक्षा नीति का पूर्ण क्रियान्वयन तभी संभव हो पाएगा जब इस पर आधारित नई पाठ्यपुस्तकें जल्द से जल्द तैयार हों। देखा जाए तो नई शिक्षा नीति के दर्शन एवं आत्मा में आजादी के बाद बनीं अनेक राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की निरंतरता दिखाई पड़ती है। इसमें राधाकृष्णन कमेटी एवं डीएस कोठारी कमेटी तथा शिक्षा क्षेत्र में हुए अन्य विमर्शों की छवियां भी दिखाई पड़ती हैं। इसमें अपनी जमीन, अपनी मातृभाषा, अपनी अस्मिता एवं राष्ट्रीयता की छवियां दिखाई एवं उनकी ध्वनियां भी सुनाई पड़ती हैं।

यह जानना सुखद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक निर्माण के कार्य में लगी है। ये पाठ्यपुस्तक छप कर आनी भी शुरू हो गई हैं। अभी हाल में कक्षा छह के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित एवं प्रकाशित पुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसायटीः इंडिया एंड बियोंड' देखने को मिली। इसका हिंदी संस्करण भी शायद कुछ दिनों में आ जाए। यह पाठ्यपुस्तक बहुत रचनात्मक ढंग से छात्रों में विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं वृत्तांत क्षमता विकसित करने वाली है। सामाजिक ज्ञान को अपने आसपास के उदाहरणों से सरल भाषा में छात्रों में प्रवाहित करने का बहुत सुंदर प्रयास करती दिखती है। विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान की चेतना जगाने की यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इस पाठ्यपुस्तक में अनेक प्रेरणादायी उद्धरणों एवं रचनात्मक अभ्यासों को अत्यंत तारतम्यता से प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऐसे-ऐसे चित्र दिए गए हैं जो किशोर मन को गहराई से छूते हैं। इस प्रकार से छात्रों में सामाजिक विज्ञान से जुड़े ज्ञान को प्रवाहित करने की कोशिश की गई है। साथ ही छात्रों को महत्वपूर्ण तथ्यों और विश्लेषणों की ओर आकर्षक ढंग से बार-बार ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है।

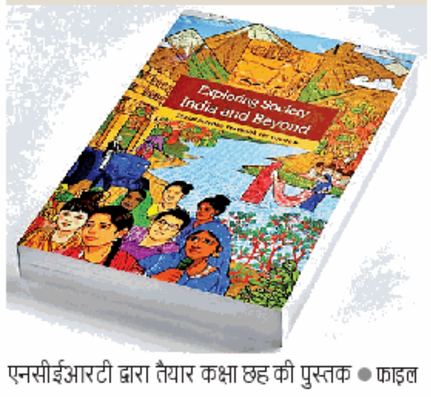

एनसीईआरटी द्वारा तैयार कक्षा छह की पुस्तक ● फाइल

भारतीय समाज की विविधता में एकता का भाव इस पाठ्यपुस्तक की एक विशेषता है। इसमें देश की इस विविधता को बनाए रखने पर खासा जोर दिया गया है। इस पाठ्यपुस्तक में शुरू से अंत तक सभी अध्यायों में संवाद के जरिये ज्ञान प्रवाहित करने की रचनात्मक कोशिशें दिखाई पड़ती हैं। भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा को भी अत्यंत निरपेक्ष एवं ज्ञानपरक ढंग से इस पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ते हुए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में 'एक में अनेक' रचने का भाव दिखाई पड़ता है। यह जानना रोचक है कि इस पाठ्यपुस्तक की शुरुआत भारतीय संविधान के मुख्य तत्वों से होती है। यह पाठ्यपुस्तक छात्रों में भारतीय संविधान के मूल आत्मा को प्रवाहित करने का सफल प्रयास करती दिखती है। अत्यंत सरल ढंग से इस पाठ्यपुस्तक में दो पृष्ठों में संविधान में बताए गए मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को प्रस्तुत किया गया है। 'गवर्नेंस एवं डेमोक्रेसी' नामक पाठ में जमीन से जुड़ी अनेक केस स्टडी, प्रेरक व्यक्तित्वों एवं घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इन उदाहरणों से यह बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार भारत में पंचायती राज की व्यवस्था ने हाशिये पर बसे अनेक समूहों में भी नेतृत्व विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे आजादी के बाद अनेक आदिवासी एवं सीमांत समूहों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, ट्रांसजेंडर एवं सामाजिक परिवर्तन में लगे तमाम प्रेरक व्यक्तित्वों का एक बड़ा नेतृत्वकारी वर्ग विकसित हुआ है।

इस पाठ्यपुस्तक में परिवार एवं समुदाय पर भी एक अत्यंत उपयोगी पाठ दिया गया है, जिसमें बहुत ही सरलता एवं ग्राह्यपरकता के साथ भारतीय परिवार व्यवस्था को सहजतापूर्वक समझाया गया है। उम्मीद है कि इससे छात्रों में अपने परिवार एवं आसपास के समुदायों के साथ आत्मिक एवं ज्ञानात्मक संबंध विकसित हो पाएगा। इस पाठ्यपुस्तक की शुरुआत में विद्यार्थियों के नाम एक छोटा पत्र लिखा गया है, जिसमें इस पाठ्यपुस्तक को कैसे पढ़ें, इसे कैसे समझें, इसके बारे में काफी सरल ढंग से बताया गया है।

जाहिर है, यह एक नवोन्मेषी प्रयास है, जिससे छात्रों को इस पाठ्यपुस्तक से निर्मित होने वाले ज्ञान की संरचना एवं उसका ढंग आसानी से समझ में आ सकता है। यह एक प्रकार से एक 'मास्टर की' की तरह है जिससे यह पुस्तक छात्रों एवं शिक्षकों के लिए खुलती जाती है। इसके अंत में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिससे छात्र सामाजिक विज्ञान से जुड़े अत्यंत रोचक ज्ञानपरक वीडियो, पहेली, खेल एवं कहानी देख पाएंगे। इन सबके कारण यह पाठ्यपुस्तक 'नए समय की पाठ्यपुस्तक' के रूप में हमारे सामने आती है। यूं तो एनसीईआरटी हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अपने बेहतर पाठ्यपुस्तक निर्माण के लिए हमेशा प्रशंसित होती रही है, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत पाठ्यपुस्तक निर्माण का उसका यह प्रयास बेहद सराहनीय है। हमारे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए यह एक नया अनुभव बनकर सामने आया है। उम्मीद है, इसका सबको लाभ मिलेगा।

(लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भक्ति और सुख

परमपुरुष का गुणगान करना कीर्तन है। संस्कृत में 'कीर्तन' का मतलब है जोर से उच्चारण करना जिससे ध्वनि दूसरों के कानों तक पहुंचे। वैसे परमपुरुष को कीर्तन की प्रतीक्षा नहीं रहती, फिर भी मनुष्य कीर्तन क्यों करता है? वास्तव में इसके पीछे का विज्ञान यह है कि मनुष्य स्थूल यानी भौतिक से सूक्ष्म यानी आध्यात्मिक जगत की ओर जाना चाहता है। पहले भी मनुष्य को गाना और नाचना पसंद था। हालांकि यह बहुत स्थूल था। धीरे-धीरे लोगों ने गानों और नृत्य को परिष्कृत किया। भगवान शिव ने विभिन्न छंदों, राग-रागिनियों और तांडव नृत्य का आविष्कार किया। इसी तरह स्थूल से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ने की इस प्रगति को 'नंदनविज्ञान' कहा जाता है। नंदनविज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने सुंदरता और आनंद की अनुभूति की। अंततः यह अवस्था 'मोहनविज्ञान' में बदल जाती है। इसमें व्यक्ति खुद ही मोहित हो जाता है और अपने को भूल जाता है। कीर्तन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां व्यक्ति परमपुरुष को आनंद देने की कोशिश में अपने आप को भूल जाता है।

कीर्तन न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता हासिल करने का भी स्रोत है। इससे व्यक्ति को आत्मिक संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। इसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि कीर्तन के समय उच्चारित होने वाली ध्वनियों और गीतों की लय हमारी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर करती हैं। ध्वनि के माध्यम से उत्पन्न होने वाली तरंगें हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और इस प्रकार एकाग्रता बढ़ाती हैं।

कीर्तन के दौरान जो भावना उत्पन्न होती है, वह हमें परमपुरुष के निकट ले जाती है और हमें शांति का अनुभव कराती है। कीर्तन के माध्यम से हम अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार यह हमें आत्मिक प्रगति की ओर ले जाता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

भयंकर एवं त्रासद बांग्लादेश

'अनिश्चितता से घिरा बांग्लादेश' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने भारतीय चिंताओं को तो उजागर किया ही है, साथ ही यह भी बताया कि बांग्लादेश के लिए भी इसमें कई संदेश निहित हैं। आज के सार्वभौम विश्व में बांग्लादेश जैसी घटनाएं आश्चर्यजनक और त्रासद हैं, जो झकझोर कर रख देती हैं। अपने ही देश के एक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लक्ष्य कर उन्हें जान से मारना, उन पर अत्याचार करना, उनकी संपत्ति को तहस-नहस करना भला किस आंदोलन का मकसद हो सकता है। यह कैसा आंदोलन है, जो अपने ही देश में रह रहे एक समुदाय विशेष पर अत्याचारों को प्रोत्साहित कर रहा है। भारत का बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका से लेकर उसकी तरक्की में भी बहुत योगदान रहा है। जिन देशों के चंदे और शह पर बांग्लादेश में यह सत्ता परिवर्तन हुआ है वे अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने में लगे हुए हैं। इस बात को बांग्लादेश जब तक समझेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इस समय सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा की है जिसके प्रति कार्यवाहक प्रमुख मुहम्मद यूनुस भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लगता है उन्हें अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों सहित भारतीय चिंताओं का भी भान है। वह नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत विभूति हैं और विश्व में उनकी प्रतिष्ठा है। हमें आशा करनी चाहिए कि वह बांग्लादेश में अराजक तत्वों को काबू करने में तत्पर होंगे। समझ नहीं आता कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था सहित विश्व के तथाकथित महान शक्तिशाली राष्ट्र किस गहन निद्रा में हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि विश्व में शांति और समन्वय का साम्राज्य हो, सभी राष्ट्र उन्नति करें और सभी लोग शांति से समृद्ध जीवनयापन कर सकें।'

योगराज, खरड़ (पंजाब)

बदलाव समय की मांग

देश में किसी भी नियम में सुधार के प्रयास के बाद संसद में टकराव और विरोध की स्थिति भयावह होती जा रही है। वक्फ कानून में सुधार की अनुशंसा वर्ष 2004 में सच्चर समिति ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सौंपी थी, जिसे अपने शासनकाल के छह वर्षों तक कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया था, क्योंकि उसे लागू करने से दल का वोट बैंक का एक हिस्सा खिसक जाता। यह सार्वजनिक तौर पर देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों का जो मूल उद्देश्य था, वह भटक कर कुछ नामी प्रभावशाली लोगों के हाथ में चला गया है, जिनकी आज भी चांदी कट रही है। सरकारी खाते में दर्ज आंकड़े बता रहे हैं कि देश में अभी वक्फ बोर्ड के पास नौ लाख एकड़ से अधिक संपत्ति है, जिसके अधिकांश हिस्से के दुरुपयोग की खबरें हमेशा आती रहती हैं। हजारों मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के एक जज की टिप्पणी अत्यंत गंभीर है, जिसमें वे वक्फ के अधिकार के दुरुपयोग की ओर संकेत करते हैं। वक्फ बोर्ड को दान में मिली संपति के कुछ अंश का उपयोग शिक्षा एवं दूसरे कल्याण कार्यों में तो किया जाता है, लेकिन इन संपत्तियों के बड़े भूभाग पर भू माफियों के कब्जे का प्रमाण भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए सर्वेक्षण में उजागर हुए हैं।

डा. अशोक कुमार, पटना

प्रगाढ़ संबंध तोड़ने की साजिश

'अनिश्चितता से घिरा बांग्लादेश' शीर्षक आलेख में संजय गुप्त ने भारत और बांग्लादेश के प्रगाढ़ संबंधों को तोड़ने की साजिशों का खुलासा किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस के सामने सबसे कठिन कार्य देश में शांति बहाल करना है। उन्होंने देश में प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है, परंतु इसका असर होता नहीं दिख रहा है। अब यूनुस के लिए दूसरा मुख्य कार्य नए चुनावों की तैयारी करना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना नौकरी में आरक्षण को लेकर कई सप्ताह तक चले छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद भारत भाग आईं। यह उनके 15 साल के शासन के खिलाफ विद्रोह था। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूनुस को बधाई देते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी और हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव में हजारों हिंदुओं ने उनपर हो रहे हमलों के खिलाफ एक विशाल रैली निकाली तथा देश के नागरिक के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना के बेटे और सलाहकार साजिश वाजेद ने कहा है कि उनकी मां ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, वो अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले भारत के छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जबकि उनके 'डीप स्टेट' साथियों को पिछली बार की तरह बड़े लाभ की उम्मीद है, लेकिन याद रहे कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती।

विक्रांत@vikrantkumar

हिंडनबर्ग प्रकरण ने कुछ साबित किया हो या नहीं, मगर एक बात जरूर रेखांकित की है कि भारत को बर्बाद करने के लिए उस पर हमले का जोखिम लेने की क्या जरूरत है? हिंडनबर्ग जैसों को खरीद लीजिए और फिर बड़ी फुर्सत के साथ उद्योग जगत से लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर अपनी सुविधा से चुन-चुनकर आरोप लगवाते रहिए। लोग केंकड़ों की तरह खुद ही मर मिटेंगे।

शिव कांत@shivkant

शेख हसीना को अपदस्थ कर उनके बांग्लादेश से पलायन में अहम भूमिका निभाने वाली सेना ने बांग्लादेशी राजनीति पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि शेख हसीना के निर्देश पर देश में लाकडाउन लगाने से मना करने वाली सेना ने तख्तापलट के बाद नागरिकों पर गोलीबारी से गुरेज नहीं किया।

ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

जनपथ

हिंदू के संहार पर चुप हैं सेक्युलर लोग,
पर गाजा के नाम पर चिल्लाने का रोग।
चिल्लाने का रोग कहां है आज ओवैसी,
निकले ना आवाज आज गाजा के जैसी!
जले बांग्लादेश आप चुप क्यों हैं बंधु,
राहुल को भी याद न आते हैं क्यों हिंदू!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 122

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75 निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक स्थापना वर्ष : 1948

स्वस्थ वातावरण एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। -टेड कुलोंगोस्की

हिंडनबर्ग का जिन्न एक बार फिर बाहर आया है। इस बार निशाना हैं सेबी प्रमुख। आरोप है कि वह पहले भी अदाणी की साख को धक्का पहुंचाने वाली रिपोर्ट इसलिए लाया, क्योंकि वह शेयरों में गिरावट पर दांव लगा रहा था। सेबी को चाहिए कि वह विधिवत जांच के जरिये चीजों को सामने लाकर रिपोर्ट का कायदे से खंडन करे।

हिंडनबर्ग का जिन्न

पिछले साल अदाणी समूह पर निशाना साध कर देश की राजनीति और शेयर बाजार में भूचाल लाने वाले अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अब शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख को निशाना बनाने से हिंडनबर्ग-अदाणी की कहानी में एक नया मोड़ आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी की वर्तमान प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर वित्तीय अनियमितताओं के कथित आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि उनकी अदाणी समूह से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदाणी समूह पर खाते में हेराफेरी और कंपनी में गड़बड़ी करने तथा शेयरों की कीमत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए थे। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही अदाणी समूह की कंपनियों के मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट आई थी और विपक्ष को भी इससे सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिला था कि सरकार के संरक्षण में अदाणी समूह फल-फूल रहा है। हालांकि हिंडनबर्ग, जो एक एलानिया शॉर्ट सेलर है, भी आरोपों से बच नहीं सका था, जिसके बारे में कहा गया कि अदाणी की साख को धक्का पहुंचाने वाली रिपोर्ट वह इसलिए लाया था, क्योंकि स्टॉक में जोरदार गिरावट पर दांव लगा रहा था। सेबी ने भी हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा था। हिंडनबर्ग पर आरोप लगा कि शॉर्ट सेलर होने के नाते उसने अदाणी के शेयरों में गिरावट पर दांव लगाकर काफी कमाया था। उस वक्त, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने तो इस मामले में किसी भी तरह की अनियमितता के सुबूत तो नहीं ही पाए थे, शीर्ष अदालत ने हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने या इस मामले को सीबीआई को सौंपने की जरूरत भी नहीं समझी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग कोई मीडिया समूह नहीं और न ही सार्वजनिक हित के उद्देश्य से गठित कोई निकाय। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि हिंडनबर्ग ने वर्ष 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है, और रिपोर्ट जारी होने के अगले ही दिन उन कंपनियों के शेयर औसतन 15 फीसदी तक टूट गए। जाहिर है, हिंडनबर्ग ने सेबी को निशाना बनाते हुए उस कहानी के दोहराने की आशंका बढ़ा दी है, जो पिछले साल की शुरुआत में अडानी के खिलाफ आई उसकी रिपोर्ट के बाद बाजार में दिखी थी। शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने इस बार बजाय एक कंपनी के सीधे सेबी पर सवाल खड़ा किया है। ऐसे में सभी तथ्यों को सामने लाते हुए विवाद का हमेशा के लिए पटाक्षेप किया जाना चाहिए।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है

शेख हसीना की आर्थिक नीतियों की बदौलत बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में एक स्थायित्व तो आया ही था, इससे घरेलू आत्मविश्वास भी बढ़ा था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में सिर्फ कपड़ा उद्योग पर निर्भरता से उपजी चुनौतियों से बांग्लादेश कैसे निपटेगा, यह देखने वाली बात होगी।

अनुप्रीता दास
द न्यूयॉर्क टाइम्स

बहुत दिन नहीं हुए, जब बांग्लादेश को आर्थिक चमत्कार की तरह देखा गया। मात्र कपड़ा और परिधान उद्योग पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर इसने अपना विकास किया, लाखों लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रसिद्धि और प्रशंसा दिलाई।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में आर्थिक सुधार 1970 के दशक में शुरू हुआ था और वस्त्र उद्योग दशकों से देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहा है। लेकिन वर्ष 2009 में सत्ता में आने वाली शेख हसीना ने सही मायनों में इस उद्योग का विकास किया और नए वैश्विक बाजार में इसका विस्तार किया, जिसने बांग्लादेश के विकास को काफी आगे बढ़ाया। सस्ते कपड़े वैश्विक परिधान के खुदरा विक्रेताओं, खासकर जारा एवं एच एंड एम जैसे फास्ट-फैशन ब्रांड्स के लिए काफी आकर्षक थे। साथ ही सस्ते परिधानों की बढ़ती मांग ने लाखों लोगों, खासकर महिलाओं के लिए आजीविका का सृजन किया और उनके जीवन स्तर को बदल दिया।

शेख हसीना ने बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च किया और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आश्वस्त किया कि वे अपनी मांगों की पूर्ति के लिए बांग्लादेश पर भरोसा कर सकती हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में बांग्लादेश संबंधी सलाहकार थॉमस कीन ने कहा, 'प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना बांग्लादेश में स्थिरता का एक ऐसा स्तर लेकर आईं, जो विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक था।' उन्होंने कहा कि अगर श्रमिकों की हड़ताल, बिजली कटौती या अन्य कारक इसे अविश्वसनीय बनाते, तो परिधान खरीदार बांग्लादेश को ऑर्डर नहीं देते। हसीना ने घरेलू आत्मविश्वास भी बढ़ाया। कीन कहते हैं कि जब उन्होंने सशस्त्र बल और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लिया, तब भी लोगों और उनकी सरकार के बीच लगभग एक तरह का समझौता था। उन्हें यह भरोसा था कि शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग ही आर्थिक वृद्धि और विकास लाएगी।

हसीना के नेतृत्व में एक दशक से भी अधिक समय तक अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ी, कुछ वर्षों में तो यह सात प्रतिशत से भी अधिक हो गई। परिधान निर्यात से देश को 80 प्रतिशत से अधिक आय हुई। लेकिन परिधान उद्योग पर अत्यधिक निर्भरता हसीना के लिए विनाशकारी साबित हुई। कोरोना महामारी के कारण वस्त्र और परिधान की वैश्विक मांग घट गई। साथ ही, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और यूक्रेन पर रूस के युद्ध ने आयातित खाद्य और ईंधन की कीमतों में तेजी से वृद्धि की। अर्थव्यवस्था में कम विविधता के चलते बांग्लादेश बिलों का भुगतान करने के लिए अन्य उद्योगों से पर्याप्त राजस्व हासिल करने में असमर्थ था। इसके अलावा, महंगाई बढ़ने पर उसे नियंत्रित करने में हसीना सरकार विफल रही। अपनी कमजोर मुद्रा को सहारा देने की कोशिश में बांग्लादेश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च कर दिया, जो इतना कम हो गया कि 2022 में उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेना पड़ा।

महामारी के बाद जब परिधान निर्यात में उछाल आया, तो बांग्लादेश अपनी अल्पकालिक समस्याओं में फंस चुका था। लचर नौकरशाही और नागरिकों की कर चुकाने की अनिच्छा के कारण बांग्लादेश बहुत कम कर राजस्व इकट्ठा कर पाता है। बांग्लादेश की विकास दर अब भी ऊंची है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुल्क में असमान विकास हुआ है और आय असमानता बहुत ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बांग्लादेश के कार्यकारी निदेशक इफ्तिखार जमान ने कहा कि लोगों को यह एहसास हुआ कि कागज पर विकास की कहानी वास्तविकता से मेल नहीं खाती, जिससे सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ा। हसीना के लिए शायद सबसे बड़ी दीर्घकालिक समस्या यह थी कि उनकी सरकार परिधान व्यवसाय पर निर्भरता के कारण नई नौकरियां पैदा करने में असमर्थ रही। देश की बड़ी कामकाजी आबादी के लिए पर्याप्त नई या बेहतर वेतन वाली नौकरियां नहीं हैं। पिछले महीने उस संचित हताशा को एक रास्ता मिल गया, जब सरकारी नौकरियों के लिए कोटा व्यवस्था को खत्म करने की मांग शुरू हुई। आंदोलन की आड़ में देश के कट्टरपंथी और विपक्षी दल भी जोर लगा रहे थे, हसीना ने प्रदर्शन को दबाने के लिए सशस्त्र बलों को भेजा, तो लोगों का गुस्सा और उबल पड़ा।

हसीना की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को उछाल दिया और एक आम बांग्लादेशी को आत्मविश्वास दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर शेख हसीना को व्यापक जन-असंतोष का सामना करना पड़ा है, तो यह जरूर विश्लेषण का विषय है। खासकर युवाओं का असंतोष देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बताया गया। कुछ अर्थशास्त्री इसके पीछे खराब नीतिगत निर्णयों को वजह बता रहे हैं। हसीना के इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी छात्रों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता और माइक्रोफाइनेंस के अग्रणी मुहम्मद यूनुस को लाया है। लेकिन उनके लिए भी राह आसान साबित नहीं होने वाली। यूनुस को सबसे पहले बांग्लादेश को शांति व्यवस्था बहाल करनी होगी और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना होगा। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले रोकने होंगे। लंबे समय तक बांग्लादेश को व्यापक आर्थिक तनावों को झेलना होगा, जिसने प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य किया था।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अंतरिम सरकार कब तक सत्ता में रहेगी और इसका व्यापक जनादेश कितना होगा। लेकिन कनाडा स्थित बाल्सिली स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के फेलो साद हम्मादी ने कहा कि सरकार और यूनुस से 'लोगों को न्याय दिलाने, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत करने, कानून का शासन और एक पारदर्शी व जवाबदेह सरकार स्थापित करने जैसी कई आकांक्षाएं हैं।' उन्होंने ईमेल के जरिये बताया कि 'अंतरिम सरकार के लिए ये चुनौतियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए नेताओं का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिये हो। पूरे प्रशासन में संस्थागत सुधारों की जरूरत होगी।' अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेते हुए 84 वर्षीय यूनुस ने शांति की अपील की और राष्ट्र से व्यवस्था बहाल करने के साथ हिंसा से दूर रहने की अपील की। एक अर्थशास्त्री होने के नाते उनसे बाजार के अनुकूल सुधार की उम्मीद की जा रही है।

©The New York Times 2024

जीवन धारा

फ्योदोर दोस्तोवस्की

आप प्रेम में आगे बढ़ेंगे, तो ईश्वर की वास्तविकता और आत्मा की अमरता के बारे में अधिक आश्वस्त होंगे। यदि आप खुद से या दूसरे से प्रेम करते हैं, तब कोई संदेह आपकी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाएगा।

प्रेम के अनमोल खजाने से दुनिया खरीद सकते हैं

मानव जाति का अस्तित्व सिर्फ जीवित रहने में नहीं है, बल्कि जीने के लिए कुछ खोजने में है। मुझे जीवन की लालसा है और मैं तर्क के बावजूद जीता रहता हूं। हालांकि मैं ब्रह्मांड के कर्म में विश्वास नहीं करता, फिर भी मुझे वसंत में खिलने वाली छोटी पत्तियां बहुत पसंद हैं। मुझे नीला आकाश पसंद है। मुझे कुछ लोग पसंद हैं, जिन्हें मैं कभी-कभी बिना किसी कारण प्यार कर लेता हूं। यह सब बुद्धि या तर्क की बात नहीं है, यह सब अपने से प्यार करना है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के अलावा और कुछ नहीं। जीवन खोज की सतत और शाश्वत प्रक्रिया है, स्वयं खोज नहीं है। इसलिए जीवन को उसके अर्थ से भी अधिक प्यार करना चाहिए।

मनुष्य एक रहस्य है। इस रहस्य को सुलझाना जरूरी है। अगर आप इसे सुलझाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, तो यह मत कहिए कि आपने समय बर्बाद कर डाला। मैं उस रहस्य का अध्ययन कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक इन्सान बनना चाहता हूं। मैं मानव जाति से प्यार करता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जितना मैं मानव जाति से प्यार करता हूं, उतना ही मैं विशेष रूप से मनुष्य से प्यार करता हूं। इन्सान बनने की पहली शर्त है कि खुद से झूठ कभी मत बोलो। जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है और खुद के झूठ को सुनता है, वह इस हद तक पहुंच जाता है कि वह अपने भीतर या आसपास के सत्य को पहचान तक नहीं पाता। ऐसे में, वह जीवन के रहस्य को कैसे समझ पाएगा! झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी सारा सम्मान खो देता है। और फिर सम्मान न होने पर वह प्यार करना भी बंद कर देता है।

अक्सर लोग स्वर्ग-नरक के बारे में बात करते हैं। मेरा मानना है कि जीवन स्वर्ग है, और हम सब इसी स्वर्ग में हैं, लेकिन इसे देखने से इन्कार करते हैं। नरक तो प्रेम न कर पाने की पीड़ा है। इसलिए प्रेम के महत्व को पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे-जैसे आप प्रेम में आगे बढ़ेंगे, ईश्वर की वास्तविकता और आत्मा की अमरता के बारे में अधिक आश्वस्त होते जाएंगे। यदि आप खुद से या दूसरे से प्रेम करते हैं, और उस प्रेम में पूर्ण आत्म-विस्मृति प्राप्त कर लेते हैं, तो आप बिना किसी संदेह के विश्वास करने लगेंगे। तब कोई भी संदेह आपकी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाएगा।

प्रेम एक शिक्षक है, लेकिन प्रेम को प्राप्त करना उतना आसान भी नहीं है। किसी से प्यार करने का मतलब है, उसे वैसे देखना जैसा उसे ईश्वर ने बनाया है। प्यार एक ऐसा अनमोल खजाना है, जिससे आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। इसलिए यह बहुत महंगा भी है और हर कोई इसे पा ले, यह भी आसान नहीं। इसलिए जिससे भी प्रेम करें, किसी पल या सीमित समय के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। यदि आप ऐसा करने का संकल्प करते हैं, तो हमेशा के लिए पूरी दुनिया को वश में करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

सूरज बनने का प्रयास करें

सूत्र

प्रेमपूर्ण विनम्रता किसी को भी जीतने का अद्भुत हथियार है। सम्मान भी प्रेम के साथ ही जुड़ा है। यदि आप दूसरों से सम्मान पाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है खुद का सम्मान करना। अगर दुनिया पर विजय हासिल करना चाहते हैं, तो पहले खुद पर विजय पाएं। सूरज बनने का प्रयास करें, ताकि सब आपकी ओर देखें।

दूसरा पहलू

चीन ने दावा किया है कि मानव इतिहास में पहली बार उसे चांद पर जो मिट्टी मिली है, उसमें अलग तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं।

शुरू हो गई चांद पर खेती की तैयारी

चीन जहां चांद पर खेती करने की योजना बना रहा है, वहीं अमेरिका ने चंद्रमा की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का तरीका खोज लिया है। नासा का आर्टेमिस-3 चंद्रमा पर पौधों की खेती का पता लगाएगा। पिछले दिनों चीन चांद से मिट्टी के नमूने लेकर आया है। उसका कहना है कि मिट्टी के नमूने में पानी होने का संकेत मिला है। भारत यह बात वर्षों से कह रहा है। भारत के चंद्रयान-1 ने 15 साल पहले ही संकेत दिए थे कि चांद की मिट्टी में पानी है। चीन अब वहां फल उगाने से लेकर खेती करने तक के सपने बुन रहा है। यह मिट्टी चांद के उस हिस्से में है, जिधर अंधेरा रहता है। गौरतलब है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 उतारने वाला पहला देश है।

निरंकार सिंह

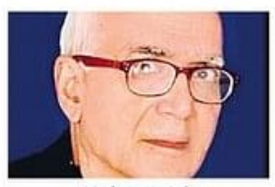

भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 ने 15 साल पहले ही संकेत दिए थे कि चांद की मिट्टी में पानी है। लेकिन चीन अब खेती करने के सपने बुन रहा है।

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ऐसे जीवाणुओं को वहां भेजा है, जो महत्वपूर्ण पौध पोषक तत्व फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं।

चीन ने दावा किया है कि मानव इतिहास में पहली बार उसे चांद पर जो मिट्टी मिली है, उसमें अलग तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं। इस दौड़ में अमेरिका, रूस, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, चीन, भारत और जापान जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन चंद्रमा के जिस हिस्से पर पानी की संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर होड़ केवल भारत और चीन के बीच है। भारत ने चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में अपना रोवर भेजा था, जिसने एक हफ्ते तक चांद की मिट्टी से कई नमूने हासिल किए, जिससे वहां पानी की मौजूदगी का पता चला था।

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ऐसे जीवाणुओं को वहां भेजा है, जो महत्वपूर्ण पौध पोषक तत्व फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं। इसके परीक्षण के लिए दो साल बाद नासा आर्टेमिस-3 को चांद पर भेजेगा। एक विशेष पेलोड चंद्र वातावरण में पौधों की खेती की अवधारणा का पता लगाएगा। अमेरिकी नेशनल एयरोनॉटिक्स ऐंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्टेमिस-3 के दौरान चंद्रमा की सतह पर तैनात करने के लिए कुछ उपकरणों को चुना है, जिनमें से एक कृषि वनस्पतियों पर चंद्र प्रभाव है। यह अंतरिक्ष की फसलों पर चंद्र सतह के पर्यावरण प्रभावों की जांच करेगा।

वर्ष 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 12 थिम्बल आकार के कंटेनरों में अरेबिडोप्सिस थालियाना नामक एक फूलदार खरपतवार उगाया, जिनमें से प्रत्येक में आधी सदी से भी अधिक समय पहले नासा मिशनों के दौरान एकत्र की गई वास्तविक चंद्रमा मिट्टी का एक ग्राम था।

आंकड़े

सड़क नेटवर्क

भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क यातायात नेटवर्क है। भारत ने इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है।

अमेरिका	65.86
भारत	63.71
चीन	52.00
ब्राजील	20.00
रूस	12.83

आंकड़े लाख किलोमीटर में। | स्रोत : CIA

एकादशी व्रत के प्रभाव से अयोध्यावासी यमपुरी नहीं जाते थे। रुकमांग का व्रत तुड़वाने के लिए ब्रह्मा जी ने माया से मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री बना दी।

रुकमांग ने नहीं तोड़ा एकादशी व्रत

अंतर्यात्रा
संकलित

अयोध्या के राजा रुकमांग एकादशी का व्रत करते थे। उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि बच्चों, अतिवृद्धों और गर्भवतियों को छोड़कर सभी के लिए एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। व्रत के प्रभाव से अयोध्यावासी यमपुरी नहीं जाते थे। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा 'इस तरह तो हमारा यमलोक सूना हो जाएगा। ब्रह्मा ने राजा का व्रत तुड़वाने के लिए अपनी माया से मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री बना दी।

इधर, राजा रुकमांग अपने बेटे धर्मांगद को राज्य सौंप कर हिमालय की ओर चले गए। इसी बीच जंगल में मोहिनी ने राजा से भेंट की। राजा मोहिनी पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने शर्त रखी, 'मैं आपसे तभी विवाह करूंगी, जब आप मेरी हर बात मानेंगे।' राजा ने वचन दे दिया और मोहिनी से विवाह कर लिया। रुकमांग ने जब एकादशी का व्रत किया, तो मोहिनी ने कहा कि महाराज आपको मेरी बात माननी होगी। उन्होंने कहा क्या बात है? मोहिनी बोली, 'आप एकादशी का व्रत करना छोड़ दें।' राजा बोले, 'कोई और बात मनवा लो, एकादशी व्रत छोड़ने के लिए बाध्य न करो।' मोहिनी बोली, ठीक है, तो अपने इकलौते बेटे धर्मांगद का सिर काटकर मुझे दे दीजिए। राजा सोच में पड़ गए, लेकिन धर्मांगद ने कहा, 'पिता जी, आपके धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।' रुकमांग जैसे ही बेटे का सिर काटने को तैयार हुए, तो भगवान प्रकट हो गए और उनके पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 04 जून, 1957

अमेरिका बगदाद संधि की सैनिक समिति में शामिल

अमरीका बगदाद संधि की सैनिक समिति में शामिल

बगदाद संधि समिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने कहा कि संधि का उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। बैठक में अमेरिका ने भी हिस्सा लिया।

सिर्फ जीडीपी ही काफी नहीं

सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) का विचार जीडीपी के साथ मिलकर आर्थिक प्रदर्शन का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।

वीर सिंह | पर्यावरण

विश्व के लगभग सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मानकों से आंकते हैं। भूटान सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस) को अपना सबसे बड़ा आधार मानता है। लेकिन 19 जुलाई को उत्तराखंड ने अपनी अर्थव्यवस्था के आकलन के लिए जिस मानक की घोषणा की, वह अद्वितीय है। सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) को अपनी अर्थव्यवस्था का मानक मानने वाला यह हिमालयी राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है, जो दुनिया भर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। हालांकि ऐसी आर्थिक विकास की नीति कोस्टा रिका तथा कुछ अन्य देशों में आंशिक रूप से प्रभावी है। इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए वर्षों से प्रयासरत पर्यावरणविद डॉ अनिल जोशी और उत्तराखंड प्रशासन की यह पहल स्वागत योग्य है, परंतु इस पर इतनी चर्चा नहीं हो रही, जितनी होनी चाहिए।

जीडीपी आर्थिक प्रदर्शन का व्यापक रूप से स्वीकृत माप है, परंतु आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी पर्यावरणीय लागतों और लाभों को ध्यान में रखते हुए यह आर्थिकी के वास्तविक आकलन की एक कमजोर कड़ी है। जबकि सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) की अवधारणा मानव सहित सभी जीवों के कल्याण और अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के योगदान को मापने के सार्थक दृष्टिकोण के रूप में उभरी है।

महात्मा गांधी ने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली, न कि लालच की पूर्ति करने वाली, आर्थिकी का दर्शन दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने 'पारिस्थितिकी ही स्थायी आर्थिकी है' का सिद्धांत दिया था।

सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) एक अभिनव मानदंड है, जिसे प्रकृति द्वारा प्रदान की गई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को मापने और महत्व देने के लिए तैयार किया गया है। जीईपी का लक्ष्य इन विविध योगदानों को एकल मौद्रिक मूल्य में समाहित करना है, जो आर्थिक और सामाजिक कल्याण के समर्थन में प्राकृतिक पूंजी के वास्तविक मूल्य को दर्शाता है। जीईपी मूल्यांकन पर्यावरणीय कारकों को शामिल करके आर्थिक प्रदर्शन का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। प्रकृति के नियमों के साथ पूर्ण राजनीतिक निष्ठा से जीईपी को अपनाने से सतत राष्ट्रीय विकास प्रथाओं को प्रोत्साहन मिल सकता है। यह बदलाव अधिक संतुलित और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों को जन्म दे सकता है, जो आर्थिक विकास का तालमेल पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ बनाए रखती है।

वैसे जीईपी की अवधारणा भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने के अनुरूप भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यतः इसकी गणना में कई चरण और पद्धतियां समाहित हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की जटिलता और विविधता को दर्शाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख दृष्टिकोण हैं : बाजार-आधारित मूल्यांकन, प्रतिस्थापन लागत विधि, आकस्मिक मूल्यांकन और लाभ अंतरण। जीईपी का उद्देश्य एक ही है-पारिस्थितिकी-केंद्रित सतत सामजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विकास। उत्तराखंड में जो जीईपी लागू किया जाना है, उसमें पर्यावरण के चार घटकों (जल, वायु, वन और मिट्टी) संबंधी सूचकांक शामिल हैं। आर्थिक विकास की नीतियों, योजनाओं और प्रक्रियाओं में पर्यावरण के इन घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित रखना किसी भी प्रशासन का नैतिक दायित्व है और इसे मूर्त रूप देने में उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण-नैतिकता के प्रदर्शन का साहस दिखाया है।

जीईपी को कार्रवाई योग्य नीतियों और निर्णयों में बदलने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है। सरकारों और संगठनों को अपनी योजना प्रक्रियाओं में जीईपी को एकीकृत करने और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक प्रोत्साहन में तालमेल बनाना चाहिए। उत्तराखंड में एक जीईपी सेल की स्थापना की बात कही गई है, जो जीईपी के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। जीईपी को नीति आयोग के साथ जोड़ने और इसे पूरे देश के लिए लागू करने की आवश्यकता है। जीईपी आर्थिक प्रगति और स्थिरता पर पुनर्विचार करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान किए गए असंख्य लाभों को महत्व देकर जीईपी आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच अंतर को पाटता है। इसमें नीतियों को नया आकार देने, टिकाऊ प्रथाओं का मार्गदर्शन करने और मनुष्यों और प्रकृति के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। जीईपी को अपनाना न केवल एक आर्थिक अनिवार्यता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए ग्रह की सुरक्षा का एक नैतिक दायित्व भी है।

edit@amarujala.com

कल्पमेधा

अहंभाव से दिया गया दान दीनता और विषमता पोसने और बढ़ाने वाला है। धर्म की अकिंचन भावना से दिया गया दान प्रीति और सद्भाव बढ़ाएगा।

– जैनेंद्रकुमार

बचत की बुनियाद

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता इस बात से भी चलता है कि उसके बैंकों का कारोबार कैसा है। बैंकों का कारोबार मुख्य रूप से लोगों से जमा आकर्षित करने और उसे कर्ज के रूप में देकर उससे ब्याज कमाने से चलता है। मगर इस समय भारतीय बैंकों में जमा और कर्ज का अंतर काफी बढ़ गया है। इसे लेकर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की चिंता स्वाभाविक है। पिछले दिनों मौद्रिक समीक्षा के वक्त आरबीआइ के गवर्नर ने बैंकों से इस अंतर को पाटने के लिए विशेष योजनाएं चलाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि बैंक ब्याज दरें निर्धारित करने को स्वतंत्र हैं। यही बात केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआइ गवर्नर के साथ बैठक में कही। वित्तमंत्री ने कहा कि बैंक अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान दें। लोगों से जमा आकर्षित करने के लिए वे आकर्षक योजनाएं चला सकते हैं। दरअसल, सार्वजनिक बैंक निवेश की कमी के चलते गंभीर परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। कायदे से बैंक अपनी ब्याज दरें रेपो दरों से आधा से लेकर एक फीसद तक ऊपर रख सकते हैं। मगर इस मामले में भी उन्हें कुछ राहत दी गई है, फिर भी उनके पास अपेक्षित जमा नहीं आ पा रहा।

इसकी वजहें साफ हैं। पिछले कुछ वर्षों से लोगों की आमदनी लगातार कम हुई है। पहले जीएसटी की वजह से छोटे कारोबारियों पर बुरा असर पड़ा, फिर कोरोनाकाल में पूर्णबंदी के बाद बहुत सारे कारोबार बंद हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। जिन लोगों के पास नौकरियां हैं भी, उनके वेतन में तुलनात्मक रूप से काफी कम बढ़ोतरी हुई है, जबकि महंगाई काफी बढ़ गई है। इस तरह बहुत सारे लोगों के पास बचत के लिए पैसे हैं ही नहीं कि उन्हें वे बैंकों में रखें। बल्कि इसका उलट यह हुआ है कि छोटे-छोटे काम के लिए भी लोगों को कर्ज लेने पड़ रहे हैं। कर्ज पर ब्याज की भरपाई करना भी बहुत सारे लोगों के लिए कठिन बना हुआ है। बचत के बारे में लोग तब सोचते हैं, जब उनके पास जरूरी खर्चों से अधिक आमदनी होती है। मगर सरकार लगातार इस हकीकत पर पर्दा डालने का प्रयास करती रही है कि रोजगार और आमदनी के स्रोत लगातार घटे हैं। कुछ दिनों पहले आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने खुद दोहराया था कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, गरीबी लगातार कम हो रही है। अगर सचमुच ऐसा होता, तो सरकार को इस तरह बचत बढ़ाने को लेकर चिंतित न होना पड़ता।

बैंकों में लोगों द्वारा जमा बचत से राष्ट्रीय बचत बनती है। जिस देश के पास राष्ट्रीय बचत जितनी अधिक होती है, उसे अपनी विकास परियोजनाएं चलाने में उतनी ही आसानी होती है। मगर इस वक्त जब चालू खाते में जमा की दर चिंताजनक देखी जा रही है, तो लंबे समय के लिए चलाई जाने वाली बचत योजनाओं में निवेश को लेकर क्या ही दावा किया जा सकता है। अगर बैंक आकर्षक योजनाएं लेकर आएंगे और उन पर अधिक ब्याज की पेशकश भी करेंगे, तो कितने लोग आकर्षित हो पाएंगे, कहना कठिन है। सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज देने की बाध्यता और उनके वापस न लौट पाने, फिर बड़े पैमाने पर कर्जमाफी के चलते भी सार्वजिनक बैंकों के जमा और कर्ज में अंतर आया है। ऐसे में, सरकार बुनियादी पहलुओं पर काम करने के बजाय बैंकों पर दबाव बना कर शायद ही इस समस्या से पार पा सकेगी।

सुरक्षा पर सवाल

अस्पतालों में महिला चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर अनेक बार सवाल उठते रहे हैं। खासकर रात के वक्त उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध की जरूरत रेखांकित की जाती है। मगर इस तकाजे पर गंभीरता से ध्यान कम ही दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि सेवा के समय अक्सर महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ जाती हैं। कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कालेज में प्रशिक्षु चिकित्सक की हत्या इसकी एक कड़ी है। प्राथमिक जांच से पता चला है कि उस चिकित्सक का बलात्कार किया गया और फिर उसे मार डाला गया। उसका शव अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में पाया गया। शव परीक्षा में उसके शरीर पर जगह-जगह गंभीर चोटें पाई गई हैं। हालांकि अस्पताल के कैमरों से मिली तस्वीरों के आधार पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर खासा सख्त रुख जाहिर किया है, मगर इस घटना को लेकर अस्पताल कर्मियों और चिकित्सा छात्रों का रोष कम नहीं हो रहा।

घटना की जांच के लिए सरकार ने सात सदस्यों का विशेष जांच दल नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर पीड़िता के परिजन चाहें तो वे इसकी सीबीआइ जांच के आदेश भी देने को तैयार हैं। मगर सवाल है कि आखिर इस तरह का साहस किसी में आया कैसे, कि उसमें कानून का जरा भी भय पैदा क्यों नहीं हुआ। अगर कानून-व्यवस्था का खौफ होता और अस्पताल प्रशासन मुस्तैद रहता, वहां सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होते, तो ऐसी वारदात होने ही न पाती। अच्छी बात है कि सरकार इस मामले पर किसी तरह की लीपापोती करने का प्रयास नहीं कर रही है, मगर सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वहां इतनी लचर व्यवस्था क्यों है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। यह केवल किसी अस्पताल तक सीमित समस्या नहीं है। सामान्य रूप से भी घर से बाहर निकलते वक्त महिलाएं सशंकित रहती हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी न घट जाए। अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सचमुच महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें इस दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए।

आर्थिक विकास पर अनुत्तरित प्रश्न

हमने तरक्की के पायदान तो कई चढ़ लिए। पांचवीं आर्थिक महाशक्ति से दो-तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहे हैं, लेकिन इसका पूरा भरोसा निजी क्षेत्र के योगदान पर ही क्यों किया जा रहा है?

सुरेश सेठ

देश 2047 में आजादी की सौवीं वर्षगांठ मनाने की ओर बढ़ रहा है। पिछले दिनों जब नए माहौल में एक नई आर्थिक विकास यात्रा शुरू करने के वादों के साथ निर्माण यात्रा शुरू हुई, तो उसकी घोषणाओं में बहुत-सी ऐसी अधूरी बातें रह गईं, जिनका समाधान इतने दशक में भी नहीं मिल पाया है। सरकार की नई पारी की शुरुआत करते हुए घोषणा की गई कि देश में एक अखिल भारतीय सहकारी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कतार के हर आखिरी आदमी को भाग लेने का पूरा मौका मिलेगा। बेशक, सहकारिता की बातें बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इसके नाम पर प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों से लेकर केंद्रीय सहकारी बैंक भी बने हैं, लेकिन नतीजा उल्लेखनीय नहीं रहा। अब भी जब उम्मीद की जा रही थी कि सहकारिता का एक नया माहौल होगा, तो फिर भ्रष्टाचार और सहकारी योजनाओं के अधूरेपन के सत्य सामने आने लगे।

पंजाब के विभिन्न इलाकों में सहकारी 'मिल्क प्लांट' खूब कोलाहल के साथ शुरू किए गए थे, वे अब करोड़ों रुपए के घाटे में क्यों चल रहे हैं। देश भर में नए आंदोलन के नाम पर सहकारी बैंकों की जो इकाइयां सामने आईं, पिछले दिनों वहां लेनदेन बंद हो गया, क्योंकि उपकरण सही नहीं थे। सर्वर काम नहीं कर रहा था और हिसाब-किताब पूरा नहीं था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा के साथ हमने अपने संविधान में आर्थिक प्रगति की सौगंध खाई थी। वादा था कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र जहां आर्थिक तरक्की की ओर देखेगा, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र जनकल्याण की परवाह करेगा, क्योंकि उसके सामने हर निवेश में लाभ कमाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। हमने तरक्की के पायदान तो कई चढ़ लिए। पांचवीं आर्थिक महाशक्ति से दो-तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहे हैं, लेकिन इसका पूरा भरोसा निजी क्षेत्र के योगदान पर ही क्यों किया जा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र उपेक्षित हो रहा है, क्योंकि उसमें नौकरशाही और लालफीताशाही के बोलबाले पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार को शून्य स्तर पर लाने की बात छोड़िए, यहां सब चलता है, की संस्कृति हावी होने लगी। इधर संसद में नए आम बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष से ठोस विचार-विमर्श की उम्मीद की जा रही थी, ताकि नई शासन पारी का नया वर्ष एक सार्थक शुरुआत बन सके। मगर इस पर राजनीति हावी होने लगी। आर्थिक समस्याओं पर चिंतन की जगह जातिवाद पर टीका-टिप्पणियों ने पूरे संवाद का मिजाज बिगाड़ दिया। कुछ सवाल थे, जो पूछे जाने चाहिए थे। देश के कर्णधारों से लेकर देश के विचारवान आर्थिक चिंतकों तक इन प्रश्नों के जवाब तलाश करने चाहिए। पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि हम 'जय जवान, जय किसान' के साथ 'जय अनुसंधान' का नारा लगाते हैं, लेकिन इस अनुसंधान पर पर्याप्त खर्च का प्रावधान कहां है। हमारे कृषिप्रधान देश में आज भी आधे से थोड़ी कम जनसंख्या खेतीबाड़ी में लगी हुई है, लेकिन उसका योगदान सकल घरेलू आय में केवल पंद्रह फीसद क्यों है?

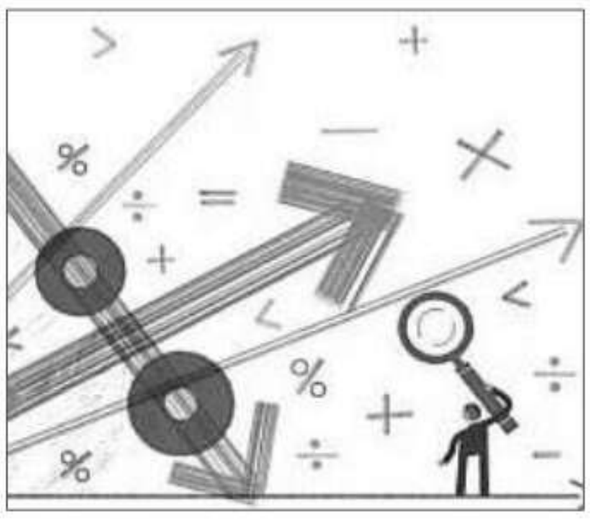

भारत के वित्तीय कर्णधारों ने भी कहा है कि भारत का विकास करना है तो कृषि में उत्पादकता और वक्त के मुताबिक बदलाव की अनुकूलता बढ़नी चाहिए। आज भी खेतीबाड़ी होती है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था में उनके

अंतिम उत्पाद बनाने के छोटे कारखाने क्यों नहीं उभर सके? ये उभर आते तो लोगों को रोजगार मिलता। इस युवा देश की आधी जनसंख्या तो काम तलाशते युवाओं की है, जिन्हें अपनी ग्रामीण जड़ों के माहौल में काम नहीं मिलता और वे समुद्र पार अपने लिए रोजगार तलाशने पर मजबूर होते, या

> **नया आम बजट आया, लेकिन कृषि शोध की राशि बढ़ी नहीं। आंकड़ों के मुताबिक कृषि विकास दर पिछले वर्ष 4.7 फीसद थी, इस वर्ष घटकर 1.4 फीसद रह गई। यहां शोध राशि और कृषि जीडीपी का अनुपात बढ़ना चाहिए था, लेकिन 2008-09 में जो अनुपात 0.75 फीसद था, वह 2022-23 में घटकर 0.43 फीसद रह गया। कृषि अर्थशास्त्री तो समझाते रहे कि शोध बढ़ाओ, एक रुपए से दस रुपए प्राप्त होंगे। पर्यावरण अनुकूलित बीज लाओ, नई सिंचाई और बिजाई तकनीकों पर काम करो, लेकिन वह नहीं हुआ। पचास फीसद आबादी अब भी खेतीबाड़ी में लगी है और उत्पादकता दुनिया में औसत से काफी कम है।**

फिर सरकारी अनुकंपा यानी रेवड़ियां बांटने की घोषणाओं का इंतजार करते हैं। क्यों बड़े पैमाने पर ग्रामीण समाज में शोध कार्य शुरू नहीं किए गए?

नया आम बजट आया, लेकिन कृषि शोध की राशि बढ़ी नहीं। आंकड़ों के मुताबिक कृषि विकास दर पिछले वर्ष 4.7 फीसद थी, इस वर्ष घटकर 1.4 फीसद रह गई। यहां शोध राशि और कृषि जीडीपी का अनुपात बढ़ना चाहिए था, लेकिन 2008-09 में जो अनुपात 0.75 फीसद था, वह 2022-23 में घटकर 0.43 फीसद रह गया। कृषि अर्थशास्त्री तो समझाते रहे कि शोध बढ़ाओ, एक रुपए से दस रुपए प्राप्त होंगे। पर्यावरण अनुकूलित बीज लाओ, नई सिंचाई और बिजाई तकनीकों पर काम करो, लेकिन वह नहीं हुआ। पचास फीसद आबादी अब भी खेतीबाड़ी में लगी है और उत्पादकता दुनिया में औसत से काफी कम है। क्या इसकी चर्चा संसद या नीति आयोग के मंच पर नहीं होनी चाहिए थी?

दुर्भाग्य से नीति आयोग की बैठक राज्यों को धनराशि के आबंटन के नाम पर राजनीति का शिकार हो गई। संसद में तो इस सवाल को सही ढंग से उठाया ही नहीं गया, सिवाय इस बात के कि दो चहेते राज्यों को धन आबंटन कर दिया, शेष रीते हाथ रह गए। सत्तापक्ष की ओर से इस बावेले को बार-बार रद्द किया गया। क्या कारण है कि संसद में जो बहस बहुत ठोस और सार्थक होनी चाहिए थी, उनमें महंगाई पर नियंत्रण और नौकरी के लिए एक नई रोजगार नीति की घोषणा नहीं हुई? जहां तक महंगाई पर नियंत्रण का संबंध है, इस समय देश की मौद्रिक नीति इस दोराहे पर ठिठकी हुई है कि क्या उसे कीमत नियंत्रण उपायों का सहारा लेते हुए अपनी मौजूदा नीति पर ही ठहरे रहना चाहिए या कि देश विकास की नीति का विकल्प अपनाकर अपनी साख नीति को उदार बनाकर देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना चाहिए।

बार-बार कहा जाता है कि विश्व महामंदी का सामना कर रहा है। भारत ने बाहुबली, आर्थिक रूप से संपन्न देशों की विकास दर को पछाड़ दिया है, लेकिन हम कुछ बातों का पूरी तरह से ध्यान क्यों नहीं कर पा रहे? महंगाई पर नियंत्रण हम नहीं कर पा रहे और हमने महंगाई के सूचकांकों की परिभाषा को अपनी सुविधानुसार बदल दिया है। महंगाई के सूचकांकों की नई रपटें अब खाद्य वस्तुओं की कीमतों को उपेक्षित करके घोषित हो रही हैं, क्योंकि लक्ष्य यही है कि किसी प्रकार कीमत की खुदरा दर को सुरक्षित चार फीसद तक लाया जाए। मगर एक बड़े सत्य की चर्चा क्यों नहीं हुई कि पिछले दिनों में थोक कीमत की दर, जो शून्य से नीचे चली गई थी, वह अचानक शून्य को पार करके ऊपर आ गई?

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मौसम के तेवर के बदलने से कुलांचे भरकर आम आदमी की जिंदगी को दूभर क्यों करती हैं? उससे भी बड़ी बात कि जब थोक कीमतों के सूचकांक गिरावट दिखा रहे हैं, तो परचून कीमत सूचकांक उनका अनुसरण क्यों नहीं करते? उनका विरोधी तेवर क्यों बना रहता है? क्या इसका कारण खुदरा व्यापारियों पर कमी के मनोविज्ञान का सहारा लेकर चोरबाजारी करना है? अगर चोरबाजारी है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इनकी चिंता तो होनी चाहिए?

इसके अलावा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर रियायतों और छूटों की घोषणा हो जाती है, लेकिन घरेलू बचत और मध्यवर्गीय बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नजर आने वाले कदम क्यों नहीं उठाए जाते? क्यों ऐसी बचतों पर कर बढ़ता हुआ नजर आता है, चाहे वह मामूली रूप से ही हो। यह आधा-अधूरा चिंतन देश के आर्थिक विकास की एक उदीयमान और संपूर्ण तस्वीर पेश नहीं करता। इसकी चिंता देश के विचारवान लोगों को करनी ही चाहिए।

खुशी और आजादी

मेघा राठी

विद्वान और दार्शनिक कहते हैं कि सच्ची खुशी पाने के लिए व्यक्ति का खुद के साथ होना जरूरी है। किसी भी बाह्य आलंबन द्वारा प्राप्त प्रसन्नता अस्थायी होती है, क्योंकि जैसे ही वे कारण दूर होने लगते हैं, प्रसन्नता उदासी या अवसाद में बदलने लगती है। यह सत्य भी है, लेकिन अपने आप में प्रसन्न रहने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है 'स्वतंत्रता', जो आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक, तीनों रूपों में प्राप्त हो। खुद को खुश रखने के प्रयास में अगर किसी को इन तीनों रूपों में स्वतंत्रता न प्राप्त हो तो व्यक्ति के मस्तिष्क पर कहीं न कहीं दबाव बना रहता है, जो उसके खुश रहने में बाधक बनता है। फिर वास्तव में खुश होने की प्रक्रिया में बाधा आती है। यानी खुशी बाधित होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज के अपने पारंपरिक मापदंड और अपेक्षाएं होती हैं, जो व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों और कार्यों पर दबाव डालती हैं।

आमतौर पर लोगों की सोच एक तरह से पहले से निश्चित परिपाटी के अनुकूल तय होती है और चलती है। अगर व्यक्ति के कार्य और विचार उसके विपरीत हो रहे हों, भले ही उनके जरिए समाज का कोई अहित नहीं हो रहा हो, तब भी उनका परंपरा के अनुरूप न होना ही लोगों को खटकने लगता है और वे उसका विरोध करने लगते हैं या फिर व्यक्ति पर परिपाटी और परंपरा के अनुरूप होने के लिए वक्त-बेवक्त समझाइश, दबाव डाला जाने लगता है। अलग-अलग प्रकार से ताने दिए जाने लगते हैं, जिससे व्यक्ति पर मानसिक दबाव बनता है। इस तरह के हालात में भी मनुष्य को अपनी आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखने में कठिनाई होती है। अगर दबाव बनाने वाले लोग परिवार के सदस्य हों, तब स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को उनकी खुशी और उम्मीदों का भी सम्मान करना पड़ता है, ताकि उनके संबंध मधुर बने रहें। संबंधों में मधुरता कायम रखने के लिए न जाने कितने लोगों को क्या-क्या छोड़ना पड़ता है। हालांकि अपनी आंतरिक प्रसन्नता के लिए व्यक्ति का अपने प्रियजनों की उपेक्षा कर देना उसका स्वार्थ कहलाएगा, स्वतंत्रता नहीं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये कारण बाधा तो बनते ही हैं।

साथ ही व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से परनिर्भर है, तब भी वह इसे प्रसन्नता की राह में बाधक पाएगा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने किसी भी निर्णय के लिए निवेश करने वाली वित्तीय आवश्यकता खुद से ही पूर्ण कर सकता है। जब व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं की चिंता नहीं होती, तो वह मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट रहता है, जिससे उसका संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।

दुनिया मेरे आगे

> **जब व्यक्ति का स्वयं पर ही विश्वास नहीं रख पाता, तो वह आत्मसम्मान की कमी महसूस करने लगता है और यह नकारात्मक सोच और विचारधारा भी आत्म प्रसन्नता को अवरुद्ध करने लगती है। अपनी प्रसन्नता बनाए रखने लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना निरंतर प्रयासों द्वारा ही संभव है, जिसे व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तरों पर क्रियान्वित किया जा सकता है।**

वास्तव में स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने की अनुमति देती है, जिससे उसका तनाव कम होता है, लेकिन उसे इन तीनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती तो उसके मन में आत्म-संदेह की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। जब व्यक्ति का स्वयं पर ही विश्वास नहीं रख पाता, तो वह आत्मसम्मान की कमी महसूस करने लगता है और यह नकारात्मक सोच और विचारधारा भी आत्म प्रसन्नता को अवरुद्ध करने लगती है। अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना निरंतर प्रयासों द्वारा ही संभव है, जिसे व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है।

स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनने के लिए आवश्यक है कि सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद न होने दिया जाए। व्यक्ति सदा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए और नकारात्मक विचारों से दूर रहे और साथ ही साथ चिंतन के माध्यम से समय-समय पर आत्म-साक्षात्कार करते हुए आत्म-सुधार पर ध्यान दे। सिर्फ अपने नहीं, बल्कि दूसरों के भी अधिकार हैं। इस सच को समझते हुए दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करने की जरूरत है। समाजिक रूप से विभिन्न समुदायों और समूहों के साथ जुड़कर और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेने से व्यक्ति की सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के अलग-अलग आयामों के बारे में अपनी समझ स्पष्ट होती है। अपनी स्वतंत्रता के समांतर दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करने की परिपक्वता हासिल होती है।

परिवार समाज की इकाई है और आपसी मेलजोल के साथ जब व्यक्ति के खुले और ईमानदार संवाद होंगे, विचार-विमर्श होंगे, एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान होगा तो निश्चित ही आपसी समझ और सहयोग भी बढ़ेगा। व्यक्ति का अपने समय का सही प्रबंधन भी परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना कर आंतरिक प्रसन्नता को बनाए रखने में सहायता करेगा। ध्यान और योग करना भी मानसिक शांति और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।

स्वतंत्रता के दायरे बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि अपनी प्राथमिकताओं को समझा जाए और अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर उनको पूर्ण करने के लिए नियमित प्रयास किए जाएं।

दूसरे व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के विषय में समझाने से बेहतर है कि खुद ही इस दिशा में प्रयास करते रहा जाए, ताकि उनके द्वारा अपने आप ही स्वतंत्रता की स्थितियां निर्मित हो जाएं और हम आत्मिक रूप से प्रसन्न रहकर अपने आसपास के परिवेश को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर सकें।

सबक और संदेश

बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता और समझदारी की सराहना करनी चाहिए। सरकार ने संसद में कोई बयान देने से पहले बांग्लादेश के विषय पर जिस तरह सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, वह सराहनीय है। किसी भी विवादित विषय पर कोई निर्णय लेने से पहले सर्वसम्मति बनाने की चेष्टा सजीव लोकतंत्र का गुण है, जिसका अभाव बांग्लादेश में अक्सर उभरता रहा है। बेशक, भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने में मदद की है, पर विदेश मंत्री ने यह भी बता दिया है कि भारत ने शेख हसीना को संयम बरतने की सलाह बार-बार दी थी और आग्रह किया था कि हालात को बातचीत से सुलझा लें। शेख हसीना का पतन वास्तव में उन सभी नेताओं के लिए सबक है, जो विपक्ष या विरोधियों के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं और जो लोकतंत्र और चुनाव की इज्जत नहीं करते हैं। आज के समय में सत्ता में बने रहने से ज्यादा जरूरी है- प्रतिकूल परिवेश न बनने देना। इसके बावजूद अगर हालात खिलाफ हो जाएं, तो समय रहते सत्ता से अलग हो जाना ही बेहतर है। इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ती है और अराजकता पर अंकुश रहता है।

– शाहिद हाशमी, जाकिर नगर, नई दिल्ली

बेलगाम हिंसा

मणिपुर में अभी तक साठ हजार से अधिक लोग बेघर, ढाई सौ से अधिक मौतें, सैनिक और सैन्य बलों की भी हत्या, सामूहिक बलात्कार और महिलाओं को नग्न घुमाने जैसी घटनाएं हुईं। हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री के काफिले पर भी हमला हुआ। इसे मुख्यमंत्री की बेबसी, नाकामी या भेदभाव का प्रतिसाद कहें, अन्यथा एक वर्ष में कुछ तो सुधार हुआ होता। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी नस्लीय हिंसा जारी रहने और न्याय न मिलने पर आरएसएस प्रमुख भागवत और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को नाकाम बताया। उल्लेखनीय है कि मैतेई और कुकी में संवाद की गुंजाइश लगभग नहीं बची है और हमार और मैतेई के बीच हुआ समझौता भी चौबीस घंटे में टूट गया, क्योंकि सरकार में दूरदर्शिता का अभाव है। नस्लीय हिंसा के सामने असहाय बनने के बजाय राहुल गांधी की तर्ज पर मणिपुर के लोगों से सतत चर्चा जारी रखनी होगी।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

आभासी दुनिया के खतरे

इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में लोग इसी के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं जो हमारे भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हमारा युवा इस सोशल मीडिया से अधिक समय और कहीं नहीं बिता रहा है। किसी एक ही और आभासी समाज से हमेशा घिरे रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आज इसमें बच्चे और बुजुर्ग, सभी लीन दिखते हैं। इससे हमारा मस्तिष्क विकृत हो रहा है जो भविष्य में घातक साबित होगा। इसलिए अब सरकार और हमारे समाज को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अन्यथा हमारा समाज विनाश की ओर बढ़ता चला जाएगा। सोशल मीडिया के अनेक ऐसे मंच हैं, जो हमारे बच्चों और युवाओं को एक तरह से मादक पदार्थों में डुबोते जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया की जिसे आदत लग गई है, वह उसे छोड़ नहीं पा रहा है और यह हमारे मस्तिष्क को कमजोर करता जा रहा है। इससे दूरी बनाना बेहद जरूरी है।

– अंकित यादव, दिल्ली

अब आगे

चीन, अमेरिका और पाकिस्तान को पता है कि बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार की दोस्ती नई दिल्ली से गहरी थी। अब शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंध बाधित हो सकते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अहम सहयोग के साथ दोनों देशों के बीच अच्छा-खासा व्यापार होता रहा है। अब दक्षिण एशिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को और मजबूती मिल सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तीस्ता सिंचाई परियोजना पर चीन अपनी नजर गड़ाए हुए था, लेकिन भारत के इसमें सहयोग के प्रस्ताव से शेख हसीना ने अपनी नीतियां भी बदली थीं। अब वहां जिन लोगों ने सत्ता का सूत्र थामा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वे बांग्लादेश में शांति-व्यवस्था कायम करें।

– युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर दूसरा ही 'खेला'

शेख हसीना के अपदस्थ होने के एक सप्ताह बाद भी बांग्लादेश संकट के भंवर से बाहर नहीं आ पाया है। शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार भी विफल नजर आ रही है। हालात काबू करने में नाकाम पुलिस अपनी सुरक्षा की दुहाई देकर हड़ताल पर है। अराजकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। आरक्षण के खिलाफ करीब एक महीने से चल रहा आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, जो आंदोलनकारियों के पक्ष में था।

उथल-पुथल जारी रहने से इन आशंकाओं को बल मिला है कि आरक्षण की आड़ में दूसरा ही 'खेला' चल रहा है। शक की सुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और चीन के अलावा अमरीका पर भी घूम रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए कुछ विदेशी ताकतों ने आंदोलन को हवा दी। दरअसल, भारत के प्रति झुकाव को लेकर शेख हसीना चीन की आंख की किरकिरी बनी हुई थीं। चीन की नजर बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का प्रबंधन हासिल करने पर थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जासूसी के लिए इस बंदरगाह के जरिए चीन वहां अपना सैन्य और मिसाइल बेस कैम्प कायम करना चाहता था। शेख हसीना का बंदरगाह का प्रबंधन भारत को सौंपने का फैसला चीन के लिए बड़ा झटका था। दोनों देशों के रिश्तों की कड़वाहट पिछले महीने ही सामने आ गई थी, जब चार दिन की यात्रा बीच में ही खत्म कर शेख हसीना ढाका लौट गई थीं। यह संयोग नहीं है कि इस घटनाक्रम के बाद आरक्षण आंदोलन दिन-ब-दिन उग्र होता गया और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर भीड़तंत्र हावी हो गया है। सभी प्रमुख सरकारी और संवैधानिक संस्थान प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख को भी पद छोड़ने को मजबूर किया गया। जेलों पर हमलों से सैकड़ों कैदी भाग निकले हैं। बांग्लादेश में रह रहे हजारों हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है। आम लोगों की तकलीफों पर सुनवाई के लिए फिलहाल बांग्लादेश में सारे रास्ते बंद हैं। बांग्लादेश में अराजकता के दौर ने भारत की सीमाओं पर भी खतरे बढ़ा दिए हैं। वहां से भारी तादाद में लोग भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। घुसपैठ टालने के साथ-साथ बांग्लादेश के घटनाक्रम पर लगातार निगरानी की जरूरत है।

सामयिक: तेहरान में हमास के शीर्ष नेता हानिया की हत्या से पनपे हालात ने बढ़ाई भारत की दुविधा

पश्चिम एशिया में तनाव और संतुलन की चुनौती

इजरायली सेना के फिलिस्तीनी इलाकों पर ताबड़तोड़ सैन्य हमलों के कारण इजरायल-हमास बातचीत में आ रही बाधाओं और नवनिर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद तेहरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की नाटकीय हत्या से पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अमरीका को अपने पक्ष में घसीटने का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है जिससे युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। इसी कारण, एयर इंडिया सहित सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने तेल अवीव की उड़ानें कम या रद्द कर दी हैं।

ईरान और हमास दोनों ने हानिया की मौत के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है। ईरान द्वारा इजरायल पर जवाबी हमले की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत ने संयम बरतने का आह्वान किया है। पर भारत का कूटनीतिक झुकाव किसी पक्ष की ओर नहीं है। हानिया की हत्या पर सीधी प्रतिक्रिया देने के बजाय पश्चिम एशिया की स्थिति को चिंताजनक करार देना भारत की तटस्थ स्थिति का एक प्रतिबिंब है। हालांकि कुछ आलोचक इसे अस्पष्ट नीति कहेंगे। वैसे भारत ने हमास को आतंकवादी समूह की सूची में प्रतिबंधित नहीं किया है, पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख एकदम स्पष्ट रहा है। हानिया की हत्या पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देकर भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष को कमजोर नहीं करना चाहता। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए आतंकवादी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की थी। इस बयान को भारत की दो-राज्य समाधान की परम्परागत फिलिस्तीन नीति में अचानक बदलाव के तौर पर देखा गया, पर भारत की पश्चिम एशिया नीति में रातों-रात कोई परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि वह संतुलन की बुनियाद पर टिकी हुई है।

विनय कौड़ा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ
@patrika.com

पश्चिम एशिया में किसी भी तरह का सैन्य तनाव भारत के सुरक्षा हितों पर विपरीत असर डालेगा। फिर यह भी याद रखना होगा कि इजरायल में लगभग 18,000 भारतीय और ईरान में लगभग 10,000 भारतीय हैं। संघर्ष बढ़ने से सरकार पर उनकी तत्काल निकासी के लिए दबाव पड़ेगा।

फिलिस्तीन का प्रश्न केवल पश्चिम एशिया के लिए ही अहम नहीं है। यह उन सब देशों के लिए महत्वपूर्ण है जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में निवास कर रही है - फिर वह पश्चिमी देश हों या फिर भारत, इसलिए हानिया पर अस्पष्ट रुख भारत की संतुलनकारी कूटनीति को ही उजागर करता है। वर्तमान में भारत की पश्चिम एशिया नीति में आर्थिक कारक काफी अहम हो गए हैं। यदि अब भारत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब जैसे देशों से व्यापारिक और निवेश भागीदारी पर अधिक ध्यान देने लगा है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए ईरान भी एक महत्त्वपूर्ण देश है। ईरान दो प्रमुख मोर्चों पर भारतीय रणनीतिक सोच का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। पहला, पश्चिम एशिया एवं अफगानिस्तान तक भारत की पहुंच आसान बनाने का जरिया। दूसरा, भारत की शिया आबादी पर ईरान की विचारधारा का संभावित असर। दरअसल, पश्चिम एशिया की विस्फोटक भू-राजनीति केवल भारतीय विदेश नीति के विकल्पों तक सीमित नहीं है, यह भारत के घरेलू विमर्श में भी शामिल है। क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ने से रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण व दुविधापूर्ण होता जा रहा है।

पिछले कुछ समय में कई जुलूसों के दौरान फिलिस्तीनी एकजुटता एवं इजरायल विरोधी भावनाओं का प्रदर्शन देखा गया है। यहां तक कि भारत में कार्यरत इजरायली कंपनियों के बहिष्कार का आह्वान भी किया गया। कुछ साल पहले भी ईरान के लोकप्रिय जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के विरोध में रैलियां निकाली गई थीं। ये तथ्य इसलिए चिंताजनक हैं क्योंकि इनका संबंध पाकिस्तान-प्रेरित आतंकवाद से न होकर भारत की मुस्लिम राजनीति की वैचारिक सोच से है। यह सही है कि इसका राजनीतिक असर फिलहाल नगण्य है, फिर भी यथास्थिति बनाए रखना अहम है ताकि इस्लामिक चरमपंथ की किसी धारा के भारत में उत्थान को रोका जा सके। जिस प्रचंडता से इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में वापसी की है वह वैसे भी भारत के लिए नया सिरदर्द बन गया है। इसी पृष्ठभूमि में ईरान और इजरायल में बढ़ता तनाव भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। गौरतलब है कि अप्रैल में ही ईरान ने दूर-दराज के लक्ष्यों तक पहुंचने में अपनी सैन्य-तकनीकी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। उस दौरान ईरान और उसके क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें लगभग एक ही समय में इजरायल पहुंचे। ऐसी क्षमता के लिए बेहतरीन योजना और सटीकता की आवश्यकता होती है। इनमें से अधिकांश सैन्य क्षमताएं ईरान ने स्वदेशी रूप से और कड़े अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद हासिल की हैं।

भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह ईरान की बढ़ती क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति और मारक क्षमताओं को पहचाने और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। ईरान लम्बे समय से अनेक शिया गुटों, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख रहा है, के जरिए अपनी क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। ईरानी प्रभाव, हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे फिलिस्तीनी समूहों तक भी फैल चुका है। धीरे-धीरे ईरान-समर्थक प्रॉक्सी गुटों की ताकत में घातक इजाफा हुआ है। इनमें यमन में हूती और इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (अल-हशद अश-शबी) शामिल हैं। अगर पश्चिम एशिया में युद्ध आरंभ होता है तो वह सीमित नहीं रहेगा क्योंकि ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए अपने प्रॉक्सी गुटों का उपयोग अवश्य करेगा। तब ईरानी ड्रोन और मिसाइलों किस-किस दिशा में रुख करेंगी, इसका तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। जाहिर है, ईरान के प्रति एक गंभीर दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कूटनीतिक, सैन्य और विचारधारात्मक तत्वों का समावेश हो।

नेतृत्व

टीम सदस्यों को सक्रिय रूप से सुनना जरूरी

लीडर प्रभावी तभी होंगे, जब वे स्वयं संवेदनशील बनेंगे

पिछले आलेख में चर्चा की गई थी कि किस प्रकार जुनून और संवेदनशीलता के साथ लीडर सफल नेतृत्व कर सकते हैं। जुनून और संवेदना के सामंजस्य से लीडर न सिर्फ अपनी टीम और संगठन को, बल्कि स्वयं की क्षमताओं को भी बेहतर बना सकते हैं। पर नेतृत्व में संवेदनशीलता मात्र दयालु होने से कहीं ज्यादा है; इसमें टीम के सदस्यों की बातें सक्रिय रूप से सुनना, उनकी चुनौतियों को समझना और जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करना शामिल है। एक संवेदनशील लीडर कार्यस्थल पर सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाता है जहां सभी कर्मचारी अपने विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं। यह खुलापन विश्वास को बढ़ावा देता है, जो किसी भी सफल टीम की नींव है।

इसके अलावा, वे वर्क-लाइफ बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य के महत्त्व को पहचानते हैं। वे ऐसी नीतियों और प्रथाओं को प्रेरित करते हैं जो उनके कर्मचारियों की समग्र भलाई का समर्थन करती हैं, जैसे फ्लेक्सिबल वर्क ऑवर्स, मेंटल हेल्थ डे, और पेशेवर क्षमता विकास के अवसर। जब वे व्यक्तिगत रूप से टीम के सदस्यों की परवाह करते हैं, तब वे संगठन के भीतर वफादारी और अपनेपन की भावना का निर्माण करने में सफल होते हैं। पर आवश्यक यह है कि जुनून और संवेदनशीलता में एक सही संतुलन हो। अधिक जुनून से भी संगठन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और अत्यधिक संवेदनशीलता से भी लक्ष्यों की प्राप्ति में समस्या आ सकती है। अतः सबसे प्रभावी लीडर इन दोनों गुणों को सहजता से एकीकृत करते हैं, जिससे एक संतुलित दृष्टिकोण बनता है जो प्रदर्शन और कल्याण दोनों में सहायक होता है। इस एकीकरण को प्राप्त करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं:

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक,
आइआइएम इंदौर
@patrika.com

1. **उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करें:** अपने कार्यों और निर्णयों के माध्यम से जुनून का प्रदर्शन करें, अपनी टीम को दिखाएं कि आप संगठन के लक्ष्यों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, सुलभ होकर, सक्रिय रूप से उनकी बातें और चुनौतियां सुनकर और सहानुभूति दिखाकर करुणा भी व्यक्त करें।
2. **प्रभावी ढंग से संवाद करें:** अपने दृष्टिकोण और लक्ष्यों को उत्साह के साथ साझा करें, और नियमित रूप से प्रगति और उपलब्धियों के बारे में संवाद करें। प्रतिक्रिया के लिए खुलापन रखें, जिससे टीम के सदस्य भी आपकी बातें सुनें, अपनी भावनाएं साझा करें और मूल्यवान महसूस करें।
3. **अपनी टीम को सशक्त बनाएं:** टीम के सदस्यों को नए विचारों और दृष्टिकोणों को खोजने की स्वायत्तता देकर नवाचार व रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। आवश्यक संसाधनों के साथ मदद करें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया दें।
4. **सफलताओं का जश्न मनाएं, असफलताओं से सीखें:** अपनी टीम की उपलब्धियों को स्वीकार करें और उनका जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। जब असफलताएं आती हैं, तो उन्हें एक संवेदनशील मानसिकता के साथ स्वीकारें और दोष देने के बजाय सीखने और सुधार पर ध्यान केंद्रित करें।
5. **सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा दें:** ऐसा कार्य वातावरण बनाएं जो सम्मान, समावेशिता और समर्थन को प्राथमिकता देता हो। टीम सदस्यों के बीच सहयोग और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करें, और संघर्षों को सहानुभूति और निष्पक्षता के साथ संबोधित करें।

प्रभावी नेतृत्व जुनून और संवेदनशीलता के माध्यम से प्रदर्शन को आगे बढ़ाने और एक सहायक और समावेशी कार्य वातावरण को पोषित करने के बीच सही संतुलन बनाने के बारे में है।

ज्वारीय बोर का जादू:

चीन की कियानतांग नदी के तट पर लहरों की लय

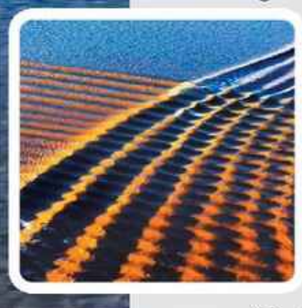

***सैकड़ों** सालों से, चंद्र कैलेंडर के आठवें महीने में, लोग हांग्जो खाड़ी के मुहाने पर चीन की कियानतांग नदी के तट पर इसके प्रसिद्ध 'बोर टाइड' या 'ज्वारीय बोर' की लहरों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। सामान्य से ज्यादा ऊंची ज्वार की लहरें खाड़ी की ओर बढ़ती नदी की धारा में घुस जाती हैं, जिससे एक चौड़ी लहर पैदा होती है जो 30 फीट तक ऊंची हो सकती है। कियानतांग नदी का ज्वारीय बोर दुनिया का सबसे बड़ा और अपनी तरह का सबसे शक्तिशाली है। कभी-कभी दो ज्वार एक साथ मिलकर क्रॉस जैसी आकृति बनाते हैं, जो सूर्यास्त के समय और भी अधिक आकर्षक हो जाती है। ज्वारीय बोर उस तट पर होता है जहां नदी समुद्र या महासागर में गिरती है। ज्वारीय बोर एक मजबूत ज्वार है जो नदी को धारा के विपरीत ऊपर धकेलता है।*

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस आज

डिजिटल माध्यम युवाओं के लिए खोल रहे हैं नई राह

भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित खारा राठौड़ान गांव की शादीशुदा युवती पूनम के लिए उस समय बड़ा संकट पैदा हो गया जब उसका पति कोविड के दौरान फैक्ट्री बंद होने से अहमदाबाद से गांव लौट आया। गांव में रोजगार नहीं, पास में पैसा नहीं और कोई मददगार भी नहीं। 27 वर्षीय पूनम मात्र 7वीं उत्तीर्ण। इस बीच पूनम को गांव में किसी ने बताया कि लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करके पैसा कमाते हैं। उसने किसी तरह से मोबाइल खरीदा, बैंक अकाउंट खुलवाया और बिना किसी टेक्नो गुरु के लगातार स्वयं प्रयास करके यूट्यूबर बन गई। देशी भाषा में हंसी मजाक के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिए। परिवार और समाज के के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वह डटी रही। पति का साथ था। देखते-देखते पूनम राजस्थानी के 7 लाख के करीब फॉलोवर्स बन गए हैं। हंसी मजाक के वीडियो में सामाजिक चेतना का संदेश भी देती रहती हैं। वे कलाकारों को मंच भी दे रही हैं। गरीबी की जिंदगी से निकलकर पूनम ने सबसे पहले अपना स्टूडियो बनाया और अब सुंदर मकान का निर्माण करा रही है। डिजिटल दुनिया ने दूर-दराज के गांव की सामान्य शिक्षा प्राप्त युवती पूनम के जीवन और आजीविका में जबरदस्त बदलाव ला दिया है। ऐसी अनेक कहानियां मिल रही हैं। डिजिटल प्लेटफार्म से युवाओं ने स्वयं को, परिवार को और समाज को सशक्त किया है.

डॉ. भुवनेश जैन
क्षेत्रीय निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन, पश्चिम क्षेत्र.
@patrika.com

मोबाइल एवं अन्य डिजिटल डिवाइस युवाओं के करियर और विकास में मददगार साबित हो रही हैं। इन युवाओं को डिजिटल निवासी, डिजिटल जीवी, डिजिटल पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने थकाऊ, उबाऊ, और आनंददायक बना दिया है। समय, धन एवं अन्य संसाधनों की बचत भी हो रही है और शैक्षिक-आर्थिक लाभ भी प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। संयक्त राष्ट्र दुनिया के नौजवानों की ऊर्जा, कुशलता और उनमे अपार सम्भावनाओं को देख रहा है और उनसे अपेक्षा भी है कि वे सतत विकास के तय लक्ष्य को 2030 तक पूरा करने में मदद करें। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 15-24 वर्ष की उम्र के दो तिहाई नौजवानों की इंटरनेट सुविधा तक पहुंच हैं जो अन्य उम्र के लोगों से ज्यादा है। भारत में नेशनल सेंम्पल सर्वे के अनुसार 24 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण परिवारों की पहुंच इंटरनेट तक है। डिजिटल डिवाइड से जो दो दुनिया सामने है, उसे पाटने की जरूरत है जिसके लिए सरकारी प्रयास भी बड़े पैमाने पर जारी हैं। युवा वर्ग डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर शिक्षा, जीवन और आजीविका को बेहतर बनाएं। साथ ही वे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण जैसे मुद्दों को उठाएं। डिजिटल साधनों का इस्तेमाल सही सूचना, शिक्षा और संचार के लिए करें। वे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा,आपदा प्रतिरोधक, कौशल और लैंगिक समानता के लिए हो रहे कार्यों में भी अपना योगदान दें।

डिजिटल साधन संवेदनशील हैं। इनका नकारात्मक उपयोग हिंसा, उत्पीड़न, नफरत , ठगी ,अलगाव आदि को बढ़ावा भी दे रहा है जिससे बचने की जरूरत है। सभी को डिजिटल ज्ञान से जोड़ना है लेकिन कुशलता और सतर्कता के साथ। अब कृषि, बाजार, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा,बैंक सुविधा, सेवा कार्य मात्र एक क्लिक से दूर हैं और पूरी दुनिया के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। डिजिटल नवाचार से युवा दुनिया के वंचित लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। वे पृथ्वी को बेहतर ,समृद्ध, सुखी और सुरक्षित बनाने में योगदान कर सकते हैं। युवा डिजिटल जीवियों, युवा डिजिटल निवासियों, डिजिटल पीढ़ी से सभी को रचनात्मक योगदान की अपेक्षा है।

श्रावण में वातावरण शिवमय

संहार में भी सृजन को समेटे हुए हैं दुखहर्ता- कल्याणकर्ता शिव

अजहर हाशमी
कवि और साहित्यकार
@patrika.com

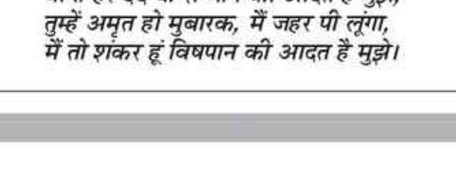

मेरे मौलिक मत में 'शिव' दीनमित्र पहले हैं कुबेर मित्र बाद में, दुखहर्ता पहले हैं देवाधिदेव बाद में, मासूम पहले हैं महाकाल बाद में, दयादाता पहले हैं दंडदाता बाद में, कल्याणकर्ता पहले हैं ताण्डवकर्ता बाद में। दीनमित्र की दरियादिली, दुखहर्ता की दृष्टि, मासूम की मुस्कान, दयादाता की दिव्यता, कल्याणकर्ता की करुणा जब एकाकार हो जाती है तो 'शिव' हो जाती है। इस प्रकार शिव नाम है कल्याण का। शिव धाम है कल्याण का। इस संदर्भ में काव्य-पंक्तियां भी हैं-

शिव यानी कल्याण है, शिव यानी उत्थान ,
शिव चिंतन, शिव-चेतना, शिव में निहित निदान,
शिव समत्व के सारथी, शिव शुभता, शिव खैर,
शिव के प्रेम प्रभाव में, प्राणी भूलें गैर,
तुरंतः प्रसन्न इसीलिए, नाम है आशुतोष,
शिव का मतलब सादगी, शिव यानी संतोष,
तप में हों तल्लीन या हो गौरी के साथ,
निर्विकार-निश्छल सदा, शिव हैं भोलेनाथ।

स्पष्ट है कि शिव का पारमार्थिक प्रवाह है कल्याण। शिव का नीतिगत निर्वाह है कल्याण। शिव की रीतिगत रवानी है कल्याण, शिव की प्रीतिगत कहानी है कल्याण। इससे सिद्ध होता है कि शिव का आध्यात्मिक स्वरूप भी कल्याण है और दिव्य रहस्य भी कल्याण है। प्रश्न उठता है कि कल्याण किसका? कल्याण कैसे? पहले प्रश्न का उत्तर है कि शिव को भले ही 'संहारक' कहा जाता हो लेकिन मूलतः वे सृजेता ही हैं। शिव सृजेता हैं कल्याण के। संहार किए बिना सृजन होता नहीं। सृजन हुए बिना कल्याण होता नहीं। इसको यों समझिए। एक इमारत का निर्माण होना है तो उसकी दीवारों को आकार सीमा और संतुलन देने के लिए ईंटों को जोड़ना होगा। लेकिन, सही शक्ल देने के लिए कुछ ईंटों को तोड़ना भी होगा। इन ईंटों को तोड़े बिना अर्थात 'संहार' किए बिना निर्माण नहीं होगा। यानी सृजन नहीं होगा। अगर इमारत का निर्माण नहीं होगा तो लोगों को रहने के लिए आसरा नहीं मिलेगा। आसरा नहीं मिलेगा तो उनकी रहने की समस्या का समाधान नहीं होगा। अर्थात कल्याण नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि शिव, संहार में भी सृजन को समेटे हुए हैं, जिसमें कल्याण निहित है। यह कल्याण उसका होता है जो समर्पण के संस्कार से युक्त हो।

दूसरा प्रश्न यह कि कल्याण कैसे? इसका उत्तर यह है कि जब कोई समर्पण से भरा होता है तो शिव उसके प्रति स्वयं समर्पित हो जाते हैं और कल्याण कर देते हैं। जैसे शिव ने श्री विष्णु का कल्याण किया। जब उन्होंने यह देखा कि विष्णु ने कमलपुष्प खो जाने पर अपना नेत्र ही शिव को चढ़ा दिया। तब शिव ने प्रसन्न होकर कमल को सुदर्शन-चक्र में परिवर्तित करके विष्णु को दे दिया। इस प्रकार शिव के द्वारा विष्णु का कल्याण हो गया। इसी तरह समुद्र-मंथन के बाद कालकूट विष कंठ में लेकर भी शिव ने सृष्टि का कल्याण किया। शिव का यह कल्याणकारी आध्यात्मिक स्वरूप इस प्रकार है।

पाप को पुण्य में भुगतान की आदत है मुझे,
यानी हर दर्द के सम्मान की आदत है मुझे,
तुम्हें अमृत हो मुबारक, मैं जहर पी लूंगा,
मैं तो शंकर हूं विषपान की आदत है मुझे।

आपकी बात

बांग्लादेश को दी जाए चेतावनी

बांग्लादेश को चेतावनी देनी चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत बंद करे। अत्याचार न रुकने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखना चाहिए। इस मामले में भारत चुप न रहे।

-दिलीप शर्मा, भोपाल, मध्यप्रदेश

आज का सवाल

शेख हसीना को शरण देने में पश्चिमी देश हिचक क्यों रहे हैं?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न रोकने के लिए भारत क्या करे? ' ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/3jm2i

इसे स्कैन करें

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 152

निराशाजनक प्रदर्शन

पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक खेलों में भारत के 117 खिलाड़ियों ने 16 खेलों में हिस्सा लिया। माना जा रहा था कि इन खेलों में देश टोक्यो ओलिंपिक के एक स्वर्ण और दो रजत समेत सात पदकों के प्रदर्शन को बेहतर करेगा। परंतु इन खेलों में हमें एक रजत और पांच कांस्य सहित केवल छह पदक मिले जो बताता है कि भारतीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय बनाने के क्षेत्र में अभी काफी काम करने की आवश्यकता है। खासकर उन खेलों में जिनके बारे में हमारा दावा है कि हम विश्वस्तरीय सुविधाएं रखते हैं। मनु भाकर द्वारा एक ही ओलिंपिक में दो पदक (कांस्य) हासिल करने और अमन सहरावत के देश का सबसे युवा ओलिंपिक पदक विजेता (कुश्ती में कांस्य) बनने के अलावा भारत के प्रशंसकों को खुशी से अधिक निराशा का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अयोग्य घोषित कर दी गईं जिनकी अपील पर फैसला आना बाकी है। भारत कई अवसरों पर करीबी मामले में पदक पाने से चूक गया।

उदाहरण के लिए भाकर 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में बहुत मामूली अंतर से तीसरा पदक पाने से चूक गईं। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में दो बार बढ़त गंवा बैठे और कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में हार कर चौथे स्थान पर रहे। यह उस खेल में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था जिसके बारे में उसका दावा है कि उसके पास विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो में रजत पदक जीता था, वह महज एक किलोग्राम वजन कम उठाने के कारण कांस्य पदक पाने से चूक गईं। हॉकी में जहां भारत को विश्व में पांचवीं वरीयता हासिल है, टीम ने लगातार दूसरे ओलिंपिक में कांस्य पदक जीता लेकिन यहां भी टीम स्वर्ण या रजत पदक जीत सकती थी। जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में ढेर सारे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल पाने में नाकामी की शाश्वत समस्या के कारण टीम को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाजों को हमेशा पदक का दावेदार माना जाता है लेकिन उन्हें भी खाली हाथ लौटन पड़ा। नीरज चोपड़ा भी टोक्यो में स्वर्ण जीतने का कारनामा दोहरा नहीं सके और उन्हें पेरिस में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कुश्ती में भारत को केवल एक कांस्य पदक मिला। फोगाट को दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद एक ऐसे खेल में यह कमजोर प्रदर्शन है जिसमें भारत वैश्विक शक्ति होने का दावा करता है।

इस कमजोर प्रदर्शन की वजह निर्धारित कर पाना मुश्किल है। यकीनन सरकार के समर्थन में निरंतरता की कमी एक वजह है। उदाहरण के लिए शूटिंग में पदक जीतने वालों में से अधिकांश अच्छे परिवारों से आते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वे प्रशिक्षण और कोचिंग का खर्च उठा सकें। या फिर खिलाड़ी सरकारी सेवा में होते हैं, मसलन नीरज चोपड़ा सेना में जबकि शूटिंग का कांस्य पदक जीतने वाले स्वप्निल कुसाले आदि सरकारी कर्मचारी हैं। देश के अधिकांश खेल संघों के गैर पेशेवर रवैये ने हालात और भी खराब किए हैं। इन संघों में वरिष्ठ पदों पर राजनेता बैठे हैं जो खिलाड़ियों के कल्याण के बजाय अन्य बातों में रुचि रखते हैं। पिछले वर्ष पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के मुखिया और सत्ताधारी दल के ताकतवर राजनेता बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन इसकी बानगी है। फोगाट का अपने वजन को तय सीमा में रखने के लिए संघर्ष आंशिक रूप से उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का भी परिणाम था। जैसा कि इस श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहलवान ने कहा भी कि निचले भार वर्ग में लड़ने की तैयारी कम से कम दो साल पहले शुरू होनी चाहिए। फोगाट के पास तैयारी के लिए एक वर्ष से भी कम समय था। पेरिस में भारत का प्रदर्शन 1900 के बाद से दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन था। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश की क्षमताओं को यह सही ढंग से नहीं दर्शाता।

सत्ताधारी पक्ष बचाव में और विपक्ष आक्रामक

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में कांग्रेस के सभी विचारों को कल्पना से परे बताते हुए खारिज करने से दूरी बना ली है। अब वह उनमें से कई विचारों को लागू भी कर रही है।

हम अक्सर क्रिकेट से जुड़े हालात और रूपकों की मदद से राजनीतिक जटिलताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस समय ओलिंपिक खेल और यूरो कप चल रहे हैं इसलिए हॉकी और फुटबॉल का जिक्र अधिक उचित होगा। आइए देखते हैं कि कैसे हॉकी या फुटबॉल के खेल में आने वाले बदलाव हमारी राष्ट्रीय राजनीति के परिवर्तनों को दर्शाते हैं। इनके संकेत संसद के मॉनसून या बजट सत्र में मिले हैं।

ओलिंपिक हॉकी के अंतिम आठ के मुकाबले को याद कीजिए जहां भारत को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ करीब 42 मिनट तक केवल 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा था। इसका फायदा उठाते हुए ग्रेट ब्रिटेन ने लगातार हमले किए और भारत सामने आकर खेलने के लिए संघर्ष करता रहा। परंतु जब कभी भारत ने हमला किया तो खेल एकदम नाटकीय रूप से बदला नजर आया। बुरी तरह हाशिये पर धकेले जाने के बाद जवाबी हमले का ऐसा उदाहरण जबरदस्त है। बचाव के पूरे समय गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजनीति में भी इस समय ऐसा ही हो रहा है।

2024 के आम चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति को नए सिरे से संतुलित किया है और यह बात हम 4 जून से जानते हैं। पूरा विपक्ष एकदम हाशिये पर धकेल दिया गया था और नाउम्मीद हो चुका था। तभी उसे जवाबी हमला करने का अवसर मिला। फर्क यह था कि ज्यादातर लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि जवाबी हमला इतना तगड़ा और प्रभावी होगा कि विजेता को अपनी योजनाएं और रणनीति बदलनी पड़ेगी। इस दौरान राहुल गांधी को एकदम अलग ढंग से देखा जा रहा है। ध्यान रहे यह वही राजनेता है जिसका हमारे इतिहास में सबसे अधिक मखौल उड़ाया गया है।

अब निष्पक्ष होकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहां उन विचारों और प्रचार अभियान के बिंदुओं की सूची प्रस्तुत है जो कांग्रेस के घोषणापत्र से लिए गए हैं:

- युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर रोजगार बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जाए और इंटर्नशिप की योजना बनाई जाए।
- गरीब, बेरोजगारों और किसानों को नकद सहायता दी जाए।
- किसानों के लिए सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हो और उनकी कर्जमाफी की जाए।
- अग्निपथ योजना पर सवाल।
- राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और उसके बाद लाभ और सहायता का हर वर्ग को उसकी संख्या के आधार पर आवंटन करना।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

इनमें से कई को भाजपा ने झूठ बताकर खारिज कर दिया। जाति से जुड़े मुद्दों की अनदेखी कर दी गई और इसके प्रतिवाद में हिंदू विचारों के उभार का सहारा लिया गया। हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के जाति जनगणना के बाद वितरण के समाजवादी रुख को सीधे तौर पर 'रेवड़ी' करार देकर खाजिर कर दिया गया। आम भाषा में कहें तो कहा गया कि कांग्रेस मुफ्त उपहारों की मदद से वोट खरीदना चाहती है। अब हमें देखना होगा कि आगे चलकर क्या हुआ।

मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में उन विचारों से तेजी से दूर हुई है जिनके तहत वह राहुल गांधी और कांग्रेस के विचारों को कल्पना से परे और मजाक मानती थी। अब वह उनमें से कई को लागू कर रही है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं:

- इस बजट में बेरोजगारी को लेकर उल्लेखनीय आवंटन किया गया है और वादे भी किए गए हैं। कंपनियों को अधिक लोगों को काम देने के लिए प्रोत्साहित किया गया और पांच साल में एक करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दिलाने की योजना बनाई गई।
- भाजपा की राज्य सरकारें, खासकर जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां की सरकारें पहले ही कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर रही हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार ने पहले की 14 के मुकाबले अब सभी 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
- अगर आप इन दिनों अखबारों में आ रहे पूरे पन्ने के विज्ञापनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हरियाणा में मुफ्त उपहारों की झड़ी लगी है। 46 लाख परिवारों को केवल 500 रुपये में एलपीजी सिलिंडर दिए जा रहे हैं। स्कूली छात्राओं के लिए निःशुल्क दूध योजना और नहर जल उपकर की माफी।
- एक लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के सभी सदस्यों को हर माह 1,000 किमी निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। भाजपा दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसी ही योजनाओं का मखौल उड़ा चुकी है।
- हरियाणा ने पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को भी छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दिया है।

महाराष्ट्र पर ध्यान देना अधिक श्रेयस्कर होगा। वह पहले ही ऐसी रेवड़ियां घोषित कर चुकी है जो सालाना 96,000 करोड़ रुपये का बोझ डालेंगी। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

- एक खास आय वर्ग के नीचे की महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा वरकारी संप्रदाय (करीब 16 लाख जातिविहीन लोगों का पंथ) को नकद हस्तांतरण तथा सब्सिडी दी जाएगी। वरकारियों को अपने सालाना पंढरपुर तीर्थ के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। संभव है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले योगी भी कांवड़ियों को भी ऐसी ही सुविधा दे दें।
- 21 से 65 आयु वर्ग की जिन महिलाओं की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम हो उनको हर माह 1,500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसकी लागत करीब 46,000 करोड़ रुपये होगी।
- कक्षा 12वीं पास करने वालों को छह माह तक 6,000 रुपये, डिप्लोमाधारियों को 8,000 रुपये और स्नातकों को 10,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी ताकि वे कौशल प्रशिक्षण ले सकें।
- पांच लोगों वाले हर परिवार को साल में तीन एलपीजी सिलिंडर निःशुल्क दिए जाएंगे।

इन सभी उदाहरणों से यही पता चलता है कि एक दशक तक रक्षात्मक रहा विपक्ष ही इस समय एजेंडा तय कर रहा है। भाजपा जो पहले ऐसे वितरण का मखौल उड़ाती थी वह अब खुद वोट जुटाने के लिए रेवड़ी बांटने में लगी है। विपक्ष ने सत्ताधारी दल को अपनी स्थिति बदलने के लिए विवश किया है।

अगर आप मानते हैं कि यह केवल चुनाव की वजह से हो रहा है तो हम और ठोस बात उठा सकते हैं और वह है हमारी राजनीति में वैचारिक मुद्दे। प्रयास करते हैं यह जानने का कि क्या उपरोक्त दलील यहां भी लागू होती है।

सन 1989 से ही दो बातें यह तय करती रही हैं कि भारत पर कौन शासन करेगा: एक यह कि क्या धार्मिक आधार पर एकजुट लोगों को जाति के आधार पर बांटा जा सकता है? या फिर क्या जाति के आधार पर बंटे हुए लोगों को धर्म के आधार पर एक सूत्र में पिरोया जा सकता है? हमने अक्सर कहा है कि बीते 25 सालों से जाति जीत रही है। मोदी के उभार ने जातियों में बंटे हिंदू मतों को एकजुट किया। हिंदुत्व की चर्चा ने तब जोर पकड़ा। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के नारे के साथ इसे चुनौती दी। उन्होंने इसे संसद में उठाया और जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी इसी संसद से जाति जनगणना कराएगी। भाजपा के पास इसका जवाब नहीं है।

जाति के मसले पर जवाब नहीं होने के कारण ही भाजपा धर्म पर बहुत अधिक जोर दे रही है। नया वक्फ विधेयक, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की 'भूमि जिहाद' की बातें, योगी द्वारा 'लव जिहाद' के मामलों में कानून में संशोधन करके आजीवन कारावास की सजा देने का प्रस्ताव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा एक समुदाय पर आबादी नियंत्रित नहीं करने का आरोप आदि इसी वजह से उठाए गए रक्षात्मक कदम हैं।

मेरे मुताबिक यह भ्रम की स्थिति है क्योंकि आम चुनाव में यह कारगर नहीं रहा। भाजपा फिर जाति के प्रश्न से जूझ रही है। जाति जनगणना को भूल जाइए, पार्टी तो 2021 में ही होने वाली सामान्य जनगणना तक की बात नहीं कर रही। भाजपा ने खुद पिछड़ी जातियों की उपश्रेणियों की बात की और दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी के अधीन इसके परीक्षण के लिए एक आयोग गठित किया। उसने अब तक रिपोर्ट नहीं दी। अगर उपश्रेणियां बनेंगी तो जाति जनगणना भी करनी होगी। यह राहुल गांधी की जीत होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हिंदू मतों का जातीय विभाजन जोर पकड़ेगा।

विपक्ष आराम से प्रतीक्षा कर सकता है क्योंकि उसका किसी हिंदीभाषी राज्य में शासन नहीं है। भाजपा संविधान संशोधन के बारे में सोच भी नहीं सकती है क्योंकि चुनाव प्रचार में यह बहुत बड़ा मुद्दा था। उसे अभी भी बढ़त हासिल है लेकिन वह रक्षात्मक रुख अपनाकर चुनौती देने वालों से निपटने के लिए जूझ रही है।

आईटीआई: रोजगार कौशल फिर से प्रासंगिक

केंद्र के बजट भाषणों में अब तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को बहुत कम जगह मिली है लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में कृषि के बाद अपनी नौ बजट प्राथमिकताओं की सूची में 'रोजगार एवं कौशल विकास' को दूसरा स्थान दिया। विभिन्न सहयोगों के माध्यम से आईटीआई को बेहतर बनाने और रोजगार सृजन करने के लिए 'रोजगार और कौशल विकास' विषय मुख्य आधार बना, जिससे यह बजट पिछले कई बजट से काफी अलग साबित हुआ।

यह संयोग हो सकता है कि देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद रोजगार के मौके तैयार करने के लिए शुरू किए गए आईटीआई को आजादी के 100 वर्ष पूरे होने और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की तैयारी के केंद्र में लाया जा रहा है। आईटीआई एक बार फिर से प्रासंगिक हो गया है लेकिन सवाल यह है कि रोजगार सृजन के अपने प्राथमिक उद्देश्य के लिहाज से उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों और स्नातकों को इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग कौशल देने के संदर्भ में आईटीआई किस जगह पर है?

केंद्र सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, आईटीआई और पूरे कौशल नेटवर्क को नियंत्रित करने वाली नीतियां बनाता है लेकिन इनमें से अधिकांश संस्थान, राज्य सरकारों या राज्यों द्वारा अधिकृत निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे में केंद्र की नीति/पाठ्यक्रम और राज्यों की प्रशिक्षण और रोजगार देने की क्षमता के बीच बेमेलपन स्पष्ट है। कुशल प्रशिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी, प्लेसमेंट के अप्रभावी तरीके, पुराना पाठ्यक्रम और प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपकरण न होना वास्तव में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना आईटीआई को विभिन्न राज्यों में करना पड़ता है।

आईटीआई की स्थापना के दशकों बाद भी इन संस्थानों में प्रभावी प्लेसमेंट सेल स्थापित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले अगस्त में श्रम एवं कौशल विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने कौशल विकास मंत्रालय से आईटीआई के लिए प्लेसमेंट और उद्यमिता सेल स्थापित करने का आग्रह किया था। साथ ही समिति ने आईटीआई के लिए अपने स्नातकों के रोजगार की स्थिति पर डेटा अपलोड करना अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने ही इन सिफारिशों पर अमल किया है। संसदीय समिति ने पाठ्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जैसे कि डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में अधिकांश की अभी सार्थक शुरुआत नहीं हुई है।

सामयिक सवाल
निवेदिता मुखर्जी

नीति आयोग ने भी पिछले साल आईटीआई तंत्र से जुड़े एक अध्ययन का जिक्र किया जिसमें बदलाव के सुझाव दिए गए थे। अध्ययन में बुनियादी ढांचे, नियमन और पाठ्यक्रम सामग्री के लिहाज से मौजूदा तंत्र की कमजोरियों के बारे में बताया गया था और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा की मान्यता के लिए एक केंद्रीय बोर्ड की स्थापना सहित सात सूत्री रणनीति का प्रस्ताव दिया गया था।

हालांकि, इस निराशाजनक पृष्ठभूमि के बावजूद कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। इस साल की शुरुआत में आई समाचार रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के आईटीआई ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में 72.3 प्रतिशत की प्लेसमेंट दर हासिल की और कई छात्रों को शीर्ष कंपनियों में नौकरी मिली। दिल्ली के कुछ आईटीआई 94 से 97 प्रतिशत तक की प्लेसमेंट दर हासिल करने में कामयाब रहे। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में प्लेसमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2023 में प्लेसमेंट दर 80 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष के 77.4 प्रतिशत से अधिक है।

रोजगार पर केंद्रित केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कुछ दिनों के भीतर ही वाहन क्षेत्र से जुड़ी कंपनी ह्युंडै ने कौशल विकास योजना के तहत नौ राज्यों में कई सौ आईटीआई छात्रों के लिए नए रोजगार के मौके देने की घोषणा की। उसी दौरान तेलंगाना सरकार ने 65 सरकारी आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की।

बजट की तैयारी के दौरान भी आईटीआई से संबंधित कुछ उत्साहजनक उदाहरण सामने आए। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में कई आईटीआई छात्रों की भर्ती जर्मनी से लेकर जापान, सऊदी अरब से लेकर इजरायल तक की विदेशी कंपनियों में की गई। यह राज्य, अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट केंद्र भी स्थापित कर रहा है। हाल ही में, जर्मनी ने कथित तौर पर केरल के संस्थानों से लगभग 4,000 पेशेवरों की भर्ती, रेलवे की आधुनिकीकरण परियोजना के लिए की जिनमें आईटीआई जैसे संस्थान भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हाल ही में बने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में से एक, आईटीआई शिकोहाबाद ने इलेक्ट्रिक वाहनों सहित नए पाठ्यक्रम शुरू किए।

आईटीआई की शुरुआत वर्ष 1948 में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में हुई थी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद अरब-की-सराय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देश के सबसे पुराने आईटीआई में से एक है जिसका नाम कई बार बदला गया है।

आईटीआई के कई दशकों के उतार-चढ़ाव भरे सफर को आंकड़ों से समझा जा सकता है। भारत के लगभग 14,993 सरकारी आईटीआई में 2021-22 में लगभग 25 लाख सीट थीं। प्रशिक्षुओं की संख्या 12 लाख थी। नए नामांकन वर्ष 2014 में हुए 9,46,000 नामांकन से बढ़कर वर्ष 2022 में 12,40,000 (12 लाख) हो गए।

आईटीआई प्लेसमेंट पर व्यापक डेटाबेस के अभाव में, दिल्ली के लोकप्रिय पूसा आईटीआई के ताजा आंकड़ों पर गौर किया जा सकता है। वर्ष 2022 में कुल 659 छात्रों में से 409 की नौकरी लगी, वहीं 101 उच्च शिक्षा के लिए गए और 149 छात्रों की नौकरी नहीं लगी।

हालांकि आंकड़े भी कहानी बताते हैं लेकिन कुछ राज्यों और कुछ संस्थानों द्वारा अलग तरह से काम करने की कोशिशें भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। केवल अधिक बजट खर्च से फर्क नहीं पड़ सकता। इसके बजाय केंद्र और राज्यों को सफल रोजगार के मौके की तलाश में एक नए दृष्टिकोण के साथ एक ही स्तर पर आना होगा।

आपका पक्ष

चीन पर निर्भरता का प्रश्न

इस समाचार पत्र में प्रकाशित लेख 'चीन पर निर्भरता' को आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने या चीन के निवेश या दोनों को भारत के हित में स्थापित करता है। व्यावहारिक पक्ष में प्रथम दृष्टया यही विमर्श सही प्रतीत होता है। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावी होना और मुख्यतः आत्मनिर्भरता से सेमी कंडक्टर और ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में चीन या अमेरिका पर निर्भरता समाप्त करने के साथ एक प्रमुख निर्यातक के रूप में स्थापित होना बहुत आवश्यक है। भारत का चीन के साथ 85 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा पिछले कई वर्षों के व्यापारिक घाटे को देखते हुए चिंताजनक नहीं है। भारत चीन के बीच आपसी व्यापार का स्वरूप बदल चुका है और अब केवल अपरिहार्य सेमी कंडक्टर और ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तक सीमित रह गया है जिनकी मांग भी बढ़ी है क्योंकि भारत ऑटोमोबाइल और

भारत को चीन से आयात निर्भरता कम करने तथा सेमीकंडक्टर का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है

इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व में अग्रणी स्थान ले चुका है। सेमी कंडक्टर और ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के उत्पादन में भारत विभिन्न प्रोत्साहन एवं पीएलआई के माध्यम से भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर है। यह भी तो प्रयास करने की जरूरत है कि चीन भारत से अपना आयात बढ़ाए और भारत के साथ सौहार्द्र स्थापित करे। यह चीन का भी प्रयास हो कि भारत चीन सीमा पर शांति रहे और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में अपना नाजायज अधिकार छोड़ दे। चीन के विस्तारवाद की सीमा यह है कि वह दक्षिण कोरिया को भी अपना भाग मानता है और 16 देशों के भूभाग पर उसका आधिपत्य है। भारत को ही चीन से व्यापार करने और अपने देश में चीनी निवेश की सीख बार बार क्यों दी जाती है और चीन को भारत को एक पड़ोसी देश के साथ यही सौहार्द्र और व्यापार की सीख क्यों नहीं दे जाती? इस एक तरफा संवाद की दिशा बदलनी चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

बांग्लादेश पर रहे पैनी नजर

तरक्की के रास्ते पर तेजी से दौड़ते शांत देश बांग्लादेश में अचानक ये परिस्थितियां नहीं बनीं कि रातोरात तख्तापलट हो गया। एक के बाद एक गलतियां सरकार करती रही और जनमानस की आग ने दावानल का रूप ले लिया। वर्ष 1971 के मुक्तिदाताओं को 30 फीसदी आरक्षण का मामला युवाओं की प्रमुख मांग थी जिसका विरोध हो रहा था। वर्ष 2018 में अवामी लीग ने इसे हटा भी दिया था परंतु जून 2024 के अदालत के निर्णय ने फिर आग भड़का दी। उस पर शेख हसीना ने आंदोलनकारियों को रजाकार के खिताब से नवाजा तो लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए। अतः शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। देश में व्याप्त भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ने लोगों की जिंदगी मुश्किल की हुई थी। बेरोजगारी और महंगाई ने आमजन का जीवन कठिन बना दिया था। लेकिन सरकार इन सबसे बेफिक्र रही। तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अब भारत को बांग्लादेश के माहौल को बहुत चौकन्ना होकर देखना होगा और सावधान रहना होगा क्योंकि चीन पहले से ही घात लगाए बैठा है।

मुनीश कुमार, रेवाड़ी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

पेरिस के वर्सेल्स के ट्रायोन में रविवार को परीक्षण के लिए एक वोलोसिटी को तैयार करते वोलोकॉप्टर के कर्मचारी। वोलोकॉप्टर विद्युत से उड़ने वाला विमान है जो एडीपी समूह से जुड़े जर्मन निर्माता वोलोकॉप्टर द्वारा निर्मित है। वोलोसिटी एयर टैक्सी का उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे परिवहन केंद्रों तक ले जाना है।

चिंतन

हिंडनबर्ग को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं

भारत में एकबार फिर से हिंडनबर्ग का बम फूटा है। इस बार निशाने पर सेबी प्रमुख हैं। पहली बार जब इस अमेरिकी निवेश फर्म ने अडाणी समूह को अपने कई आरोपों से लपेटे में लिया था, तब भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। अडाणी समूह के शेयर को रातोंरात भारी नुकसान हुआ, निवेशकों के कई करोड़ रुपये डूब गए। उस वक्त शॉर्ट सेलिंग का खेल खेला गया था। भारत में अडाणी समूह विपक्ष के राजनीतिक निशाने पर रहा है, इसलिए जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो विपक्ष के राजनीतिक आरोपों को बल मिला। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें हिंडनबर्ग के आरोप बेदम साबित हो गए। उस वक्त सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया और पक्षपातपूर्ण शॉर्ट सेलिंग के मकसद से जारी रिपोर्ट को लेकर जवाब मांगा। इस नोटिस का तो हिंडनबर्ग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधबी पुरी बुच व उनके पति पर पर्दे के पीछे निवेश का आरोप मढ़ दिया है। हिंडनबर्ग ने शनिवार रात को जारी एक रिपोर्ट में संदेह जताया है कि अडाणी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख और उनके पति धवल बुच की अडाणी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। आरोप के जवाब में सेबी की प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी शोध एवं निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और चेयरपर्सन की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। हिंडनबर्ग के इन आरोपों के जवाब में बुच दंपति ने रविवार शाम को जारी एक विस्तृत बयान में कहा कि आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट के एक फंड में उनका निवेश सिंगापुर स्थित निजी नागरिक के रूप में किया गया था। माधबी के सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल होने से दो साल पहले यह निवेश किया गया था। इसके साथ ही दंपति ने कहा कि 2019 से ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार धवल निजी इक्विटी फर्म के रियल एस्टेट पक्ष से नहीं जुड़े हैं। वर्ष 2017 में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में माधबी की नियुक्ति के तुरंत बाद उनकी दो परामर्श कंपनियां निष्क्रिय हो गई थीं। चूंकि, भारत में कई तरह के नियामकीय उल्लंघनों के लिए हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस का जवाब देने के बजाय उसने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और सेबी चेयरपर्सन की छवि भंजन का विकल्प चुना है। संपदा प्रबंधन कंपनी 360 वन ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में किए गए दावों पर सफाई दी है कि उसके पूर्ववर्ती आईपीई-प्लस फंड-1 ने अडाणी समूह के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया था। कंपनी 360 वन (पूर्व में आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट) ने एक बयान में कहा कि सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का इस निवेश फंड में कुल प्रवाह का 1.5 प्रतिशत से भी कम निवेश था और किसी भी निवेशक की निवेश निर्णयों में कोई संलिप्तता नहीं थी। बुच ने कहा कि फंड ने किसी भी समय किसी भी अडाणी समूह की कंपनी के किसी भी बॉन्ड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया। भारतीय कंपनी व नियामकों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित रही है, यह साबित हो चुका है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडाणी ग्रुप ने भी खंडन किया है कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। इस बार भी सेबी प्रमुख पर लगे आरोपों पर विपक्ष की राजनीति तेज हो गई है, जो निराशाजनक है। विपक्ष को देखना चाहिए कि एक अमेरिकी फर्म की मंशा क्या है? भारत क्यों निशाने पर है?

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस

डॉ. अशोक कुमार वर्मा

युवाओं को चाहिए नई दिशा

संसार के 195 देश हैं और भारत इनमें जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। इसके साथ ही भारत संसार का सबसे युवा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता था लेकिन आज भारत विश्व का सर्वोच्च जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यूएनएफपीए द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या 15 से 64 आयु वर्ग के व्यक्तियों की है जबकि 65 वर्ष से ऊपर की आयु के मात्र 7 प्रतिशत लोग हैं। संसार में आयु समूह की कोई सार्वभौमिक रूप से सहमत अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है तथापि भारत की राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को युवा माना जाता है लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तकनीकी विज्ञान, इंटरनेट और संचार साधनों के साथ साथ मोबाइल कंप्यूटर आदि संसाधनों की पहुँच के फलस्वरूप 10 से 11 वर्ष का बच्चा भी मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व हो चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। यद्यपि भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथापि 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर वर्ष 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 12 अगस्त 2000 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। तब से लेकर हर वर्ष यह दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे के कारणों पर चिंतन करना आवश्यक है। युवा किसी भी देश के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि वह ही देश का भविष्य है। जिस देश का युवा जागरूक होगा वह देश उतनी ही शीघ्रता से विकास की और बढ़ेगा। इसीलिए सरकार द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने और समाज में उनकी भूमिका और योगदान को पहचानने के लिए समर्पित है। किसी भी देश के विकास में युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन विकसित और विकासशील दोनों देशों में, युवाओं को मानसिक और सामाजिक जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, युवाओं को इन चुनौतियों के बारे में जागरूक करने, देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनकी क्षमता का सम्मान करने के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।

युवाओं की ऊर्जा, शक्ति और सोच को सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाना माता-पिता, समाज और राष्ट्र का दायित्व है। 10 से 18 वर्ष की आयु युवाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। वे अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। वे अपने शिक्षकों, मित्रों, चलचित्रों से बहुत अधिक प्रभावित होकर उनसे सकारात्मक और नकारात्मक सीख लेते हैं। सत्य तो यह है कि ये कच्चे घड़े के समान होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से बर्तन आदि बनाता है और जो आकृति वह चाहता है वैसी आकृति बना देता है उसी प्रकार समाज और आसपास के लोग जैसे होते हैं वैसे ही युवा बन जाते हैं। जैसा संग वैसा रंग वाली युक्ति यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। माँ बच्चे के लिए सबसे प्रथम गुरु है। छत्रपति शिवाजी का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि बाल्यावस्था में ही उनकी माता जी ने उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी। परिणामस्वरूप छत्रपति शिवाजी महान शासक जी नहीं बने अपितु राष्ट्र के महानायक भी बने।

आज युवा पीढ़ी को नई सोच के साथ साथ सकारात्मक दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है। भारत का युवा प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उसकी विद्यालय की प्रारम्भिक शिक्षा में ही देश प्रेम, नैतिक मूल्य, पर्यावरण के प्रति सजगता, राष्ट्र के प्रति दायित्व, संस्कार, भारत की संस्कृति और संस्कार के अध्याय जोड़े जाएं ताकि उसका जीवन नैतिकता से पूर्ण हो। महापुरुषों के चरित्र उनकी शिक्षा के अध्याय में जोड़ने की आवश्यकता है। अल्पायु में खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। ऐसे चरित्र उनकी शिक्षा का अध्याय होने चाहिए। क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जीवनी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा दी थी। इतना ही नहीं शिक्षा के साथ साथ जीविका उपार्जन के लिए कार्यशाला की नियमित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि युवा शक्ति विदेशों की और प्रस्थान न करें।

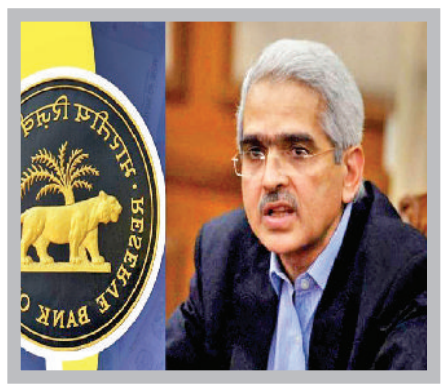

(लेखक पुलिस अधिकारी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मौद्रिक समीक्षा
सतीश सिंह

महंगाई व विकास के बीच संतुलन

मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार रेपो दर में बदलाव नहीं करके इसे 6.5 प्रतिशत के स्तर पर यथावत रखा है। इसके पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की गई थी। भारत में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के बावजूद चिंताजनक स्तर पर है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखा गया है। महंगाई को लेकर केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा संवेदनशील है और यह महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ताकि आम आदमी को परेशानी भी नहीं हो और विकास की रफ्तार भी तेज बनी रहे।

महंगाई और विकास के बीच संतुलन साधने के लिए ताजा मौद्रिक समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार रेपो दर में बदलाव नहीं करके इसे 6.5 प्रतिशत के स्तर पर यथावत रखा है। इसके पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की गई थी। रिजर्व बैंक मुख्य तौर पर रेपो दर में बढ़ोतरी करके महंगाई से लड़ने की कोशिश करता है। जब रेपो दर अधिक होता है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है, जिसके कारण बैंक भी ग्राहकों को महंगी दर पर कर्ज देते हैं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है और लोगों की जेब में पैसे नहीं होने की वजह से वस्तुओं की मांग में कमी आती है और वस्तुओं व उत्पादों की कीमत अधिक होने के कारण इनकी बिक्री में कमी आती है, जिससे महंगाई में गिरावट दर्ज की जाती है।इसी तरह अर्थव्यवस्था में नरमी रहने पर विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के लिए बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ाने की कोशिश की जाती है और इसके लिए भी रेपो दर में कटौती की जाती है, ताकि बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दर पर कर्ज मिले और सस्ती दर पर कर्ज मिलने के बाद बैंक भी ग्राहकों को सस्ती दर पर कर्ज दे। मौजूदा समय में महंगाई दर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। केयर एज रेटिंग के अनुसार कर्ज दर के नरम नहीं होने के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में ऋण वृद्धि दर 16 प्रतिशत के आसपास रही है और वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 14 से 14.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही सकारात्मक है। हालांकि, इसे अपवाद वाली स्थिति कहा जा सकता है। बहरहाल, कर्ज देने की रफ्तार में तेजी बनी रहने के कारण आर्थिक गतिविधियों और विकास दर दोनों में तेजी आ रही है। इसी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने विकास अनुमान को 7.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है।

वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 6.1 प्रतिशत रही थी। वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से 1.2 प्रतिशत अधिक है यानी रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7 प्रतिशत लगाया था। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रही थी। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार विनिर्माण और खनन के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन से आलोच्य अवधि में विकास दर तेज रही। विनिर्माण क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में माइनस 2.2 प्रतिशत रही थी। इसी प्रकार खनन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 1.9 प्रतिशत रही थी. उल्लेखनीय है कि विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

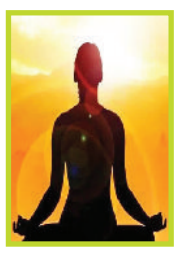

खुदरा महंगाई अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बाढ़ और बारिश की वजह से जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमत उफान पर रहने का अनुमान है। वैसे, सर्दी में इसमें कुछ नरमी आ सकती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष

2025 में मुद्रास्फीति के 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, लेकिन यह स्तर विकास के लिए निर्णायक निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जून महीने में खुदरा महंगाई मई महीने के मुकाबले 0.33 प्रतिशत बढ़कर 5.08 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई, जबकि मई महीने में यह 4.75 प्रतिशत रही थी, जो 12 महीने का निचला स्तर था। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई में कुछ कमी आई थी, लेकिन वह मई महीने से थोड़ी अधिक 4.83 प्रतिशत के स्तर पर थी। जून 2023 में खुदरा महंगाई 4.81 प्रतिशत थी, जबकि जुलाई 2023 में यह 4.44 प्रतिशत रही थी। महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6 प्रतिशत है, तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा। इसलिए महंगाई के स्तर के अनुरूप निवेशकों को निवेश करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रतिफल कम मिलेगा। महंगाई का बढ़ना और घटना उत्पाद की माँग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा उत्पाद खरीदेंगे और ज्यादा उत्पाद खरीदने से माँग बढ़ेगी और माँग के मुताबिक आपूर्ति नहीं होने पर उत्पादों की कीमत बढ़ेगी।इस तरह, बाजार महंगाई के दुष्चक्र में फंस जायेगा। बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या उत्पाद की कमी महंगाई का कारण बनता है। वहीं, अगर माँग कम होगी और आपूर्ति ज्यादा होगी तो महंगाई कम होगी।

ग्राहक खुदरा बाजार से सामान खरीदते हैं और बाजार में मौजूद उत्पादों की कीमत में हुए बदलाव को मापने का काम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) करता है। उत्पाद और सेवाओं के लिए जो औसत मूल्य चुकाया जाता है, सीपीआई उसी को मापता है।कच्चे तेल, उत्पादों की कीमतों, निर्माण की लागत के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं, जो खुदरा महंगाई दर को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में लगभग 300 उत्पाद ऐसे हैं, जिनकी कीमतों के आधार पर खुदरा महंगाई दर तय होती है। इसतरह, किसी की क्रय शक्ति को निर्धारित करने में मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तु एवं सेवा दोनों की कीमतों में इजाफा होता है, जिससे व्यक्ति की खरीददारी क्षमता कम हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम होती है। फिर, उनकी बिक्री कम हो जाती है, उनके उत्पादन में कमी आती है, कंपनी को घाटा होता है, कामगारों की छंटनी होती है, रोजगार सृजन में कमी आती है आदि। इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं और विकास की गति बाधित होती है। विगत कुछ महीनों से उधारी ब्याज दर के उच्च स्तर पर बने रहने के बावजूद भी ऋण वितरण में तेजी आ रही है और विकास दर की रफ्तार भी तेज बनी हुई है। वैसे, ऐसी स्थिति अपवाद वाली है।

एचएसबीसी इंडिया का पीएमआई आंकड़ा जुलाई 2024 में 58.1 रहा, जो जून महीने में 58.3 पॉइंट रहा था और मई महीने में 57.5 पॉइंट रहा, वहीं अप्रैल महीने में यह 58.8 पॉइंट रहा था। यह आंकड़ा आर्थिक गतिविधियों में तेजी को दर्शाता है और 50 पॉइंट से अधिक इस आंकड़े के रहने का अर्थ है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है। भारत में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के बावजूद चिंताजनक स्तर पर है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखा गया है। मंहगाई को लेकर केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा संवेदनशील है और यह महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ताकि आम आदमी को परेशानी भी नहीं हो और विकास की रफ्तार भी तेज बनी रहे।

(लेखक अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

मन को स्थिर रखना ही है जीवन का सूत्र

संकलित
दर्शन

काम, क्रोध, लोभ और मोह की स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी असत दृष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है, तो उसे यह संसार खुशनुमा लगने लगता है। काम अर्थात इच्छा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठी इच्छा की पूर्ति होती है, तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है, पर वह यह भूल जाता है कि उसकी यह इच्छापूर्ति उसी तरह से उसके मन में एक और इच्छा जागृत करके उसके चित्त को अव्यवस्थित कर देगी, जिस तरह से जलती हुई अग्नि पूरी मात्र में घी पाने पर भी बुझती नहीं है, अपितु और वेग से जलने लगती है। इसी भांति से यदि अन्य किसी व्यक्ति के साथ विचार भिन्नता होती है तो वे दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने चित्त की सहज शांति खो बैठते हैं। इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुखी होता ही है, जो लाभ में रहता है वह भी हारे हुए पक्ष की ओर से आने वाली संभावित प्रतिक्रिया से हर दम चिंता में डूबा रहता है। और इस तरह से क्रोध भी व्यक्तियों को पीड़ित करने का कारण ही बनता है। वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं कि हमारे पास इतनी अथाह संपत्ति हो, जिसकी बराबरी धरती का कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी न कर सके और हमारी अपनी संतान भी ऐसी हो, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला न हो सके। रावण से लेकर कंस आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं, जो अपने जीवन में अपनी ऐसी ही मानसिक विकृतियों से कभी भी पार नहीं पा सके।

आखिर कर्म ही महान है

संकलित
प्रेरणा

एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहां गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछाः कहां चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया, उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूं कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत में मजबूत है लोकतंत्र

हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभी भी यहां के लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास है। अगर यहां लोकतंत्र पर लोगों को विश्वास नहीं होता तो लोग लंबी-लंबी कतारों में लगकर अपने कीमती मत का प्रयोग कर सरकारें न चुनते और न ही अपनी मांगों के लिए धरने-प्रदर्शन कर पाते। हाल ही में अमरीकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कितने लोग अपने यहां के लोकतंत्र से खुश या संतुष्ट हैं। इसमें हमारा देश एशिया का दूसरा और विश्व का तीसरा देश है। यहां लगभग 77 फीसदी नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश या संतुष्ट हैं। हमारे देश के लोकतंत्र पर उंगली उठाने वाले देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका आदि के लोग अपने लोकतंत्र से उतने संतुष्ट नहीं हैं। यह रपट उन लोगों को भी आईना दिखाती है, जो अपने ही देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं। *- किरण खरे, बलौदा बाजार*

करंट अफेयर

तुर्किये ने इंस्टाग्राम पर लगाया प्रतिबंध हटाया

तुर्किये ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच शनिवार को बहाल कर दी। देश के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण ने दो अगस्त को बिना कोई विशेष कारण बताए इंस्टाग्राम तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी थी। बाद में सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि प्रतिबंध इसलिए लगाया गया, क्योंकि सोशल मीडिया मंच तुर्किये के कानूनों का पालन करने में विफल रहा है। तुर्किये के परिवहन एवं बुनियादी ढांचा मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'इंस्टाग्राम के अधिकारियों के साथ बातचीत में हमें आश्वासन दिया गया कि हमारा अनुरोध स्वीकार किया जाएगा, खासतौर पर आपराधिक गतिविधियों से संबंधित अनुरोध। हमसे वादा किया गया कि हम उपयोगकर्ताओं को सेंसर करने के उपायों पर मिलकर काम करेंगे।' उरालोगलू ने 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि इंस्टाग्राम 'तुर्किये के कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और जिन मामलों में कानून का उल्लंघन किया गया है, उनमें त्वरित एवं प्रभावी हस्तक्षेप करेगा।' मंत्री ने कहा कि 'आतंकवादी' संगठनों से जुड़े सभी अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

ऑफ बीट

खाज एक प्रकार का त्वचा संक्रमण है

खाज एक प्रकार का त्वचा संक्रमण है, जो सरकोप्टेस स्कैबी (एक प्रकार के सूक्ष्म कीटाणु) के कारण होता है। यह हमारी त्वचा के नीचे पनपता है धीरे-धीरे फैलने लगता है। आमतौर पर इसके लक्षणों में खुजली भरे दाने, त्वचा पर सूजन या फिर खरोंच शामिल हैं। आपको त्वचा फटती भी नजर आ सकती हैं, जो दिखने में मोटी, छोटी या फिर बेरंग लकीरों जैसी प्रतीत होती है। खाज सामान्य रूप से आपके शरीर पर ऐसी जगह होती है, जहां त्वचा आपस में जुड़ती है जैसे उंगलियों के बीच, काख (आर्मपिट) या फिर गुप्तांग वाली जगह। रात में या फिर गर्म पानी से नहाने के बाद खाज ज्यादा तेज होने लगती है। खाज अन्य प्रकार की त्वचा समस्याओं की ही तरह दिखाई देती है जैसे एक्जिमा, सोरायसिस या फिर रूखी त्वचा। इस संक्रामक त्वचा रोग को फैलाने वाला कीट इंसानों के शरीर के अलावा अन्य चीजों पर मुश्किल से 48 घंटों तक जीवित रहता है। इतना ही नहीं खुजली करने से आपको दूसरा जीवाणु (बैक्टीरियल) संक्रमण हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनियाभर में कम से कम 20 करोड़ लोगों को कभी न कभी खाज होती है।

ट्रेंड

नटवर का समृद्ध योगदान

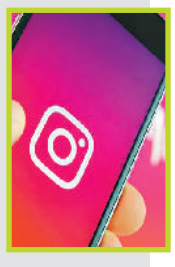

नटवर सिंह के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया। वह अपनी बुद्धिमत्ता के साथ-साथ बेहतरीन लेखन के लिए भी जाने जाते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। **-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

निधन से दुखी हूं

पूर्व विदेश मंत्री, पद्म भूषण से सम्मानित कुंअर नटवर सिंह जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। **-अखिलेश यादव, पूर्व सीएम यूपी**

अर्थव्यवस्था में समस्याएं

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बैंकों में लोगों का भरोसा बहाल करने की है। अर्थव्यवस्था में कई तरह की समस्याएं हैं। **-सालेहुद्दीन अहमद, वित्त व योजना सलाहकार, बांग्लादेश**

लोकार्नो को धन्यवाद

इस बेहद सुंदर, सांस्कृतिक, कलात्मक शहर लोकार्नो में बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। शाहरुख खान को स्विट्जरलैंड में 'पार्डो अला कैरियरा अवार्ड-लोकार्नो टूरिज्म' या 'करियर लेपर्ड' से सम्मानित किया गया। **-शाहरुख खान, अभिनेता**

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।